Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] विधान सभा के पंचम सत्र का पचासवां दिवस [संख्या 20

सोमवार,

दिनांक 8 मई, 1972

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(योजना, पशुपालन, जन-स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, सहकारिता, शिक्षा, वन, जन-सम्पर्क, आबकारी, भू-जल मण्डल, कृषि, अकाल सहायता-विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री प्रद्युम्नसिंह।

प्रति व्यक्ति आय

344. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. राज्य में प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय कितनी है ?

2. इस आय को निश्चित करने का क्या आधार है ?

3. दूसरे प्रान्तों की तुलना में राजस्थान का स्थान कहां पर आता है ?

योजना मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) मासिक आय के आंकड़े अलग से तैयार नहीं किए जाते। किन्तु वर्ष 1970-71 में प्रचलित कीमतों पर प्रारम्भिक अनुमानों के आधार पर प्रति व्यक्ति वार्षिक आय रु. 630 आंकी गई है। इसकी मासिक औसत (12 से भाग देने पर) रुपया 52.50 आती है।

(2) राज्य आय को उसी वर्ष की अनुमानित जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय आंकी जाती है। प्रति व्यक्ति आय को 12 से भाग देकर मासिक औसत बताया गया है।

(3) जब तक सभी राज्यों के वर्ष 1970-71 के आंकड़े उपलब्ध न हों राजस्थान का स्थान बताना संभव नहीं है। इस वर्ष के अन्य राज्यों के आंकड़े अप्राप्य हैं।

Page No 2

श्री प्रद्युम्नसिंह : मन्त्री महोदय ने करेंट मूल्यों पर आय बताई है 630) वार्षिक आय। मैं जानकारी चाहता हूं कि स्थिर मूल्यों के आधार पर मासिक आय और वार्षिक आय क्या है ? दूसरी बात···

श्री चन्दनमल बैद : एक एक करके पूछें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बार बार आपको तकलीफ नहीं देना चाहता।

श्री चन्दनमल बैद : मैं तकलीफ करने को तैयार हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : किस साल के मूल्यों के आधार पर···

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : हमेशा 1955-56 को बेस यीअर माना जाता है।

श्री चन्दनमल बैद : जी नहीं। 1954-55 को हम यीअर मानकर चलते हैं। उसके अनुसार वार्षिक आय 302) है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह 302) जो आपने बताया है····

श्री चन्दनमल बैद : 1954-55 में जो वार्षिक आय थी वह उस समय के मूल्यों के आधार पर 233) थी। 1970-71 में 302) है। 29.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो आंकड़े मन्त्री महोदय ने दिए हैं उनसे जाहिर होता है कि राजस्थान में औसत आदमी की आमदनी 50) प्रति माह से बहुत कम है। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो आय कर दाता हैं, उनकी जो आमदनी है करोड़ों रुपये प्रति वर्ष की, क्या इस औसत आय को निकालने के लिए, उनकी आमदनी को भी जोड़ा गया है ?

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्यों को गलतफहमी है। 1954-55 के स्थिर मूल्यों पर आमदनी 237 निकाली गई तब भी राजस्थान का हर निवासी शामिल था। और 1970-71 में औसत आय निकाली गई तब भी राजस्थान का हर व्यक्ति चाहे अमीर चाहे गरीब शामिल है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : प्रश्न यह नहीं है। सवाल यह है कि इस तरह के आंकड़े निकाल कर सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। दरअसल प्रश्न यह है कि आमदनी 50) रुपया माहवार से कम है और बड़े बड़े आदमियों की आमदनी को इनक्लूड कर दिया गया है। हकीकत में यह आमदनी कितनी है, आज तक पता नहीं। औसत आदमी की औसत आमदनी क्या है ? हालांकि मन्त्री महोदय के पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन इस बात का प्रयत्न होना चाहिए कि ऊपर हवा में उड़ने से काम नहीं चलेगा। आप बड़े बड़े आदमियों की आमदनी को छोड़ कर इस प्रकार के आंकड़े दे रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आपने पूछा है, राजस्थान में प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय कितनी है। औसत आदमी का नहीं पूछा है। इसका तरीका तो यही है जो मैंने बताया है। अगर माननीय सदस्य को सन्तोष नहीं है तो मुझे दुःख है।

श्री केदारनाथ : प्रश्न यह है कि प्लानिंग कमीशन ने प्रति व्यक्ति आय के पैटर्न को बदलने के लिए जो कहा है क्लासवाइज

(श्री केदारनाथ) सैक्शनवाइज, कम्यूनिटिवाइज आमदनी निकालने के लिए कहा है, इस बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : हमारी चौथी योजना तक कितना लक्ष्य था, वास्तव में कितनी बढ़ी ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं बता चुका हूं 29.6 प्रतिशत।

श्री केदारनाथ : मैंने प्रश्न पूछा है कि प्लानिंग कमीशन ने इसके पैटर्न को बदलने के लिए कहा है, क्या उस तरह आमदनी निकालने के लिए आपने कोई मशीनरी इनवाल्व की है ?

श्री चन्दनमल बैद : अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

आपरेशन फ्लड योजना

345-श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि पशुपालन विभाग द्वारा दुग्ध विकास के लिए 'ऑपरेशन फ्लड' नामक 4 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. उक्त योजना की राशि की उपलब्धि किस प्रकार कब तक करदी जाएगी ?

3. उक्त योजना से किस क्षेत्र को किस प्रकार लाभ पहुंचेगा ?

पशुपालन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां। अभी यह योजना भारत सरकार के विचाराधीन है। अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने पर ही वह सदन की मेज पर रखी जा सकेगी।

(2) इस योजना हेतु 3.82 करोड़ रुपये भारतीय दुग्धालय निगम द्वारा प्राप्त होंगे। योजना स्वीकृत होने पर ही यह धन-राशि उपलब्ध हो सकेगी।

(3) बीकानेर तथा जोधपुर प्रत्येक स्थान पर एक लाख की क्षमता का दुग्ध सन्तुलन संयत्र लगाया जावेगा। बीकानेर प्लांट का दुग्ध संचय क्षेत्र बीकानेर, चूरू तथा गंगानगर के क्षेत्रों में होगा। जोधपुर यंत्र का दुग्ध संचय क्षेत्र जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर जैसलमेर व बाड़मेर में होगा। इसके अलावा अलवर एवं भरतपुर में 50,000 लिटर क्षमता के प्रदायक (फीडर) दुग्धालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही एक प्रदाय संयंत्र (फीड प्लांट) पशु संकरण का कार्यक्रम, चारा विकास एवं पशु स्वास्थ्य सुधार की योजनायें भी सम्मिलित की गई है। इस कार्यक्रम से उपरोक्त क्षेत्रों में उपलब्ध अतिरिक्त दूध इकट्ठा किया जाकर दिल्ली दुग्ध वितरण योजना को भेजा जायेगा। इससे पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य मिलेगा तथा अधिक दूध उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इस योजना से बाड़मेर जिले का कौनसा एरिया कौनसा स्थान कवर होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : बाड़मेर जिले का वह एरिया जो जोधपुर से लगा हुआ है

Page No 4

(श्री परसराम मदेरणा)

वह कवर होगा। प्रस्तावित योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया है। न ही अभी स्वीकृति मिली है लेकिन प्लांट बालोतरा में लगेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : चोहटन एरिया में बड़ी अच्छी अच्छी गायें हैं और जो जोधपुर में गायें आती हैं उस क्षेत्र से आती हैं तो चोहटन क्षेत्र को बाड़मेर क्षेत्र से प्रस्तावित योजना में इनक्लूड करने का प्रयास करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : इस स्टेज पर आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जो अच्छी ब्रीड के लिए राशि रखी है, डेयरीज का प्रावधान रखा है यह राशि अलग है या योजना में शामिल है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह अलग है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जो एरिया मैंने बताया है बाड़मेर जिले का महत्वपूर्ण एरिया है पशुधन की दृष्टि से, जो चोहटन और शिव एरिया है, अगर इनक्लुड नहीं करेंगे तो बाड़मेर जिले को कोई लाभ नहीं होगा।

श्री परसराम मदेरणा : सवाल धन-राशि का है। जो भारत सरकार और वर्ल्ड फुड आरगनाइजेशन के बीच समझौता हुआ, उसके अन्तर्गत जोधपुर योजना सम्मिलित नहीं थी, उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा प्रयास किया गया, उसके बाद में मिल्क कारपोरेशन ने स्वीकार कर लिया है। इन प्रप्पोजल, स्वीकार करते हैं कि जोधपुर में मिल्क प्लांट लगाया जाए लेकिन अब तक वर्ल्डफुड प्रोग्राम के अन्तर्गत जो फुड एण्ड एग्रीकल्चरल आरगेनाइजेशन है, उसकी टीम भारत में दौरा कर रही है और उसके चेयरमेन भी बम्बई और दूसरे इलाकों में घूम रहे हैं। अब तक उन्होंने स्वीकृत नहीं किया है। जो समझौता भारत सरकार और एफ. ए. ओ. के बीच में हुआ था उसमें जोधपुर में किसी प्रकार प्लांट दुग्ध योजना के लिए कोई नहीं था। एडीशनल कोशिश की जा रही है और उसकी स्वीकृति होने के बाद में जो पैसा मिलने वाला है वह प्रस्तावित योजना पर लगाया जायेगा। अब तक स्वीकृत नहीं हुआ है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह जो प्रस्तावित योजना है, इसके लिये किस प्रकार प्रबन्ध किया जाएगा, यह राशि फाइनेन्शल इन्सटीट्यूशन्स से उपलब्ध की जाएगी।

श्री परसराम मदेरणा : प्रस्तावित योजना के अनुसार काम हो रहा है। अभी तक तो बीकानेर में प्लान्ट होगा, उस पर राज्य स्तर पर विचार किया जा रहा है। उसका प्रारूप तैयार हो गया है और स्कीम फाईनल बनकर तैयार हो गयी है। इसके लिये कुल 139 लाख रुपये की योजना तैयार हुई है जिसमें तीन आते हैं। इसका पैसा तीन जगह से आयेगा। 40 लाख रुपये तो इण्डियन डेयरी कारपोरेशन से प्राप्त होगा। 89 लाख रुपये स्टेट प्लान के प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मिलेगा और 40 लाख रुपये और प्राप्त होगा। इस प्रकार कुल 139 लाख रुपये की राशि है।

श्री भीमसेन : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस मामले को जल्दी ही क्यों नहीं किया जा रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : तीन जगहों से पैसा आना है। काम दिल्ली की स्कीम के अन्तर्गत चल रहा है। प्लान्ट अभी तक लगे हुए नहीं है और और भी कई कारण हैं जिससे थोड़ा समय लग गया है।

श्री भीमसेन : ये कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं कुछ नहीं कह सकता अभी।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, जमीन दी जा चुकी है, मशीनरी आ चुकी है, फिर भी इतना समय लग रहा है। इसका कन्सट्रक्शन कब तक हो जायेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : ये अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 346। श्री राजेन्द्रसिंह।

नगरपालिका शाहपुरा द्वारा निर्माण कार्य की स्वीकृति

346. **श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा)** : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

1. क्या यह सही है कि नगरपालिका शाहपुरा जिला भीलवाड़ा द्वारा कुण्ड दरवाजे के बाहर किसी व्यक्ति को तामीर की स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां तो कब और क्या स्वीकृति थी ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

2. क्या यह सत्य है कि नगरपालिका द्वारा उक्त निर्णय को बदल दिया गया है ? यदि हां तो कब ? और क्या ऐसा करना नियमानुसार है ?

3. क्या यह सही है कि श्री ज्ञानसिंह पुत्र श्री लाभसिंह को उपजिलाधीश-शाहपुरा ने उक्त तामीर रोकने के लिये कोई नोटिस दिया है ? यदि हां तो कब ?

4. क्या यह सही है कि नगरपालिका के नियमानुसार यह कार्यवाही पालिका द्वारा की जानी चाहिये थी ? यदि हां, तो कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

5. क्या यह सत्य है कि उपजिलाधीश शाहपुरा द्वारा अभी हाल ही में पुलिस फोर्स द्वारा तामीर को बन्द करवा दिया गया है और तामीर को तुड़वाया जा रहा है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न की सूचना जो चाही वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस लिये इसे स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री राजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो गम्भीर स्थिति है। अभी तक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और इसमें समय लग जावेगा। और तब तक सड़क बन जावेगी और मकान तोड़ दिया जावेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार ऐसा हुक्म दें कि वह मकान नहीं तोड़ा जाये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इनका कहना यह है कि मन्त्री महोदय ऐसे आदेश जारी करें कि मकान तुड़वाना बन्द हो जाये।

श्री अध्यक्ष : चेतराम ।

टोडाभीम में पेय जल की व्यवस्था

347. श्री चेतराम (टोडाभीम): क्या जनस्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि टोडाभीम (जिला सवाई माधोपुर) जल योजना के लिये बनाये गये कुओं में पानी का अभाव है और गर्मियों में नलों से बहुत कम पानी दिया जाता है जो कि नगर की पेय जल समस्या को हल नहीं कर पाता ? यदि हां तो क्या सरकार इस संकट को दूर करने के लिये कोई धनराशि निर्धारित कर योजना बना रही है ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : जी हां, जी हां, इस वक्त जो पानी सप्लाई हो रहा है, वह पर्याप्त मात्रा में नहीं है और उसके लिये नये श्रोतों की तलाश की जा रही है ।

श्री चेतराम : इसकी व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

श्री चन्दनमल बैद : इसके लिये तो अगर म्युनिसिपैलिटी हमें कुए दे दें तो हम इस समस्या के लिये कुछ कर सकते हैं । ऐसा पहले आश्वासन म्युनिसपैलिटी ने कुए देने का राज्य सरकार को दिया था । वहां पर 3 कुए खोदे गये थे पर उससे जो पानी की सप्लाई होती है, वह पर्याप्त मात्रा में नहीं है । अगर माननीय सदस्य म्युनिसपैलिटी से कुए दिलवा दें, तो हम कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय, अगर म्युनिसपैलिटी के पास कुए नहीं हों, तो फिर जनता को जो पेयजल की समस्या है, उसका क्या होगा । क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह पेय जल की समस्या का हल निकाले ।

श्री चन्दनमल बैद : राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । इस लिये तो कहा है कि अगर नगरपालिका कुए दे दे तो निश्चित रूप से पानी की सप्लाई में सुधार होगा ।

प्रश्न संख्या 348

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 349

श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 350

श्री मनोहर कोठारी ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री मोहरसिंह ।

सहकारिता विभाग के निरीक्षक

351. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. सहकारिता विभाग में पंचायत विभाग व अन्य विभागों से आए हुए कर्मचारियों को निरीक्षक के पद पर लगाया गया

(श्री मोहरसिंह)

..था उनकी वरिष्ठता निर्धारित की गई अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गयी?

2. ऐसे लोगों का वेतन स्थिरिकरण नवीन वेतनमान 1961-66 और 1968 में किया गया अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं किया गया?

3. जिन लोगों का वेतन स्थिरिकरण नहीं किया गया, उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

4. जिन लोगों की वरिष्ठता निर्धारित नहीं की गई, उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

5. इस समस्या का समाधान कब तक कर दिया जावेगा;

सहकारिता मन्त्री (श्री नारायणसिंह): सहकारिता विभाग में पंचायत व अन्य विभागों से आये हुए 19 कर्मचारियों को तो समावेश नियम 1969 में लागू होने के पश्चात दिनांक 22-10-70 को जारी की गई वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किया जा चुका है। शेष कर्मचारियों को उनके सेवा विवरण सम्बन्धित विभागों से प्राप्त न होने के कारण उनकी वरिष्ठता अब तक निर्धारित नहीं की जा सकी है।

(2) जिन कर्मचारियों का सेवा विवरण पूर्व प्राप्त हो चुकी है उनका नवीन वेतन श्रृंखला 1961-66 व 1968 में स्थरीकरण किया जा चुका है शेष 58 कर्मचारियों का सम्बन्धित विभाग द्वारा 1961 की वेतन श्रृंखला में स्थरीकरण नहीं किये जाने के कारण सहकारिता विभाग में 1966 व 68 के नवीन वेतनमानों में स्थिरीकरण नहीं किया जा सका।

(3) जिन लोगों का स्थरीकरण नहीं किया जा सका है उनकी सूची परिशिष्ट 1 "क" पर संलग्न है।

(4) जिन लोगों की वरिष्ठता निर्धारित नहीं की गई है उनकी सूची परिशिष्ट 1 "ख" पर संलग्न है।

(5) शेष 116 कर्मचारियों का सेवा-विवरण सम्बन्धित विभागों से प्राप्त हो चुका है। अतः शीघ्र ही वरिष्ठता सूची में शामिल कर लिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट सं. 1 देखें)

श्री मोहरसिंह: ये कब तक हो जावेगा कितना समय हो गया है और अभी तक लोगों की वरिष्ठता सूची नहीं निकाली गयी है। लोगों का फिक्सेशन नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है। आखिर कब तक तक हो जायेगा।

श्री नारायणसिंह: अब जल्दी ही फाईनल कर दिया जायेगा।

श्री मोहरसिंह: जल्दी का क्या मतलब हुआ। एक साल या दो साल या छः महीने या 30 साल तक लग जायेंगे। आखिर जल्दी का मतलब क्या? कोई स्पेसीफाइड टाइम तो होना चाहिये।

श्री नारायणसिंह: इसमें स्पेसीफाइड टाइम की बात तो इसलिये नहीं हो सकती है, क्योंकि कई लोगों के सर्विस रेकार्ड नहीं आये हैं। कई लोग इनमें अलग अलग डिपार्टमेन्ट्स से आये हैं, तो उनके सर्विस रेकार्ड के बारे में इनफोरमेशन आने में देर लगती है इसलिये थोड़ा समय तो लग ही जाता है।

Page No 8

श्री मोहरसिंह : सर्विस रेकार्ड कोई राजस्थान के बाहर से थोड़ी ही आ रहा है। है तो राजस्थान सरकार के कर्मचारी ही।

श्री नारायणसिंह : बात यह है कि लोग वेरियस डिपार्टमेन्ट से सरप्लस होकर आये थे। उनके सर्विस रेकार्ड अलग अलग डिपार्टमेन्ट्स से वेरीफाई होकर आने में समय लग जाता है अब जल्दी से जल्दी इनफोरमेशन क्लेक्ट करवा कर पूरा कार्य करा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री केदारनाथ।

"न्यास की कोई योजना नहीं," प्रमाण-पत्र देने का आधार

352. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

1. जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा अपने क्षेत्र के किसी भूखण्ड के लिये न्यास की कोई योजना नहीं है का प्रमाण-पत्र देने का क्या नियम है ?

2. क्या ऐसा प्रमाण-पत्र देते समय किसी भू-खण्ड के विषय में न्यास की बैठक में विचार किया जाता है ? यदि हां, तो जनवरी, 1965 से अब तक न्यास द्वारा कुल कितने प्रमाण-पत्र इस आशय के प्रदान किये गये ? ये प्रमाण-पत्र किस भू-खण्ड के लिये किन किन व्यक्तियों को दिये गये, ब्लॉक खसरा नम्बर, भूमि का नाप, प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम और व्यवसाय तथा किस कार्य के लिये विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

3. क्या "न्यास की कोई योजना नहीं है" का प्रमाण-पत्र देने का अधिकार न्यास ने अध्यक्ष तथा सचिव को दे रखा है ? यदि हां तो कब और किस प्रस्ताव के आधीन ?

4. क्या अध्यक्ष तथा सचिव द्वारा बिना न्यास की स्वीकृति के न्यास की कोई योजना नहीं है के प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे प्रमात्र-पत्र किस व्यक्ति के लिये कब और क्यों दिये गये ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट सं. 2 देखें)

(3) नगर न्यास जयपुर ने अपने प्रस्ताव संख्या 276 दिनांक 31-12-70 के द्वारा सिनेमा निर्माण के प्रति अनापति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में न्यास के अध्यक्ष को अधिकार दिये हैं।

(4) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री केदारनाथ : इसके लिये कितनी स्कीमस बनायी हुई है। इसके अलावा जो स्कीम बनी हुई है, क्या उनका कोई प्लान बन रहा है ?

श्री परसराम मदेरणा : इस काम के लिए जो भी स्कीम होती है उसके लिये नोन एवेलबिलिटी सरटिफिकेट दिया जाता है, उसके लिये कोई स्कीम नहीं है।

श्री केदारनाथ : मेरे कहने का मतलब यह है कि जो यह सिनेमा वगैरहा की बिल्डिंग्ज बनती है उसके लिये ......

श्री परसराम मदेरणा : ये बिल्डिंग्स वगैरहा जो जहां जहां बनते हैं, उसके लिए म्यूनिसपल बोर्ड व ट्रस्ट की ही कमेटी होती है।

श्री केदारनाथ : तो जो कमेटी है उनके रूल्स वगैरहा तो होंगे।

जिनके अन्तर्गत ये एन० ए० सी० वगैरहा दिये जाते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि नगर विकास न्यास ने ऐसे कार्य के लिये कोई सर्वे किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका सर्वे से क्या सम्बन्ध है। यह तो नो ओबजेक्शन सरटिफिकेट देने का प्रश्न है। वह न्यास द्वारा दिया जाता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल जयपुर) : नोन ओबजेक्शन के बारे में मेरा यह कहना है कि अगर यू. आई. टी. के पास कोई स्कीम नहीं तो, क्या शहर की चार दिवारी के बाहर भी म्यूनिसपैलिटी का अधिकार है कि जो भी खरीद फरोक्त हो, वह म्यूनिसपैलिटी से ही हो। और इसके लिये यू. आई. टी. का कोई क्षेत्र नहीं है

श्री परसराम मदेरणा : शहर के बाहर का क्षेत्र जो भी है उसमें म्यूनिसपैलिटी का कोई क्षेत्र नहीं है, वह तो यू. आई. टी. का क्षेत्र होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : चाहे यू आई. टी. के पास कोई योजना नहीं हो ? तो भी क्या यू. आई. टी. का ही अधिकार होगा। उसमें तो नगरपरिषद् को अधिकार होना चाहिये कि ....

श्री परसराम मदेरणा : अगर कोई शहर के बाहर का होगा तो ट्रस्ट के कार्य क्षेत्र में ही वह कार्य आयेगा। नगरपरिषद् के अन्तर्गत नहीं आयेगा।

प्र. सं. 353

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती भगवती देवी।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

श्रीमती मदनकौर।

बांस व कत्थे की ठेका प्रणाली

354. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

1. क्या यह सही है कि राज्य में कोयला और लकड़ी का प्रबन्ध विभागीय तौर पर कराया जाता है ?

2. यदि हां, राज्य में बांस एवं कत्थे का प्रबन्ध विभागीय तौर पर नहीं कराने का क्या कारण है ?

3. क्या यह सही है कि कत्था और विशेष रूप से बांस का प्रबन्ध करने में अधिक तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता होती है ?

4. क्या यह सही है कि बांस का प्रबन्ध निरन्तर ठेके प्रणाली से कराने के

Page No 10

(श्रीमती मदनकौर)

फलस्वरूप राज्य में बांस के जंगल लगभग समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया है ?

5. क्या राज्य सरकार बांस और कत्थे का प्रबन्ध इसी वर्ष से विभागीय तौर पर कराने का निर्णय लेगी ?

वन मन्त्री (श्री नारायणसिंह) :

(1) जी हां।

(2) बांस व कत्थे का कार्य परीक्षण के तौर पर कुछ कूपों में कराया गया हैं। बांस एवं कत्थे का कार्य भी विभागीय तौर पर कराने का सरकार विचार कर रही है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या 355

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह कुड़ी।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री निरंजननाथ आचार्य ।

स्मारिका के लिये विज्ञापन

356. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे --

1. कमला नेहरु टैक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट, मुलतानपुर उ. प्र. द्वारा प्रकाशित होने वाली स्मारिका के लिये राज्य के किन किन सरकारी विभागों व अन्य राजकीय संस्थानों द्वारा विज्ञापन दिये गये और किन के आदेश से दिये गये ?

2. उक्त विज्ञापनों को देने की तारीख एवं प्रत्येक विज्ञापन की धनराशि क्या है ?

3. क्या राज्य पथ परिवहन निगम को भी उक्त स्मारिका में विज्ञापन देने के लिये आदेश दिये गये ?

4. कमला नेहरु टैक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट सुलतानपुर के कौन कौन पदाधिकारी हैं ?

5. उक्त विज्ञापन किसका प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दिए गए ?

राज्य मन्त्री, जन सम्पर्क (श्रीमती कमला बेनीवाल) : इस स्मारिका को एक पृष्ठ (अन्तिम पृष्ठ) दो हजार रुपये (रुपये 2000) का विज्ञापन जन सम्पर्क विभाग द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार दिया गया। राज्य के अन्य विभागों व अन्य राजकीय संस्थाओं द्वारा सीधे दिये गये विज्ञापनों का ब्यौरा इस विभाग द्वारा नहीं रखा जाता।

(2) इस विभाग द्वारा इस स्मारिका को विज्ञापन दिनांक 29-5-72 को रुपये दो हजार का दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) विज्ञापन के लिये आवेदन जन सम्पर्क कार्यालय तथा संबंधित मन्त्री के कार्यालय में आये थे।

(कृपया परिशिष्ट सं० 3 देखें)

Page No 11

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह स्मारिका प्रकाशित हो गई और आपका विज्ञापन भी उसमें प्रकाशित हो गया, क्या यह ठीक है ?

श्रीमती कमला बैनीवाल : यह जानकारी मैं अभी देने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : और स्मारिका का नाम क्या है, इसकी जानकारी है ?

श्रीमती कमला बैनीवाल : जो चिट्ठी इस कार्यालय को प्राप्त हुई, उसमें उन्होंने अशोक होटल कन्वेन्शन हाल में स्टार नाईट का सामारोह आयोजित किया उसमें उस स्मारिका में योगदान देने के लिये चिट्ठी थी । उसके उत्तर में यह प्रार्थना-पत्र आया था ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रार्थना-पत्र आया है वह किन का है और आदेश किन मन्त्री महोदय का है ?

श्रीमती कमला बैनीवाल : इसके लिये निवेदन करने के लिये श्री के० एन० सिंह का नाम है जो फाउन्डर आफ मेमोरियल है ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : पूरा नाम यही है जो डिप्टी मिनिस्टर सेन्टर में है ?

श्रीमती कमला बैनीवाल : जी हां ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : और आपके विभाग में और कौनसे डिपार्टमेंट है जो आपके यहां से कोर्डनेटेड है और आप उनके लिये विज्ञापन देते हैं ।

श्रीमती कमला बैनीवाल : समस्त विवरण उपलब्ध नहीं है लेकिन इस स्मारिका के लिये दो हजार का विज्ञापन दिया गया है और विभागों के द्वारा और संस्थाओं के लिये कितना विज्ञापन दिया गया है । यहां से आदेश प्रसारित नहीं हुए हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह जो हजार रुपये दिये गये हैं क्या विज्ञापन प्रकाशित होने से पूर्व ही दे दिये गये हैं । क्या यह ठीक है ?

श्रीमती कमला बैनीवाल : जी हां ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या यह परम्परा पूर्व में रही है.......

श्रीमती कमला बैनीवाल : अभी तक नहीं दिया गया या दिया गया, यह नहीं कह सकती हूं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : विज्ञापन देने से पूर्व पैसे दिये जाने की व्यवस्था है या नहीं, प्रश्न दो हजार रुपये देने का है और दर का प्रश्न है माननीय के० एन० सिंह जो उप मंत्री है और यह तो आपके यहां का प्रश्न है । दो हजार रुपये उनको दिये गये हैं या नहीं दिये गये हैं और अगर दिये गये हैं तो क्या दिये गये हैं जब तक आपका विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ......

श्रीमती कमला बैनीवाल : यह मैं आपको मालूम करके बता सकती हूं । मैं वैसे इसलिये नहीं मानती हूं कि आम तौर से विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद ही और उस विज्ञापन की कापी प्राप्त होने के बाद रुपया दिया जाता है । अब आपने विशेष तौर से कहा है कि विज्ञापन प्रकाशित होने से पूर्व ही पैसा दे दिया गया है तो मैं इसकी जांच करवा लूंगी ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें नम्बर दिया है केदार नाथ फाउन्डर ऑफ नेशनल मेमोरियल चेम्बर है। यह वही माननीय उप मंत्री महोदय हैं, जिनका जिक्र इस विज्ञापन में देने ··

श्रीमती कमला बेनीवाल : केदारनाथ सिंह का छोटा नाम के० एन० सिंह हो सकता है लेकिन श्री के० एन० सिंह इज दी फाउन्डर आफ दी चेम्बर।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने तो अभी कहा है यह वही के० एन० सिंह जो सेन्टर में उप मंत्री हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह मैंने नहीं कहा है, यह तो आपने कहा कि क्या यह वे ही के० एन० सिंह जो सेन्टर में उप मंत्री हैं और मैंने कहा जी हां, हो सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या आप बता सकती हैं क्या इन्होंने जयपुर में आकर प्रार्थना-पत्र दिया या दिल्ली से ही प्रार्थना-पत्र दिया था या किसी के साथ प्रार्थना-पत्र भेजा है और यह विज्ञापन का संग्रह करने के लिये कब से दिया ··

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस चिट्ठी के साथ दो पेम्पलेट प्राप्त हुये हैं और जो संस्था की गतिविधियां होगी वह शायद होगी······

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय क्या यह सही है कि इस विज्ञापन की जो मांग की गई है वह सुल्तानपुर में कमला नेहरू मेमोरियल की स्थापना के लिये रुपया इकट्ठा करने के लिये की गई है, जिससे वह इन्स्टीट्यूट जल्दी बन सके, इसलिये इस प्रकार का विज्ञापन इकट्ठा किया गया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं, जो दरख्वास्त पेश की गई है, उसके मसविदे को भी जानना चाहता हूं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : दरख्वास्त में लिखा है-

"I am enclosing herewith a folder issued in connection with Star Nite being organised in the Convention Hall of the Ashoka Hotel on the 6th of April, 1972, in aid of Kamla Nehru School of Science.

I shall be grateful if you kindly arrange to send suitable advesrtisement for the Seminar and extend your helping hand for this cause."

श्री निरंजननाथ आचार्य : और ऊपर है डिप्टि मिनिस्टर फार्म पर···(विराम) लिखा है, यह मैं देख रहा हूं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब एक जानकारी शेष रह गई है जो एडवरटाईजमेंट के रुपये शेष रहे हैं या उसका भी चुकारा भी कर दिया गया है और अगर आपने पूर्व में दे दिये हैं तो क्या यह नियमों के अनुकूल है? अध्यक्ष महोदय, इस जानकारी के लिये इस प्रश्न को ऐडजोर्न किया जाय।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो दिया जा चुका है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : स्मारिका में विज्ञापन प्रकाशित होने से पहले आम तौर से रुपये दिये जाने की परम्परा नहीं है। लेकिन आप खास तौर से यह कह रहे है और मैं यह कहती हूं कि प्रकाशित होने से पहले नहीं हुआ है तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह जानकारी मुझे दे देंगे कृपया।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप पहले कहिये तो सही कृपया।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

सार्वजनिक नल

357. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. जयपुर की किस किस कच्ची बस्ती में कितनी कितनी जनसंख्या पर पानी के कितने कितने सार्वजनिक नल लगे हुये हैं?

2. किस किस बस्ती में पानी के नल जन संख्या के आधार पर नहीं लगे हुये हैं?

3. कच्ची बस्तियों में कहां कहां पर कितने नल लगाये जाने का सरकार का विचार है और वे कब तक लगा दिये जावेंगे?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची (ख) में अंकित सभी बस्तियों में जनसंख्या के आधार पर नल लगे हुये है।

(3) कच्ची बस्ती (1) तोपखाना हजूरी कच्ची बस्ती व (2) कोली बस्ती लगर का बालाजी में नल लगाने के लिये जलदाय विभाग को आदेश दिये हुये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या जनसंख्या के हिसाब से लगे हुये नलों की संख्या से आप सन्तुष्ट है?

श्री परसराम मदेरणा : एक हजार की जन संख्या पर एक नल लगाये जाने का प्रस्ताव है और उस काइटेरिया को देखते जो सूची मैंने आपको दी है वह सही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह जो सूची मुझे दी गई है, अध्यक्ष महोदय, गलत है और मैं समझता हूं सदन में यह परम्परा पड़ गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय, जैसे पिछली बार अभी दो दिन पहले गृह विभाग की ओर से पुलिस कर्मचारियों की जो सूची मुझे मिली थी वह चार वर्ष पहले की सूची मिली है और आज जो सूची मिली है जनसंख्या के आधार पर नल लगाये गये हैं यह भी गलत है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा यह जो 80 नं॰ पर राधागोविन्द जी का कुन्ड है पहले मैं मेरे क्षेत्र की ही बात कर लूं उसमें नल नहीं लगा हुआ है इसी

Page No 14

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

प्रकार और दूसरे क्षेत्रों में भी जैसे नायला नं० 84 पर है नल नहीं लगा हुआ है, कच्ची हरिजन बस्ती में नल नहीं लगा हुआ है। गोविन्द देवजी के मन्दिर पर नल नहीं लगी है, मेरा निवेदन है कि कम से कम गोविन्द देवजी के मन्दिर को तो छोड़ना चाहिये था और बम्लाई हरिजन बस्ती में नल नहीं लगे हुये हैं–इस तरह बहुत सारी बस्तियां है जहां पर नल नहीं लगे हुये हैं क्या यह सूची दी है आप पुनः एक बार देखेंगे कि कौनसी सूची सही और कौनसी सूची गलत है।

श्री परसराम मदेरणा : जो सूचना अध्यक्ष महोदय, मुझे दी गई है उसमें राधा गोविन्द के कुन्ड पर नल लगा हुआ है, यह बताया गया है इसी तरह नायला के मोहल्ले में एक नल लगा हुआ है। आज मैं स्वयं जांच कर लूंगा अगर गलत इनफारमेशन दी है और अगर यह सूचना जो मैंने दी है, गलत है तो जिन अधिकारियों ने मुझे यह सूचना दी है उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मुझे यू. आई. टी. से जो सूची प्राप्त हुई है उसमें भी अधिकांश में कच्ची बस्तियों में नल लगाने का विचार है केवल इस प्रकार दर्शाया गया है। आप कहें तो यह सूची मैं सदन की मेज पर रख सकता हूं। इसमें आधी से ज्यादा कच्ची बस्तियों में नल लगाने का विचार हैं, यही लिखा हुआ हैं और जगह जगह लिखा हैं एक नल और लगाना है, दो नल और लगाने तीन नल और लगाने है और मेरी धारणा है अध्यक्ष महोदय, केवल नल लगाने का विचार है। आपको जो सूची दी है उसमें नल लगा दिये गये हैं–यह बताया हैं, क्या यह सही हैं। यह जो कच्ची बस्तियों की सम्पूर्ण संख्या हैं 109 यह मेरे पास मौजूद हैं और अगर आप कहें तो मैं आपको चलकर भी दिखा सकता हूं। इस समय वहां पर नल नहीं लगे हुये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री चिमन सिंह।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है इस बारे में जो सूची यू. आई. टी. ने दी है और जो सदन में अभी मिली है इन दोनों में से कौनसी गलत है। अधिकांश आधी से ज्यादा कच्ची बस्तियों में नल नहीं लगे हैं। 31 दिसम्बर, 1969 को पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु आश्वासन दिया गया था। अब क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि मई के अन्त तक जितने नल लगाने की घोषणा है वह जून के महीने में पूरी हो जायगी और यह कभी गर्मियों का मौसम प्रारम्भ होने से पहले पहले समाप्त हो जायगी। इतना सा आश्वासन चाहिये मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जब प्रश्न सदन में आया जैसे कि मैं निवेदन कर चुका हूं कि जयपुर की म्यूनिसिपल बोर्ड और ट्रस्ट के ऐरिया में कुल मिलाकर 109 कच्ची बस्तियां हैं। इन 109 कच्ची बस्तियों में पूर्व में जब प्रश्न सदन में आया था उस समय मैंने निवेदन किया था कि 21 कच्ची बस्तियों में अब तक नल नहीं लगे हुए हैं आज जो मेरे पास सूचना है उस सूचना के आधार पर 13 कच्ची बस्तियों में नल नहीं लगे हैं उसमें से दो म्युनिसिपल कौंसिल के ऐरिया में हैं और

(श्री परसराम मदेरणा)

11 यू. आई. टी. की कच्ची बस्तियां हैं, यह मैं स्वीकार करता हूं। इसके बाद मैंने 109 में से 96 कच्ची बस्तियों की सूची दी है। 96 कच्ची बस्तियों की सूची दी है उसमें कितने नल लगे हुए हैं यही मैंने बताया है कि नल लग रहे हैं और प्रस्तावित कितने हैं यह मैंने सूची नहीं दी है। वह गलती होगी तो मैं देख लूंगा। 13 में तो मैं स्वीकार करता हूं नहीं लगे हैं और नहीं लगने के कई कारण हैं लेकिन 96 में नहीं लगे जिन के तीन-चार के आपने नाम बताये तो मैं जानकारी करके बता दूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अधिकांश कच्ची बस्तियों में नल नहीं लगे हैं और गर्मियां पड़नी शुरू हो गयी है। मेरा कहना है कि वाटर लाइन ही नहीं है वहां पर नल की व्यवस्था होगी जहां वाटर लाइन ही नहीं है। मैं समझता हूं कि पीने के पानी के नाम पर जो सूची आपने दी है इसकी गलत सूची देकर सदन को गुमराह नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, क्या आप आश्वासन देते हैं कि मई तक काम करा देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : जिन 13 बस्तियों में नल नहीं लगे हैं .....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मई तक आप लगा देंगे क्या ? इतना सा आश्वासन आप दे सकते हैं क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : शीघ्रातिशीघ्र

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह तो कोई जवाब नहीं है। यह तो एक प्रकार से काम न करने का बहाना है।

श्री अध्यक्ष : श्री चिमन सिंह भाटी।

ग्राम भीम में पीने के पानी की व्यवस्था

358. **श्री चिम्मनसिंह भाटी** (भीम): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. ग्राम पंचायत भीम, जिला उदयपुर में पीने के पानी की योजना कब से चल रही है और क्या जो कुआ भीम तालाब के पिछोडे में खुदवाया जा रहा है उसमें पानी निकल चुका है या निकलने की सम्भावना है ?

2. क्या यह सच है कि स्थानीय जनता ने भीम तालाब के पिछोडे में कुआ खोदने के लिए मना किया था ?

3. क्या भीम पंचायत की जनता ने भोपालसागर से भीम को पानी देने के लिए सुझाव दिया था ? यदि हां, तो उसका क्या हुआ और उसका एस्टीमेट कितना था ?

4. क्या राज्य सरकार की दृष्टि में भोपालसागर से भीम को पानी देने की योजना उचित थी ?

5. क्या यह सच है कि भोपालसागर योजना से भीम को पानी देने का एस्टीमेट उदयपुर वाटर सप्लाई विभाग द्वारा तैयार होकर स्वीकृति के लिए जयपुर भेज दिया गया है और उसको बहुत समय हो चुका है? यदि हां, तो अब उस पर आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

6. क्या राज्य सरकार को यह मालूम है कि भीम की जनता इन गर्मी के मौसम में पानी के लिए त्राहि त्राहि कर रही है

(श्री चिम्मनसिंह भाटी)

और जयपुर वाटर सप्लाई विभाग के मुख्य अभियन्ता इस योजना को दबाये बैठे हैं?

मंत्री जन स्वास्थ्य (श्री चंदनमल बैद): (1) नवम्बर, 71 से। कुए में इस वक्त 3 फुट पानी है, कुआ गहरा करवाया जा रहा है और अधिक पानी प्राप्त होने का सम्भावना है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, उसके लिए योजना बनाई जा रही है, इसकी अनुमानित लागत लगभग 5.44 लाख होगी।

(4) जी हां,।

(5) जी नहीं, अभी तक योजना तैयार की जा रही है।

(6) जी हां पानी की दिक्कत है, और इसी के लिए भीम तालाब जो योजना में नल स्रोत के रूप में है और गहरा करवाया जा रहा है इसके बावजूद भी इस कस्बे में भोपालसागर से पानी प्राप्त करने के लिए संशोधित योजना तैयार की जा रही है। अभी तक योजना मुख्य अभियन्ता के पास नहीं आई है।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : भीम के तालाब में 3 फुट पानी है फिर कुआ गहरा क्यों करवाया जा रहा है ?

श्री चन्दनमल बैद : आशा है कि पानी बढ जायेगा।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : वहां कोई आशा नहीं है, मैं स्वयं देख कर आया हूं।

श्री चन्दनमल बैद : इसी बात के लिए आल्टरनेटिव योजना बनाई जा रही है जो कि भोपालसागर की है।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : कब तक बन जायेगी ?

श्री चन्दनमल बैद : अभी बन रही है, उसकी सर्वे होकर टेक्नीकली देखा जायेगा और फिर स्वीकार होगी।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : वहां पर मजदूरों का भी पेमेन्ट नहीं हुआ है तो क्या वह पेमेन्ट जल्दी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : यह अलग प्रश्न है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मगर मजदूरों का पेमेन्ट नहीं हुआ है तो करवा दें इसमें अलग से प्रश्न की बात है ?

श्री चन्दनमल बैद : यह मैं कैसे कह सकता हूं कि पेमेन्ट हुआ है या नहीं हुआ है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जांच करवा लें और फिर करवा दें।

श्री देवीलाल : माननीय सदस्य कोई बात कह रहे हैं तो उसमें क्या बात है।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य तो बहुत से बाते कहते रहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने का मौका मिला है और आपने अलग से प्रश्न कह कर पानी समस्या को टाल दिया तो मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बैरवा

Page No 17

बूंदी जिले की नगरपालिकाओं को निर्माण कार्यों के लिए राशि

359. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. जिला बूंदी की बूंदी, नैनवा, लाखेरी तथा पाटन नगरपालिकाओं को 1971–72 में कितनी कितनी धनराशि निर्माण कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा ऋण अथवा अनुदान के रूप में दी गई? अलग अलग रूप से सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. क्या यह सत्य है कि निर्माण कार्य हेतु औजार आदि की खरीद की गई उसमें अनियमिततायें पाई गई? यदि हां, तो कौनसी नगरपालिका में?

3. क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार के नियमानुसार जिन निर्माण कार्यों के लिए ऋण अथवा अनुदान दिया गया था उसको उसी मद में व्यय किया जाना था? यदि हां, तो कौन कौनसी मद में व्यय किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) वर्ष 1971–72 में बून्दी जिले की किसी भी नगरपालिकाओं को कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया। उक्त वर्ष में इस जिले की नगरपालिकाओं को निर्माण कार्य हेतु दिये गये अनुदान की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1971-72 में दी गई राशि का उपयोग वर्ष 1972-73 में होना है। इसलिए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) प्रश्न के भाग 2 में दिये गये उत्तर के अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(कृपया परिशिष्ट सं० 4 देखें)

श्री नन्दलाल बैरवा: यह जो निर्माण कार्य की राशि दी गयी थी यह किस वर्ष में खर्च करनी थी?

श्री परसराम मदेरणा: मैंने जैसा निवेदन किया कि जो अनुदान दिया गया वह 1971-72 में दिया गया और उसका खर्च 1972-73 में होगा।

श्री नन्दलाल बैरवा: अध्यक्ष महोदय, मुझे जो सूची दी गयी है उसमें 1971-72 में दिखाया गया है और 1972–73 में कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा: 1971–72 में बजट में प्रावधान था लेकिन सैंक्शन मार्च के अन्तिम सप्ताह में हुई इसलिए खर्च करने के लिए अवधि दी गयी है कि 1972–73 में कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती गौरी पूनिया।

बांका पट्टी पेय जल योजना

360. श्रीमती गौरी पूनिया (मकराना): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. मकराना पंचायत समिति को बांका पट्टी पेय जल योजना कब मन्जूर हुई थी तथा यह कुल योजना कितने लाख की बनी है?

2. अब तक योजना की क्या प्रगति हुई है? इस योजना के अन्तर्गत कुल

(श्रीमती गौरी पूनिया)

कितने गांवों को लिया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

3. क्या राज्य सरकार के पास कुछ अन्य खारे पानी वाले गांवों के प्रार्थना-पत्र भी आए हैं जिन्हें कि इस योजना में जोड़ना अतिआवश्यक हैं ?

4. इस योजना से गांवों को पेय जल कब तक उपलब्ध हो सकेगा ?

जन-स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) दिनांक 25-4-70 को यह योजना 55,74,000 रुपये की लागत की बनी है।

(2) रेल्वे क्रासिंग एवं विद्युत कनेक्शन को छोड़कर समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इस योजना में 51 गांवों को लिया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, जी नहीं।

(4) विद्युत सम्बन्ध उपलब्ध होने पर इस योजना से इस वर्ष के अन्त तक जल उपलब्ध कर दिये जाने की सम्भावना है।

(कृपया परिशिष्ट सं० 5 देखें)।

श्रीमती गौरी पूनिया : इस योजना के लिए जो मुख्य होद बना है इससे विद्युत कितनी दूरी पर है ?

श्री चन्दनमल बैद : मेरे लिए यह कहना बहुत मुश्किल है।

श्रीमती गौरी पूनिया : अध्यक्ष महोदय, इस योजना से 51 खारे पानी वाले गांवों को पानी देने की योजना है और 55 लाख रुपया खर्च कर दिया गया है और 3 लाख रुपया विद्युत विभाग में जमा करा दिया है और उसके बावजूद भी लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो सका है, इसका भी आपको ध्यान नहीं है। इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। राज्य सरकार के ही दोनों विभाग हैं तो फिर कोआर्डीनेशन में कमी कैसे ? लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं माननीय सदस्या की नाराजगी को महसूस करता हूं लेकिन रेल्वे क्रासिंग बीच में पड़ता है उसका भी प्रश्न है और रेल्वे क्रासिंग को हम बिना उनके पूछे क्रास नहीं कर सकते हैं। पहले क्रास करने की इजाजत मिलेगी, फिर विद्युत का कनेक्शन होगा और कनेक्शन के बाद टेस्टिंग होगा। इस सब काम में कुछ समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्रीमती गौरी पूनिया : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और पूछना है।

श्री अध्यक्ष : और पूछना ही चाहती हैं तो फिर पूछ लीजिए।

श्रीमती गौरी पूनिया : ऐसा है कि इसमें तीसरे भाग में मैंने पूछा है कि क्या राज्य सरकार के पास कुछ अन्य खारे पानी वाले गांवों के प्रार्थना-पत्र आये भी हैं जिन्हें कि इस योजना में जोड़ना अति आवश्यक है और आपने कहा है जी नहीं। तो उसका क्या कारण है ?

Page No 19

श्री चन्दनमल वैद : पहले 44 गांवों की स्कीम थी फिर इसमें 7 और जोड़े गए। इस स्कीम में इससे ज्यादा गांव जोड़ना उचित नहीं है।

श्री भीमसेन : इन गांवों में पानी के पीने से कितने लोग लंगड़े और कुबड़े हो गए इसकी जानकारी माननीय मंत्री महोदय के पास है ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां।

प्रश्न संख्या 361

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा। (अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रावतराम।

जल प्रदाय योजना बीदासर

362. **श्री रावतराम (छापर) :** क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. कस्बा बीदासर जल प्रदाय योजना की स्वीकृति कब हुई थी और कब तक इस योजना में कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

2. इस योजना का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

3. क्या यह सही है कि उक्त योजना के लिये ग्राम बरजांगसर से पानी लिया जा रहा है ? यदि हां तो वहां पानी की क्या स्थिति है और कितने कुओं से पानी लिया गया है ?

4. ग्राम बरजांगसर और बीदासर के बीच में कितने किलो मीटर का डिस्टेंस हैं ? क्या यह सही है कि बीच में आने वाले गांवों को भी इस पाइप लाईन से पानी दिया जायेगा ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) योजना की स्वीकृति दिनांक 19-1-70 को हुई थी। इस योजना पर अब तक 13.89 लाख रुपया का कार्य हो चुका है, इस योजना पर लगभग 20.74 लाख रुपया की धनराशि खर्च की जावेगी।

(2) इस योजना का कार्य इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है।

(3) जी हां, वहां पर एक नलकूप व 2 कुए हैं जिनमें करीब डेढ़ लाख गेलन पानी मिलने की आशा है।

(4) 25 किलो मीटर की दूरी है। इस पाइप लाईन से बीच में अन्य गांवों को पानी देने का प्रावधान इस योजना में नहीं हैं।

श्री रावतराम : बीच का जो डिस्टेंस है इसमें एक दो गांव हैं उन गांवों को पानी देने का विचार है क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : अभी तो नहीं है।

श्री रावतराम : आप विचार करेंगे क्या ?

एक माननीय सदस्य : बीच में जो पाइप लाइन है बीच में परदानासर और के गांव हैं उसी गांव में होद बने हैं तो इसका ख्याल रखते हुए राशि भी गांव में जमा कर दी गई है और मन्त्री महोदय ने भी आश्वासन दिया था तो इनको शामिल करने की योजना हैं ?

Page No 20

श्री चन्दनमल बैद : सोचा जायेगा।

श्री रावतराम : परदामासर और धनेरू जिन गावों से पानी लिया जा रहा है उन गावों को तो दिया जाये।

श्री चन्दनमल बैद : उसमें तो दिक्कत नहीं है। धनेरू के बारे में कहा कि सोचा जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

बीकानेर में मिल्क चिलिंग प्लाण्ट

363. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में राठी नस्ल की गायों का दूध काफी तादाद में पैदा होता है ?

2. क्या यह भी सही है कि पशुपालकों को अपने दूध की वाजिब कीमत नहीं मिलती ?

3. क्या सरकार पशुपालकों की आर्थिक हालत सुधारने एवम इस दूध के समुचित उपयोग हेतु उपयुक्त स्थानों पर मिल्क चिलिंग प्लान्ट्स लगाकर तथा बीकानेर में दिल्ली मिल्क स्कीम का बैलेंसिंग स्टेशन लगाने के सम्बन्ध में कदम उठा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

4. क्या इण्डियन डेयरी डवलपमेंट कारपोरेशन के अध्यक्ष डा० क्यूरियन बीकानेर में उपरोक्त दुग्ध फैक्ट्री लगाने के पक्ष में हैं ?

पशुपालन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) राज्य सरकार "आपरेशन फ्लड" योजना के अन्तर्गत बीकानेर में एक लाख लीटर क्षमता का दूध उद्योग लगाने की स्कीम बना रही है और योजना के स्वीकृत होने की पूरी आशा है। इसे सम्पादन करने की निश्चित तिथि देने की स्थिति आज नहीं है।

(4) इंडियन डेयरी कारपोरेशन जिसके अध्यक्ष डा० क्यूरियन हैं ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में है।

श्री भीमसेन : तो क्या यह सही है पिछले तीन चार वर्षों से देहली मिल्क स्कीम बैलेंसिंग स्टेशन लगाने की इच्छुक है और उन्होंने सारी तैयारी भी कर ली है लेकिन राज्य सरकार उनको स्वीकृति नहीं देना चाहती है। अगर स्वीकृति नहीं देना चाहती है तो क्यों नहीं देना चाहती है ?

श्री परसराम मदेरणा : देहली मिल्क स्कीम बैलेंसिंग स्टेशन लगाना चाहती है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर देहली मिल्क स्कीम बैलेंसिंग स्टेशन लगाना चाहती तो फिर इस बैलेंसिंग स्टेशन को इण्डियन डेयरी कारपोरेशन के द्वारा स्वीकृत कराने की बात कहां से पैदा होती है और उनको धनराशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि इण्डियन डेयरी कारपोरेशन ने पूरे का पूरा खर्चा जो बीकानेर में बैलेंसिंग स्टेशन लगायेंगे उसकी इन्फार्मल स्वीकृति दे दी है और पूरी योजना जिस तरह की वे चाहते हैं बनाई जा रही है। अगले कुछ दिनों में तैयारी हो जाने के बाद बैलेंसिंग स्टेशन लगायेंगे।

श्री भीमसेन : क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि जो एक लाख लीटर का प्लान्ट लगाया जा रहा है तो एक लाख लीटर का उत्पादन तो केवल एक तहसील में होता है जबकि बीकानेर में तीन तहसीलें और भी हैं जहां लाखों लीटर दूध का उत्पादन होता है। आप जो वहां के लोगों की हालत सुधारने के लिए प्लाण्ट लगाना चाहते हैं तो यह एक लाख की क्षमता का प्लाण्ट तो बहुत छोटा रहेगा और यह वहां की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकेगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बैलेंसिंग प्लान्ट और आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत दुग्ध योजना स्वीकृत करने की बात कह रहा हूं। यह ठीक है कि वहां पर और भी ज्यादा दुग्ध होता होगा और सरप्लस मिल्क रहता होगा लेकिन इसको वहां के जो गोपालक हैं वे लोग भी कंज्यूम करते हैं। आज भी कुछ ही हजार लीटर दूध दिल्ली मिल्क स्कीम को बीकानेर से मिलता है। इसलिए यह जो एक लाख लीटर की क्षमता का प्लान्ट लग रहा है यह तो मैनीफोल्ड ज्यादा होगा।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि योजना के बारे में जो आप कह रहे हैं कि यह योजना छोटी रहेगी तो पहले आप योजना तो बनने दीजिए। हमारे पास में जो इण्डियन डेयरी कारपोरेशन ने बीकानेर के लिए जो धनराशि स्वीकृत की है वह एक करोड़ 82 लाख के बैलेंसिंग प्लान्ट की हैं, इससे ज्यादा पैसा वे नहीं देना चाहते हैं। इसलिए हमारी जो वेज एण्ड मीन्स की पोजीशन है, उसको ध्यान में रखते हुए जो धनराशि उपलब्ध है उसी के अनुसार प्लान्ट लगाया जाएगा। कट यूवर कोट अकार्डिंग टू क्लाथ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि...

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे-अश्रव्य)

श्री रावतराम : यह प्लान्ट जो लग रहा है वह बीकानेर जिले के लिए लग रहा है इसमें क्या चूरू जिले वालों को शामिल नहीं किया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह बैलेंसिंग प्लान्ट तो बीकानेर में लगाया जाएगा लेकिन चूरू और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के लिए चिलिंग प्लान्ट होगा जो इसका फीडिंग स्टोर होगा।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि 3 करोड़ 82 लाख रुपये खर्च कर नेशनल डेयरी डवलपमेंट कारपोरेशन बीकानेर में बैलेंसिंग स्टेशन लगाना चाहता है लेकिन राज्य सरकार उसकी स्वीकृति नहीं दे रही है ? आपको इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य क्षेत्रीय भावनाओं से प्रभावित हो गए हैं। राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं हो सकती लेकिन वह स्कीम कहां है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

अंग्रेजी शराब की बिक्री

364. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह भी सही है कि गत वर्ष अंग्रेजी शराब की बिक्री हेतु देशी शराब की

Page No 22

(श्री मूलचन्द सामरिया)

भांति ठेका प्रथा चालू करने की घोषणा की गई थी ?

2. क्या यह निर्णय मंत्रि-मंडल द्वारा लिया गया था ?

3. यदि हां, तो अब सरकार की क्या नीति है ? यदि बिना मंत्रि-मन्डल की पूर्व स्वीकृति के सम्बन्धित मंत्री ने इस आशय की घोषणा की तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) :

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मूलचन्द सामरिया : अखबारों में जो न्यूज प्रकाशित हुई है उसके अनुसार तो राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि अंग्रेजी शराब का भी देशी शराब की तरह ही बेचने का ठेका दिया जाएगा और जो इसके लाइसेंस होल्डर हैं उनके तमाम लाइसेंस कैंसिल कर दिए जायेंगे। अखबारों में तो इस प्रकार की न्यूज निकली है और आपने बड़ी आसानी से मना कर दिया कि जी नहीं। शायद आपने इसे समझा नहीं है। आप पुनः सोचकर जवाब दें कि जो घोषणा की गई है वही सही है या क्या है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं जवाब दे चुका हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री केदारनाथ : इसको ओपन आक्शन करने में क्या आपत्ति है ?

श्री चन्दनमल बैद : प्रश्न आपत्ति का नहीं है। प्रश्न फैक्ट्स के बारे में पूछा था और उसका जवाब दिया गया है।

श्री केदारनाथ : यह नीति का सवाल है।

श्री चन्दनमल बैद : नीति का सवाल प्रश्न के जरिये नहीं उठाया जाता है।

प्रश्न सं० 365

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

(अनुपस्थित :कृपया आगे देखें)

श्री गुरदयालसिंह संधु।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मिस प्रिंट है। मैंने पंचायत विभाग के मंत्रीजी से प्रश्न पूछा था और इसमें कृषि विभाग दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछना चाहते हैं या नहीं ?

पदमपुर मण्डी

366. श्री **गुरदयाल सिंह संधु** (करणपुर) : पूछ लेता हूं। क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. मण्डी पदमपुर को नए स्थान पर तबदील करने हेतु आज तक क्या क्या कार्य किया जा चुका है ?

2 मण्डी में कुल कितनी दुकानें होंगी और उनको किसके द्वारा बेचा जाएगा ?

Page No 23

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

3. आवास के लिए जो स्थान मुकर्रर किया गया है वह किसके द्वारा बेचा जाएगा और हरिजन अथवा पुराने रहने वाले नागरिकों को मुफ्त व थोड़ी कीमत पर क्या आबादी भूमि में आवास हेतु स्थान दिया जाएगा ? यदि हां, तो कैसे, यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) पदमपुर मण्डी को नए स्थान पर स्थानान्तरित करने के विषय में कृषि उपज मण्डी समिति पदमपुर ने जुलाई 1968 में प्रस्ताव पारित किया था कि करणपुर जाने वाली सड़क पर 187-5 एकड़ भूमि जो राज्य सरकार की सम्पत्ति हैं वह मण्डी समिति को स्थानान्तरित कर दी जाय । इस संदर्भ में उप निवेशन विभाग सचिवालय के पत्र दिनांक 24-11-71 द्वारा जिलाधीश श्री गंगानगर से भूमि स्थानान्तरण से मण्डी के विकास के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई थी । जिलाधीश श्री गंगानगर ने राज्य सरकार को 50 एकड़ भूमि पदमपुर मण्डी के लिए आवंटन हेतु 1 मई को सिफारिश कर दी है । अतः शीघ्र ही निर्णय लिया जा सकेगा ।

(2) मण्डी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भ में लगभग 60 दुकानें होंगी तथा लगभग 40 दुकानों का स्थान विस्तार हेतु रखा जायेगा । इस प्रकार अनुमानतः 100 दुकानें होंगी । नगर नियोजन विभाग से स्वीकृति नक्शे के अनुसार ही मण्डी का निर्माण कराया जायगा । दुकानों को मण्डी समिति द्वारा लीज पर या ऐसे तरीके से जैसा कि राज्य सरकार तय करे, बेचा जायेगा ।

(3) मंडी हेतु अवाप्त भूमि में आवास हेतु हरिजन अथवा पुराने रहने वाले नागरिकों को भूमि अलाट करने का कोई प्रश्न नहीं है । मण्डी में मण्डी समिति द्वारा भूमि दुकानों के लिए सिर्फ अनुज्ञा-पत्र प्राप्त व्यापारी व आढ़तियों को ही दी जावेगी ।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : क्या उस क्षेत्र में जितनी भी भूमि है वह सारी की सारी मण्डी समिति द्वारा दी जायेगी या कुछ पंचायत भी देगी ?

श्री परसराम मदेरणा : जिलाधीश ने मण्डी कमेटी को भूमि ट्रांसफर करने का प्रस्ताव किया है और जिसमें सौ दुकाने और यार्ड बनाया जावेगा । इसमें किसी दूसरे काम के लिए, आवास या अन्य काम के लिए भूमि देने का कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : मण्डी का सारा कार्य इस मण्डी एरिया में एक ही जगह सम्मिलित कर दिया जाएगा या कुछ को मण्डी से अलग भी कर देंगे ।

श्री परसराम मदेरणा : मण्डी समिति को 50 एकड़ भूमि दी जा रही है, इसमें कहां क्या होगा इसका तो मैं आफहैंड रिप्लाई नहीं दे सकता । लेकिन इस पचास एकड़ में सौ दुकानें और यार्ड की स्थापना की जाएगी । इसमें दूसरे लोगों को बसाने का तो सवाल ही नहीं है ।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : क्या इण्डस्ट्रियल एरिया इसमें शामिल नहीं किया जाएगा ।

श्री परसराम मदेरणा : मण्डी कमेटी के अन्दर इण्डस्ट्रियल एरिया शामिल नहीं किया जाता है।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : हर मण्डी के अन्दर एक डिवलेपर्ड इण्डस्ट्रियल एरिया होता है, तो पदमपुर ने ही क्या कसूर किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : वह मण्डी स्थापना का प्रश्न हो सकता है। यह कृषि उपज मण्डी का प्रश्न है जिसमें केवल दुकानें और यार्ड बनेंगे।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : यह मण्डी कोलोनाईजेशन एरिया की मण्डी है, गंग केनाल और कॉलोनाईजेशन के क्षेत्र की मण्डी है और इसका पैटर्न भी वही रहेगा जो कालोनाईजेशन की मण्डियों का रहता है। इस क्षेत्र के अन्दर भी इण्डस्ट्रियल एरिया होना जरूरी है।

श्री परसराम मदेरणा : मण्डी कमेटी में जो कालोनाईजेशन की मण्डियां होती है उनका प्लान तो मास्टर प्लान की तरह से होता है और उनका जो मास्टर प्लान तैयार होता है उसमें तो इण्डस्ट्रियल एरिया भी रखते हैं लेकिन यह एक कृषि उपज मंडी है जिसमें यार्ड बनाने का प्रश्न है और उसी काम के लिए पचास एकड़ जमीन दी जा रही है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : केवल कृषि उपज मंडी और उसका यार्ड बना रहे हैं ? पदमपुर की मण्डी एज ए कोलोनाईजेशन मण्डी बन रही हैं ? आजादी के पहले भी पदमपुर की मण्डी कच्ची मण्डी थी। 1928 से यह रायसिंहनगर और पदमपुर दो कच्ची मण्डियां चली आ रही है स्टेट के टाईम से इनको पक्की बनाने का प्रावधान था और लेटर आफ इन्टेंट भी इश्यू हो गया था लेकिन राजस्थान बनने के कारण और स्टेट का इन्टिग्रेशन होने के कारण वह कार्य रुक गया। आज भी उनकी वही स्थिति है जो राजाओं के टाईम में थी। केवल कृषि उपज मंडी के नाम से कुछ एकड़ जमीन देकर सरकार अपनी सारी जिम्मेदारी से दूर होना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : नो स्पीच प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : इसका सारा सम्बन्ध कोलोनाईजेशन डिपार्टमेंट से है।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया

कर्मचारियों की बकाया का भुगतान

367. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

उपनिवेशक, सघन पशु योजना बीकानेर के कार्यालय में कितने कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिल एवं कितने मेडिकल रीएम्बर्समेंट बिलों की किस किस कर्मचारी की कितना कितनी धनराशि बकाया है ? आज तक इन बिलों की धनराशि का भुगतान न होने का क्या कारण है ? सरकार इन बकाया बिलों की धनराशि का भुगतान कब तक कराने का इरादा रखती है ?

पशुपालन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): इनमें से कुछ बिल तो पहले से जेर जांच रहे और कुछ माह मार्च 1972 में ही प्राप्त हुए। इस समय ये सारे बिल जिलाधीश बीकानेर ने मंगवा रखे हैं और उनसे

Page No 25

(श्री परसराम मदेरणा)

वापस प्राप्त होने पर उनके भुगतान के सिल सिले में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री चुन्नीलाल इन्द्रलिया : जिलाधीश ने इन बिलों को किस आधार पर मंगाया है ?

श्री परसराम मदेरणा : शायद उनके पास में कोई कम्पलेंट आई होगी।

श्री भीमसेन : उनके बिल्स कितने कितने वर्ष के हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : इनमें से एक बिल सन् 69 का है। एक बिल सन् 70 का है। 5-6 बिल्स 71 के हैं और बाकी के मार्च 72 के हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्द्रलिया : इन बिलों को रोकने का क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : उत्तर में निवेदन किया है कि इनकी जांच चल रही है और इस सम्बन्ध में कुछ बिलों का भुगतान भी देरी से जरूर हुआ है। मैं इसकी जांच करूंगा। मैं पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सका हूं कि एक एक बिल पर क्या आब्जेक्शन किये गये हैं। मैंने यह आदेश दिये हैं कि जिलाधीश से बिल वापिस मंगवा कर यह बताया जाये कि आब्जेक्शन क्या 2 हैं। सन् 69 के जो बिल हैं वे यात्रा भत्ता और मैडिकल के हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्द्रलिया : जांच क्यों हो रही है और किन कारणों से हो रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी मैं नहीं मंगवा सका हूं।

श्री रावतराम (छापर) : क्या पूरी तफ्तीश के बाद इन बिलों का भुगतान किया जायेगा ?

श्री चुन्नीलाल इन्द्रलिया : इन बिलों के अन्दर क्या कुछ लेने देने का सवाल है ?

श्री परसराम मदेरणा : ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इन्द्रलिया : क्या मन्त्रि महोदय इसकी जांच करवायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : आपको लेने देने की कोई जानकारी हो तो बता दीजिये मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 7-4-72)

केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालोर

16. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर के प्रशासन में भयंकर पार्टीबाजी फैल रही है ? अगर हां तो क्यों व कब से ?

2. क्या यह भी सत्य है कि उक्त बैंक के व्यवस्थापक ने कई बार सरकार का

Page No 26

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

ध्यान आकर्षित किया है ? अगर हां तो कब कब तथा सरकार द्वारा अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई ? अब तक कोई सक्रिय कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं तथा इसके लिये दोषी कौन है ?

3. उक्त बैंक के अध्यक्ष द्वारा अब तक अपने कार्यकाल में कितनी अनियमितताएं की गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। इन पर क्या कार्यवाही की गई हैं एवं आगे क्या कार्यवाही की जावेगी ?

4. उक्त बैंक के कितने संचालक अयोग्य घोषित किए जाने योग्य हैं ? उनके नाम क्या क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी ?

5. पिछले एक साल की अवधि में बैंक का कुल खर्चा कितना हुआ एवं आमदनी कितनी हुई तथा कुल घाटा कितना हुआ इतने खर्च होने के क्या कारण हैं ? एवं इसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

6. पिछले एक साल की अवधि में बैंक द्वारा काश्तकारों को कितना ऋण अब तक बांटा गया है ? ऋण वितरण में कमी के क्या कारण हैं ?

7. अब उक्त बैंक का प्रशासन कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें ?

राज्य मन्त्री, सहकारिता (श्री जुझारसिंह) : (1) जी नहीं। बैंक के अधिकारियों में समन्वय की कमी रही है।

(2) जी हां। 29-1-72, 31-1-72 व 5-2-72 को। इस पर जांच की जा रही है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जांच में अनियमितता सही पाई जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, (कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

(4) उक्त बैंक के निम्न तीन संचालक अयोग्य घोषित किये जाने योग्य हैं:–

1– श्री आईदानसिंह

2– श्री आसू खां

3– श्री भैरूंसिंह

इनको हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(5) सहकारी वर्ष एक जोलाई से आरंभ होकर 30 जून को समाप्त होता है। पिछले एक वर्ष 1-7-70 से 30-6-71 की अवधि में 457034.90 पैसे की आय एवं 427552.42 पैसे का व्यय हुआ है। इस प्रकार गत वर्ष 29483.48 का लाभ हुआ है। घाटा नहीं हुआ है। अतः जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता है।

(6) वर्ष 70-71 में बैंक द्वारा काश्तकारों को 8 लाख 53 हजार रुपये का अल्पकालीन एवं 20400/- रुपये का मध्यकालीन ऋण दिया गया था। चालू वर्ष में अब तक 4 लाख 97 हजार रुपये का अल्पकालीन ऋण काश्तकारों को वितरित किया गया है। ऋण के वितरण में कमी का कारण बैंक के अवधि पार ऋणों से ज्यादा हो जाने से रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया द्वारा ऋण सीमा स्वीकृत नहीं करना है।

(श्री जुझार सिंह)

(7) बैंक के प्रशासन के सम्बन्ध में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन पर जांच कराई जायेगी और यदि उनमें कमी पाई गई तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसमें अनियमितताएं बताई गई हैं और वहां के मेनेजर को रिलीव कर दिया गया है। वहां पर गवर्नमेन्ट के जितने भी आर्डर गये हैं उनको डिफाई किया गया है। और उनकी पालना नहीं की गई है। आज तक इस बैंक में सिर्फ एक ही इन्सपेक्टर हैं और ए. आर, मार्केटिंग आफिसर कोई नहीं है। आज सिर्फ बैंक में एक ही कर्मचारी है। यह आगे लिखा है कि 15-10-71 को गवर्नमेंट के आर्डर को डिफाई करने के कारण स्पेअर कर दिया। उसके बाद साल भर हो गया वहां पर ए० ओ० को नियुक्ति नहीं की गई हैं। दूसरा जो मैनेजर काम कर रहा था उसको भी दूसरी जगह भेज दिया गया है। वहां पर अब एक इन्सपेक्टर है वही बैंक के मैनेजर, ए. ओ. और मार्केटिंग सोसाइटी का काम कर रहा है। क्या यह सही है कि वहां पर एक ही कर्मचारी काम कर रहा है। और क्या इस हिसाब से आप इसको सही मानते हैं ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या एक के पहले जवाब में बता दिया है बैंक के जो कर्मचारी हैं उनमें आपस में मतभेद है इसलिये वहां पर बैंक की व्यवस्था खराब चल रही है। वहां के बैंक का जो मैनेजर था उसका तबादला कर दिया गया है दूसरे जो कर्मचारी हैं उनको भी वहां से हटाने की कार्यवाही की जा रही है। आपस में राज्य कर्मचारी एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और इस कारण बैंक की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। मैनेजर को वहां से हटा दिया गया है और दूसरे अधिकारियों को भी शीघ्र ही हटा दिया जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वहां पर ऐसी अव्यवस्था है अध्यक्ष महोदय कि 15-10-71 से कोई अधिशासी अधिकारी नहीं है, जिस पर की रिकवरी का जिम्मा होता है उसको बगैर आर्डर के रिलीव कर दिया गया और उसके स्थान पर कोई दूसरा अपाइन्टमेन्ट नहीं किया गया। मैनेजर को हटा दिया गया है। वहां पर सिर्फ एक इन्सपेक्टर है और कोई मैनेजर का कार्य नहीं कर रहा है।

श्री जुझारसिंह : इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह शोचनीय व्यवस्था है सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक। वहां पर मैनेजर, अधिशासी अधिकारी नहीं, मार्केटिंग आफिसर नहीं है। तो क्या बैंक भगवान के भरोसे पर चलेगी ? इनकी जगह पर दूसरों को लगाना चाहिये था।

सहकारिता मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : दूसरे अधिकारियों को भेजने के लिये आदेश दे दिये गये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्री महोदय ने स्वयं ने बताया है कि जो अनियमितताएं हुई हैं, उन पर कार्यवाही की जायेगी। परन्तु इसको एक साल हो गया है और गवर्नमेंन्ट ने कोई कार्यवाही नहीं की है। इसका क्या यह मतलब नहीं होगा कि

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

गवर्नमेंट इस बैंक को फेल कराने के लिये जिम्मेदार है। वहां पर ऋण ओवरड्यू हो गया है और बाकी का ऋण देने में बैंक असमर्थ है।

श्री जुझारसिंह : जो ओवरड्यू हो गया है वह आपके टाइम का है। जैसा कि मैंने निवेदन किया है इसका बाकायदा ऑडिट होता है। जिस साल का ओवरड्यू हो गया है उस साल के माननीय सदस्य ही वहां के बैंक के अध्यक्ष थे और उनके टाइम का ऑडिट होकर सामने आया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ओवरड्यू की रिकवरी कौन करते हैं? अधिकारी करते हैं या बैंक करता है।

श्री अध्यक्ष : श्री चिम्मनसिंह भाटी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह क्या जवाब हो रहा है?

श्री अध्यक्ष : काफी जवाब दे चुके हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो बता दीजिये कि क्या यह सही है कि बैंक के अन्दर कोई कर्मचारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय जो कह रहे हैं वह आपने सुना है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह स्पष्ट हो चुका है कि इस बैंक को फेल कराने में सरकार का हाथ है। एकमात्र यही इन्स्टीट्यूशन है जिनसे किसान कर्जा ले सकते हैं और इस पर हमारी सरकार सो रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री चिम्मनसिंह भाटी।

स्थगित प्रश्न

(20-4-72)

फसल की जिन्सवार रिपोर्ट

138. श्री चिम्मन सिंह भाटी (भीम) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. अ. क्या उदयपुर जिले की भीम व देवगढ़ तहसील की खरीफ 1971 की फसल की जिन्सवार रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है?
   ब. यदि हां तो राज्य सरकार द्वारा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई?
   स. यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?
2. अ. क्या राज्य सरकार को यह जानकारी है कि उदयपुर जिले की भीम व देवगढ़ तहसील को रबी की सारी फसलें पाला गिरने से जल गई हैं?
   ब. यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) (अ) जी हां।

(ब) राज्य सरकार द्वारा उस पर विचार किया जाकर अभाव स्थिति की घोषणा कर दी गई है।

(स) प्रश्न नहीं उठता।

(श्री परसराम मदेरणा)

(2) (अ) जी नहीं।

(ब) जिलाधीश से अभी अभाव स्थिति का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त होने पर यदि अभाव स्थिति पायी गई तो आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

प्रश्न संख्या 167

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह कुड़ी।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखिये)

प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा प्लाटों का आवंटन

348. श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : क्या नगर योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. नगर विकास न्यास जयपुर में जनवरी, 1969 से फरवरी, 1972 तक कुल कितने वह कौन कौन सी श्रेणी के भू-खण्डों का आवंटन किया है ?

2. 550 वर्ग गज से अधिक के भू-खण्ड कितने व्यक्तियों को दिये गये हैं उनके नाम व पतों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

3. नगर विकास न्यास भू-खण्डों का एक्सचेन्ज करने में किन किन बातों का ध्यान रखता है ?

4. गत 3 वर्षों में कितने व्यक्तियों ने अपने पहले आवन्टन किये गये भू-खण्ड के बजाय दूसरा भू-खण्ड एक्सचेन्ज में प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये और इनमें से कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये ?

5. उन स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या क्या है जिनमें पूर्व आवंटित भू-खण्ड के क्षेत्रफल से बड़े क्षेत्रफल का भू-खण्ड बाद में स्वीकार किया गया है ? ऐसे व्यक्तियों के नाम व पते सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास जयपुर ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जनवरी, 1969 से फरवरी, 1972 तक 1370 भू-खण्डों का आवंटन द्वारा विक्रय किया है। विविध योजनाओं में स्थिति के मुताबिक भू-खण्डों को श्रेणियों में बांटा जाता है व श्रेणी के अनुसार आवंटन व नीलामी द्वारा भू-खण्ड दिये जाते हैं। सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विविध योजनाओं में 550 वर्ग गज से अधिक के भू-खण्ड 119 आवंटित किये गये हैं सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) साधारणतया एक ही योजना में भू-खण्ड विनिमय किये जाते हैं किन्तु एक योजना से दूसरी योजना में भू-खण्ड विनिमय राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकृत किये जाते हैं।

(4) गत तीन वर्षों में न्यास को आवंटन किये गये भू-खण्ड के बजाय दूसरा

Page No 30

(नगर योजना मंत्री)

भू-खण्ड विनिमय में प्राप्त करने के लिये कुल मिलाकर 223 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं जिनमें से 69 आवंटियों को भू-खण्ड विनिमय किये गये हैं।

(5) स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या 69 है। तालिका (स) जिसमें ऐसे व्यक्तियों के नाम अंकित हैं, सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पाली जिले की पेय जल योजना

349. श्री शंकर लाल (पाली): क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि 125 लाख की योजना पाली जिले के गांवों में पेय जल की व्यवस्था के सम्बन्ध में भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजने की सूचना जन-स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा विधान सभा में दिनांक 8-4-72 को दी गई? यदि हाँ, तो यह योजना किन किन गांवों के लिये है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. यह योजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु कब भेजी गई है और इसकी स्वीकृति कब तक मिलने की सम्भावना है?

3. इस योजना के तहत पानी का श्रोत क्या रहेगा?

उत्तर

(1) जी हां, इस योजना में पाली जिले के 68 गांव तथा 8 गांव जोधपुर जिले को सम्मिलित किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है?

(2) यह योजना भारत सरकार को दि० 13-9-71 को भेजी गई अभी तक स्वीकृति अपेक्षित है।

(3) इस योजना में पानी का श्रोत जवाई हेमावास तथा सुमेरसमन्द नहर है।

(कृपया परिशिष्ट सं० 6 देखें)

नाथद्वारा नगर का मास्टर प्लान

350. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या नाथद्वारा नगर के लिये राज्य सरकार ने कभी कोई मास्टर प्लान बनवाया है? यदि हां, तो वह कब बनाया गया?

2. क्या नाथद्वारा में उक्त मास्टर प्लान लागू किया गया? यदि नहीं तो क्यों?

3. क्या राज्य सरकार ने नगरपालिका को यह निर्देश दिये हुए हैं कि जब तक प्लान लागू न हो नाथद्वारा के बाहर भवन निर्माण के लिये कोई स्वीकृति नहीं दी जाय और क्या नगरपालिका उक्त निर्देशनों का पालन कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों और उसके लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

4. गत वर्षों में बस स्टेण्ड की ओर कितने नये मकान बने और क्या वे मकान मास्टर प्लान के अनुसार बनाये गये हैं?

Page No 31

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा नगर के लिये अभी तक कोई मास्टर प्लान नहीं बनवाया गया है।

(2) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

(3) जी नहीं ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये थे।

(4) नगरपालिका ने सूचित किया है कि बस स्टेण्ड की ओर नौ नये मकान बन रहे हैं।

(क) शेष भाग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ग्राम ढसूक में मिडिल स्कूल

353. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सत्य है कि पिछले सत्र में राज्य में 400 मिडिल स्कूल खोले गये थे ?

2. क्या यह सत्य है कि अजमेर जिले में अराई पंचायत समिति में एक भी मिडिल स्कूल नहीं खोला गया ? यदि हां, तो क्यों ?

3. स्कूल खोलने के क्या आधार थे ?

4. क्या यह सही है कि ढसूक ग्राम पंचायत समिति अराई में करीब 200 छात्र पढ़ते हैं और मिडिल स्कूल बनाने लायक थी ?

5. क्या यह सत्य है कि ढसूक के 7 मील की दूरी में कोई मिडिल स्कूल नहीं है ? तथा स्कूल के अभाव में कई बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते हैं ?

6. क्या आगामी सत्र में सरकार ढसूक की स्कूल को मिडिल स्कूल में परिणित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां!

(2) यह सत्य है ?

(3) बजट में प्रावधान होने पर औचित्य को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर शालायें खोली जाती है।

(4) ढसूक ग्राम पंचायत समिति अराई में माह मार्च, 1972 में छात्र संख्या 171 थी। शाला क्रमोन्नति के प्रस्ताव विभाग को नहीं भेजे गये।

(5) यह सही है। ग्राम ढसूक से 8 मील की दूरी पर अराई में उच्च माध्यमिक विद्यालय है। विभाग के पास ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

(6) अन्य प्रस्तावों के साथ इस पर भी विचार कर लिया जावेगा।

खेराट ग्राम में पानी की व्यवस्था

355. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि जायल तहसील के खेराट गांव में पीने के पानी का एक पक्का तालाब है एवं उसके अलावा पीने

(श्री रामसिंह कुड़ी)

के पानी का कोई स्रोत नहीं है तथा कुओं का पानी चिड़ियां भी पीले, तो मर सकती है, ऐसा खारा है ?

2. क्या फर्टिलाइजर कोरपोरेशन खेराट के खान की खोदी खड्डी में से उस गांव के व पड़ोस के गांवों के प्राथमीय व्यवस्था हेतु कुछ भाग बेच सकता है ? यदि हां, तो किस दर से, तथा नहीं, तो सरकार क्या इस बारे में कोई व्यवस्था करने को तैयार हैं ?

उत्तर

(1) जायल तहसील के गांव खेराट में पीने के पानी के लिये केवल एक पक्का तालाब है, तथा कुओं का पानी खारा है जो कि पीने योग्य नहीं है ।

(2) यह इस विभाग से संबंधित नहीं है ।

पत्ता तेंदू का ठेका

361. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में रेन्ज बकानी असनावर व अकलेरा के पत्ता तेंदू का ठेका 1971-72 में नहीं देकर टोंक की सोसाइटियों को साल की औसत पर दिया गया ? यदि हां, तो किन किन सोसाइटियों को कहां कहां की रेंजों का औसत पर ठेका दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

2. क्या यह सही है कि इस वर्ष पत्ता तेंदू के ठेके पंचायतों के दीगर सालों की अपेक्षा कई गुने मंहगे हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या इस तरह औसत पर ठेके देने के कारण राज्य कोष को काफी नुकसान हुआ है ?

3. क्या यह भी सही है कि उक्त सोसाइटियां केवल नाम मात्र की हैं और उनका कोई वर्क नहीं है और यहां ठेकेदार इनके नाम से कम रकमों में पत्ता तोड़ते आ रहे है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

(2) पंचायत द्वारा दिए गए ठेकों की सूचना इस विभाग में नहीं है ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

लालसोट व चाकसू तहसील में पानी का भण्डार

365. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या भू-जल मण्डल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जयपुर जिले की लालसोट तहसील व चाकसू तहसील के पूर्वी भाग में भू-तल-जल का अपार भण्डार है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिये कोई विस्तृत योजना तैयार की है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

लालसोट एवं चाकसू पंचायत समिति का प्रारम्भिक भूजल सर्वेक्षण सन् 1968

(भू-जल मण्डल मन्त्री)

में किया गया एवं इस सर्वेक्षण के आधार पर इन तहसीलों के उत्तर पूर्व भाग में 50 से 70 मीटर गहरे नलकूप खुदवाने की सिफारिश की गई है, इस भाग का विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण होना अभी बाकी है। अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण किये जाने के उपरान्त भू-जल सम्बन्धी योजना बनाने पर विचार किया जा सकेगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1-5-72)

नागौर तथा जायल तहसीलों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत मजदूरों की बकाया

167. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

नागौर व जायल तहसीलों में सं. 2025 व 2026 के अकाल राहत कार्यों की मजदूरों की कितनी मजदूरी बकाया है ? यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? कृपया कैम्प वाइज मजदूरों की बकाया की वसूलियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. नागौर व जायल तहसीलों के सम्वत् 2025-2026 में अकाल राहत कार्यों की बकाया देय मजदूरी क्रमशः 67,301-45 पै० व 11,555-93 पै० है। बकाया के भुगतान हेतु राशि उठाली गई है और भुगतान किये जाने की प्रक्रिया चालू है। कैम्प वाइज मजदूरों की बकाया की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जे. बी. हायर सैकेन्डरी स्कूल लाडनूं के अध्यापकों को चैक द्वारा वेतन का भुगतान

114. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सत्य है कि जे. बी. हायर सैकेन्डरी स्कूल लाडनूं के अध्यापकों को चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना शुरू किया था ? यदि हां, तो कब और क्यों तथा किस किस माह का भुगतान चैक द्वारा किया गया और बाद में बन्द क्यों कर दिया गया ?

2. क्या राज्य सरकार चैक द्वारा वेतन भुगतान करने की प्रणाली सम्पूर्ण सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में लागू करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. जी हां, चैक द्वारा भुगतान संस्था ने प्रयोगात्मकरूप में प्रारम्भ किया था। निम्न माह का भुगतान चैक द्वारा किया गया। चैक द्वारा भुगतान करने पर अध्यापकों को बैंक जाकर राशि लानी पड़ती है जिससे अध्यापन कार्य में बाधा पड़ती है:—

अप्रेल, 1967	सितम्बर, 1967
मार्च, 1968	अगस्त, 1967
फरवरी, 1969	सितम्बर, 1971

Page No 34

(शिक्षा मन्त्री)

(2) सहायता प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को चैक द्वारा भुगतान करने की प्रक्रिया अभी तक अपनाई नहीं गई है। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

बयाना में छात्रों द्वारा प्रदर्शन

115. **श्री नत्थासिंह** (नदबई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बयाना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के साथ परीक्षा के समय वहां के प्रधानाध्यापक के दुर्व्यवहार और गलत फीस की वसूली के कारण छात्रों ने कई दिन प्रदर्शन किये हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

यह सही नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता।

बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापक

116. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. सारे राज्य में कितने प्रशिक्षित एस.टी.सी. बेरोजगार अध्यापक हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

2. इन बेरोजगार अध्यापकों को रोजगार देने की सरकार की क्या योजना है और ये सभी प्रशिक्षित अध्यापक कब तक रोजगार पा सकेंगे ?

उत्तर

(1) राजस्थान में एस. टी. सी. प्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या करीब 7,510 है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) केन्द्रीय सरकार ने प्रशिक्षित अध्यापकों को रोजगार देने के लिये 2,600 तृतीय श्रेणी के अध्यापक गत वर्ष दिये थे और इस वर्ष भी 6,000 अतिरिक्त अध्यापक रोजगार पाने के लिये भारत सरकार दे रही हैं।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में मजदूरों का प्रतिनिधित्व

117. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सार्वजनिक उद्योगों के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में मजदूरों का प्रतिनिधित्व देने हेतु सरकार की क्या नीति है तथा सरकार ने इस ओर क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

सरकार की नीति सार्वजनिक उद्योगों के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में मजदूर हितों का प्रतिनिधित्व देने की है।

यह किस प्रकार किया जावे इस पर विचार किया जा रहा है।

देहाती क्षेत्र की पेयजल भू-समस्या

118. श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. चौथी पंचवर्षीय योजना काल में देहाती क्षेत्र की पेयजल समस्या के निवारण हेतु कुल कितनी राशि का प्रावधान है ?

2. उपरोक्त प्रावधान के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से कुल कितनी राशि मिलने की संभावना है ? तथा अब तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

उत्तर

(1) 2,000 लाख रुपये

(2) उपरोक्त प्रावधान के अतिरिक्त 335 लाख रु. की राशि रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत मिलने की संभावना है तथा अब तक निम्न प्रकार राशि व्यय की जा चुकी है:—

वर्ष	प्लान मद में	फेमिन मद में
1969-70	113.39 लाख रु.	171.34 लाख रु.
1970-71	205.70 लाख रु.	230.32 लाख रु.
1971-72	275·10 लाख रु. बजट प्रावधान	—

फागी व चाकसू तहसीलों का भू-जल मण्डल द्वारा सर्वे

119. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या राजस्थान भू-जल मण्डल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या फागी व चाकसू तहसील का राज्य सरकार द्वारा भू-जल मण्डल द्वारा सर्वे कराया जा चुका है ? यदि हां, तो विस्तृत रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें? यदि नहीं कराया गया तो कब तक सर्वे करा दिया जावेगा।

2. सर्वे रिपोर्ट के आधार पर क्या राज्य सरकार के समक्ष कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई योजना बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

1. फागी एवं चाकसू तहसीलों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण इस विभाग द्वारा जयपुर जिले के सर्वेक्षण के अन्तर्गत सन् 1967-68 में किया गया। विस्तृत सर्वेक्षण नहीं हुआ है।

2. फागी एवं चाकसू तहसीलों का विस्तृत सर्वेक्षण अभी करना है। इस विस्तृत सर्वेक्षण करने के पश्चात् ही उक्त क्षेत्र में भू-जल सम्बन्धी योजना तैयार कर सकेगी।

लूनकरणसर एवं बीकानेर तहसीलों का भू-तल जल बोर्ड द्वारा सर्वे

120. श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की लूनकरणसर एवं बीकानेर तहसीलों के भू-तल जल का सर्वे हो चुका है ?

Page No 36

(श्री भीमसेन)

2. अगर हां, तो इन तहसीलों के भू-तल जल बाहुल्य वाले गांवों में ट्यूब वैल्स खुदवाने की कोई योजना है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

1. लूनकरणसर पंचायत समिति का प्रारम्भिक भू-जल सर्वेक्षण 1968 में किया गया था। प्रारम्भिक सर्वेक्षण में भू-जल संभावना मालूम हो जाती है परन्तु कितना भू-जल निकाला जाय इसके बारे में वैज्ञानिक धारणा नहीं बनती। इसके लिये विस्तृत सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण में लूणकरणसर पंचायत समिति के दक्षिणी पूर्वी भाग में लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र 150 मीटर गहराई के नलकूपों के लिए उपयुक्त पाया गया था। इसी कारण इस क्षेत्र का इस वर्ष अर्ध विस्तृत सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसके आधार पर इस क्षेत्र की समूह नलकूप योजना बनाई जा सकेगी तथा नलकूप खरीदने के लिये ए. आर. सी. जैसी संस्थाओं की सहायता से कृषकों को ऋण भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

2. बीकानेर के बाकी क्षेत्र का प्रारम्भिक सर्वेक्षण 1971-72 में किया गया है। परिणाम अभी उपलब्ध नहीं है। नोखा पंचायत समिति का अर्ध विस्तृत सर्वेक्षण 1971—72 में पूरा हुआ था और वहां भी नलकूप संभावनाएं हैं।

खाद्यान्न एवं अखाद्यान्न उपज

121. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) राज्य में कौन कौन सी खाद्यान्न एवं अखाद्यान्न उपज की जाती है ? दोनों उपजों का अनुमानित उत्पादन जिलावार कितना है। सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) राज्य में खाद्यान्न उपज का प्रति एकड़ उत्पादन व्यय कितना है ? जिलेवार तालिका सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. सूची संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. विभागीय अनुमानों के अनुसार खास खास खाद्यान्नों की औसतन प्रति एकड़ उत्पादन व्यय निम्न प्रकार हैं—

गेहूं सिंचित	900)	रुपया प्रति एकड़
जो	550)	,,
चना	330)	,,
संकर बाजरा	675)	,,
संकर ज्वार	715)	,,
संकर मक्का	715)	,,

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

फागी तहसील में सहायता वितरण में अनियमितताएं

122. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

फागी तहसील में बाढ़ व अतिवृष्टि में वितरित सहायता में क्या क्या अनियमितताएं बरती गईं और उनमें कौन कौन दोषी

(श्री जयकिशनलाल तोशावड़ा)

पाए गए। क्या दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सरकार ने कोई कदम उठाया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

उत्तर

क फागी तहसील में बाढ़ एवं अति-वृष्टि के समय पीड़ित परिवारों के सम्बन्ध में नुकसान का विवरण नियमानुसार तैयार नहीं करने से व सहायता का नियमित रूप से वितरण करने में अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें निम्न व्यक्ति दोषी पाये गए:-

(क) श्री हरसहायक शर्मा, पटवारी हल्या रेनवाल (फागी)

(ख) श्री हरिनारायण शर्मा पटवारी, हल्या चित्तौड़ा (फागी)

(ग) श्री सवाई सिंह, गिरदावर, हल्का रेनवाल

उपरोक्त तीनों कथित दोषी कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध विभागीय जांच विभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही है।

शोक प्रस्ताव

श्री दामोदर संजीवैया, कांग्रेस अध्यक्ष के निधन पर

श्री अध्यक्ष : शोक प्रस्ताव। मुख्य मंत्री महोदय।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री दामोदर संजीवैया का अचानक निधन होने के कारण यहां इस सदन में मैं शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। श्री संजीवैया बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे। उनकी 51 वर्ष की उम्र थी। उनकी जन्म तारीख सही मालूम नहीं है लेकिन उनके सर्टीफिकेट की जो तारीख सामने आई है उससे लगता है कि वे 51 साल से ज्यादा के नहीं थे। वे जीवन भर संघर्ष में रहे लेकिन संघर्ष में रहते हुए भी उन्होंने एल.एल.बी. पास किया। शुरू से जब से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया, गरीब हरिजनों की सेवा में लगे रहे और इस कार्य को हाथ में लेते हुए वे आन्ध्र के पहले हरिजन मुख्य मंत्री बने और पहली बार कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट बने और कांग्रेस के इतिहास में यह पहला मौका था जब कि कोई हरिजन पहली बार कांग्रेस का प्रेसीडेन्ट बना। सेन्टर में वे मिनिस्टर रहे और आन्ध्र के चीफ मिनिस्टर रहे और उसके बाद में जब कांग्रेस मोड़ पर खड़ी थी उस मोड़ के वक्त समाजवाद का मोड़ देने के लिए श्री संजीवैया ने कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में सम्हाली। मैं निजीतौर से जानता हूं कि इस बीमारी की हालत में जब डाक्टर ने उन्हें मना कर रखा था कि किसी से बोले नहीं तब भी वे सब लोगों से मिलते थे और बात करते थे। कुछ समय पहले यह तय हुआ था कि उनका इलाज रूस के अन्दर ही हो सकता है इसलिए वहां भेजा जाय और यह बातचीत चल ही रही थी तो प्रेसीडेन्ट महोदय ने कहा कि इस समय कार्य बहुत ज्यादा है, मैं रूस नहीं जाना चाहता। आजादी का यह सैनिक, एक गरीब तबके से उठा हुआ इन्सान, जो कभी गरीबी से शर्माया नहीं, गरीबों की ओर से जिसने मुंह नहीं मोड़ा, और जिस तबके में पैदा हुआ था और जिस तबके से उठा था, उस तबके

(श्री बरकतुल्ला खां)

से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि हमेशा इस बात का उन्होंने खयाल रखा कि गरीबों की और पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद की जाय और कभी भी शर्माए नहीं, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि एक आदर्श जीवन उन्होंने हमारे सब के सामने रखा, वह आदर्श जीवन आज समाप्त हो गया।

जैसा कि सदन के सामने मैं अपना शोक प्रस्ताव पेश कर रहा हूं अपने निजीतौर से और सदन की ओर से उनके परिवार के साथ समवेदना प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि यह महान् आत्मा स्वर्ग में जल्दी पहुंचे, और उनके परिवार को जो पीछे रह गये हैं उनको तसल्ली मिले। ऐसी कामयाब जिन्दगी बहुत कम लोगों की बीतती है जैसी की संजीवैया में बीती है। हमारे सब के सामने चाहे वे किसी दल के हों, कांग्रेस के हों या और किसी दल के एक बड़ा जीवन सामने आया है। वह एक ऐसे इन्सान थे जिन्होंने सारी जिन्दगी सेवा में लगा दी—दलों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने हिन्दुस्तान की सेवा में अपना जीवन लगा दिया और सेवा के अन्दर पूरा जीवन गुजार दिया, और मरते समय तक हमेशा उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि गरीब और पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले।

श्री निरन्जन नाथ आचार्य (मावली): अध्यक्ष महोदय, एक लोकोक्ति है "दोज हूम गाड लव्ज दे डाई यंग।" दुःखी आदमी को सन्तोष देने के लिए यह लोकोक्ति है, संजीवैयाजी के सम्बन्ध में सारा भारतवर्ष उनके निधन पर अवाक रह गया। अवाक इसलिए रह गया कि वे एक ऐसे ऊंचे व्यक्ति थे। अपने विश्वासों के धनी दृढ़ संकल्प को हमेशा दृढ़ रहने वाले तेजस्वी असफलताओं और संघर्षों से जूझते हुए आगे बढ़ते हुए सफलताओं की चोटी पर पहुंचे और राष्ट्र का विश्वास-प्राप्त किया समाजवादी परम्पराओं और आस्थाओं की जड़ों को मजबूत किया। देश को उनसे बड़ी आशा थी। रुग्णावस्था में भी यद्यपि उनका स्वास्थ्य बहुत कुछ साथ नहीं देता था वे काम करते ही रहे। किन्तु वे मनस्वी थे, कर्मनिष्ठ थे और "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः" इन मान्यताओं के साथ में, अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते हुए भी राष्ट्र को अपनी मान्यताओं से आगे बढ़ाते हुए वे रात-दिन काम करते रहे। फिर भी देश को ऐसी आशा नहीं थी कि एक महान व्यक्तित्व जिसकी राष्ट्र के प्रति इतनी बड़ी निष्ठा थी और राष्ट्र जिसके प्रति इतना आशावान था, वह यकायक हमारे बीच में से उठ जायेगा।

राजनेता के आधार पर भी और समाजनेता के आधार पर वे पिछड़े वर्ग के मसीहा थे। उनका निधन देश की सबसे बड़ी क्षति है। देश में ऐसे लोग बहुत कम रह गये हैं जो पिछड़े वर्ग को उठाने में भावनाओं और मान्यताओं के साथ और हृदय के साथ इस नीति में विश्वास रखते हों। उन इने-गिने लोगों में से जो महात्मा गांधी की आस्थाओं के साथ रहे, उनमें से संजीवैया एक थे। स्वयं उनका निधन राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी खामी है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस महान आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भगवान इस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।

श्री मोहम्मदगफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, संजीवैया साहब की कब्जुलवक्त और अचानक मौत यह बहुत बड़ा सानिया है। वह न सिर्फ एक बहादुर सिपाही थे, बल्कि वे एक मानवता के प्रतीक थे, और धर्मनिरपेक्षता और दूसरे सिद्धान्तों, जिनको हम हिन्दुस्तान का आधार मानते हैं, उसके भी मानने वाले थे। जब तक वे जीवित रहे वे पिछड़े हुए वर्ग, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हकूकों के तवफ्फुस के लिए हमेशा कोशिश करते रहे और उन्होंने हकीकतन शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की हिमायत की और जो लोग ऐसे वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, वे उनसे बड़ी आशाएं लगाये बैठे थे। वे ऐसे समय में हमसे जुदा हुए कि उनकी जुदाई हमारे लिए बड़ी तकलीफदेह है। कोई तबई उम्र पहुंच कर अगर दुनिया से रुखसत होता है तो उसका इतना रंज नहीं होता है। आज अखबार ने उन्हें 48 साल का बताया और चीफ मिनिस्टर साहब ने 52 का बताया अगर वह भी माना जाय तो काफी कम उम्र थी। कम उम्र में वे हमसे जुदा हुए। मैं उनको खिराजे अकीदत पेश करते हुए अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से जो पस्मानगान हैं उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं और दुआ करता हूं कि उनकी रूह को शान्ति मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूं।

श्रीमती जमुना सोलंकी : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्षजी। सदन के नेता ने जो संजीवैया के निधन के बारे में शोक-प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हरिजन परिवार में पैदा हुए और उस वक्त के समाज के बीच में इस तरह के विकास करना, यह एक साधारण व्यक्ति का काम नहीं था। वे एक सेल्फ-मेड व्यक्ति थे और संघर्षों के बीच में उनके व्यक्तित्व का विकास हुआ और वर्कर से लीडर बने। ऐसी बहुत कम मिसाल मिलेगी। हमारे यहां एक मिसाल है कि 'सम मेन आर बोर्न ग्रेट, सम आर क्रियेटेड ग्रेट एण्ड सम बिकम ग्रेट' तो वे थर्ड कैटेगरी में से थे। जो शोक प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए मेरी अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे बीच में से आजादी का एक महान सेनानी उठ गया। इस भारत पर यों ही विपदाएं कई हैं और विपदाओं के बीच में से हमारे महान् सेनानी का उठ जाना, आज बड़े खेद की बात है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो गरीब और गरीबी के साथ हरिजन तबके में पैदा हुए थे और जिन्होंने गरीबों की सेवा की, हरिजनों की सेवा की और मरते दम तक भी बावजूद डाक्टरों की सलाह के भी उन्होंने जिन जिन लोगों ने उनसे सम्पर्क किया उनको अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए भी नेक सलाह दी और उसके देने से नहीं चूके। ऐसा महान् सेनानी हमारे बीच में से आज उठ गया। मैं मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हूं और परमात्मा से इस प्रकार की मेरी प्रार्थना है कि वह उनको स्वर्ग प्रदान करें और वह जो परिवार अपने पीछे छोड़ गये हैं, क्योंकि उनका निधन हो गया है, इसलिए उनके बिछोह और अभाव को सहने की क्षमता प्रदान करे।

श्री रावत राम (छापर): अध्यक्ष महोदय, आज सुबह जब अखबार में यह समाचार पढ़ा कि हमारे देश के एक प्रिय नेता श्री संजीवैया का रात्रि को निधन हो गया तो हृदय पर आघात लगा। अध्यक्ष महोदय, संजीवैयाजी एक बहुत ही निर्धन और गरीब हरिजन परिवार में पैदा हुए थे। यह वह समय था, जिन दिनों में जहां वह पैदा हुए थे, हरिजनों को पीने का पानी तक नहीं मिलता था और जब हरिजन सड़कों पर चलते थे तब भी लोग ऐतराज करते थे। संजीवैयाजी ने अपने जीवन में कितने ही संघर्ष किये, किस तरह से उन्होंने एजूकेशन ली, किस तरह से वह आगे बढ़े—यह कहानी जब हम सुनते हैं तो हमें उनके जीवन का सही पता चलता है। एक बार 1965 में उनसे मिलने का अवसर मिला था, जब वह उदयपुर पधारे थे तब उनको नजदीक से देखा, तब उनके व्यक्तित्व को देखा तो मुझे लगा कि कोई भी आदमी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उन्होंने कहा, आज समय क्या है, ऐसा समय था जब कई तरह विपदायें थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दलितों का, हरिजनों का एक महान्, जिसने इस राष्ट्र को, करोड़ों को एक रास्ता दिखाया, आगे बढ़ने का और मार्ग-दर्शन दिया, हमारे बीच से उठ गया है। इसके लिए सारे देश और करोड़ों गरीब लोगों को आज बड़ा दुःख है। मैं उस महान आत्मा के लिए अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और उन्हें सद्‌गति दें।

श्री सुरेश चन्द्र (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, आज अचानक माननीय संजीवैया के देहावसान का समाचार सुना तो अविश्वास हुआ। हमने यह सोचा भी नहीं था कि वह इतनी जल्दी और अचानक हमारे बीच से चले जायेंगे। यह समाचार सुनकर उन्होंने जो देश को दिया है उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो हम महसूस करते हैं, जिसकी समाज को अधिक आवश्यकता थी वह अचानक बहुत ही जल्दी हमारे बीच से चले गये। जहां जहां भी जिस पद पर रह कर उन्होंने काम किया, उन्होंने अपनी एक बड़ी छाप छोड़ी। उन्होंने हर जगह रह कर कई क्रांतिकारी परिवर्तन किये, जिससे आगे काम करने का लोगों को मौका मिला। समाज को उन्होंने अपना जीवन दिया और वास्तव में यदि देखा जाय तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया। आज जब हमारे बीच से वह चले गये हैं तो हमें ख्याल होता है, एक महान् आत्मा हमारे बीच नहीं है। उनकी कर्तव्य परायणता, निष्ठा और व्यवहार कुशलता और नेक नीयति हमारे सामने उदाहरण स्वरूप है। मैं स्वयं की ओर से और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, आज जब अचानक अजमेर से आते हुए संजीवैयाजी के बारे में सुना,

Page No 41

(श्रीमती जमुना सोलंकी)

तो मुझे बहुत धक्का लगा। अभी पन्द्रह दिन पहले मैं मिल कर आई थी। इतने बीमार होते हुए भी वह इतने व्यस्त थे और हरएक व्यक्ति को समय देकर उनका दुःख और दर्द वह सुना करते थे। संजीवैया जी के बारे में हम कहना चाहें तो जितना भी कहें वह थोड़ा है। पिछले कई सालों से उनसे और उनके परिवार से मेरा अच्छा सम्बन्ध रहा है। जब वह आन्ध्र में थे, मिनिस्टर बने, तो पहले हरिजन मिनिस्टर थे। बाद में चीफ मिनिस्टर बने, फिर सेन्टर में आये। जब वह आन्ध्र में मिनिस्टर थे, हमें वहां रहने की वजह से उनसे मिलने का मौका मिलता था। हम उनके भाषण सुनने जाते थे। वह तेलगू में अच्छी भाषा में बोलते थे। मुझे तेलगू आती है, इसलिए मुझे इन्ट्रेस्ट होता था, उनके भाषण सुनने में। मैं उनके भाषण सुनने जाती, उनके भाषण में एक दर्द होता और गरीब के प्रति उनके दिल में जो भावना थी वह उनके भाषण में उभर आती थी।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हरिजनों की भलाई के लिए काम करने वाला एक महान् पुरुष हमारे बीच से उठ गया है। उनके अभाव की पूर्ति नहीं हो सकती। भगवान उनके परिवार को, उनके विछोह को सहने की शक्ति प्रदान करें तथा उनकी आत्मा को शांति दे। यही मेरी प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री दामोदर संजीवैया के निधन पर माननीय नेता महोदय, तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, जो भावना सदन में रखी है, उनमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं और उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री संजीवैयाजी कुछ समय से अस्वस्थ थे, बीमार थे और बीमारी की हालत में भी बराबर काम-काज जारी रख रहे थे। नियमितरूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर आते थे। जो उस समय उनसे मिले थे तो कौन कह सकता था कि उनसे मिलने का आगे भविष्य में अवसर नहीं मिल सकेगा। ऐसी बात उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, लेकिन ईश्वर की मर्जी है, इस पर वश किसी का चलता नहीं।

संजीवैयाजी उन लोगों में से थे जिनको गरीबों की गरीबी का अहसास होता है क्योंकि वह खुद एक गरीब तबके से आते थे। जैसी कि कहावत है—जाके फटी न बिवाई वह क्या जाने पीर पराई। यह कहावत उन पर लागू नहीं होती क्योंकि वह उसी तबके से आते थे। उन्होंने फटी बिवाई भी देखी और उनके दर्द का अनुभव भी किया था क्योंकि वह गरीब आदमियों की खराब हालत देखते थे, तो वह हालत देख कर जो दर्द होता है, तकलीफ होती है उसके कारण वह रात दिन बराबर कोशिश करते रहे कि समाज, विशेषरूप से उनका समाज पिछड़े हुए लोगों का समाज आगे जा सके। उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में काम किया, वह आपके सामने अभी सदन में आया। उनकी सेवायें देश भूल नहीं सकता है, हमेशा याद रखेगा। वे दो दफा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बहुत कम लोगों को यह गौरव प्राप्त हुआ है कि दो दफा कांग्रेस के

(श्री अध्यक्ष)

बने हों। उनके बारे में मुझे एक मिसरा याद आता है, वह यह है—

"अफसोस उन गुंचों पर है जो बिन खिले मुरझा गये।"

इसमें मैंने इतना सा संशोधन और परिवर्तन कर दिया है।

"अफसोस उन गुंचों पर है जो अधखिले मुरझा गये।"

उनकी 51 वर्ष की उम्र थी, जो इतनी उम्र नहीं थी, उनका विकसित होने का समय था, पुष्पित और पल्लवित होने का समय था। लेकिन कुदरत ने उनको छीन लिया। जैसा आचार्य जी ने कहा, भगवान को उनकी वहां ज्यादा जरूरत होगी इसलिये उन्हें वहां बुला लिया। खैर, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का।

मैं निवेदन करता हूं कि दो मिनिट के लिये खड़े होकर उनकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(सदन ने मौन खड़े रह कर दो मिनिट तक दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना की)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री झाबरमल सुंडा, सदस्य विधानसभा ने राजस्थान में आबकारी विभाग द्वारा देशी शराब के ठेके दिये जाने से राज्य सरकार को होने वाली हानि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय पर दिनांक 5 मई, 1972 को सदन में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आ चुका है और विस्तारपूर्वक चर्चा हो चुकी है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सदस्य विधान सभा ने श्री गणेशचन्द्र जोशी मन्वन्तर द्वारा लिखित वनमानव के कुछ अंशों को हिन्दू धर्म के खिलाफ होने के कारण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जयपुर शहर में पर्चे बांटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सम्बन्ध में इसी सत्र में हाल ही में एक प्रश्न के उत्तर में विस्तार से चर्चा हो चुकी है और यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा ने कस्बा मेनसीसर, जिला झुंझुनू में पेय जल की समस्या के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दिनांक 3-5-72 को दी थी। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

सर्वश्री निरंजननाथ आचार्य, केदारनाथ और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें उन्होंने दिनांक 6 मई, 1972 को उदयपुर विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ष विज्ञान की रसायन शास्त्र परीक्षा का बहिष्कार करने वाले छात्र-छात्राओं पर पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति की चर्चा की है।

(श्री अध्यक्ष)

सर्वश्री निरंजननाथ आचार्य, केदार नाथ और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में युद्ध विराम के पश्चात् पाकिस्तान द्वारा किये जाने वाले अतिक्रमणों से उत्पन्न स्थिति की चर्चा की हैं।

इन विषयों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जावेगा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने फरमाया कि इस विषय में चर्चा हो चुकी है। मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में निवेदन किया है कि इस पर चर्चा हो चुकी है और चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने इस पर खेद प्रकट किया कि इस प्रकार की बात राज्य सरकार द्वारा की गई लेकिन उसके बावजूद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने पर्चा बांटा है, शहर के अंदर और हिंदू धर्म और संस्कृति के नाम को लेकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने खेद प्रकट किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बारे में जानकारी की जाएगी, दोषी आदमियों को दंडित किया जाएगा, उसके बावजूद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् हिंदू धर्म और संस्कृति के नाम पर पर्चे बांटे और इस तरह साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की जाए तो यह गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में पर्चा भी दिया है इसमें लिखा है:

अंधेर नगरी चौपट राजा·······

बरकत शाही में शिक्षा का स्तर?

हिंदू धर्म व संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं—

राजस्थान के शिक्षा विभाग के अंधेपन का भंडाफोड़ जब होता है तब गणेशचन्द्र जोशी "मन्वन्तर" लिखित "वन मानव" के दो खंडों "जनकजा" व अशोक वासिनी को विद्यार्थियों के पढ़ने हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिन पुस्तकों में लिखा गया है कि राम नपुंसक थे, सीता लक्ष्मण पर आशक्त थी, राम, लक्ष्मण भरत व शत्रुघन को वशिष्ठजी ने नियोग द्वारा पैदा किए क्योंकि दशरथ अशक्त थे। हनुमान बलात्कार द्वारा पैदा हुए ऐसे ही अन्य कई प्रकरण विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को बिगाड़ने वाले व हिंदू समाज की संस्कृति को कुठाराघात पहुंचाने वाले विषय हर पन्ने पर मनगढ़न्त, विभत्स चित्रण।

जिस व्यक्ति को इस हरकत पर सरकार द्वारा दंड दिया जाना चाहिए था, उलटा प्रोत्साहित करना प्रजातंत्र के माथे पर कलंक का टीका है। केवल लेखक व प्रकाशक ही दोषी नहीं अपितु पुस्तक को स्वीकृत करने वाले अधिकारी व सरकार स्वयं जिम्मेदार हैं। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए सरकार को विवश करने हेतु विद्यार्थीवर्ग व जनसाधारण में भी चेतना की आवश्यकता है।

विनीतः

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् व
अखिल भारतीय युवा मोर्चा

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के पर्चे बांटे गए जबकि मुख्यमंत्री ने इस बात का

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आश्वासन दे दिया, इस बात के लिए खेद प्रकट किया और आश्वासन दिया कि इसकी जांच की जाएगी और दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाएगा उसके बाद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, हिंदू धर्म और संस्कृति के नाम पर लोगों में साम्प्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करें...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह प्रश्न गंभीर है। राज्य सरकार की पुलिस को मालूम होना चाहिए, सी. आइ. डी. को मालूम होना चाहिए। आप विचार करें कि अगर इस प्रकार के पर्चे बांटे गए और मुख्यमंत्री के आश्वासन पर भी अखिल भारतीय परिषद्, जो जनसंघ पार्टी की है, उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा और हिंदू मुस्लिम तनाव फैलाने की कोशिश की और बरकतशाही को बीच में घुसा दिया, यह लिख दिया कि हिंदू धर्म व संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस आदमी ने किताब लिखी है वह भी हिंदू है वह भी दोषी है, जिसने उसको स्वीकृत किया है उसको भी दंडित किया जाना चाहिए लेकिन साम्प्रदायिक भावना पैदा करना और राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश की जाए और उसके बाद सदन में इस प्रकार की चर्चा हो चुकी है और आश्वासन दिया जा चुका है तो गंभीर विषय बन जाता है। आज शहर के अन्दर इस प्रकार के हजारों और लाखों पर्चे बंट चुके हैं, यह पर्चा चर्चा का विषय बन गया है। इस तरह साम्प्रदायिक भावनायें उभार कर जनता के मन पर किस प्रकार से असर हो रहा है, इस विषय में राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य आना चाहिए कि इस प्रकार के पर्चे कहां कहां बंटे हैं शहर में, इस पर्चे का क्या असर हुआ? यह लॉ एण्ड आर्डर का मामला है, कम्यूनल रायट्स हो जायेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा। जनसंघ पार्टी, विद्यार्थी परिषद् से इस प्रकार पर्चे बटवाए और राज्य सरकार को जानकारी न हो तो यह दुःख की बात है। जानकारी हो तो वक्तव्य आना चाहिए। यह गंभीर विषय है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : यह गंभीर विषय है इस पर...

(श्री गिरधारी लाल भार्गव और श्री योगेन्द्र नाथ हांडा साथ साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : नो डिस्कशन।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं बहस नहीं कर रहा हूं। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि सदन के बाहर राजस्थान भर के सारे हलवाई, छोटा छोटा धन्धा करने वाले, पकौड़ी, कचोरी, परावठा बनाने वाले आए हैं। मैंने इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव आपके पास रखा है।

श्री अध्यक्ष : जी नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बाहर प्रदर्शन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : 10 बजे तक तो आपका स्थगन प्रस्ताव नहीं आया। आपकी जानकारी के लिए निवेदन करूं कि 10 बजे तक स्थगन प्रस्ताव लेते हैं, यह प्रस्ताव उसके बाद प्राप्त हुआ है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वे बाहर प्रदर्शन करते रहे, आखिरकार उनके बारे में कुछ सोचना चाहिये। छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको रोजाना 90 रुपये का धन्धा होता है। विधान सभा के समस्त सदस्यों को उन्होंने प्रस्ताव की कापी भेजी है, वे नारेबाजी कर रहे हैं, रास्ता रोक रखा है। ऐसे लोग जो सदन के बाहर आए हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं। 90 रुपये रोज धन्धा करते हैं उसमें 10 कमायेंगे। यदि 10 रु० सेल्स टैक्स के आपको दे देंगे तो उनको क्या बचेगा ? 10 रु. रोजाना कमाने वाला व्यक्ति इसका मतलब 300 रु. प्रति माह कमाई हो और उस पर सेल्स टैक्स...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यूं ही बेचारे पकौड़ी बेचते हैं, मंदे और सूजी पर पहले ही टैक्स देते हैं। ये छोटे छोटे लोग बाहर खड़े हैं। कम से कम उनका शिष्ट-मण्डल बुला कर वित्त मन्त्री महोदय द्वारा उनको आश्वासन देना चाहिए कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, अनपढ़ लोग हैं उन पर जो सेल्स टैक्स लगाया है, उनसे उनको मुक्त करेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था शासन से हम चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : श्री सुरेन्द्र व्यास ने साम्प्रदायिक तनाव का जो प्रस्ताव रखा है, उसके लिए शहर में वाता-वरण बिगड़ रहा है...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनसंघ का उसमें कोई सवाल नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, राज्य के मुख्य मन्त्री पर कीचड़ उछाला गया है। मैं बार बार कह रहा था...

(दोनों श्री गिरधारीलाल व श्री हांडा साथ साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

इसका राजनैतिक उपयोग होता रहा...

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र
अधि-सूचनायें

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मन्त्री) : मैं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 29 के अन्तर्गत राजस्व उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या एफ 22 (69) रेव/कोल/65 दिनांक 28 मार्च, 1972 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टे) शर्तें 1955 में और संशोधन किये गये हैं।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 22 (54) राज/उप/69 भाग 3 दिनांक 24-4-1972 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (1955 के पश्चात् के अस्थायी कृषि पट्टाधारियों तथा अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन) द्वितीय संशोधन नियम, 1972 जारी किये गये हैं।

वार्षिक लेखा

श्री हरिदेव जोशी (विद्युत मन्त्री) : मैं विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक लेखे 1970-71 सदन की मेज पर रखता हूं।

अनुदान की मांगों का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर विचार।

श्री हरिदेव जोशी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक-

50. सार्वजनिक निर्माण कार्य।

50. सार्वजनिक निर्माण कार्य भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार स्थिर संयंत्र पर व्यय।

52. सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13, 16, 56,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43 मुख्य शीर्षक 109 अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2 हजार रुपये तक की राशि, जिसमें लेखा अनुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : मांगें प्रस्तुत हुईं।

श्री नारायणसिंह मसूदा (मन्त्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक 68 लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,15, 53,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव।

मांग संख्या 28, 33 एवं 43 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 28

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : 1. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा, कोठारी बिजनोल सड़क, नाथद्वारा स्टेशन सालोर पाखण्ड सड़क की दुर्व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : 2. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रायसिंह नगर, अनूपगढ़ सड़क के संबंध में सरकार द्वारा बरती जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गजसिंहपुर से रायसिंह नगर वाया चान्देवाला, भादूगल सड़क के संबंध में सरकार के दुर्लक्षपूर्ण रवैये की चर्चा के लिये)।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

4. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर से अनूपगढ़ तक सड़क के निर्माण की उपेक्षा पर चर्चा के लिये) ।

5. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ठेकेदारों द्वारा सड़कों, पुलों, डिग्गियों के निर्माण कार्यों में लाखों रुपया अवैध तरीके से एडवान्स लेकर भी कार्य न करने पर चर्चा के लिये) ।

6. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर की सड़कों के निर्माण में हुये भयंकर भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

7. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले के बार्डर क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये) ।

8. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्य की मन्थर गति पर चर्चा के लिये) ।

9. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 52 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मण्डी विकास मंडल में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

10. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 52 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में मंडियों के विकास विभाग की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये) ।

11. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 52 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा क्षेत्र की मंडियों के विकास की दुर्लक्षपूर्ण स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 33

12. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 68 लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राजकीय मुद्रणालय कर्मचारियों को विभिन्न अवकाशों की सहुलियतें दिलाने के संबन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 28

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : 13. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में सुरक्षा सड़कों की मरम्मत एवं संधारण नहीं किया गया है इस पर चर्चा के लिये) ।

14. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में अधूरी सड़कें पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

15. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनी हुई सड़कों को पूर्ण कराने में विभाग द्वारा की गई लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनी हुई सड़कों के निर्माण में सार्वजनिक निर्माण अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में (1) बाड़मेर से हरसाणी वाया बैसाली (2) रामसर से चौहटन (3) बाड़मेर से जोधपुर वाया बायट सीमावर्ती सड़कों को सुरक्षा की दृष्टि से सम्मिलित किये जाने के विषय पर चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) :

18. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में सड़कों की खराब हालत एवं मरम्मत न किये जाने में होने वाले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

19. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में कोठरी खंड पिड़ावा रोड पर कार्य न होने पर भी सड़क बन जाना बताया जाना तथा 2 लाख रुपया फर्जी खर्च बताने पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में डाक बंगला रोड़ (पाटन से) पर सड़क नहीं बनने पर भी सरकारी रेकार्ड में खर्चा होना बताया गया इस पर चर्चा के लिये)

21. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में रीछवा भालना रोड़ के पूरा न होने व सड़क की हालत खराब होने पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में झालरापाटन मकानी रोड़ पर कार्य न होवे व खराब सड़क की मरम्मत न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ से पाटन अकलेरा रोड़ की मरम्मत न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

24. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालरापाटन सुनेल रोड का कार्य पूरा न किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

25. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ के सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 28

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) :

26. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता द्वारा सार्वजनिक हित में निर्मित भवनों को विभाग के अन्तर्गत न लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

27. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल विभाग द्वारा निर्मित सड़कों को विभाग के अधीन न लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 33

28. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक, 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय मुद्रणालयों की विभागीय व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 28

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

29. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नापासर से गुसाईंसर सड़क की मरम्मत न कराये जाने पर चर्चा के लिए) ।

30. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर डिस्ट्रिक्ट एवं सिटी डिविजन्स के कार्य-क्षेत्र के मनमाने ढंग से बटवारे किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

31. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नापासर-गुसाईंसर सड़क की मरम्मत न किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :

32. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में सड़कों का अभाव एवं सड़क निर्माण के लिए ईंटे बनाकर अन्य काम में लेने पर चर्चा के लिये ।

33. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कच्चे रास्तों एवं नदियों में कच्ची रपटें बनाने के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

34. मांग संख्या 21. मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर, अरणाव, खारा सड़क, खारा गुंदाऊ सांकड़ सुरावा, दुगावा के लिये पक्की सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

35. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर-मवातड़ा, रिड़का सड़क, सेवाड़ा-चीतलवाना सड़क, सांचोर चीतलवाना सड़क, आमली, डेडवा, नारवल चोहटा अरणाय सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

36. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खोड़ा गरडाली सांचोर गांधव सुरक्षा सड़क की विशेष मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

37. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांकड़-गुजरात सरहद तक सड़क निर्माण कार्य में प्रगति लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

38. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रानीवाड़ा-सांचोर सड़क की मरम्मत पर चर्चा के लिये) ।

39. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में वार्षिक सड़क निर्माण हेतु बजट प्रावधान पर चर्चा के लिये) ।

40. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों के द्वारा बनी हुई पक्की सड़कों के मेन्टीनेन्स के लिए स्थाई गेंगों को लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर)

41. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय राज्य मार्गों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

42. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामप्रकाश सिनेमा भवन के किराये का पुनः असेसमेंट कराये जाने पर चर्चा के लिये) ।

43. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकार में आई हुई दुकानों व मकानों के किराये के बारे में चर्चा के लिये) ।

44. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

(सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भवनों की मरम्मत के अभाव में इनकी दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दुकानों को बेचने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर की सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर की समस्त गलियों की कच्ची सड़कों को व टूटी सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र में लेकर इनको ठीक कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

48. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 68-लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय मुद्रणालय की छपाई प्राइवेट मुद्रणालय के मुकाबले में खराब होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

श्रीमती भगवतीदेवी (भिनाय) :-

49. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत के अन्तर्गत रहे अधूरे कार्य को पूरा न कराने पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले की सड़कों की मरम्मत की उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती गौरी पूनिया (मकराना)

51. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागोर जिले की सड़कों की जीर्ण-शीर्ण हालत पर तथा विशेषरूप से मकराना क्षेत्र में सड़कों के अभाव पर प्रकाश डालने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीडोरा)

52. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर एलॉटमेन्ट में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में सड़कों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री नाथूराम)

मांग संख्या 33

54. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 68- लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 5 रुपया कम कर दिया जाये (लेखन सामग्री के क्रय में मितव्ययिता)।

मांग संख्या 28

श्री झाबरमल (फतेहपुर)

55. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फतेहपुर-झुन्झुनूं सड़क के निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लक्ष्मणगढ़ से डूंडलोद स्टेशन तक की सड़क तथा फतेहपुर से मंडावा सड़क निर्माण में अनावश्यक देर किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा)

57. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ओवरसीयर का हैड क्वार्टर अलीगढ़ से उनियारा स्थानान्तरित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक-उनियारा सवाई माधोपुर सड़क की बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जाने पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक के उनियारा से जहाजपुर वाया नैनवा सड़क का निर्माण नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा से इन्द्रगढ़ सड़क जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से चल रही है उसे पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक की खराब सड़कों की विभाग द्वारा समय पर मरम्मत नहीं कराई जाती— इस पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनराज (बाली)

62. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रानी-देसूरी सड़क किसी भी प्रकार के वाहन के चलाने के अयोग्य होने के कारण उसे तत्काल दुरुस्त कराने पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री मोहनराज)

दिया जाय (बाली-फालना 5 मील की सड़क अत्यन्त टेढ़ी मेढ़ी होने के फलस्वरूप प्रतिवर्ष एक्सीडेंट्स से अनेक जानें जाती हैं इस सड़क को सीधा करने की योजना पर चर्चा के लिये)

64. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सादड़ी-पिंडवाड़ा सड़क का कार्य कई वर्षों से अपूर्ण पड़ा हुआ है उसे शीघ्र पूरा कराने पर चर्चा के लिये) ।

श्री भंवरलाल भदादा (भीलवाड़ा)

65. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले की सड़कों और भवनों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली)

66. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूरा करने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा करने हेतु) ।

श्री देवीलाल (सराड़ा)

67. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में इटाली से बड़ाबली सड़क को थारोबा तक निर्माण कराने पर चर्चा के लिये) ।

68. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में जयसमन्द से गामड़ी, अदवास, जावद से माल तक सड़क निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिये) ।

69. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में सराड़ा से सेजारी कुण्डा सड़क पर डामर का कार्य कराने पर चर्चा के लिये) ।

70. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में चावण्ड से थाना, डोगरी उदयपुरिया, जागीर, सालमाड़ा बसी सड़क के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

71. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में पलादेदा से जावर माइन्स सड़क सेमारी से कठोड़ा सड़क पर कार्य कराने के लिये चर्चा के लिये) ।

72. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर)

73. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत

(श्री रोशनलाल शर्मा)

मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर से सलूम्बर वाया कुराबड़ बम्बोरा एवं कुराबड़ से गींगला वाया जगत रोड को प्लान में नहीं लेने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

श्री चिमनसिंह (भीम)

74. मांगसंख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति भीम व देवगढ़ जिला उदयपुर में कई वर्षों से अधूरी पड़ी हुई सड़कों का निर्माण कराये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

श्री हरलाल (प्रतापगढ़)

75. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील प्रतापगढ़ की सड़कों का निर्माण कार्य नहीं होने के सबन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा)

76. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा, छीपाबड़ोद में सड़कों की मरम्मत एवं नई सड़कों का निर्माण किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (पाली)

77. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय (भवन निर्माण का कार्य आवासन बोर्ड के द्वारा कराने की नीति अपनाने के बारे में नीति का अनुमोदन)।

78. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के अन्तर्गत बनी अधूरी सड़कों को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री भरतलाल (बामनवास)

79. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बामनवास गड़मोरा व गंगापुर गोंवड़ी रोड सवाई माधोपुर की सडकों की ओर विभाग का ध्यान दिलाने पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बामनवास व बौंली, सवाई माधोपुर क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन)

81. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील केशोरायपाटन-लाखेरी से उतराना बून्दी रोड में तावेडा पाटन से बून्दी रोड, इन्द्रगढ़ से करवर तक की सड़कों की मरम्मत न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री नन्दलाल बेरवा)

82. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में सडकों के अधूरे कार्यों को पूरा नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर से टोंक, देवली, बून्दी, कोटा, झालावाड़ा जाने वाले मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग अब तक नहीं बनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) :

84. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करणपुर-गजसिंहपुर सड़क का 5-10 किलोमीटर के ठेके देने में अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर-बुढ़ा जोहर (Budhajohar) सड़क का 5-10 किलोमीटर का ठेका देने में अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रायसिंहनगर-जेतसर-सड़क पर राजस्थान नहर की सूरतगढ़ शाखा पर पुल बनाने के लिए नहर डाइवर्शन (डाफ) की 70,000 रु० के भुगतान पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (Link Road) (लिंक सड़क डेट्लवा की मन्जूरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़क सूरतगढ़-बादूमल पर किये गये अधिक व्यय पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। लिंक (Link Road) सड़क 39 आर० बी० जो 1957 में मन्जूर हो गई थी नहीं बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक-निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा किये जाने वाले नाजायज स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा)

91. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चौमूं-दांता-रामगढ़ सड़क पर डामर बिछवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के

(श्री पी० के० चौधरी)

अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कालाडेरा से बादल तथा अस्तिकला से बादल सड़क पर कार्य प्रारंभ कराने हेतु चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (Lalpura-Mandha Bhim Singh सड़क को Bhadwa तक बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (Jobner-Renwal and Jobner Phulera सड़क पर डामर बिछाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फुलेरा काछरोद सड़क निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टियोल से खंडेल तक सड़क निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद)

97. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की सड़कों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री मालाराम (नीम का थाना)

98. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माऊंडा से मेवाड़ा जिला सीकर में सर्वे होने के पश्चात् सड़क न बनने पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मूदोली से गणेसर होकर सावलपुरा अधूरी सड़क को पूरा कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जीर की चौकी से रामपुर तक सर्वे होने के पश्चात् सड़क निर्माण कार्य न होने पर चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाटन से रिलपुरा होकर हरियाणा राज्य की सीमा तक सड़क निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

102. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गणेसर से टोडा सड़क निर्माण करवाने पर चर्चा के लिये)।

Page No 57

(श्री मालाराम नीमकाथाना)

103. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100. रुपया कम कर दिया जाय (नीमकाथाना से सेहपुरा गुंवार तक सर्वे होने पर भी सड़क निर्माण कार्य न होने पर चर्चा के लिये) ।

104. श्री सुग्णाराम (डूंगरगढ़) : मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में सड़कों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

105. श्री चुन्नीलाल इन्दुलिया (नोखा) : मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हुसेरुणा से इयोंरा कैम्प को वाया सूड़सर, सांवतसर, राजेडू, सोनियासर सड़क पर कंकरीट व डामर किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

106. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरगढ़ से बोदासर वाया बाना रिड्डी तक रोड को ठेकेदारों द्वारा समय पर पूरा न करने व इसमें विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये) ।

107. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोखा में डाक बंगले के निर्माण नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये) ।

108. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सींथल से जसरासर वाया मुंडेसर, उत्थोर, आथुरी, साधासर, जसरासर तक सड़क बनाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

109. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोखा मंडी से पांचू वाया नाथूसर, धरनोंक, ऊदासर, कूदसू तक सड़क निर्माण न कराये जाने पर चर्चा के लिये) ।

110. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नापासर से गुसाईंसर तक सड़क की मरम्मत व डामर कराने के लिए सरकार एवं चीफ इंजीनियर की आज्ञा की अवहेलना पर चर्चा के लिये) ।

111. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मामलसर से कोलायत वाया मामलसर, देसावसर, जांगलू, पिकरासर, नेसिहदेसर, मगरा, झझू रोड पूरा न करने पर चर्चा के लिये) ।

112. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोखा मंडी से सेरूणा तक वाया कक्कू, साधुना तक डामर रोड को बनाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

113. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोखा मंडी से रोडा तक 12 मील की सड़क की मरम्मत व डामर कराने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

114. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वाया बेरासर, बीनया, कुचोर आगूणी, बादनू, सोंवलसर, डूंगरगढ़ तक रोड़ बनाने में असफलता पर चर्चा के लिये) ।

115. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर से डूंगरगढ़ वाया कालू तक सड़क निर्माण को पूरी कराये जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

116. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़क ग्राम काकड़ से बेरासर तक 5 माइल डाम्बर रोड बनाने पर चर्चा के लिये) ।

117. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पलाना से लालमदेसर बरसिंहसर, मिंयरासर, जेसिंहदेसर, भगरा, थरवाके तक सड़क निर्माण पर चर्चा के लिये) ।

118. मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (मेहनसर से थावरिया ग्राम भालेड़ी, उड़सर, भड़ीवाला, बेरासर, सिच्चू मोड़ खाना, गजलेदेसर, पीकनेवर तक रोड़ बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

119. श्री मोहन लाल छंगाणी (फलौदी): मांग स० 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों में (Priority) प्राथमिकता की व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

120. श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा): मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक हित के नवीन निर्माण कार्यों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

121. श्री मगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : मांग सं० 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर एवं बाड़मेर जिलों में सार्वजनिक निर्माण कार्यों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा का बर्ताव किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा करने हेतु)

122. श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बूंदी): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा से बूंदी होकर जाने वाले व बूंदी में पैदा होने वाले 50 लाख रुपये के पत्थर

(श्री राजेन्द्र कुमार मारतोया)

की रायल्टी दी जाती है फिर भी सरकार वहां सड़कों के बारे में नहीं सोच रही है इस पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50- सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जावरा, भीमपुरा, गुल खेड़ी, जिला बुन्दी में नदियों के पानी से जाने के अलावा रास्ता बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

124. श्री फारुक हसन (सवाई माधोपुर): मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर विधान सभा हलके में गत 20 साल में कोई सड़क नहीं बनाई गई है उस पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरूंलाल (अकलेरा):

125. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कन्या माध्यमिक विद्यालय, अकलेरा भवन के निर्माण को पूरा कराया जाने पर चर्चा के लिए)।

126. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोहरथाना से हुरनावदा वाया जावर सड़क को वापस निर्माण विभाग में ली जाकर पक्की कराये जाने पर चर्चा के लिए)।

127. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अकलेरा के आसनपुर ग्राम में बैरागढ़ ग्राम तक की रोड़ का निर्माण करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर):

128. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 - सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्राथमिकता पर चर्चा के लिए)।

129. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर की डामर की समस्त सड़कें सन् 1963 में सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दी गई थी किन्तु सरकार द्वारा इनकी अभी तक देखभाल नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

130. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा ठेकेदारी प्रथा के उन्मूलन न किये जाने पर चर्चा के लिए)।

131. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की मन्थर-गति पर चर्चा के लिए)।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

मांग संख्या 33

132. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लेखन सामग्री तथा मुद्रण विभाग की अकर्मण्यता एव मुद्रणकार्य में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिए)।

133. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 68––लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संचालक मुद्रण एवं लेखन सामग्री द्वारा राजस्थान के बाहर की संस्थाओं की निविदायें स्वीकार की जाना तथा राजस्थान की संस्थाओं की उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा):

134. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय एजेन्सी द्वारा सड़कों एवं मकानों का काम न करवा कर ठेके की प्रथा को प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिए)।

135. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के पी. डब्लू. डी. विभाग में ठेकेदारों द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं धांधलियों की ओर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

136. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मण्डावा से बिसाऊ तक की सड़क निर्माण में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिए)।

137. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू से भूरासर का बास तक सड़क निर्माण में किए जा रहे अनावश्यक विलम्ब पर चर्चा के लिए)।

138. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं से राजगढ़ वाया मलसीसर सड़क के निर्माण की उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

139. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 – सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुकुन्दगढ़ से मंडावा तक की सड़क पर डामर (तारकोल) अभी तक नहीं गिरवाने के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

140. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझनूं जिले में सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त साधन नहीं जुटाये इस पर चर्चा के लिए)।

Page No 61

(श्री रामनारायण चौधरी)

मांग संख्या 33

141. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 68—लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लेखन सामग्री की खरीद में घोटाले एवं घटिया किस्म की सामग्री सप्लाई करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

श्री नानालाल (राज समन्द)

142. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खंडेल से कुरंज सड़क का टुकड़े बनाने हेतु चर्चा के लिए)।

143. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेलमगरा से फतहनगर सड़क का कार्य पूरा कराने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री गौरीशंकर (खानपुर)

144. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानपुर विधानसभा क्षेत्र, जिला झालावाड़ में पक्की सड़कों की दुर्दशा एवं मरम्मत न किये जाने पर चर्चा के लिए)।

श्री जेठमल (परबतसर)।

145. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर से हरसोरे रोहन्डी की घाटी तथा परबतसर से पुष्कर एवं खुन्दियास से हरसोर सड़क की मरम्मत पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 28

श्री मोहरसिंह (चूरू)

146. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार ने डेडराज भरतिया अस्पताल चूरू की मरम्मत नहीं करवाई और उसके बाग को भी उजाड़ दिया है सड़क पर आई हुई मिट्टी उठा उठाकर अस्पताल में भर दी है इस पर चर्चा के लिए)।

147. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार ने चूरू जिले में सड़कों के नीचे आई हुई भूमि का मुआवजा न देकर कानून, नियम और संविधान का उल्लंघन किया है इस पर चर्चा के लिए)।

148. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार चूरू से फतेहपुर सड़क निर्माण कार्य पूरा करवाने में असफल रही है और अपने आश्वासनों को पूरा नहीं किया इस पर चर्चा के लिए)।

149. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री मोहरसिंह)

दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग चूरू--झुंझुनूं सड़क की मरम्मत करवाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिए)।

150. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार चूरू जिले में अकाल राहत कार्य में खुदवाये गये घाघले पत्थर का दुरुपयोग, चोरी और गबन रोकने में असफल रही है और कोई हिसाब भी नहीं रखा गया है इस पर चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराने में सरकार असफल रही है इस पर चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार साहवा से मालेरी सड़क निर्माण कार्य पूरा करवाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा पंचायत समितियों में ओवरसियर आदि के स्थानान्तरण नहीं किये जाने से पंचायत समितियों की ग्रांट का उपयोग नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरदारशहर से नोहर सड़क बनाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू में सरकार डाक बंगलों को बनाने में असमर्थ रही है तथा विश्रामगृह में आवास की कमी दूर नहीं कर सकी है इस पर चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू में अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय भवन बनवाने में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार ने चूरू से मालेरी सड़क को क्रमोन्नत करने में बहुत देर की है इस पर चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार चूरू से रतननगर सड़क की मरम्मत करवाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 28 मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के

(श्री मोहरसिंह)

अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार दूधवाखारा से दूधवाखारा स्टेशन की मरम्मत वर्षों से कराने में असफल रही है जिससे वह सड़क बहुत टूट फूट गई है इस पर चर्चा के लिये) ।

160. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार चूरू से तारानगर सड़क निर्माण पूरा करवाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये) ।

161. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार मालेरी से साहवा सड़क का निर्माण पूरा कराने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये) ।

162. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू से सरदारशहर सड़क का निर्माण पूरा करने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये) ।

163. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू से रतनगढ़ व मालेरी सड़कों के मिलने के स्थान से चूरू शहर से सड़क द्वारा जोड़ने में असफल रही है जिससे लोगों को एक किलोमीटर के बजाय 7 किलोमीटर चलना पड़ता है इस पर चर्चा के लिये) ।

164. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार ने चूरू से दूधवाखारा स्टेशन सड़क बनाने में अत्यधिक विलम्ब किया है उसमें घटिया सामग्री लगाई जा रही है । सड़क में निर्धारित स्तर व नाम से घटिया व कम सामान लगाया जा रहा है इस पर चर्चा के लिये) ।

165. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चूरू के पशु अस्पताल की 20 वर्षों से मरम्मत नहीं करवाई जा रही है इस पर चर्चा के लिये) ।

166. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार रतननगर के देपालसर सड़क पर चढ़ी हुई 8′–8′ रेत वर्षों से नहीं उठवा सकी है वह सड़क बन्द हो गई है इस पर चर्चा के लिये) ।

167. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने विभाग का काम हिन्दी में करने में असफल रहा है इससे जनसाधारण इस विभाग की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है इस पर चर्चा के लिये) ।

168. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री मोहरसिंह)

दिया जाय (सरकार राजस्थान के गांवों के लिए सड़क बनाने की ठोस योजना बनाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

169. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय प्रेस सरकारी सूचनायें प्रकाशित करने में अत्यधिक विलम्ब करते हैं इस पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 68, लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुद्रणालय जनसाधारण के लिए सस्ते और एकीकृत समुचित कानूनी प्रकाशन उपलब्ध कराने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 68 लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज-पत्र छपाई की अशुद्धियों से भरा रहता है तथा बिना शुद्धिपत्र साथ लगाये पढ़ना भी संभव नहीं होता तथा राज-पत्र बहुत ही घटिया कागज पर छपता है उस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 28

श्री बद्रीप्रसाद (बानसूर)

172. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बानसूर तहसील की खेड़ा श्यामपुरा सड़क के निर्माण के 5 साल से ढिलाई पर चर्चा के लिये।

173. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले की बानसूर तहसील की सड़कों की मरम्मत की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले की बानसूर तहसील में नई सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले की बानसूर तहसील के पिछले पांच साल से सड़क निर्माण की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) :

176. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य की वार्षिक योजना (1972–73) में सड़कों के निर्माण के लिये उचित प्राथमिकता दिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

177. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

Page No 65

(श्री अमृतलाल गहलोत)

दिया जाय (जोधपुर तहसील की सड़कों के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री गोरधन सिंह (सीकर) :

178. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्य जो विभाग द्वारा किये जाते हैं उनमें होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सीकर में यातायात की सुविधा एवं ग्राम पंचायतों को सड़क द्वारा जोड़ने हेतु सड़क निर्माण को प्राथमिकता देने के संबंध में चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कूदन-रसीदपुरा, जिला सीकर की सड़क का कार्य आधे से भी कम हुआ है उसमें गति लाने हेतु चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर-डीडवाना वाया सीहोटबड़ी की सड़क का निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोसल-डीडवाना सड़क के भाग की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंगरावट-नछेवा सड़क, जिला सीकर के अधूरे कार्यों को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर धोद सड़क का कार्य संतोषप्रद नहीं हुआ इस पर चर्चा के लिये)।

श्री केसरीमल (ब्यावर):

185. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाना जिला अजमेर) में पोस्टमार्टम रूम के अभाव पर चर्चा के लिये)।

186. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर के ए० के० शफाखाने के भवन के अभाव पर चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा कराये गये कार्य की खराबी पर चर्चा के लिये)।

Page No 66

श्री गोपालसिंह (खन्डेला) :

188. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील श्री माधोपुर में खंडेला पलसाना सड़क निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

189. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक क्षेत्र में बनास नदी पर सड़क निर्माण पर चर्चा के लिये)।

श्री ज्ञानसिंह (मादरा) :

190. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला श्रीगंगानगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से भवन निर्माण व सड़कों के सुधारे जाने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा) :

191. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में माण्डव माइन्स से सरोदा वाया पाड़वा भासौर रोड़ और सागवाड़ा से रुही वाया सरोदा रोड़ पर चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में तहसील सागवाड़ा, डूंगरपुर व आसपुर तहसील की सड़कों के निर्माण कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल (लालसोट) :

193. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट मोटर स्टैण्ड पर सड़क पर पड़े हुए खड्डे को शीघ्र ठीक कराए जाने हेतु चर्चा के लिये)।

194. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट, डीडवाना, रामगढ़ पचवारा सड़क का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाने पर चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जंक्शन पर रेलवे क्रॉसिंग पर पुल का कार्य शीघ्र करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट सवाई माधोपुर सड़क पर बनास व मोरेल नदी पर शीघ्र पुल बनवाये जाने पर चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के

Page No 67

(श्री मीठालाल)

अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तूंगा कोटखावड़ सड़क कार्य शीघ्र चालू कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

198. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट गढ़मोरा सड़क शीघ्र पूर्ण कराई जाने हेतु चर्चा के लिये)।

199. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट कोथून सड़क पर पड़े हुये खड्डों को शीघ्र ठीक कराया जाने पर चर्चा के लिये)।

200. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा गंगापुर सड़क पर पड़ रहे खड्डों को शीघ्र ठीक कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

201. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा लालसोट सड़क पर बन रहे राहूवास नदी के पुल के निर्माण कार्य को पूर्ण कराया जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशनलाल (फागी):

202. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी क्षेत्र में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री रामरघुनाथ (डेगाना):

203. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तरनाऊ, डेगाना, अजमेर सड़क के अपूर्ण रहने पर चर्चा के लिये)।

श्री बनवारी लाल (निवाई):

204. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री हरीकिशन (राजगढ़):

205. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील थाना गाजी में अजबगढ़ प्रतापगढ़ रोड पर स्थित ग्राम झिरी से ग्राम नटाटा तक सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर, जो जयपुर से इस पिछड़े क्षेत्र को जोड़ेगी, इस पर चर्चा के लिये)।

206. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में लक्ष्मणगढ़ गढ़ी सड़क पर आवश्यक पुल बनाने व सड़क पर डामर न होने पर चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

Page No 68

(श्री हरिकिशन)

(राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र, जिला अलवर में सड़क निर्माण कार्य जो गत सालों से चालू है उसे पूरा कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)

208. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजगढ़ पुपडावर रोड पर के पास रेलवे लाइन फाटक के दोनों तरफ पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पालपुर से लिराना बुरजा तक रहूला गोला का बास रोड पर रोडी व तारकोल बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पिनान खोहरा सड़क पर स्थित ग्राम भलावली से गढी लक्ष्मणगढ़ रोड को जोडने वाली लिंक(Link Road) बिचगापा तक निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेलवे स्टेशन करनपुरा से पुपडावर मण्डी तक सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

212. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आंदीकुई सिकन्दरा रोड पर बाना नदी का पुल निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

213. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर राजगढ़ रोड पर रुपारेल नदी पर सेाहनपुर ग्राम के पास पुल बनाने तथा सपेल रायपुरा नदी पर भी पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजगढ अलवर रोड पर स्थित कोठी नारायणपुर के सिवारे से राजगढ़ पुपडावर रोड को जोड़ने के लिये मा ाठी तक लिये (Link) रोड बनवाने हेतु चर्चा के लिये)।

215. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा राजगढ़ जिला अलवर में (Bye pass) बाई पास रोड निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोला का बास अजबगढ़ रोड पर सरसादेवी के स्थान पर आवश्यक पुल के निर्माण की चर्चा के लिये)।

श्री सांवरमल (श्री माधोपुर) :

217. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत की उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये)।

श्री मुन्शीलाल महावर (बस्सी) :

218. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्यों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लवान तूंगा सड़क ठेका प्रथा द्वारा निर्माण कराये जाने में हुई अनियमितताओं के कारण मार्ग अवरुद्ध हो रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़)

219. मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्यो आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अन्तर्गत सड़कों की मरम्मत का कार्य पूर्ण कराने के क्रम में चर्चा के लिये)।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) :

220. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 68-लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केन्द्रीय मुद्रणालय द्वारा घटिया किस्म की लेखन सामग्री क्रय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 68-लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लेखन सामग्री एवं मुद्रित साहित्य समय पर उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये)।

अनुदान की मांगें

अनुदान की मांग सं० 28, 33 व 43 पर विचार एवं पारण

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 28, 33 व 43 के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती के प्रस्ताव दिये हैं, उनमें आज तक जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो जो कार्य हुए हैं, उसका भी मैं कुछ उल्लेख करना चाहूंगा। क्योंकि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। इसके साथ साथ चूंकि यह एक सीमान्त प्रदेश है और इसकी सारी की सारी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है इसलिए इसकी और भी महत्ता हो जाती है। आज राजस्थान के गंगानगर जिले व और भी दूसरे जिले जो हैं, उनमें पेय जल की बहुत ही भारी समस्या है। आज राजस्थान के अन्दर जो ट्रान्सपोर्टेशन की स्थिति है, वह भी बड़ी दुर्लक्षपूर्ण स्थिति है। ऐसी खराब स्थिति भारतवर्ष के किसी भी राज्य के अन्दर नहीं है। एक प्रदेश जो कि सीमान्त प्रदेश होता है और वहां पर अगर सड़कें ठीक तरह से नहीं बनी हुई हों तो बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है। इसलिए हमें सड़कों के विकास के लिए गम्भीरता से सोचना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान की जो पिछली चार योजनायें बनी थीं उनमें सड़कों

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

के लिए किस किस प्रकार से कितनी धनराशि खर्च हुई, उसका अगर हम अवलोकन करें तो हमारे प्रदेश की स्थिति बड़ी ही दुर्लक्षपूर्ण दिखाई देगी। पहली पंचवर्षीय योजना में हमारे यहां पर सड़कों के ऊपर 553.29 लाख रुपया खर्च हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारे यहां 111.35 लाख रुपये का खर्चा हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारे यहां जो राशि खर्च हुई वह करीब 90.1 लाख रुपये के करीब खर्च हुआ। तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार राशि घटती ही गई और चौथी योजना तो बनी ही नहीं। इसमें एक प्रारूप तैयार किया था जिसके अनुसार 760 लाख रुपये का खर्च करना था पर उसमें से करीब 400 लाख रुपया खर्च किया गया और 360 लाख रुपये को बोर्डर रोड्स व कोलोनाइजेशन के ऊपर खर्च करने के लिए था वह प्रावधान पुरानी सड़कों को ठीक कराने के लिए था। इसमें नई सड़कों को बनाने का कोई प्रावधान नहीं था। सन् 1951 में जो सड़कें 100 स्क्वायर मील बननी थी, वह 5.41 मील बननी थी वह सड़क सन् 1969 तक सिर्फ 9.95 किलो मीटर ही पूरी हो सकी। यह जो उपलब्धि हुई है वह तो नहीं के समान है। इसके अलावा सन् 66, 67 व 68 में जो धनराशि का प्रावधान सड़कों के लिए रखा गया वह 199 लाख रुपये 1966 में और 122 लाख रुपये सन् 1967 में और 1968 में एक सो लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी दुर्लक्षपूर्ण स्थिति है। पहले भारत पाक संघर्ष हुआ तो इसके बाद में कुछ सड़कों का निर्माण हुआ था लेकिन वह बहुत ही कम है। अभी जो भारत पाक संघर्ष हुआ उसके बाद में भारत सरकार इन सीमान्त जिलों में सड़कें बनाने के लिए तैयार है। पर अभी तक सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। आज बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर के लिये जो कि सीमान्त जिले हैं, उनमें सड़कों का विकास करने की अत्यन्त आवश्यकता है। लेकिन राज्य सरकार इस ओर सक्रिय नहीं है। अभी एग्रीकल्चरल कमीशन के श्री रामोराव आये थे उन्होंने कोलोनाइजेशन और दूसरे एरिया में सड़कों के विकास कार्यों के लिये 40 करोड़ रुपये की राशि की सेंक्शन की पर यह राशि बहुत ही थोड़ी है, क्योंकि अकेले कोलोनाइजेशन के एरिया में 12 करोड़ रुपये की लागत की सड़कों का बनाना अत्यन्त आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, सड़कों की बहुत ही खराब स्थिति है इस एरिया में और जो इधर धनराशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत होती हैं, उसमें भी बड़ी दुर्लक्षपूर्ण स्थिति है क्योंकि जो सड़कें प्रोजेक्ट के अन्तर्गत तैयार होती हैं उसके लिए पी. डबल्यू. डी. तो कहती है कि कोलोनाइजेशन वाले बनायेंगे और कोलोनाइजेशन वाले कहते हैं कि यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग का है। इस तरह दोनों ही विभागों में खींचतान होती रहती है और सड़क बन नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में हम तो यही चाहते हैं कि हमारे तो काम होना चाहिये चाहे पी. डबल्यू. डी. वाले करें अथवा कोलोनाइजेशन वाले करें। इस सन्दर्भ में अध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर के जिले की जो सड़कें हैं उसके बारे में विशेषरूप से निवेदन करूंगा कि वहां की सड़कों का हाल यह है कि पहले तो सड़कें ही कम हैं और जो हैं वे बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। आज अगर रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो मैं समझता हूं, अध्यक्ष

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

महोदय, कि गंगानगर जिले से राजस्थान सरकार को हाइएस्ट रेवेन्यू की प्राप्ति होती है चाहे एक्साइज से हो चाहे कस्टम से, चाहे इनकमटेक्स से, चाहे राजस्व कर हो। लेकिन आज जो बुरा हाल वहां की सड़कों का है वह आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर हम गंगानगर जिले की तुलना दूसरे जिलों से करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि इस जिले में कितनी कम सड़कें बनी हैं। आज अजमेर में कुल 8147 किलो मीटर्स में से 1465 किलो मीटर तक की सड़कें बनी हुई हैं इसी प्रकार अलवर में 7695 किलो मीटर में से रोड माइलेज 183 किलो मीटर का है, उदयपुर में 10,093 किलो मीटर में से कुल सड़क 1340 किलोमीटर्स है जब कि गंगानगर जिले में 20,649 स्क्वायर किलो मीटर्स में सिर्फ 784 स्क्वायर किलो मीटर्स सड़क है। अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिला एक सीमान्त जिला है वहां सड़कों का होना निहायत जरूरी है। इसके अलावा मैंने कुछ कट मोशन सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके सम्बन्ध में दिये हैं। मैं कुछ उसके बारे में भी निवेदन करूंगा। आज वहां पर इस विभाग की ऐसी स्थिति है कि जल्दी वहां के लोग नटवरलाल और नागरवाला बनने वाले हैं। वहां पर ठेकेदार लोगों ने 27 लाख रुपये एडवान्स ले रखे हैं जबकि काम सिर्फ 28 लाख का ही है और वह भी काम पूरा नहीं हुआ है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश करना चाहूंगा। सूरतगढ़ से गंगानगर तक सड़क निर्माण के लिए चार कान्ट्रैक्ट हुए। उसमें एक टेन्डर श्री कुलदीपसिंह का स्वीकृत किया गया जो सबसे लो टेन्डर देने वाले से 42 परसेन्ट ऐबो था। यह है एक टेन्डर के बारे में दूसरे बी. सी. डी. इन टेन्डर्स में जिसका बिलो टेन्डर था, उससे कुलदीपसिंह की रेट 37 प्रतिशत ऐबो थी और इसी प्रकार 10 प्रतिशत दूसरे टेन्डर्स से ज्यादा थी पर टेन्डर श्री कुलदीपसिंह का ही पास किया गया। इस कुलदीपसिंह ठेकेदार ने 3.5 लाख रुपये का टेन्डर पार्ट ए और 4.5 लाख रुपये का टेन्डर बी. सी. डी. का स्वीकृत करा लिया। अध्यक्ष महोदय, कैसी दुर्लक्षपूर्ण स्थिति है कि एक सड़क हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ बननी थी जो कि जीरो मील से 13 मील का टुकड़ा था. उसमें इस कुलदीपसिंह ठेकेदार ने 3.5 लाख रुपया एडवान्स उठा लिया और काम भी पूरा नहीं किया। यह सड़क अकाल राहत कार्य के समय में भी बनी थी। इस प्रकार इस सड़क पर कुल 13.5 लाख रुपये का खर्चा हुआ और स्थिति यह है कि अध्यक्ष महोदय, इस 0 मील से लेकर जो 13 मील तक की सड़क जो बननी थी, उसमें सिर्फ पांच मील तक ही सड़क बन सकी बाकी काम ही नहीं हुआ और इस पांच मील के टुकड़े के लिये जिसमें 7.8 लाख का ही काम हुआ, उसके 13 लाख तीस हजार रुपये का पेमेन्ट श्री कुलदीपसिंह को हो गया। अभी एक बिल उनका पांच लाख रुपये का और पास होने को पड़ा है। तो वहां पर एक एस० सी० सांघी पहुंच गये और उन्होंने पांच लाख के बिल को रोक दिया। कुलदीपसिंह ने भरे बाजार सांघी को कहा तेरा ट्रान्सफर करवा दूंगा। तू जानता नहीं है 1971 में मेरी 60 हजार जीप पार्लियामेंट के इलेक्शन में चल रही थीं। अध्यक्ष महोदय, ओपन बाजार में कुलदीपसिंह ने कहा मैंने पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर हरिदेव जोशी को पांच लाख रुपये का चन्दा दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : इलेक्शन के समय हरिदेव जोशी पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर नहीं थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा: लेकिन आपने चन्दा लिया है ।

श्री हरिदेव जोशी : गलत है । जब डिपार्टमेंट ही मेरे पास नहीं था तो मेरे पास कैसे आये और मैं कैसे लेता ......

श्री योगेन्द्र नाथ हान्डा : वह तो मैं बताता हूं कैसे लिये हैं। आपकी समझ में नहीं आयेगा, मैं समझा दूंगा। माननीय मंत्री हटे तो उसका चार्ज उन पर लगा और कांग्रेस में लगा और वह चार्ज इन्दिरा गान्धी के पास लगा कि माननीय मंत्री महोदय हरिदेव जोशी राजस्थान के बड़े बड़े उद्योगपतियों से राजस्थान के बड़े बड़े ठेकेदारों से चन्दा इकट्ठा किया है, जबकि इसके बारे में हरिदेव जोशी से पूछा तो कहा

श्री हरिदेव जोशी : सवाल ही नहीं आया है ।

श्री योगेन्द्र नाथ हान्डा : आया है ।

श्री हरिदेव जोशी : आप गलत कह रहे हैं ।

श्री योगेन्द्र नाथ हान्डा : जो जोशीजी कह रहे हैं वह पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर को बचाने के लिये कह रहे हैं। जब आपने कहा "मैं उस समय पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर नहीं था तो आपको चन्दा कैसे मिला है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं आप को चन्दा मिला है और इस बारे में आपको सबूत चाहिये, मैं प्रस्तुत कर दूंगा। माननीय सुखाड़िया साहब ......

(12.41 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

ने कहा है यह जो चन्दा दिया गया है यह सारा का सारा चन्दा हरिदेव जोशी ने मेरे कहने से इकट्ठा किया है। अब ऐसा कहने से हरिदेव जोशी की तो मुक्ति हुई। यह सारा का सारा हुआ है, यह मैं जिम्मेदारी से कहता हूं ।

एक और चीज है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर में कान्ट्रेक्ट हुआ। यह कान्ट्रेक्ट 1970 में हुआ और उस समय यह बात कुलदीपसिंह की दीप सिनेमा के निर्माण के बारे में है । इस सिनेमा का निर्माण कार्य दिल्ली में चल रहा है। जिस समय हमारे राज्य मंत्री चौधरी मनफूलसिंहजी थे तो उनकी श्रीमती का उस सिनेमा में चौथाई हिस्सा था। उस सारे के सारे ऐडवान्स को कुलदीपसिंह ने सिनेमा हाल के निर्माण कार्य में लिया और इतना ही नहीं एक एक्स.इ. एन. श्री कमला कान्त वहां पर आये और अपाइन्ट हुए और जब चैक करना चाहा, इनका एडवान्स रोकना चाहिए तो इनका बिल रोक दिया, तो उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी चीजें गायब हो गई उसका उपाध्यक्ष महोदय, सीता हरण हो गया था, इस राज्य के अन्दर सीता हरण होगया। यह घटना इस प्रकार हुई। जीरो माइल से 13 माइल तक की सड़क हनुमानगढ़ डिविजन से बदल कर गंगानगर पहुंच गई जहां कुलदीपसिंह को पेमेन्ट कराने के लिये बिना किसी काम के दस्तखत कराने को तैयार रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा काण्ड इसमें 18 लाख रुपया इन्वोल्व है चार साल से

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

को आये हुये थे और जैसे ही कुलदीपसिंह ने कहा सांधी का ट्रान्सफर रातोरात हुआ। रायसिंहनगर का 34 किलोमीटर का टेन्डर, वह भी बहुत ऊंचा टेन्डर दूसरों के मुकाबले कुलदीपसिंह और उनके तीन भाई थे उनको दे दिया गया और 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर जबकि कोई कार्य नहीं हुआ था कम्प्लेक्सन के तीन लाख का बिल कर दिया जबकि कोई कम्प्लेक्सन नहीं है उसका पेमेन्ट करा दिया। मैं कहता हूं आप उसके लिये एन्क्वायरी बिठा दें इस सदन को मैं चेलेंज के साथ कहता हूं कि कुलदीपसिंह को बिना किसी काम के पेमेन्ट करा दिया गया और उपाध्यक्ष महोदय, उस समय के एक्स. ई. एन. श्री गुलाबसिंह भण्डारी ने उसे देने से इन्कार कर दिया। कुलदीपसिंह रातों रात वहां पहुंचा और गुलाबसिंह एक्स. इ. एन. को छुट्टी पर चला दिया। छुट्टी पर जाने के बाद जो ऐडीशनल एक्स. ई. एन. है श्री कमल कान्त उसको उसका चार्ज दिलवाया और कमल कान्त के चार्ज लेते ही उसको पेमेंट करा दिया गया और जब भण्डारी आये तो उन्होंने कहा यह सारा पेमेन्ट गलत है–सारी रिकवरी कराई जाय तो उपाध्यक्ष महोदय, श्री भन्डारी का रातोरात ट्रान्सफर कर दिया। जब चार्ज दिया तो सारा नोट उस पर दे दिया कि यह सारा काम ऐसा है जो बिलकुल नहीं हुआ है और इसको पेमेन्ट नहीं होना चाहिये। भन्डारीजी चार्ज देकर चले गये और जब वे वहां से चार्ज देकर जाने लगे तो भन्डारी की छाती पर पिस्तौल रख दी और जो नोट वे देकर गये थे उनके ही हाथ से कटवा दिया गया। यह फाइल मंगवाई जाय उपाध्यक्ष महोदय, और उसे देखा जाय कि जिसका नोट था उसी के हाथ से उसको कटवाया गया है। मेरा निवेदन है कि उस फाइल को सदन में अवश्य मंगाकर देखी जाय ताकि घोटाले का मालूम पड़ जाय। इसमें 9 लाख का गबन हुआ है। एक उपाध्यक्ष महोदय, पी. डबल्यू. डी. का भट्टा लगना था किन्तु वह भट्टा नहीं लगा। एक बोर्ड लगा दिया गया और उसमें से एक करोड़ ईंटें निकली और केवल 15 दिन में निकल गई। मैं चेलेंज करता हूं 50 साल तक भी अगर भट्टा चलता रहे तो एक करोड़ ईंटें नहीं निकाल सकता हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, निकली और पी. डबल्यू. डी. का भट्टा। 50 लाख ईंटें तो मारकन्डेय ने रायसिंहनगर से विजयनगर रोड़ पर लगवा दी और चार लाख का पेमन्ट कर दिया। अब मौके पर जाकर देखें उपाध्यक्ष महोदय, तो एक ईंट भी कहीं नहीं पड़ी है। आप उसका एग्जामिन करवा लीजिये–एक भी ईंट आपको उस रोड़ पर नहीं मिलेगी और फिर उसी भट्टे से 50 लाख ईंट रायसिंहनगर–विजयनगर रोड पर लगी बता दी और पांच लाख का पेमेन्ट वहीं से करवाने का किया गया और जब वहीं सांधी पहुंचे तो उसके पेमेन्ट को स्टॉप कर दिया और इसको चैलेन्ज किया गया और जब वहां पर ईंटे गिन रहे थे तो एक इन्जिनियर आर.एस.सी. का आगया वह कहने लगा कि हमारा भट्टा है दो चौकीदार पी. डबल्यू. डी. के भी आगये और कहने लगा भट्टा हमारा है, आर.एस.सी. वाले कहते हैं,यह भट्टा हमारा है। दो चौकीदार गंग केनाल के भी आ गये वे भी कहे भट्टा हमारा है तो मेरा निवेदन हैं राज्य सरकार से वह उस जगह को जाकर देखें जिसमें करोड़ों रुपयों की और लाखों रुपयों की ईंटे निकल आती हैं उसको तो पकड़ी देनी चाहिये उपाध्यक्ष महोदय

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अब उपाध्यक्ष महोदय, यह 9 लाख का ठेका करनपुर में नरसिंहपुर रोड जो जीरो माइल से पांच किलो मीटर का है उसमें 1.03 लाख का एडवान्स पेमेन्ट कर दिया और आप उस सड़क का मुलाहिजा फरमा लीजिये एक छटांक गिट्टी कहीं पर नहीं पड़ी है। अपने यहां एक कहावत है घघरी से दुल्हान महंगी हो गई। एक पुल बन रहा है जो रायसिंहनगर से सूरतगढ़ चली जाती है। इसका डाईवर्जन बनाने से पहले कॉस्ट 2500 रुपया थी जो 700 फीट गहरी और 25 फीट चौड़ी थी। इस पर पुल बनाने की जो पहले का एस्टीमेट था वह 80 हजार का था बाद में यही एस्टीमेट दो लाख का होगया। यह जो 25 हजार की बात थी उसमें कुलदीपसिंह को एक लाख तीस हजार का एडवांस पेमेन्ट हो गया। घघरी की कीमत दुल्हन से कई ज्यादा गुनी बढ़ गई। पुल की ओरिजिनल कीमत से डाईवर्शन की कीमत ज्यादा हो गई। इसमें भारी मात्रा में गड़बड़ियां हैं, भारी मात्रा में घोटाले हैं। यह जो कुल ऐडवांसेज हैं वह 30 लाख के ऐडवांसेज है। मैं सदन का बहुत ज्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा लेकिन मैं चैलेंज करता हूं एक करोड़ पचास लाख के ऐडवांसेज बिना किसी काम के इस कुलदीपसिंह को कर दिये गये हैं। क्यों कर दिये गये हैं क्योंकि यह भूतपूर्व राज्य मन्त्रि श्री मनफूलसिंह का साझेदार है। अगर मारकन्डेय नें ईंटे ले लीं तो जैन ने लेने से इन्कार कर दिया और इंकार कर दिया तो रातोंरात उसका ट्रांसफर कर दिया।

अब एक दर्दभरी कहानी अन्त में कहूंगा वह है ई. एस. आई. हॉस्पीटल के बारे में। यह हॉस्पीटल केवल एक या दो किलोमीटर दूरी पर माननीय मुख्य मंत्री जी के निवास से निर्मित हुआ है और अजमेर रोड पर स्थित हैं और प्रायः सभी मंत्री इसी ई. एस. आई. हॉस्पीटल के पास से गुजरते हैं। 38 लाख रुपया की लागत से इसका निर्माण हुआ, जिसमें दीवारों पर सारे क्रेक्स आये हुए हैं, चूना गिर रहा है और हॉस्पीटल की छत पर डामर डाला गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जनवरी, 1970 में इस हास्पीटल को पूरा हो जाना चाहिये था लेकिन आज तक यह पूरा नहीं हुआ। पी. डब्लू. डी. ने 'एल' फार्म भर दिया लेकिन उसमें बिजली नहीं आई, पानी के लिए बोरिंग नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या है कि स्टाफ बुला लिया गया है, 7-8 महीने हो गए है, नर्सेस आ चुकी है, कम्पाउन्डर्स आ चुके हैं, डॉक्टर आ चुके हैं और उनको बैठे-ठाली का पैमेन्ट हो रहा है और 90 हजार रुपये महीने के हिसाब से 1 लाख का पैमेंट उनको बैठे-ठाली हो गया है। फिर ई. एस. आई. हॉस्पीटल की जमीन कुम्भाराम जो ने एक दफा एक सज्जन को अंगूरों का फार्म बनाने के लिए दे दी थी, यह जमीन ई. एस. आई. की नहीं थी। झगड़ा हुआ और बातचीत हुई, समझौता हुआ। उन सज्जन को 9 हजार रुपया ई. एस. आई. की कारपोरेशन की तरफ से दे दिया गया— 5 हजार रुपया तो जमीन का कास्ट और 4 हजार रुपया लेवलिंग का और इसके बाद कारपोरेशन ने 80 हजार रुपया उसकी लेवलिंग पर खर्च किया, उपाध्यक्ष महोदय, यह 80 हजार रुपया किस लेवलिंग पर खर्च हुआ? यह मान लीजिए कि जमीन का टोटल लेवलिंग हो चुका है और 38 लाख रुपये में मैं चैलेन्ज के साथ कहूंगा कि

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

6 लाख रुपये का घोटाला है। यह ई. एम. आई. हॉस्पीटल 113 बैड्स का है और अजमेर रोड पर स्थित है। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए। आज रीजनल कमेटी ने इस सारे पेमेंट की जिम्मेदारी से बिलकुल इन्कार कर दिया और कह दिया कि सारे पेमेंट की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान गंग केनाल, राजस्थान कैनाल, भाखरा की मण्डियों की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज भाखरा की मण्डियों की जो स्थिति है वह बड़ी सोचनीय है। 20 मण्डियां भाखरा के लिए प्लान की गयी और इनमें 1 मण्डी 'ए' क्लास का हनुमानगढ़ जंक्शन को, 7 मण्डियां 'बी' क्लास की और 13 मण्डियां 'सी' क्लास की थीं। दूसरे प्लान में 50 लाख का बजट में इसके लिए प्रावधान हुआ था लेकिन 26 लाख रुपया लगा। आप इन सारी मण्डियों में जाकर देख लें, भाखरा की मण्डियों में जाकर देख लें, गंग कैनाल की मण्डियों में जाकर देख लें, पीली बंगा में जाकर देख लें, सूरतगढ़ में देख लें, हनुमानगढ़ जंक्शन में देख लें, विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है, कोई प्लाट नहीं बिके हैं और किसी किस्म का बिजनैस स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई मार्केट क्रियेट नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, जब गंगनहर बनी थी सन् 1928 में इसका निर्माण हुआ और दो साल और कुछ महीनों में 3 करोड़ 25 लाख की लागत से बन गयी थी और 3 करोड़ रुपये की इर्रीगेशन 1928 में शुरू हो गया थी और उसके बाद गंगनहर की इकानॉमी सैल्फ जनरेटिंग होती चली गयी। इसमें बीकानेर राज्य ने थोड़ा सा लाख रुपया केवल उधार के शकल में लिया था। मण्डियों के प्लाट्स बेचे थे, इन्डस्ट्रियल एरिया बेचा था और अकेले रामनगर में 90 लाख रुपये के प्लाट्स बेचे थे और मण्डियों की आबादी से 3½ करोड़ का फासप्लिने क्रियेट करके गंगनहर का निर्माण 1928 में किया और आज मशीनरी है, इतनी साइन्स एडवान्स हो चुकी है लेकिन आज हमारी मण्डियों की क्या हालत है। बीसियों मण्डियों में देख लें कहीं एक प्लाट की बिक्री नहीं हुई है, कहीं कोई मार्केट क्रियेट नहीं हुआ है। ऐसी शर्तें रखी हैं कि कोई प्लाट नहीं खरीद सकता। इस तरह की कीमत रखी है ओपिन आॅक्शन की कि कोई मिडिल क्लास या कोई हरिजन की ताकत नहीं है कि प्लाट खरीद लें। 100 ईयर्स लीज पर देते हैं और किया क्या है? इन मण्डियों में छोटे छोटे रेडी वालों को बेदखल किया जाता है, सादुलशहर में 100 दुकानदार बैठे थे और सबके सबको आपने इजेक्ट कर दिया और माल गोदाम में कूड़े में डाल दिया। पीलीबंगा में 200 लोगों को इजेक्ट कर दिया है और सारे के सारों को कूड़े करकट में डाल दिया। आज उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं। यही स्थिति तमाम मण्डियों की आपने क्रियेट कर दी है। अगर थोड़ा बहुत विकास सूरतगढ़ की मंडी में नजर आता है या हनुमानगढ़ जंक्शन की मण्डी में नजर आता है तो वह म्युनिसिपेलिटी द्वारा किये गये काम हैं और उनमें म्युनिसिपेलिटी का पैसा लगा है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

इतना कहकर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरदयाल सिंह संधु।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्तावों द्वारा पी. डब्लू. डी. के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं जिस गांव से आया हूं उस गांव के बाहर आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। 1957 में वहां पर एक सड़क मन्जूर की गयी थी और उसके टेन्डर्स भी मन्जूर किये गये और उसकी एक्वीजीशन की कार्यवाही 15-4-62 को कम्प्लीट हो चुकी थी और उसमें नोटिस उनको सेक्शन 9 के तहत मुआवजा देने के लिए और अवार्ड देने के लिए हुआ। जो अवार्ड देना था वह आज तक नहीं बनाया गया जिसकी प्रासीडिंग्स कम्प्लीट हो चुकी है लेकिन उसके बाद उसका इन्तजार किया जाता रहा कि कोई उसमें बहाना मिले तो 1962 में हाईकोर्ट में हुआ जो कि 11-3-66 को फैसला हो गया और आज तक उस हिस्से को नहीं लिया गया, यह कहकर कि कुछ कमियां हैं फण्ड्स की। इसके अतिरिक्त अभी थोड़ी सी बातें आई हैं एक पी. डब्लू. डी. विभाग के ठेकेदार की। इस सूरतगढ़ सड़क की बात चली। सूरतगढ़-रोपड़ सड़क की बात चली। अभी कहा गया कि गंगानगर जिले में कन्स्ट्रक्शन आफ रोड किसी भी सड़क का नहीं हुआ, कोई भी सड़क नहीं है कि जहां रोलर चलाया गया हो और यहां पर रोलर चलाया गया और 5 लाख रुपये उस ठेकेदार को दिये गए जब कि उस ठेकेदार के पास कोई अपना रोलर नहीं है और न ही उसने कहीं पर से किराये पर लिया है। अगर वह रोड पर चलाने के लिए बाहर से किराए पर लाता तो कुदरतन वह रकम डिडक्ट होती जब कि उसको पेमेन्ट किया जाता उसमें से। इसका मतलब यह है कि रोलर उसने कहीं से नहीं लिया और क्योंकि बहुत सी बातें इसके बारे में बता दी गई हैं इसका पहले अलाइनमेंट कर दिया गया और अलाइनमेंट करने का 1 लाख 25 हजार रुपया खर्च हुआ। कहीं पर निशान नहीं लगाये गये, कागजों में अलाइनमेन्ट किया गया और 1 लाख 25 हजार रुपये दे दिये गये और फिर सड़क की नयी अलाइनमेन्ट कर दी गयी और उस सड़क के बारे में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने बता दिया है। उसको 16 लाख का पेमेंट हो चुकी है और उसमें से बहुत सा फर्जी है।

तो मैं इसके सम्बन्ध में इतना ही कहूंगा और इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि चुनावों के दिनों में एक साथ नाराज हो गया और उसको खुश करने के लिए उसके घर तक एक सड़क बनानी पड़ी। जो पदमपुर करणपुर रोड़ में से 13 वें गांव के नाम से मंजूर की गई। सड़क की मंजूरी होने से दो दिन पहले 27 हजार का ठेका इस कुलदीपसिंह एण्ड कम्पनी को दिया गया। सड़क उसको दे दी और 27 हजार का ठेका दे दिया और उस सड़क पर उसने थोड़ी बहुत मिट्टी डाल दी, साथी मान गया, उसको ऐतबार हो गया कि सड़क बन जाएगी। लेकिन अब उस सड़क का काम बन्द पड़ा हुआ है और इसलिए काम बन्द पड़ा हुआ है जो मिट्टी डाली गई है वह बह जाय और सत्ताईस हजार की रकम का दुबारा पेमेंट हो। ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप इन पर गौर करें।

एक सड़क पदमपुर से कोटाभोर को जाती है। इस सड़क पर पहले 0 पोइन्ट से 6 किलोमीटर का ठेका दिया गया है जो

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

सवा छः परसेंट से बिलो है और क्योंकि इलेक्शन के दिनों में ठेकेदार ने गवर्नमेंट का साथ दिया था इसलिए वहां काम नहीं हुआ काम अधूरा पड़ा हुआ है लेकिन फिर 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक का ठेका दे दिया गया है और 45 परसेंट से कम पर दिया गया है और कहा यह जाता है कि रेट्स बढ़ गई है। वह ठेका भी आज से कुछ दिनों पहले दिया गया था, अभी कुछ महीनों पह ही दिया गया था लेकिन कहते हैं कि रेट बढ़ गई। उसका काम भी अभी नहीं हुआ है।

इसी तरह से करणपुर-घासीपुर रोड है। उसका ठेका भी पहले $7\frac{1}{2}$ परसेंट बिलो था, अब जो पांच किलोमीटर का उसका ठेका मंजूर हुआ है, उसमें एक बड़ी मजेदार बात है कि गंगानगर में कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसमें झावा साढ़े चार इंच से ज्यादा मंजूर किया गया हो। इस ठेकेदार को जो झांपा मंजूर किया गया है वह छः इंच का है लेकिन छः इंच का झांपा किसी जगह पर नहीं है। कहीं पर भी तीन इंच से ज्यादा नहीं है लेकिन उसको पेमेंट हो रहा है छः इंच का। वहां पर कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उसका पेमेंट रोक सके। उसको जो पेमेंट हो रही है वह छः इंच की रेट से हो रही है। तो इस तरह से इस ठेकेदार से कई रकमें हैं जो उससे वसूल नहीं की जा रही हैं। 1966 में इसने एक सड़क बनाई थी जिसको गंगानगर बीकानेर डिफेंस रोड़ कहते हैं और उसमें इसके जिम्मे 10,685.27 पैसे नहर के पानी के बाकी थे, वे आज तक नहीं दिए गए हैं। आज तक वसूल करने की पी. डब्ल्यू. डी. की हिम्मत नहीं है। अगर कोई इससे रकम मांगेगा तो उसका ट्रांसफर आर्डर जेब में तैयार है। एक छोटा सा ओवरसियर था। वह ओवरसियर था इमेजा कैनाल में, उसका नाम था रामलाल। उसको यह कहा गया कि मेरी सोलह हजार की रकम को तीन हजार रुपये कर दो। उन्होंने इन्कार किया तो उसको आर्डर हो गए कि गंगानगर जिले में वह नहीं रह सकता। इस बारे में मैंने मुख्य मन्त्रीजी को भी लिख कर दिया है लेकिन आजतक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरह से वहां पर एक एस. ई. है जो चार पांच महीने पहले ही आए थे। उन्होंने इसकी पेमेंट रोक ली तो उनको सरे बाजार यह बात कही गई कि आपको सात दिन के अन्दर 2 तब्दील करवा दिया जाएगा। ठीक 48 घन्टे में उसका तबादला हो गया। अब इनका जितना भी काम है, चाहे किसी डिवीजन में हो, चाहे सूरतगढ़ डिवीजन में हो, चाहे हनुमानगढ़ डिवीजन में हो, उसकी देखरेख करने के लिए गंगानगर डिवीजन को ही मुकर्रर किया जाता है। गंगानगर के एक दलजीतसिंह संधु से इनका सम्बन्ध है। वहां एक व्यक्ति होश्यारसिंह है, उनके साथ एक असिस्टेंट इन्जीनियर लगाया जाता है और एक दो ओवरसियर रखे जाते हैं। उसमें मिस्टर मलिक हैं, मिस्टर यादव हैं। इन्हीं आदमियों को लगाया जाता है, वही वहां जाकर 70-75 मील की दूरी पर, दूसरे इलाके में जाकर इसके काम को देखभाल करते हैं। यह है इसके काम का तरीका। कोई व्यक्ति इनका पेमेंट रोकने की कोशिश करते हैं तो कोई फौरन तब्दील कर दिया जाता है। एक मिस्टर जैन हैं वह आर. सी. पी. में हैं उसने इनका 75 हजार का पेमेंट रोकने

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

की कोशिश की तो उसका ट्रान्सफर हो गया। अभी भी इसी तरह से एक दो ट्रान्सफर होने वाले है। एक गुरुदेवसिंह हैं। एक सड़क पर ईंटें डाल दी गई, बहुतसी ईंटें मिल गईं, गंगानगर आर. सी. पी., पी. डब्ल्यू. डी. और इर्रीगेशन की। सब मिलाकर इनको दे दी गई। उसने अपने विभाग को इसके बारे में रिपोर्ट की। एस. ई. साहब ने उसको कहा कि तुम इसको वापिस लो नहीं तो मैं आपको सस्पेंड करता हूं। वह सस्पेंड ऑर्डर उनकी जेब में है और उसका सस्पेंशन ऑर्डर लेकर एस. ई. साहब जयपुर भी पहुंच चुके है और जल्दी ही उसको सस्पेंड किया जाएगा। वही व्यक्ति गंगाननर में रह सकेगा। चाहे आर. सी. पी. का मामला हो, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. का हो, चाहे गंग कैनाल का मामला हो- जो इस ठेकेदार को खुश रखेगा वही गंगानगर में रह सकेगा।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि चार्जेज लगाने में तो बड़े 2 चार्ज लगाए है मेरे साथियों ने बड़े 2 चार्ज लगाए हैं, लेकिन मैं बात और अर्ज करता हूं। एक शगल होता है। बैठे 2 कहते हैं कि आज तो पांच दस हजार कमा लेना चाहिए। तो बैठे 2 ही विचार कर लिया कि किस तरह से कमाना है। फिर एक दो ठेके दे दिए। सड़क पर से डब्बे हटाने का ठेका दे दिया। पी. डब्ल्यू. डी. के बिरादर हैं उनको सड़क पर से डब्बे हटाने का ठेका दे दिया। एक हजार का ठेका पदमपुर सड़क का ठेका दिया, एक हजार का ठेका गंगानगर सड़क का दे दिया और इस तरह से पच्चीस तीस हजार का पेमेंट हो जाता है। एक उनके लिए रोजमर्रा का काम है। मैं एक और उदाहरण दूंगा। गंगानगर से मोहनपुरा को एक सड़क जाती है उस पर आज तक डब्बा नहीं हुआ लेकिन उसका भी एक हजार का ठेका दिया गया और पेमेंट कर दिया गया। दूसरे क्षेत्रों में भी डब्बे हटाए जाते हैं। एक दिलीपसिंह हैं और उसके भाइयों को ठेके दिए जाते है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इस मामले पर जरा अच्छी तरह से गौर करें कि क्या हालत पी. डब्ल्यू. डी. की गंगानगर में हो रही है।

आप से मैं यह भी अर्ज करूंगा कि आप मिस्टर कल्ला जो वहां पर हैं उनके टेलीफोन के बिलों को देख लें। एक जनवरी से इलेक्शन के टाइम में गंगानगर में कितने टेलीफोन किए गए है। इन टेलीफोनों का रिकार्ड मंगा लीजिए। क्या इतनी जरूरत थी कि एक एक दिन में आठ आठ, दस दस टेलीफोन होते थे और कहा जाता था कि ठेकेदार को जल्दी से जल्दी पेमेंट करो। आप रिकार्ड को मंगा लीजिए। मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि ठेकेदार को जो इतना ज्यादा पेमेंट होता है तो इसके काले कागज भी हैं और वह रुपया काले कागजों में दर्ज है। किस तरह से दूसरे डिपार्टमेंटों के भी काले कागज हैं, अगर कोई उनकी जांच करने के लिए तैयार हो तो मैं इन काले कागजों की हिस्ट्री भी बता सकता हूं। अभी मैं इस बात को ज्यादा ओपन नहीं करता क्योंकि शायद मैं अपने दूसरे काम में इससे सफल नहीं हो सकूं। गंगानगर जिले में जो पी० डब्ल्यू० डी० को बोगी है, वह अच्छी नहीं है। इसको वहां से ट्रान्सफर करो। दो-तीन-चार ही अच्छे हैं। बाकी को वहां से हटाओ और अच्छे अच्छे आदमियों को वहां पर भेजो।

(श्री गुरदयालसिंह संधु,)

गुलाबसिंह जैसे आदमियों को वहां पर भेजो। मैं आपको यह कहूंगा कि यदि आप निष्पक्षता से काम करना चाहते हो, तो वहां के सारे रिकार्ड को सीज कर लीजिये और फिर उसकी जांच करिये और आपको पता चल जायेगा कि वहां पर किस तरह से कार्य चल रहा है। एक आदमी की पांच साल पहले जो हालत थी, उनके यहां पर दोनों वक्त खाने को रोटी का प्रबन्ध नहीं था। अब पांच साल के अन्दर ही वह व्यक्ति तीन तीन सिनेमाओं का मालिक हो गया है। उसके बापके पास एक मुरब्बा जमीन नहीं था। लकड़ी बेचने की मामूली दुकान थी वह आज लाखों-करोड़ों से खेल रहा है। मुझे यहीं निवेदन करना है। मैं आपसे फिर यही अर्ज करूंगा कि आप इसकी निष्पक्षता से जांच करवा देंगे तो इससे आपकी स्थिति अच्छी हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्र बाला।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50, सार्वजनिक निर्माण कार्य की धनराशि पर मेरा कटौती का प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्यों हमें यहां पर ये कटौती के प्रस्ताव देने पड़ते हैं। यह माना कि यह परम्परा है। सदन के अन्दर इस विषय पर कुछ बोल सकें किन्तु साथ में सत्य है कि जो धनराशि जिन कार्यों पर खर्च की जाती है, वह नहीं होती है। सार्वजनिक निर्माण कार्य एक ऐसा कार्य है जिसका जनता से सीधा सम्पर्क रहता है। आज कोटा जिले की सड़कों की दयनीय दशा है, उनके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि कृपा करके इसका अवलोकन करें। वे यदि इनका अवलोकन करेंगे तो पता लगेगा कि यहां पर सड़कें भी थीं या नहीं थी। नियम यह है कि टाररोड़, या दूसरी जो सड़कें हैं उनके बनने के किसी निश्चित अवधि साल में उनकी मरम्मत हो जानी चाहिये। परन्तु इस नियम के अन्तर्गत कोटा जिले की सड़कों की कभी मरम्मत भी हुई है या नहीं, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मैंने वहां पर इस विभाग के कर्मचारियों से पूछा कि ये सड़कें कब कब बनी थी। उनका कहना था कि यह पता नहीं लग पा रहा है कि ये सड़कें थीं या नहीं थी। तो यह स्थिति कोटा जिले के ग्राम सड़कों के बारे में हैं। यदि यह कहूं कि यही स्थिति कोटा डिवीजन की सड़कों के बारे में है तो कोई गलत नहीं होगा। कोटा जिले में, कोटा के तहसील हैड क्वार्टर, एस० डी० ओ० हैड क्वार्टर तक आने जाने का रास्ता सुलभ नहीं है। जो आम रास्ते हैं, उन पर किसानों को आने जाने की पूरी सुविधा नहीं है। कोटा से इटावा रोड़ ले लीजिये, कोटा से रामगंज मण्डी रोड़ को ले लीजिये, जहां पर एस० डी० ओ० हैड क्वार्टर है, कोटा से मांगरोल, यह भी तहसील हैड क्वार्टर है, कोटा से रंगपुर रोड़, कोटा से केथून रोड यहां मसूरिया की साड़ियां बनती हैं जो हिन्दुस्तान भर में मशहूर है, कोटा से बून्दी रोड़ को ले लीजिये-यही नहीं कोटा के आस पास की सड़कों को ले लीजिये, यही हालत सारे हाड़ौती क्षेत्र की सड़कों की है, किन्तु मैं यहां पर केवल कोटा जिले के बारे में ही कहना चाहूंगी। तो यह हालत है हमारे जिले की सड़कों

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

की। किसी प्रकार भी आवागमन की सुविधा नहीं है। मैं आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि हमारे जिले की सड़कों की देखभाल के लिये इस विभाग के राज्य कर्मचारियों पर आप कितना खर्चा करते हैं। लगभग मेरा अन्दाज है कि 10/12 लाख इस्टेब्लिशमेन्ट पर आप खर्चा करते हैं। यह खर्चा आप किस लिये कर रहे हैं? जब वहां की सड़कों की मरम्मत नहीं होती है तो इनकी क्या जरूरत है। आप इसको बंद क्यों नहीं कर देते हैं। इसको तोड़ देना चाहिये। जो मरम्मत का काम था, जहां पर तीन वर्ष के अन्दर, दो वर्ष के अन्दर, चार वर्ष के अन्दर सड़क की मरम्मत होनी चाहिये थी, वह तो की नहीं गई है। फिर कैसे यह कार्य किया जा रहा है, यह बताया जाये। मैं यह भी निवेदन करूंगी जब आप इसका जवाब दें तो कम से कम इतना बताने का कष्ट करें कि कोटा जिले में इन सड़कों की मरम्मत की रकम कहां पर गई? सीलिंग का दुष्प्रभाव पड़े तो कोटा डिवीजन पर पड़ता है, सड़कों की कटौती हो तो कोटा जिले पर पड़ती है, इर्रीगेशन का दुष्प्रभाव कोटा जिले पर पड़ता है। यह सब कोटा जिले पर ही क्यों हो रहा है? यह समझ लीजिये कि वहां का प्रतिनिधित्व कमजोर है। परन्तु क्या सरकार भी कमजोर है और वह भी इसकी तरफ नहीं देखती है। सरकार इस तरफ देखती तो मेरा निश्चित मत है कि जो हालत वहां पर आज सड़कों की हो रही है, वह नहीं होती। हमें इस सरकार पर विश्वास है, उससे आशा है-चाहे कहां का प्रतिनिधित्व कमजोर हो। इटावा, आज वहां पर बढ़िया गेहूं पैदा होता है, बारां मण्डी, जहां पर अच्छा चावल पैदा होता है, वहां पर सड़कों की हालत खराब है। वहां का किसान अपने धान की अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिये मण्डी में नहीं आ सकता है। इसलिये नहीं आ सकता है कि वहां के रास्ते खराब हैं। बैलगाड़ी उन रास्तों पर नहीं चल सकती है। आप यह बात ट्रक वालों से पूछें, बस वालों से पूछें। इसके अलावा जिन पर बस रूट सैक्शन्ड है उन रूटस् पर वे बसें नहीं चलती हैं। इसके बारे में भी मैं पूछना चाहूंगी। कोटा जिले में ट्रैफिक के जो साधन है, आने जाने के जो आम रास्ते हैं, उन आज चलना दुर्भर हो गया है और इस कारण जिन रूटों का परमिट दिया गया है वहां पर बसे नहीं चल रही हैं और दूसरे रूट्स पर वे चल रही हैं। आपके विभाग के जो एस. ई. साहब है वे टूर किया करते हैं। मैं पूछती हूं कि टूर किस लिये करते हैं? जिन सड़कों के बारे में उनसे पूछो वे कहते हैं हमारे पास में पैसा नहीं है। सरकार से आप दिला दो तो काम हो जायेगा। फिर मैं कहती हूं कि वे किस मर्ज की दवा हैं? मुझे यह प्रश्न पूछना चाहिये था कि कोटा जिले के अन्दर पिछले दस–बारह साल के अन्दर सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने कितना टी० ए०, डी० ए० लिया है। जब वहां पर काम नहीं होता था तो वहां वे किसलिए दौरा करते हैं। यह तो कोई ईमानदारी की बात नहीं है। जब तक हमारे देश के राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण नहीं होगा, देश की समृद्धि नहीं होगी। मैं नजदीक की बात करना चाहती हूं। किसी भी आदमी को ले लीजिए चाहे वह ओवरसीयर हो, चाहे वह इन्जीनियर हो,

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

उनकी स्थिति आज क्या है और जब वे आये थे क्या थी ? मन्त्री महोदय, मैं आपको निमन्त्रण देती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये कि आप आइये और देखिये कि आज कोटा जिले के अन्दर क्या हो रहा है, आप के विभाग के द्वारा क्या कार्य हो रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारे मन्त्री महोदय इस विभाग को अच्छी तरह से सम्भाल सकेंगे। मेरा तो निवेदन है कि जो लीकेज हो रहा है उसको पकड़ने की आप कोशिश करें। मुश्किल तो यह है कि आम मनी का लीकेज हो रहा है, पैसे का लीकेज हो रहा है। यह रुक जाये तो हमारे देश का जो सारा काम है वह पूरा हो जाये। बजट में जो धनराशि रखी जाती है,उसका निश्चित-रूप से हम अच्छा बंटवारा चाहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र को, प्रत्येक जिले को पैसा मिले परन्तु यह भी अच्छी चीज नहीं है कि जिस इलाके की हालत ज्यादा खराब हो, वहां पर ज्यादा धन न दिया जाये। उसका विकास, तरक्की भी होनी चाहिये। उसके बाद उसका बंटवारा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, 6-7 साल पहले जो इन्जीनियर आया था वह साइकिल पर चलता था। उसके मकान की हालत देखिये और आज उसकी हालत देखते हैं तो आंखें चकरा जाती हैं। इतना बड़ा मकान, इतना बढ़िया फर्निशिंग और यह सामान आया कहां से ? आप क्यों नहीं इस तरफ ध्यान देते हैं ? आपको देखना चाहिये कि आपके अमुक प्रकार के कर्मचारी की स्थिति क्या है ? कब से वह नौकरी करता है। मैं यहां पर नाम तो नहीं लेना चाहती हूं परन्तु आम लोगों की धारणा है कि हमारे इन्जीनियर्स अपने अपने घरों में बैठे रहते हैं और बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं। जब इनके पास में काम नहीं है तो आप इनको हटाते क्यों नहीं हैं ? आज कोटा की सड़कें अच्छी नहीं है। आज कोटा का नाम एक अजीब स्थिति में आ गया है। वहां पर बड़े बड़े कल कारखाने लग गये हैं। इन्डस्ट्रीज बन गई हैं, शहर के लोग इस जगह पर आकर लाभ उठा कर मौज करते हैं। वे अपना जीवन आराम से बसर कर रहे हैं परन्तु जो कोटा के निवासी हैं उनको आप देखिये वे किसी न किसी प्रकार की एक विशेष बुरी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, वे यह महसूस करते हैं कि उनको आजादी के जीवन की राहत नहीं मिल पाई है। हम यह मानते हैं कि वहां पर बड़ी मिलें जरूर लगीं, शहर के कुछ भागों में सड़कें भी ठीक हैं लेकिन जो गांवों की सड़कें हैं, उनकी स्थिति को देखिये। कोटा शहर की बात करते हैं तो कुछ सड़कें ठीक हैं। वहां पर यू० आइ० टी० की स्थापना पिछले दो साल हुए हुई है। कुछ उसके द्वारा काम हुआ है, सड़कों का कुछ सुधार हुआ है, परन्तु उसको और म्युनिसिपैलिटी का जो एरिया है उसको छोड़ कर आगे जाइये, वहां पर सड़कों की ऐसी हालत है कि एक इन्सान उस पर नहीं चल सकता है मोटरगाड़ी नहीं चल सकती है, बैलगाड़ी उस रास्ते पर नहीं चल सकती है। तो यह हालत है हमारे जिले के सड़कों की उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस सैशन के बाद, या इसके बीच में, जब भी उनको मौका मिल जाये, एक दफा के लिए वे जरूर कोटा क्षेत्र का दौरा करें। वहां का दौरा करने

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

पर मैं समझती हूं कि उनके दिल में जरूर ही कुछ दया आ जायेगी, रहम आ जायेगा और वे कुछ कहीं और से निकाल कर कोटा जिले की सड़कों की मरम्मत के लिए जरूर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले की सड़कों के बारे में जो मैंने निवेदन किया उसका कारण एक यह भी है कि कोटा में चम्बल से नहर निकलने से वहां पर उससे इरिगेशन होता है और इरिगेशन होने से किसानों की माली हालत कुछ ठीक हुई है। किसान के लिए को आपरेटिव बैंक जगह जगह खुले हुए हैं, कोआपरेटिव सोसाइटीज जगह जगह खुली हुई हैं, मार्केटिंग सोसाइटीज जगह जगह खुली हुई हैं और ट्रैक्टर से उसको अपना माल वहां पर लाना है तो उसके लिए एक किसान की आम आवाज निश्चित रूप से यह है कि सड़कें ठीक होनी चाहिए। अगर वहां पर सड़कें ठीक नहीं होंगीं तो मण्डियों पर प्रभाव पड़ेगा, किसान पर प्रभाव पड़ेगा। पी० डबल्यू० डी० एक मुख्य विभाग है जिसका शहरों से ही वास्ता नहीं होता है, किसानों से भी उतना ही सम्बन्ध रखता है जितना कि शहरों से सम्बन्ध रखता है।

आपकी घण्टी बज रही है इसलिए मैं सोचती हूं कि मुझे बैठ जाना चाहिए। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहती हूं कि मन्त्री महोदय केवल सुन कर ही न रह जायं। वे निश्चित् रूप से कोटे का दौरा करें। मैं उनको निमन्त्रण देती हूं। अगर वहां की सड़कों की हालत सुधर जायगी तो भगवान को आपके नाम दुआ देंगे और आपकी जय जय कार मनायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा कि कोटा के क्षेत्र की सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, किन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि राजस्थान में कोटा की ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों की सड़कों की जो दुर्दशा है वह यह है कि लोग बाग यह कहने लग गये हैं इसके बजाय तो सड़कें यदि नहीं बनती तो ज्यादा अच्छा रहता। आज स्थिति यह है कि जहां पर डामर बिछ जाती है वह सड़क तो ठीक रहती है, लेकिन जहां पर केवल रोड़ी और काम्क्रीट बिछा दी जाती है तो उसके बाद में कोई भी उस सड़क का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कोई भी बैलगाड़ी वाला जायेगा तो सड़क के नीचे से जायेगा और आदमी पैदल चलेगा तो सड़क के नीचे हो कर जायेगा। जब तक डामर नहीं बिछती है तब तक उस सड़क से एक प्रकार से रास्ता रुक जाता है। आज स्थिति यह है कि कोई भी सड़क की देख भाल नहीं करता है। जो दौसा से गंगापुर और दौसा से सवाई माधोपुर और जयपुर से कोटा जो सड़क जाती है उनकी क्या हालत है। यह तो मुख्य सड़कें है। दौसा से लालसोट और दौसा से गंगापुर और करोली ये मुख्य सड़कें है, जिन पर कि आवागमन बहुत कुछ होता है, उन पर जब कभी माननीय मन्त्री महोदय कई दफा दौरा करते हैं तो होता यया है कि जब माननीय मन्त्री महोदय पधारते हैं तो सड़कों का सुधार हो जाता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है वह

(श्री मीठालाल)

किसी रास्ते पर माननीय मन्त्री महोदय अचानक जा कर देखें बिना रचना के। आज स्थिति यह है कि सड़कों पर इतने गड्ढे पड़े हुए हैं कि जिससे अनजाना चालक हो तो निश्चित रूप से दुर्घटना हुए बिना नहीं रहेगी। दौसा से गंगापुर सड़क पर कई जगहों पर एक एक फुट के गहरे खड्डे हैं, और सड़क के दोनों तरफ इस ढंग के गड्ढे पड़े हुए हैं कि अगर चालक बचाना चाहे तो भी नहीं बच सकता है उसको किसी खड्डे में गाड़ी डालनी ही पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों का तो यह हाल है लेकिन इसके अतिरिक्त पुलियाओं का क्या हाल है। लालसोट से सवाई माधोपुर मुख्य सड़क है और मुख्य नदियां मोरल और बनास है। सरकार हमेशा आश्वासन देती है कि पुलिया बनाने का प्रावधान कर लिया है और निश्चित रूप से पुलियों का कार्य चालू करेगी लेकिन बनास नदी पर सवाई माधोपुर और लालसोट की बीच का पुल जो है उसके बारे में यह है कि जहां कोई बड़ा नेता पधारता है तो पुलिया पर 15-20 हजार रुपया खर्च आसानी से किया जाता है और जैसे ही दौरा समाप्त हुआ वह पानी में मिट्टी गिरी और सब कुछ बह जाता है और वही ढाक के तीन पात। उपाध्यक्ष महोदय, 10 साल का भी यह खर्चा जोड़ा जाय तो मैं समझता हूं कि पुल के खर्चे का आधा खर्चा तो हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, गंगापुर से सवाई माधोपुर के लिए कई दफा माननीय मन्त्री दौरा करते हैं। जब उनकी सड़क मलारना डूंगर होकर माडोती जाती है तो क्यों वे लालसोट का 50 मील का चक्कर लगाकर गंगापुर से लालसोट आते हैं और वहां से सवाई माधोपुर जाते हैं। जब सीधी सड़क बनी हुई है तो माननीय मन्त्री उस सड़क पर दौरा क्यों नहीं करते हैं? लेकिन सही हालत, उपाध्यक्ष, यह है कि सड़क अत्यन्त खराब बनी हुई है और पुलियाएं नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो शहरों में सड़कें हैं उनके बारे में माननीय मन्त्रीजी जरूर ध्यान देंगे। जो शहरों की सड़कें हैं जो शहरों या कस्बों में से होकर गुजरती हैं उनको न तो नगरपालिका ठीक कराती है और न सार्वजनिक निर्माण विभाग ठीक कराता है। गंगापुर शहर में स्थिति यह है कि स्टेशन से ट्रक यूनियन तक जो सड़क है उस पर आधा आधा फुट के गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं और चारों तरफ उनमें पानी भरा हुआ है। नगरपालिका से निवेदन करते हैं तो कहते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ठीक करेगा और सार्वजनिक निर्माण विभाग से कहते हैं तो वह कहता है कि नगरपालिका ठीक करेगी। आखिर कौन जिम्मेवार है?

उपाध्यक्ष महोदय, लालसोट में मोटर स्टेण्ड की रोड मुख्य सड़क है। वहां पर 20-25 फुट के एरिया में गड्ढा खुदा हुआ पड़ा है और उसमें लगभग 1 फुट तक पानी भरा रहता है लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है। हर कस्बे और हर शहर की यह समस्या बहुत बड़ी है कि इन सड़कों को कौन ठीक कराये जो कस्बों में से और शहरों में से होकर निकलती है।

सड़कें ठीक नहीं हैं और पुलियों के बारे में यह आम बात होगई है पी० डब्ल्यू० डी० के लिए अगर पुलियां बनाई जाती हैं

(श्री मीठा लाल)

तो ठेकेदारों को कितना सामान मिलता और कितना सीमेंट मिलता है यह तो भगवान ही जाने लेकिन साल 6 महीने बने हुए नहीं हुए कि उनमें दरारें पड़ जाती हैं और हर साल की मरम्मत का उन लोगों के लिए ठेकेदारों के लिए बन रही है और इन्जीनियरों का एक तरह का धन्धा खुल जाता है। पुलियां बन गई तो वे समझते हैं कि हमारी पेन्शन हो गई और उसमें से रोटी निकलती रहेगी। राजस्थान में कहीं पर पुरानी पुलियाएं बनी हुई हैं उनके लिए वे कहते हैं कि वे लोग ऐसे थे कि अपनी रोजी रोटी खत्म कर गये। ऐसे ठेकेदार या इन्जीनियर्स अगर आज हों तो हमारा दिवाला न हो। जो पुलियाएँ बनती हैं या भवन बनते हैं वे साल- 6 महीनों में चूने लग जाते हैं और उनमें दरारें पड़ जाती हैं और हर साल उनको सुधारते रहते हैं और मरम्मत करते रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, नई पुलियाएं बनाने का सवाल तो दूर रहा लालसोट और दौसा के बीच में राहूवास का जो बन्धा है उसकी पुलिया को बनाते हुए 10-15 साल हो गये हैं। पुलिया का काम गर्मियों में चालू होता है जून और जुलाई में काम शुरू होता हैं और बरसात में वह बह जाता है। दीवाली के बाद में उसकी सेन्क्शन निकलती है मंत्री महोदय के यहां से और फिर जून में काम होता है और बरसात में बह जाता है। इससे हर साल यातायात रुक जाता है और आने जाने में भारी तकलीफ उठानी पड़ती है और 8-8 दिन और 10-10 दिन तक बिल्कुल यातायात बन्द हो जाता है। तो माननीय मंत्रीजी से अर्ज करना चाहता हूं कि राहूवास के बन्ध का जो पुल है वह बहुत ज्यादा बन गया है और अब उस पर छावन की कमी है। उसे बरसात से पहले पहले बना द।

उपाध्यक्ष महोदय, इन पुलियाओं के अतिरिक्त सवाई माधोपुर शहर और जन्क्शन के बीच में ओवरब्रिज के लिए केन्द्रीय सरकार ने 70-72 में काम चालू करने के लिए 50 हजार रुपया लगाने का प्रावधान रखा गया था और राज्य सरकार को केवल कान्क्रीट बिछानी थी, लेकिन वह काम अब कुछ शुरू किया गया है, लेकिन इतनी ढील से हो रहा है कि 3-4 साल में बनकर तैयार होगा जब कि 73-74 तक उसको पूर्ण करने की सरकार की योजना थी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त भवनों के बारे में मेरा निवेदन है, चाहे स्कूल के भवन हो, चाहे किसी डिस्पेन्सरी का हो या हास्पीटल का, हर साल उनकी मरम्मत की जाती है। हर साल पुताई वगैरह भी की जाती है। उनमें टूट फूट मामूली होती है, उसको न सुधरवाकर केवल पुताई कर दी जाती है और टूट फूट के बिल बनते हैं। वामनवास में जो अस्पताल है, उसका चारों तरफ से परकोटा वगैरह टूटा हुआ है। उसमें मरीजों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। इसके अलावा उसकी छत बरसात में चूती रहती है जिससे दवा आदि बेकार हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, इन स्कूल आदि के भवनों की ओर मंत्री महोदय विशेष ध्यान देकर इस तरह से इनका स्थाई हल करने का प्रयत्न करें जिससे दो चार साल तक इनकी मरम्मत कराने की आवश्यकता न पड़े।

(श्री मीठालाल)

उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय न लेकर मैं नई सड़कों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। लालसोट से गढ़मोरा तक की सड़क बन कर चालू हो गई है, वह चार पांच मील बन चुकी है। आगे के निर्माण के लिए आगे की योजना में प्रावधान रखा है। मैं माननीय मंत्री से यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि कंकरीट रोड़ी के साथ साथ बने हुए हिस्से पर डामर बिछाने का काम अवश्य कर देना चाहिए, अन्यथा डामर बिछाने के समय कंकरीट रोड़ी का खर्चा फिर दुबारा करना पड़ेगा वामनवास से गढ़मोरा की सड़क की योजना थी दस बारह साल से चली आ रही है, कच्ची मिट्टी की सड़क बनी आ रही है। इस पर बरसात के समय में यातायात रुक जाता है और वहां रहने वाले लोगों को इस कारण से परेशानी होती है। लालसोट से रामगढ़ की सड़क, लालसोट से तुंगा, बस्सी से तुंगा और तुंगा से कोटखावड़ा देहिली से कोटखावदा सड़क हैं वह मंजूर कर ली है। यह सड़क दो चार मील बन जाती है लेकिन आगे आगे का काम नहीं होता है। सरकार से निवेदन करते हैं तो वह उत्तर देती है, पैसा नहीं है। मेरा निवेदन है कि ऐसी योजना आप बनायें जो पूर्ण हो सकती हो। अगर पन्द्रह मील का टुकड़ा सरकार ने बिना योजना के ले लिया दो मील, दो मील काम चालू होकर बन्द हो जाता है और पूरा पन्द्रह मील की सड़क नहीं बन पाती है, इससे जो पैसा खर्च होता है दो मील के टुकड़े पर, वह पूरी तरह से बरबाद हो जाता है। राज्य सरकार का पैसा इस तरह बरबाद हो जाता है। मैं निवेदन करता हूं अधिक समय न लेकर मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें। इसके अलावा दौसा से गंगापुर की सड़क पर खड्डे पड़े हुए हैं। दौसा से लालसोट शहर की सड़क है, उस पर रेत उड़ कर जमा हो गई है और सड़क ढकी हुई है। वैसे सड़कों की देखरेख के लिए बारहमासी रहते हैं, उनको तनख्वाह वगैरह भी लगती है। उनके द्वारा काम भी होना चाहिए। विभाग यह देखे कि बारहमासी काम कर रहे हैं, या नहीं वह क्या काम कर रहे हैं। गंगापुर से दौसा की सड़क पर खड्डे पड़े हुए हैं और अगर नगरपालिका का झगड़ा है, इस पर विचार करके आप जनता को राहत दें, साथ ही सड़कों की मरम्मत की ओर भी पूरा ध्यान देकर उनका सुधार करें। मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर विचार कर लेते हैं, जवाब दे देते हैं तो ठीक है, वरना मेरा निवेदन है कि इस मांग में एक पैसा भी नहीं दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फारूक हसन !

श्री गौरीशंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं.....................

श्री उपाध्यक्ष : अर्ज करने का यह टाइम नहीं है।

श्री गौरीशंकर : दो मिनिट के अन्दर मैं अर्ज कर देना चाहता हूं, और कुछ नहीं बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्य को सम्बोधित किया जा रहा है, आप विराजिये।

Page No 86

श्री गौरी शंकर : मै निवेदन करना चाहता हूं, न मुझे कटौती प्रस्ताव-पर बोलने का मौका मिलता है, न तारांकित प्रश्न पर बोलने का मौका मिलता है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने दल के सचेतक से वार्तालाप कीजिये । विराजिये ।

श्री मीठालाल : इधर आ जाइये न उधर टाइम नहीं मिलता है तो ।

श्री फारूक हसन (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, तामीरी दौर में सड़कों की अहमियत इस बात में समझी जाती है, शहरों को गांवों के साथ और गांवों को शहरों के साथ सड़क से जोड़ देने से गावों की खुशहाली हो जाती है, आर्थिक स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ता है । गुजिस्ता बीस सालों में, आज जो माँग रखी है पी. डब्ल्यू. डी. की, इस विभाग की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, गुजिस्ता बीस साल से सवाई माधोपुर की स्थिति सड़कों के सम्बन्ध में रही है, चूंकि हमारे मन्त्री महोदय का काफी ताल्लुक सवाई माधोपुर से रहा है वह बखूबी वाकिफ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सवाई माधोपुर का हल्का, जो विधान सभा हल्का है, उस हल्के में गुजिस्ता बीस साल से कोई सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जबकि वहां पर ऐसे बड़े बड़े गांव हैं, अगर वहां सड़क का साधन हो जाय तो निश्चित रूप से बड़ी बड़ी मण्डियां कायम हो सकती है । भाडोती से खिरनी, शामपुरा, वलाड़ना चौक डूंगर है, इन मुकामात पर सड़क बन जाती है तो यकीनी बात है कि बहुत बड़ी मण्डी की स्थापना हो सकती है । लेकिन पता नहीं किन वजूहात की बिना पर सवाई माधोपुर क्षेत्र को बीस साल से सड़कों से महरूम रखा गया है । मैं यह गुजारिश करूंगा पी. डब्ल्यू. डी. मन्त्री से पार्लियामेन्ट इलेक्शन के टाइम पर आप उस क्षेत्र के दौरे पर आये थे, जो आपने दौरा किया, उसमें जो मुश्किलात उस सफर में पेश आई-मैं यह मान कर चल रहा था उसके बाद आप इस बात को महसूस करके, यकीनी बात है, उस क्षेत्र के लिए सड़कों की गुंजाइश रख कर चलेंगे । इलेक्शन में कामयाब होने के बाद हम भी उम्मीद रखते थे कि इस बजट में, यकीनी बात है, सवाई माधोपुर के लिए सड़कों के लिए प्रावधान रखा जायगा । लेकिन पूरा बजट देखा, सवाई माधोपुर के नाम पर कोई सड़क दर्ज नहीं है । पता नहीं, किन वजूहात की बिना पर गुजिश्ता बीस साल के बाद भी आने वाले साल में भी सवाई माधोपुर को सड़कों से महरूम रखा गया है । मैं मन्त्री महोदय की इस ओर तवज्जह दिलाना चाहता हूं, इस मर्तबा यदि आपके पास गुंजाइश है तो इस क्षेत्र में सड़कों के लिए कुछ गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करें । मैं थोड़ा यह भी निवेदन करूं, शेरपुर से शामपुरा का चौदह मील का फासला है । इस फासले में यदि सड़क का निर्माण हो जाता है तो यकीनी बात है, साठ–सत्तर गांवों को फायदा पहुंच सकता है और लोगों को आने जाने के अन्दर सुविधा हो सकती है । बिना सड़कों के साठ-सत्तर गांवों के लिए तीन चार महीने ही रास्ता खुला रहता है, बरसात के महीनों में और उसके बाद सर्दी के महीनों में भी रास्तों पर पानी की बहुतायत रहती है और उस कारण से आमद-रफ्त बन्द हो जाती है, उनका शहरों से ताल्लुक खत्म हो जाता है । अगर मरीजों को लेकर आते हैं तो वह

(श्री फारूक हसन)

रास्ते में ही मर जाते हैं। इस किस्म की मुश्किलात उस तरफ के रहने वाले लोगों को हैं। इसमें ज्यादा लम्बी चौड़ी सड़क की बात नहीं है, चौदह मील की सड़क है। इस सड़क को पूरा कर दें तो मेरे क्षेत्र के अन्दर रहने वाले लोग हैं उनको राहत हो जायगी।

सूरवाल से भागवतगढ़ की सड़क है, इसका आठ मील का फासला है, उस पर फेमिन के टाइम पर काम हुआ था और डेढ़ लाख रुपये एकत्र हो गये। आज इस पोजीशन में यह है कि जो काम हुआ है उस पर तवज्जह नहीं दी गई, तो यकीनी बात है, बहुत कम खर्च होने पर ही आठ मील का यह टुकड़ा सड़क का रूप धारण कर सकता है। मैं मन्त्री महोदय से गुजारिश करूंगा अभी बिल्कुल थोड़ा काम बाकी है, इस पर कुछ रुपया खर्च कर दिया जाता है तो इस आठ मील की सड़क से चालीस-पच्चास गांवों को फायदा पहुंच सकता है।

माडोती से बोंली वाया खिरनी सड़क है इससे सौ गांवों को लाभ हो सकता है। मन्त्री महोदय इस बात पर विचार करें तो इस क्षेत्र में सड़क नाम की चीज जनता को दिखाई पड़ सकती है। मैं निवेदन करूंगा कि मैंने तीन सुझाव आपके सामने रखे हैं, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस तरफ आप तवज्जह देंगे।

एक सड़क बोंली से गई है। मैं निवेदन करूं, वह पिछले दस साल से बन रही है। यह आठ दस मील का टुकड़ा है। उस पर डामर पड़ने का मौका आता है तो गिट्टी गायब हो जाती है और गिट्टी डालते हैं तो उस पर डामर नहीं पड़ती है। इस किस्म की हालत है। यकीनी बात है कि इससे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इन दिनों में काम होने से ज्यादा नुकशान की सम्भावना नहीं है, मैं निवेदन करूं, इस साल पांच हजार रुपये की मन्जूरी हुई थी, उस पांच हजार में से सात पर्सेन्ट कम करने के बाद जो बचा वह खर्च हो चुका है। लेकिन जो सड़क की पोजीशन थी, वह वैसी ही बनी हुई है, उसमें प्रगति नहीं हो पाई है। मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत, इस तरफ ध्यान दें तो उचित होगा।

रणथम्भौर सवाई माधोपुर में है, उसका महत्व माननीय सदस्य जो यहां विराजे हुए हैं उनसे छिपा हुआ नहीं है। यह महत्वपूर्ण स्थान है। वहां की सड़क की शुरूआत हुई थी, वह शुरूआत हुई लेकिन खत्म कब हुई यह बात समझ में नहीं आती। इस सड़क के लिए पांच हजार रुपये मन्जूर हो पाये हैं और उसमें से सात पर्सेंट कम करने के बाद में चार हजार लग पाये हैं। इसके बाद कुछ फर्लांग सोलिंग का काम हो गया है। तो सोलिंग के पहले जो सड़क की थोड़ी बहुत सहूलियत थी, वह क्योंकि सोलिंग हो गया, उस पर से ट्रक आदि पार नहीं हो सकते और सात आठ मील का डाइवर्शन आ गया है। इसकी वजह से जो यात्री गेम्स सेंक्चुरी जाते हैं उससे क्या होता है कि जो लोग जाने वाले होते हैं उनको 8 डाइवर्ट रूट पास करना होता है, जिससे सिर्फ जीप पास हो सकती है। टांगा पास नहीं हो सकता। तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जो सवाई माधोपुर का क्षेत्र है पिछले 20 वर्षों से सड़क के मामले में नजरअन्दाज होता रहा है, मुझे यकीन है, आप इस तरफ विस्तार

(श्री फारूक हसन)

से ध्यान दें। सवाई माधोपुर में सड़कों से 150 गांवों का फायदा हो सकता है। मैं इतना ही कहता हुआ हमारे मन्त्री महोदय से आशा करता हूं कि इन सड़कों को योजना में लेंगे, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग पर रखे हुए कटौती प्रस्तावों पर अपने विचार रखता हूं। किसी देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सड़कों का महत्व है। सड़कों के विकास से व्यक्तियों के विचारों में, सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन आता है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि सड़कों का अभाव है। सीमा की रक्षा के लिए भी सड़कों का महत्व है, एक तरफ पीने के पानी की समस्या है। सीमा के जिलों में पीने का पानी नहीं मिलता है। इसलिए जरूरी है कि सड़कों के साधन हों, जिससे टैंक और अन्य साधनों द्वारा लोगों को पीने का पानी पहुंचाया जा सके। अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए भी जरूरी है कि सड़क के साधन हों, जिससे पशुओं का चारा मिल सके और लोगों को अनाज पहुंचाया जा सके। जब हम देखते हैं कि इस बजट में सड़कों के लिए कोई विशेष क्रान्तिकारी कदम नहीं हैं, देखते क्या हैं कि जैसे पहले के सालों में बजट में प्रावधान आते रहे वैसे वैसे का वैसा इसमें भी रख दिया है। राजस्थान के क्षेत्र को देखते हुए जो 31,500 किलो मीटर सड़क है, यह कम है। हर तहसील हैडक्वार्टर को सड़क से जोड़ना चाहिए लेकिन आज तक कुछ ऐसी तहसीलें हैं जहां सड़कों के साधन नहीं हैं। आज भी 5000 से अधिक आबादी के गांव ऐसे हैं जहां सड़कें नहीं हैं। तहसील हैडक्वार्टर्स के अलावा कई बड़े बड़े गांव हैं जिनको जल्दी से जल्दी हैडक्वार्टर्स से जोड़ना बहुत जरूरी है।

जब हम देखते हैं कि एग्रो इण्डस्ट्रीज को स्थापित करना चाहते हैं तो देहातों को मण्डियों से सड़कों के द्वारा जोड़ना आवश्यक है। देहातों के अन्दर कॉटेज इण्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं तो उनके द्वारा तैयार किया हुआ माल मण्डियों तक पहुंचाने के लिए देहातों में सड़कें आवश्यक हैं। शहरों के अन्दर यू. आई. टी. सड़कों का विकास करते हैं, म्युनिसिपल बोर्ड्स सड़कों का विकास करते हैं लेकिन देहातों में ऐसी कोई संस्था नहीं है, देहातों के विकास के लिए सड़कों का काम नहीं हुआ। एक तरफ देखते हैं कि देहातों के अन्दर सड़कों का विकास नहीं हुआ है। आज किसान को सामान ढोने के लिए, मण्डियों तक अनाज पहुंचाने के लिए यदि सड़क हो तो 5 आने खर्च करने पड़े लेकिन सड़क के न होने से उनको 5 रुपये खर्च करना पड़ता है। आज किसान गरीब है। उसके पास इतने साधन नहीं हैं कि वह अपने सामान के लिए इतना पैसा खर्च करें लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि किसान को सड़कों की सुविधा मिल सके।

गंगानगर जिले की सड़कों की दुर्दशा के बारे में श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने इस बारे में काफी बताया है। आज हम देखते हैं, गंगानगर जिले की सड़कों का बुरा हाल है। काफी सड़कें जो 1952 की योजना के अन्दर हैं लेकिन आज तक उनका काम पूरा नहीं हुआ। आज कुछ ठेकेदारों ने कई सड़कों पर गंगानगर जिले में मोनोपोली कर रखी है, उन्होंने क्या किया और क्या करना चाहते

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

है, यह गंगानगर क्षेत्र के विधायकों ने बता दिया है। मैं मांग करता हूं कि इस प्रकार के कांडों में राष्ट्र के विकास के नाम पर पैसा लोगों की जेब में जाता है, सिनेमाओं की स्थापना होती है। इस तरह के कांडों की जांच करें और जो अधिकारी या ठेकेदार इनमें शामिल हैं उन पर कार्यवाही की जाय क्योंकि हम मानते हैं कि राष्ट्र के विकास के पैसे का गोलमाल करना, राष्ट्र के साथ विश्वासघात है। आज जब हम बरकत सरकार को देखते हैं जिसने कुछ समय से बाग-डोर सम्भाली है जो न ठेकेदारों से पैसा लेती है, न अधिकारियों से मिली हुई है, फिर भी यह परिवर्तन होने के बाद भी राजस्थान में क्यों घोटाले होते हैं। इस प्रकार की आस्था जो सरकार में बनी है, उसको कायम रखने के लिए जनता का उनमें विश्वास कायम रखने के लिए, इस प्रकार के घोटालों की तुरन्त जांच करें।

गंगानगर में काफी सड़कें हैं जो 1952 से पड़ी हैं, अधूरी पड़ी हैं। एक सड़क शाहबा से मादरा है। कुछ मीलों का टुकड़ा बाकी है, जिससे बसें नहीं चल सकतीं। उनका पैसा कहां गया, कोई जानकारी नहीं। एक तहसील हैडक्वार्टर टी. बी. है जिसका सड़क से कोई सम्बन्ध नहीं है। हनुमानगढ़ जाने के लिए 30-30 मील होकर जाना पड़ता है। एक स्थान पर बांध न बनने, सड़क न बनने से लोग परेशान हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो काम अधूरे पड़े हैं जो 4-5 मील के टुकड़े हैं। वहां आवागमन के साधन बढ़ सकते हैं, उनको पूरा किया जाए। दूसरी तरफ सड़कों की मरम्मत का सवाल है। हरियाणा को देखिये वहां सड़कों का विकास हुआ कि उसकी सीमा में घुसते ही महसूस होता है कि हरियाणा में पहुंच चुके हैं। यहां सड़कों की मरम्मत नहीं होती, मिट्टी गिरती है। आंधी के बाद स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। सड़क की मरम्मत के लिये पैसा आता है उसकी जांच होनी चाहिए और सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि सड़कों की मरम्मत होती है या नहीं। उसके बाद सवाल उठता है सीलिंग का कि किसान की सीलिंग लगने के बाद छोटी जोत जरूर होगी, एक तरफ सिंचाई के रेट्स बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ कर लगा रहे हैं। इन बातों का तो हम समर्थन करते हैं। चाहते हैं कि सीलिंग होनी चाहिये। आज किसान चाहता है कि गांवों में सड़क हों, बिजली व सिंचाई के साधन हों, ताकि उपज बढ़े ताकि सड़कों से अनाज मंडियों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे और अच्छी कीमत में बिके। इन बातों के लिये आवश्यक है कि सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे गांवों का रोडिफिकेशन हो, गांवों में सड़कों का विकास हो सके। इसके साथ सरकार को चाहिये कि ये जो घोटाले होते हैं उनको रोका जाय। जब इस तरह की बातें होती हैं तो सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जहां राष्ट्र के विकास का प्रश्न है सरकार को ध्यान देना चाहिए तो मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं जिनकी तनख्वाह तो 600 या 700 है लेकिन जयपुर में पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि जितने बड़े बंगले हैं उनमें से आधे से ज्यादा तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के हैं। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम चाहते हैं कि हम त्याग करें लेकिन उसका फल गरीब को मिले, उस त्याग का फल अधिकारियों या विशेष व्यक्तियों की जेब में नहीं

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

जाना चाहिए क्योंकि हम परिवर्तन की बात करते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि इस परिवर्तन का फायदा किसी अधिकारी को या बड़े आदमी को नहीं मिलना चाहिए। इसलिए पहले तो सड़कों की मरम्मत की जाय, जो 1952 से अधूरी पड़ी हुई हैं उनको पूरा किया जाय उसके बाद योजना बने जिससे गांवों का रूरल रोडिफिकेशन हो और देहातों और मण्डियों को सड़कों से जोड़ा जाए। आज सबसे बड़ी समस्या है कि हमने मण्डियों की स्कीम बनाई लेकिन वह क्यों नहीं विकसित हो रही है? इसका कारण सड़कों का अभाव है।

आज गांवों में सड़कों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। पहले तो सड़कें राजस्थान में ही बहुत ही कम हैं। पर मेरे क्षेत्र में सड़कों का विकास बहुत ही कम हुआ है। आज जो सड़कें मेरे क्षेत्र में हैं उनमें बहुतसी पुरानी हैं और जो सड़कें हैं उनमें जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। पक्की सड़कों का अभाव है। आज गांवों से किसान जब अपने अनाज को मण्डियों में ले जाता है तो इन्हें सड़कों के अभाव में बहुत ही असुविधा रहती है। इसलिए मेरा राज्य सरकार से उपाध्यक्ष महोदय, आपके मारफत यह निवेदन है कि ग्रामों में सड़कें बनायी जायं। आज राज्य सरकार जब गांव वालों से टैक्स लेती है तो राज्य सरकार के लिये यह अनिवार्य हो जाता है वह सड़कें बनावें और जनता को राहत दे। सड़कें बन जाने से किसानों को अपने अनाज को मण्डियों में ले जाने की सुविधा होती। इसके अलावा राज्य सरकार को चाहिये कि किसानों के लिये बिजली और सिंचाई व पीने का पानी भी दे। बस मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीत सिंह।

श्री अजीतसिंह (टौंक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 28 के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज टौंक जिले के अन्दर जो सड़कें हैं उनका बहुत ही बुरा हाल है। मैं आपके जरिये राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर सड़कों का अभाव है इसलिए जनता को राहत पहुंचाने के लिये टौंक जिले की सड़कों का विकास होना चाहिये। आज राजस्थान बने इतने साल हो गये हैं पर राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया गया। जो सड़कें पहले राजा महाराजाओं के वक्त सड़कें बनी थी, वही आज तक बनी हुई हैं। उन सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है। नयी सड़कें तो बनी ही नहीं हैं। पुरानी सड़कों को ठीक नहीं कराया गया है और उनकी मरम्मत नहीं होने की वजह से उन सड़कों में जगह जगह गड्ढे बन गये हैं। इससे जनता को बहुत ही परेशानी होती है। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि टौंक जिले की पुरानी सड़कों की मरम्मत करायी जाय ताकि जनता को सुविधा हो। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, टौंक जिले में एक नदी बनास पड़ती है जो कि टौंक को जयपुर जिले से मिलाती है। इस सड़क पर जो पुलिया बनी हुई है उसकी व उस सड़क की मरम्मत होना तुरन्त आवश्यक है क्योंकि उस पुलिया को क्रोस करके जाना पड़ता है। एक और जो बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर एक ठेकेदारी प्रथा है

(श्री अजीतसिंह)

जिससे जो व्यक्ति अपना माल वगैरह ले जाता है, तो उसे ठेकेदारी प्रथा के अनुसार जो ठेकेदार होता है उसे 15 पैसे देने पड़ते हैं। यह ठेकेदारी प्रथा पहले जागीरदारों के जमाने से ही चली आ रही है और आज भी 15 पैसे ठेकेदार द्वारा वसूल किया जाता है । मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके मारफत मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रथा को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसी प्रथा सारे राजस्थान में कहीं भी नहीं है। आज काश्तकार अपना अनाज लेकर जाता है तो टैक्स ठेकेदारों को देना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, टौंक में खरबूजे बहुत होते हैं और यहां से खरबूजे बाहर बहुत ही मात्रा में जाते हैं। आज जब यहां से कोई किसान खरबूजे लेकर बाहर जाता है तो उसे 15 पैसे के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े काश्तकार की तो कोई बात नहीं पर छोटे काश्तकार जो अपना माल लेकर जाते हैं उन्हें ठेकेदार द्वारा परेशान किया जाता है और अगर उसके पास पैसा नहीं होता है तो कई बार लोगों के साफे तक छीन लिये जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रथा को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये। इसके अलावा आज टौंक से मालपुरा जो सड़क जाती है उसकी स्थिति भी बहुत खराब है। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। टौंक डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है वहां पर जनता का मालपुरा वगैरह से लोगों का आना जाना रहता है वहां पर इस प्रकार की सड़कों से जनता को काफी परेशानी रहती है। अगर यह सड़क पक्की और अच्छी हो जाये तो जनता को काफी सुविधा होगी। इसलिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि इस रोड को अच्छी बनायी जाये। उपाध्यक्ष महोदय, टौंक जिले में सड़कों का विकास बिलकुल ही नहीं किया गया है। पहले एक योजना बनी थी जिसके अनुसार दस हजार रुपये एक सड़क बनने के लिये सेंक्सन हुए पर वह भी पूरी नहीं हो सकी। इसके अलावा एक पांच लाख रुपये की योजना सेंक्सन हुई थी गट्टा बनाने के लिये उसमें भी सिर्फ 500 रुपये होतो स्वीकृत किये गये हैं। जब इन्जीनियर महोदय से बातचीत की तो पता लगा कि इससे तो कुछ नहीं होने का है क्योंकि 500 रुपये में क्या हो सकता है। आज वहां पर सड़कें बहुत ही पुरानी हैं, और जगह जगह से टूटी हुई हैं हरसाल उन सड़कों की मरम्मत भी नहीं होती है तो फिर इसका हल कैसे निकलेगा। नयी सड़कें आप बना रहे हैं जिसकी भी बहुत ही आवश्यकता है। इसी तरह टौंक को मालपुरा तहसील को सड़क से मिलाने की बहुत ही आवश्यकता है। ताकि जनता को सुविधा हो। दूसरी बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा वह है जो सड़कें पुरानी नहीं हुई हैं उनमें जगह जगह गड्ढे पड़े हैं और जब बरसात आती हैं तो उनमें पानी भर जाता है, और बरसात में फ्लड के कारण जो रास्ते में गड्ढे हैं वहां पर पानी भर जाने से एक्सीडेन्ट का भी खतरा ज्यादा बना रहता है । इसलिये उन्हें ठीक करायी जाय, सड़कों को पक्की बनायी जाय तथा नयी सड़कों का निर्माण कराया जाय। इसके लिये आवश्यक है कि बजट में स्वीकृति की जावे ताकि नयी सड़कों का निर्माण किया जावे । आज मालपुरा से टोडा रायसिंह की ओर टौंक से उणियारा की सड़क पर डामर नहीं होने से

(श्री अजीतसिंह)

जनता को काफी परेशानी है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि उन सड़कों को डामर की बनायी जाय, ताकि जनता को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। वैसे भी टौंक जिले में सड़कों का अभाव है और खासतौर पर इस क्षेत्र में से जो टौंक से उनियारा व टौंक से मालपुरा की सड़क पर जहां कि कच्ची सड़क है वहां पर जो मरम्मत नहीं होने की वजह से जगह जगह गड्ढे पड़ गये हैं उन्हें ठीक कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। दूसरी बात मैं जो आपके मारफत मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा वह है टौंक को जाने वाली मेन सड़क के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, इस सड़क की स्थिति बहुत खराब है वही पुराने जमाने की सड़क बनी हुई है। राजे-महाराजाओं ने जो सड़क बनायी थी वही चली आ रही है। जगह जगह पर टूटी हुई है और इसके लिये कई बार राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे पर राज्य सरकार ने इसे ठीक कराने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की। आज स्थिति ऐसी है कि जनता को इससे भारी परेशानी हो रही है। मेन रोड पर ही मण्डी लगती है। इधर बसें वगैरह खड़ी हो जाती हैं, बसें आती जाती रहती हैं। सड़क टूटी फूटी सी है और चौड़ी भी कम होने की वजह से लोगों के आने जाने के लिये बहुत ही कम रास्ता रहता है। वहां पर अगर एक लिंक रोड़ है उसे ठीक करवादी जाय या नयी सड़क बनवादी जाय तो जनता को काफी सुविधा होगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो पुरानी सड़क है उसकी मरम्मत कराकर उन्हें पक्की करायी जाय और जो टौंक शहर के अन्दर जो सड़क जाती है वह ठीक करायी जाय ताकि जो लोग यात्रा करते हैं या किसान लोग जो खरबूजे वगैरह लेकर जाते हैं उन्हें आराम पहुंचे। बनास नदी पर जो सड़क है, उसकी हालत ठीक होना अत्यन्त आवश्यकता है और जो जनता को तकलीफ होती है और विशेषतौर से अच्छी सड़कों के अभाव में किसानों को अपने माल ले जाने के लिये जो तकलीफ होती है उन्हें राहत पहुंचे। आज टौंक से बाहर खरबूजे वगैरह दिल्ली और दूसरे प्रान्तों को जाते हैं उसमें जो काश्तकारों को अच्छी सड़कों के अभाव में तकलीफ होती है उसे मिटायी जानी चाहिये। आज हमारे जो पैसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत होते हैं वे तो सड़कों की मरम्मत कराने के लिये भी कम पड़ता है तो नयी सड़कों का निर्माण कैसे हो सकता है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि नयी सड़कों के निर्माण के लिये उचित धनराशि स्वीकृत की जानी चाहिये और खासतौर से जो लिन्क रोड है उसे ठीक करवायी जानी चाहिये।

दूसरा मैं आपका ध्यान फ़ैस वर्क पर जो सड़कें हैं उन पर दिलाना चाहूंगा पी.डबल्यू.डी. उन सड़कों को देखती है मन्त्री महोदय, यह मेरे यहां की समस्या है। माइनिंग डिपार्टमेंट वालों ने ठेका दे रखा है। जब सड़क वाले कंकरी उठाते हैं तो रायल्टी मांगते हैं और वह रायल्टी पी.डबल्यू.डी. देता नहीं है। जब तक आप इस बारे में कोई फाइनल व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक सड़कों का काम नहीं होगा।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो कंकर पटकने वाली समस्या है, उसको समाप्त करें। फ़ैस योजना के अन्दर जो 20 फी सदी खर्च कर सकते हैं और अगर मेटेरियल

(श्री अजीतसिंह)

पर 20 प्रतिशत से ज्यादा खर्च आये तो वे मन्जूर नहीं करते हैं। इसलिये कोई समस्या का समाधान निकालें। कंकरों का कोई उपयोग ही नहीं इसलिये मेरा निवेदन है उसका सही उपयोग करवायें।

दूसरा मेरा निवेदन है क्रैश योजना में मजदूरी देने की बड़ी दिक्कत है 10 महीने की जो रोजगार देने का आपने रखा है, इसमें बड़ी मुसीबत है। जब सड़क आगे चली जाती है और आज जिन जिन पंचायतों ने 10-20 नाम दिये थे, उनको तो मजदूरी मिल गई, लेकिन जब सड़क दूर पहुंचती है तो आगे के गांवों के नाम नहीं आते हैं और न ही पिछले गांवों के मजदूर इतनी दूर जाना चाहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है मजदूरो की उचित व्यवस्था कराई जाय। आज पांच मील सड़क चली गई तो कोई मजदूर पांच मील दूर काम करने नहीं जाता है। आपका 6 लाख रुपया अभी इसी बिना पर लैप्स भी हो गया। मजदूरों की जो समस्या हैं वह पूरी नहीं हुई है। जहां पर सड़क पहुंच गई वहां के नाम नहीं दिये गये। यह बड़ी समस्या है इसलिये निवेदन करूंगा 10 महीने जो रोजगार देने की व्यवस्था है उसमें उचित सुधार किया जाय हर महीने पी. डब्ल्यू. डी. देने की स्वीकृति दे, ऐसा कुछ किया जाय। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा आप इस समस्या का जरूर निदान करें। यह गांव वालों को परेशान करने वाली बात है।

मन्त्री महोदय, इसके अलावा जो लिन्क रोड्स हैं और जो बरसात से सारी की सारी खराब हो गई हैं, बाढ़ से सड़कें बह गई हैं, बन्धे टूट गये हैं टोडारायसिंह वाली सड़क बिलकुल खराब हो गई है इसलिए मेरा निवेदन है इस सड़क की भी मरम्मत कराई जाय। यह हमारी एकमात्र सड़क है जो टोडारायसिंह से मिलाती है।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि जो क्रैश योजना में सड़कें बन रही हैं और जो सड़कें तैयार हो गई हैं उनकी पुलियों के बारे में विचार नहीं हो रहा है। इन पर छोटी-मोटी पुलिया नहीं बनने से गांव वालों को परेशानी हो रही है। उस रोड़ पर ट्रक नहीं जा सकता है, बैलगाड़ियां नहीं जा सकती हैं और न कोई दूसरे आवागमन के साधन आ जा सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आम जगह, खास खास जगह पुलियों का निर्माण कराया जाय ताकि गांव वालों की दिक्कत दूर हो सके। जैसे भी आपके पास धन की व्यवस्था हो तो करवा दें तभी गांव वालों को असली फायदा होगा। मेरा यह भी निवेदन है कि 9 किलोमीटर के हिसाब से ही हमारे यहां पर सड़कें हैं जबकि और जिलों में 13 फी सदी सड़कें हैं। हमारे जिले की सड़कों का हिसाब कम बैठता है इसलिए मेरा यह भी निवेदन है कि नई सड़कों की भी स्वीकृति प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग सत्तारूढ़ दल के पास और सरकार के पास सबसे बड़ा हथियार है। बड़े बड़े पूंजीपती जिनको ठेकेदारों के नाम से पुकारा जाता है उन पर सत्ता में बैठे हुए लोग

(श्री मूलचन्द सामरिया)

नियन्त्रण रखते हैं और मनमाने तरीके से उनका उपयोग और दुरुपयोग करते हैं। सबसे पहले मैं नीति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज जब राजस्थान में कांग्रेस का प्रबल बहुमत है और कांग्रेस ने यह घोषणा की है कि हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं और जिसमें मजदूरों का राज्य लाना चाहते हैं, किसान का राज्य लाना चाहते हैं। सार्वजनिक विभाग ऐसा विभाग है जिसमें मजदूर कहे जाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। आज ये इन्जीनियर और सरकार तथा कुछ ठेकेदारों के बीच में बुरी तरह पीसे जाते हैं। इनको वाजिब तरीके से पैसे नहीं मिलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूं, कई बार ऐसा होता है ठेकेदार काम कराने के बाद एक पैसा नहीं देते हैं और सरकार के द्वारा भी कोई व्यवस्था उनकी नहीं होती है। आज स्थिति यह है कि सरकार अगर यह करे कि सारे वर्क अपने खुद के स्तर पर करे अथवा ठेकेदारों को निकाल दिया जाय तो इस विभाग में जो भ्रष्टाचार है, उसमें कमी आ सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, ठेकेदार वह व्यक्ति है जो एक तरफ मजदूरों का शोषण करता है और दूसरी तरफ उच्च अधिकारियों को खुले दिल से रिश्वत देता है। अगर 100 रुपये का काम होता है तो बड़ी मुश्किल से 50 रुपये का काम मिलेगा। 50 फी सदी काम होता है और 50 फी सदी का पैसा भ्रष्ट अधिकारियों के बीच बंटता है। अगर सरकार यह तय करे चाहे 100 रु० का काम हो और चाहे एक करोड़ का काम हो, मजदूरों की सोसायटी के थ्रू काम होगा और उसमें जो व्यक्ति एक्सप्लाइटर है, ठेकेदार है उसमें शामिल नहीं किया जायगा और जो वास्तविक मजदूर है उन्हीं की सोसायटी हो तो उनका शोषण रुक सकता है और वह व्यक्ति सोसायटी के थ्रू भ्रष्टाचार को रोक सकता है और दूसरी तरफ मजदूरों का जो शोषण होता है उसको रोकने के लिये अगर यह तय हो कि कोई भी वर्क सोसायटी-उन मजदूरों की सोसायटी जो एक्चुअल में फावड़ा और गेंती लेकर काम करते हैं-उनकी सोसायटी है उनके थ्रू करवाना चाहिये और सरकार को चाहिये जब तक उनके बिल का पेमेंट नहीं हो तब तक के लिये सरकार उनको एडवान्स दे और जब बिल का पेमेंट हो जाय तो उनका रुपया उसमें से काटा जा सकता है। इस तरह मजदूरों के साथ न्याय हो सकता है।

अब मैं कुछ और निवेदन करूंगा। दौसा क्षेत्र ऐसा है जिसमें कई सड़कों पर इतनी गहराई है कि वाहन उन पर चल नहीं सकते हैं। खैरवार और भारकिया ऐसे क्षेत्र हैं जहां बरसात में रास्ते बिलकुल रुक जाते हैं। आपके कांग्रेस के एक बड़े नेता श्री रामधन का वहां पर निधन हो गया जो भूतपूर्व विधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। उनके निधन पर उनके निकटवर्ती रिश्तेदार और बड़े बड़े लोग उनके गांव में इसलिये नहीं पहुंच सके कि उस गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं है। न उस गांव में ट्रक जा सकते हैं, न जीप जा सकती है, न कार जा सकती है और न बैलगाड़ियां ही जा सकती हैं। इस कारण से उनके रिश्तेदार उनके यहां नहीं पहुंच सके। और ऐसे भी गांव हैं। अगर ऐसे गांवों की प्लिन्थ ऊंची करके ऊंचाई पर मिट्टी की

(श्री मूलचन्द सामरिया)

सड़क और उसके किनारे पत्थर लगाकर सड़क बना दी जाये तो गांव के रहने वाले लोगों का बरसात के दिनों में अन्य लोगों के साथ भी सम्पर्क कायम रह सकता है। दौसा के गांव में दौसा–आगरा रोड से हजारों की तादाद में व्हीकल्स निकलते हैं वहां पर रेलवे क्रासिंग ऐसी जगह आ जाता है कि कम से कम 15-15 मिनट 50-60 गाड़ियों को खड़ा रहना पड़ता है। इसके बारे में कुछ दिनों पूर्व चर्चा भी थी कि ओवरब्रिज का निर्माण करने के लिए विचार हो रहा है लेकिन मेरी समझ में यह आता है कि यह कुछ सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का काम है। इसके लिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जो काम सेन्टर के अधीन होता हो उसके लिए केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी की जाये और सड़क का काम राज्य सरकार करा सकती है। इस तरह से आवागमन के साधनों में बहुत बड़ा अवरोध 15-20 मिनट तक क्लोजिंग आफ रोड से होता है, उससे हजारों की तादाद में लोगों को रुकावट पैदा होती है और बहुत सा सामान समय पर नहीं पहुंच सकता है और उसमें देरी होती है तो ओवरब्रिज बना दिया जाये, उससे लोगों की यह सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। तो दौसा का ओवरब्रिज का काफी महत्व है क्योंकि यहां एक बड़ी मन्डी है और यात्रियों की दृष्टि से जयपुर के पास होने की वजह से इसका बहुत महत्व है।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दौसा की सड़क के दोनों तरफ थड़ियां हैं और उनके सड़क से दूर होते हुए भी सरकार उनको हटाना चाहती है और सुनने में ऐसा आया है कि एक बाइ-पास की योजना सा मिल के पीछे से होकर बना दी गयी है। तो मैं निवेदन करूंगा कि 70-80 लोग जो कि वर्षों से वहाँ रोजगार करते आ रहे हैं–किसी की पान की दुकान है, किसी की नमकीन की दुकान है, किसी की चाय की दुकान है उनको बेरोजगार नहीं किया जाये और अगर यह बाइ-पास नहीं बनाया जाये तो इससे सरकार की करीब करीब 1लाख रुपये की बचत होगी और जो लोग पहले से वहां रोजगार कर रहे हैं वे बेरोजगार भी नहीं होंगे।

दौसा से लालसोट रोड में एक कुन्डलवाड़ा का एक मील का टुकड़ा है अगर उसको चौड़ा कर दिया जाये तो इससे एक्सीडेन्ट्स में काफी बचत हो सकती है क्योंकि दौसा में पास होकर आमने सामने गाड़ियां हो जाती हैं तो कुछ ऐसी जगह आ जाती हैं कि वहां निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर दो-तीन फीट सड़क को चौड़ा किया जाय तो आने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर दो-तीन केसेज बड़े भयंकर हो गए। नागौरी मोहल्ले में एक बच्चे की मौत हो गयी और उसका मुख्य कारण यह है कि सड़क की चौड़ाई कम है और आबादी के बीच में से पास होती हैं व्हीकल्स और जब वे व्हीकल्स आमने सामने हो जाती हैं तो उनका निकलना मुश्किल हो जाता है।

इसके अलावा दौसा से कुन्डलवाड़ा रोड है उसके लिए इतना ध्यान दिया जाय कि उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाये क्योंकि वहां पर कुछ जगह मिट्टी डाली गयी है और यही हालत रही तो सावन भादों के महीने में यह मिट्टी भी साफ हो

(श्री मूलचन्द सामरिया)

जायेगी और जब मिट्टी साफ हो जायगी तो सरकार फिर कहेगी कि मिट्टी का काम चालू किया जाये इसलिए उस सड़क को स्पीडीली चालू कर दिया जायेगा तो वह मिट्टी रह सकती है वरना आने वाले सावन भादों में वह सड़क साफ हो जायेगी। फिर कुछ गांव ऐसे हैं कि जिनको लिंक करने के लिए पुलों के निर्माण की आवश्यकता है। 72 के चुनावों में आपके दल की तरफ से मन्दिरों में कसमें खाई गयी हैं कि हम इन कामों को पूरा करायेंगे और ये आपके दल के बड़े ऊंचे नेताओं ने मन्दिरों में कसमें खाई हैं इसलिए उन नेताओं के वचनों को पूरा किया जाना चाहिए। बामन का खेड़ा का ऐसा ही पुल है, एक नदी है उसके ऊपर एक पुल बना दें, सेंथल की सड़क है उसके ऊपर भी पुल बनाने की बात है इसके बारे में भगवान को साक्षी लेकर आपने कहा था कि पूरा कराया जायेगा।....

श्री रावतराम : मन्दिरों में कब गये थे? भगवान को साक्षी लिया और मन्दिरों में कसम खाई यह कहां की बात कह रहे हैं? कृपया इसकी जानकारी तो दें।

श्री राजेन्द्र भारतीया : माननीय सदस्य की आदत में है कि बात को तोड़ मरोड़ कर कहें।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसलिए भगवान आपको सद्बुद्धि दे। यह वास्तविकता है कि इलेक्शन के दिनों में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने शपथ खाई।....

श्री मुंशीलाल : माननीय सदस्य झूठ बोल रहे हैं, कोई कसम नहीं खाई।

श्री मूलचन्द सामरिया : बाकी मांगें यदि वायदे करने के बाद भी पूरी नहीं की गयी तो जनता उनको पूरी करायेगी। मैं अगर और मगर में बोलने वाले माननीय सदस्यों को कहूंगा कि चलने के लिए रास्ते ठीक नहीं हैं और उनको ठीक कराने की मांग की जाय तो बीच में इन्टरप्ट करने की कोशिश करते हैं।

श्री राजेन्द्र भारतीया : लेकिन इस प्रकार के मिथ्या प्रचार से काम नहीं होने वाला है।

श्री मूलचन्द सामरिया : अगर आश्वासन दिये हैं तो उनको पूरा किया जाये नहीं तो इस विभाग में कटौती के लिये जो प्रस्ताव मैंने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाये और इनकी मांगों में से कटौती की जाये।

श्री रावतराम : आपको कोई आश्वासन नहीं दिया जायेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : You are not in such position, my friend.

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया
(अनुपस्थित)
श्री भीमसेन चौधरी
(अनुपस्थित)
श्री जयकिशन

श्री जयकिशन (फागी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण कार्यों के संबंध में जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन सामान्य वाद-विवाद के ऊपर हमें भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी समय नहीं दिया इसके लिए बड़ा दुःख है....

श्री उपाध्यक्ष: जो समय मिला है उसका बोलने में ही उपयोग करें।

श्री जयकिशन: दूसरी बात मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं और आज के लिए धन्यवाद इसलिए देता हूं कि एक शेर की पंक्ति याद आ गयी किसी कवि ने कहा है:

"हमें भी याद रखो सनम हम भी जवां हैं"।

इसलिए मैं आपको पुन: धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देने के पश्चात इस सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में अपने विचार रख देना चाहता हूं। प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर अपने विचार, अपनी भावनायें, अपनी संस्कृति और अपने रहन सहन के सिद्धान्तों को ठीक तरह से समझ सके लेकिन वह तभी समझ सकता है जब कि उसे जाने कि सुविधा हो। वह तभी उस चीज को ग्रहण कर सकता है जब कि उसे आने और जाने के रास्ते पूर्णरूप से उपलब्ध हों। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं और अपने विचार आपके समक्ष इसलिए रख देना चाहता हूं कि आज हमारे राजस्थान के क्षेत्र में शहरों को छोड़कर यदि गांवों की ओर हम बढ़ने की कोशिश करें तो हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय की कार रुक जायेगी, हमारे माननीय मंत्री महोदयों की कारें भी वहां रुक जायेंगी। केवल शहरों के अन्दर जिस प्रकार की चमचमाहट को देखकर हम बड़े प्रसन्न हैं और प्रसन्नता के साथ एक जगह से दूसरी जगह बड़े आनन्द के साथ घूमते रहते हैं फिर मैं आप लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं कि यदि मेरे क्षेत्र में आप चलकर देखें तो आपकी कार और जीप को एक एक कदम पर धक्का लगाकर रास्तों से पार करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि एक सड़क जो कि फागी से चाकसू तक बनी हुई है, कुछ दिनों पहले उसके निर्माण करने के लिए हमारी सरकार ने कच्ची से पक्की बनाने का आदेश दिया था लेकिन उस सड़क के ऊपर केवल 3 मील का टुकड़ा बन पाया है बाकी सामान ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। आप उस रास्ते से गुजरेंगे तो कहीं ऐसे नदी और नाले बांडी नदी पर हैं जिनमें कुछ तो टूटे फूटे पड़े हैं और कुछ पर वहां इतनी मिट्टी पड़ी हुई है कि वहां पर पैदल चलना भी मुश्किल है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक लम्बी सड़क हो, जिससे कि कस्बे को जोड़ा जा सके। हम आपसे एक लम्बी सड़क नहीं चाहते हैं। हम तो ऐसा रास्ता चाहते हैं जिससे हमारे क्षेत्र के लोग बड़ी आसानी से एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जा सके और अपने दु:ख को ठीक प्रकार से मिटा सकें जो कि उनको गांवों में उस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

दूसरी सड़क जो अकाल राहत कार्यों के अन्दर प्रारम्भ की गई थी यदि वह नहीं भी करते तो बहुत अच्छा था, क्योंकि उस सड़क को निकालने में कई किसानों के खेतों को तोड़ा गया था, कइयों की लहलहाती हुई फसल को नष्ट किया गया था और खेतों के बीच में से सड़क निकाली गई थी। कई आदमियों की आबादी की जमीन ली गई थी और जिनके बाड़े बंधे हुए थे उनको तोड़ कर उस रास्ते से सड़क निकाली गई थी। लेकिन बाढ़ आ जाने के कारण उस जगह पर इस प्रकार के खड्डे

Page No 98

(श्री जय किशन)

हो गए हैं कि पैदल चलना भी मुश्किल है। किसी साधन को लेकर या किसी वाहन को लेकर चलना तो दुश्वार बात है, कोई व्यक्ति यदि पैदल भी चले तो भी शायद एक फर्लांग में ही दस गड्ढों में से होकर निकलना पड़ेगा। यह मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि यह सड़क निबाड़ा से लेकर मंडावरी तक है और दस मील का चक्कर काट कर ही एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक पहुंच सकते हैं।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क को सुधारने से दो फायदे मिल सकते हैं। एक तो ग्राम रास्ता प्रत्येक ग्रामीण के लिए उपलब्ध हो सकता है। साथ ही साथ जो वहां के लोग, मजदूर वर्ग के लोग इसके अन्दर शामिल हैं, उन मजदूर वर्ग के व्यक्तियों को अपनी रोजी मिलेगी। गर्मी के अन्दर जो ऊपर से सूर्य की प्रचण्ड धूप पड़ रही है, उसके अन्दर बेरोजगारी के कारणवश वह एक जगह से दूसरी जगह भटकने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ग्राम से कोसों दूर कभी दिल्ली और कभी अहमदाबाद लारियां, ठेलियां घसीटा करते हैं और अपनी मजदूरी प्राप्त करने के लिए घर से निकलते हैं। यदि इस प्रकार के राहत कार्य शिघ्रातिशीघ्र प्रचलित कर दिए जावें तो उन गरीबों को भरपेट खाने को अन्न और रोटी मिल सकती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, के माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के कार्य प्रारम्भ कर दिए जावें तो हमारे क्षेत्र को दो लाभ हो सकते हैं जो मैं आपके समक्ष वर्णन कर चुका हूं।

दूसरी बात आपके समक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, यह कह देना चाहता हूं।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

कि चाकसू तहसील में शिवदासपुरा से चंदलाई कस्बे तक एक सड़क गई है। सन् 1969-70 के अन्दर वहां पर एक रोडवेज की बस चला करती थी लेकिन कुछ दिनों पश्चात् बन्द कर दी गई और अब वहां पर एक प्राइवेट बस चलती है। प्रातःकाल चली जाती है और सायंकाल वापिस आ जाती है। उसको पक्का करने के लिए ग्रामवासियों ने अपना प्रस्ताव रखा, सरकार ने मंजूर भी किया उसको पक्की बनाने के लिए तय भी किया गया था लेकिन और तो और वास्तव में आप देखेंगे कि उस सड़क का निर्माण करने के लिए पड़ी हुई रोड़ी, पत्थर, डामर वगैरह को भी वहां से हटाया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क तो भले ही देर से बने लेकिन उस पर पड़ा हुआ मलबा, रोड़ी वगैरह है जो वहां पर पड़ी हुई उसको तो कम से कम हटाना बन्द करवा दीजिए, जिससे वहां को जनता में आशा बन्धे, वहां की जनता में विश्वास पैदा हो और मैं भी जाकर गांव में लोगों को सांत्वना दे सकूं कि सामान पड़ा हुआ है, कभी न कभी तो रास्ता ठीक होगा।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

(श्री जयकिशन)

इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक हमारे इस प्रदेश के अन्दर

(अनवरत समय समाप्ति सूचक घन्टी)

एक मिनिट साहब। सड़क नहीं होने से किसानों को भी बड़ी कठिनाई होती है। वे अपना माल मण्डियों तक नहीं ले जा पाते हैं, चाहे वह कच्चे माल की मन्डी हो, चाहे अनाज की मन्डी हो, चाहे साग सब्जी की मण्डी हो या अन्य काश्त के माल की मन्डी हो, वहां तक माल ले जाने में कठिनाई होती है और किसानों को अपनी पैदावार का पूरा पैसा नहीं मिलता है। इसलिए यह भी बहुत जरूरी है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

इसके अलावा बरसात के दिनों में ऐसा है कि सांप, बिच्छू लोगों को काट जाते हैं और ठीक समय पर उन्हें अस्पताल में नहीं पहुंचा पाते हैं और दवाइयां उपलब्ध नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि

(अनवरत समय समाप्ति सूचक घन्टी)

इस प्रकार लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाने के लिए सड़कों का निर्माण करा दीजिए, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपालसिंह।

श्री गोपालसिंह (खंडेला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय का श्रीमाधोपुर तहसील की सड़कों के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और श्रीमाधोपुर में भी मुख्यरूप से खन्डेला–पलसाना सड़क की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मन्त्री महोदय…

श्री उपाध्यक्ष : जो भी आप कहना चाहें आसन को सम्बोधित करके कहें।

श्री गोपालसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि खण्डेला गोटे की भारतवर्ष की सबसे बड़ी मण्डी है और सूरत के मुकाबले की मण्डी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्डेला पलसाना बस रूट है लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। मुझे यह जानकर खुशी हुई थी कि इस सड़क का काम जल्दी ही शुरू कर देंगे लेकिन अब बताया गया है कि इस सड़क का काम बन्द कर दिया गया है और यह भी कहते हैं कि फिलहाल यह काम स्थगित रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि यह खण्डेला कस्बा नीमका थाना सब डिवीजन का सबसे बड़ा कस्बा है। इसमें पन्द्रह हजार की जनसंख्या निवास करती है और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि यह गोटे की सबसे बड़ी मण्डी तो है ही, साथ ही इसके पास में माइनिंग के बड़े भारी डिपोजिट्स हैं, यहां मजदूर लोग रहते हैं। इस तरह से इस क्षेत्र का बड़ा महत्व हो गया है। इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि सीकर दिल्ली को जोड़ने के लिए यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है और अगर यह सड़क बन जाती है तो दिल्ली का सबसे नजदीक रास्ता बन जाएगा इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन

(श्री गोपाल सिंह)

करता हूं कि इस सड़क के महत्व को समझते हुए और माईनिंग की आबादी को ध्यान में रखते हुए इस सड़क का निर्माण जो रोक दिया गया है, पुनः चालू करवाया जावे और मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देकर इस सड़क को पुनः चालू करवायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ चौधरी ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सार्वजनिक कार्यों के सम्बन्ध में एक कटौती प्रस्ताव दिया है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । विशेषरूप से तरनाऊ से तो एक सड़क डेगाना होकर अजमेर को जाती है जो नागौर को भी मिलाती है । इस सड़क का निर्माण आधे से अधिक हो चुका है लेकिन तरनाऊ से अजमेर जो सड़क जाती है वह ग्रेवल रोड़ बनी हुई है । सन् 68 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत इस पर कुछ कार्य हुआ था और करनाऊ से साजू तक करीब 11 किलोमीटर पर कार्य हुआ था । इस पर डामर सड़क बनाने के लिये कुछ सामान डाला हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यहां पर कन्सोलिडेशन का कार्य हुआ था और इसमें प्रति किलोमीटर 6 से 8 हजार रुपया करीब खर्च हुआ है । इस तरह से 66 हजार की लागत का काम हो चुका है और बाकी का या तो इन्जीनियर्स के कार्य नहीं करने व समय की कमी के कारण नहीं हो सका । मेरा यह निवेदन है कि यहीं पर जो सड़क का कार्य कन्सोलिडेशन का करा लिया गया है, वह सड़क अब धीरे धीरे टूटने लगी है यदि इस पर डामर करायी जाये तो इस पर करीब 12 हजार रुपया प्रति किलोमीटर की लागत आती है । इस तरह से पूरे नागौर जिले में जितनी भी सड़कें कन्सोलिडेशन से बनी हैं उनमें कुछ का तो कार्य हो चुका है और कुछ में कार्य हो रहा है । 50 किलोमीटर की सड़क इस तरह की बची हुई है जिस पर कन्सोलिडेशन का कार्य हो चुका है और अगर इस पर लगी लागत को देखें तो वह करीब 3 लाख आती है । इतना रुपया हम लगा चुके हैं । अगर यह सड़क डामर की सड़क नहीं होती है तो आने वाले 3-4 सालों के बाद मे वह सड़क टूट कर बेकार हो जायेगी और तीन लाख की जो लागत लगी हुई है वह बेकार में जायेगी । इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर 12 लाख रुपया और लगा दिया जाये क्योंकि जो कन्सोलिडेशन का काम हुआ था वह अभी तक टूटा नहीं है, उसमें अभी तक टूट फूट नहीं हो पाई है परन्तु अगर इसको नहीं देखा गया तो आने वाले सालों में टूट फूट हो सकती है । इसको डामर करा लिया जाता है तो यह सड़क बहुत अच्छी बन सकती है और इस पर जितना रुपया अब तक लगा चुके हैं उसका भी पूरा पूरा उपयोग हो जायेगा ।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि डीडवाना से जयपुर एक सड़क जाती है वह सांभर होकर दूदू को मिलाती है । यह एक महत्वपूर्ण सड़क है जो नागौर को जोधपुर व जयपुर से सीधा मिलाती है । सन् 68 में बहुत वर्षा हुई थी और उस में यह सड़क टूट फूट गई थी । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बरसात में यह सड़क इतनी टूट गई थी कि 5-6 महीने तक इस सड़क पर आवागमन बंद रहा। इसको ठीक भी किया गया परन्तु यह अभी तक पूर्णतया ठीक नहीं हो पाई है। इस सड़क पर जगह जगह मैटेरियल पड़ा हुआ है पर 68 के बाद आज तक वहां पर काम नहीं हुआ है। रास्ते में एक डाबसी नदी पड़ती है। एक किलोमीटर का इसका पाट है और इस पर भी डेढ़ लाख का मैटेरियल पड़ा हुआ है। परन्तु आज तक कोई कार्य नहीं किया गया है। इस वजह से छोटी मोटी गाड़ियां आसानी से इस रास्ते से नहीं निकल सकती हैं। बैलगाड़ी भी वहां से नहीं निकल सकती हैं। रोड़ी गिट्टी वगैरह वहां पर डाल रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेढ़ लाख रुपये का सामान पड़ा हुआ है और आज तक कार्य नहीं हुआ है डाबसी नदी के अन्दर बालू मिट्टी बह कर आती है। वह गिट्टी व पत्थरों को दबाने लगी है और इस पर तुरन्त काम नहीं हुआ तो मेरा ख्याल है कि जितने पत्थर मिट्टी पड़ी हुई है वह बह जायेगी या मिट्टी से दब जायेगी और बालू रेत भी पत्थर व मिट्टी के मकबरे बन जावेंगे और इन पत्थरों को निकालने में हमारा उतना ही पैसा लग जायेगा जितना कि अब तक लग चुका है। वहां पर लोगों को काफी कठिनाई है। वहां का ट्रैफिक बन्द हो जाता है और लोगों को अपना ट्रक, मोटर निकालना मुश्किल हो जाता है। बरसात के दिनों में तो आदमियों के जाने का रास्ता भी नहीं रहता है। छोटी मोटी गाड़ियां भी इस पर नहीं निकाल सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले में जो ग्रेवल रोड्स बनी हुई हैं उन पर मरम्मत कार्य होना चाहिये। पिछले कई सालों से मैंने देखा है कि इन सड़कों की मरम्मत का कोई कार्य नहीं हुआ है। इन सड़कों की मरम्मत के लिये गेंगमैन रखे जाने चाहिए। वहां पर जो गेंगमैन और मेट रखे हुए हैं उनको देखा जाये तो ज्ञात होगा जैसे कि डेगाना में एक ओवरसीयर के पास 7 मेट हैं और उनके अधीन 6 गेंगमैन हैं। जब कि एक मेट के पास 6-7 गेंगमैन होने चाहिए। मेट अपने आपको हाजरी लेने वाला, कार्य को देखने वाला और छोटा मोटा मिस्त्री समझता है और वह मिट्टी डालने व सड़क मरम्मत का कार्य नहीं करता है, तो इसका एवरेज है एक मेट के पास एक गेंगमैन का जब कि दो तीन किलोमीटर की देखरेख पर एक गेंगमैन होना चाहिए तब जा कर सड़कों की मरम्मत हो सकती है। आज हालत यह हो गई है कि इस सड़क पर न तो बैल गाड़ियां चल सकती हैं और न मोटर गाड़ियां ही। हिम्मत करके कोई मोटरगाड़ी चलावे भी तो उसकी स्पीड 10·11 या 20 किलोमीटर से अधिक की नहीं हो सकती। अगर हिम्मत कर बैलगाड़ी कोई चलावे तो या तो बैलों के पांव नहीं रहेंगे या गाड़ी का पहिया नहीं रहेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की सड़कों की जल्दी से जल्दी मरम्मत करायी जानी चाहिये। (समय समाप्ति सूचक घण्टी) यहां पर इन्हीं कुछ एक सड़कों पर फैमिन के अन्दर काम चला था। इस पर पत्थर डाल दिये गये है और अब ऐसी हालत हो गई है कि सड़क तो टूट गई है। पर आस पास से रास्ता निकाल कर के भी नहीं निकल सकते क्योंकि सड़कों के आस पास गिट्टी पत्थर का मैटेरियल पड़ा हुआ है

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

इस प्रकार हालत बहुत बुरी हो गई है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि डेगाना व नागौर जिला की सड़कों की हालत को मद्देनजर रखते हुए इसकी मरम्मत का कार्य जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाये।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक रपट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। एक सड़क डेगाना से मेड़ता जाती है। यह तीस मील लम्बी है। इस सड़क पर ग्राम तीलानेस के पास 25-30 फिट चौड़ा एक नाला बहता है। बरसात का पानी आता है तो यह भर जाता है और चार-पांच महीनों तक भरा रहता है और इससे रास्ता बन्द हो जाता है। आसपास होकर भी नहीं निकल सकते क्योंकि वहां की मिट्टी काली और चिकनी है इससे वहां पर कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती है। नतीजा यह होता है कि करीब 4-5 महीनों तक वह सड़क बन्द हो जाती है। इसके लिए पहले भी निवेदन किया गया था और अब फिर आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की जो छोटी मोटी रपटें हैं, जिनके कारण ऐसी दिक्कतें पैदा होती हैं, उनको ध्यान में रख कर उनको तुरन्त बनाया जाना चाहिये ताकि जितने रुपये लगे हैं, सड़कों के निर्माण में उनका उपयोग पूर्णतया से हो सके। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि 8 महीने सड़क पर से निकल जाये और 4 महीने सिर्फ एक रपट के कारण रास्ता बन्द रहे।

इसके साथ ही एक और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां पर फेमिन के अन्दर काम हुआ था 1968 में। 1970 तक मेरे ख्याल में 900/1000 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। पहले की सड़कों को भी ठीक ठीक किया गया था परन्तु अब इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यह समझ में नहीं आता है आखिरकार कौन जिम्मेवार है। राज्य सरकार ने फैमिन के अन्दर जरूर कार्य कराया था। अब इन सड़कों की हालत अधिक खराब हो गई है। जब इन्जीनियर्स से निवेदन करते हैं वे कहते हैं कि इन सड़कों को नियमित नहीं किया गया है इसलिए इसकी मरम्मत नहीं करायी जा सकती है। इस तरह की सड़कें करीब अकेले नागौर जिले में एक हजार किलोमीटर है। अगर दस हजार एक किलोमीटर पर लागत समझी जाये तो यह एक करोड़ रुपये का मामला है और अगर इनकी मरम्मत नहीं होती है तो यह रुपया बेकार जावेगा। हमारे बजट में बड़े खेद के साथ यह बात कही गई है कि हमारे राज्य की आमदनी नहीं हो रही है और आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार टैक्स लगा रही है। भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज हम नहीं चुका पा रहे हैं। परन्तु इधर जो खर्च हम कर चुके हैं उसकी भी देखभाल नहीं कर रहे हैं और इनकी मरम्मत या देखभाल नहीं की गई तो जो पैसा हमने अब तक इन पर खर्च किया है, उसका सदुपयोग नहीं कर पायेंगे और आने वाले सालों के अन्दर ये सड़कें और टूट जायेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम जो काम हो चुके हैं, उनके ऊपर थोड़ा रुपया और लगाकर, उनको ठीक ठीक रखा जाये तो यह नागौर जिले पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा और हम हमारे रुपयों का सदुपयोग कर पायेंगे।

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

इसके साथ ही एक और निवेदन करना चाहता हूं। हरसोर से एक सड़क परबतसर के लिये जाती है। इस सड़क के पास ही एक भकरी बांध बना हुआ है। 68 में जोरदार बरसात हुई थी तब सड़क टूट गई थी। यह सड़क बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। परबतसर में मेला लगता है और लोग बैलों को लेकर जाते हैं। परबतसर के मेले में प्रति वर्ष एक लाख से अधिक बैल बिकने के लिए आते हैं, इतना ही नहीं और मवेशियां भी इकठ्ठी होती हैं और इन मवेशियों के लिए चारा वगैरह भी इधर से ही जाता है। माननीय उपाध्यक्ष जी, उस सड़क ऊपर करीब 200 फीट लंबाई में लगातार इतना पानी भर जाता है कि रास्ता बन्द हो जाता है और इतना पानी हो जाता है कि न तो ट्रेक्टर जा सकता है और न पैदल लोग जा सकते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ निवेदन किया गया है लेकिन आज तक 200 फीट लम्बी सड़क के टुकड़े के लिए कोई रपट या पुलिया का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस सड़क से लाखों रुपयों की आमदनी होती है और उस मेले में लाखों मवेशी और दर्शक जगह जगह से इकट्ठे होते हैं और यह एक मुख्य सड़क हैं लेकिन उस 200 फीट जगह पर पुलिया या रपट का निर्माण आज तक नहीं हो सका है। यह हमारे लिए बड़े खेद की बात है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए।

नई सड़कों के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर बजट को देखते हुए और दूसरी बातों को देखते हुए नई सड़कों के लिए मेरा निवेदन करना शायद अच्छा महसूस नहीं किया जावे। नई सड़कों के लिए कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कई ऐसे रेतीले इलाके हैं कि वहां पर बैलगाड़ी तो क्या पैदल चलना भी कठिन है। मोटरों के बारे में तो यह है कि ऐसे कई गांव हैं कि जहां पर वृद्ध महिलाओं ने चुनावों के दिनों में ही मोटरें देखी होंगी वर्ना वहां पर मोटरें दिखने का सवाल ही नहीं आता है। उन गांवों से जो नाज बिकने के लिए आता है, वह लादों पर आता है या फिर व्यापारी लोग नाज खरीदने के लिए वहां पर जाते हैं और 5-5, 10-10 रुपया प्रति क्विन्टल के हिसाब से कम लेते हैं। आज तो वैसे ही किसान की कमर टूट रही है। बड़ी मुश्किल से तो कभी कभी बरसात होती है। और कभी कभी बड़ी मुश्किल से पैदावार होती है और उसके बाद में भी पूरा पैसा उसको नहीं मिल पाता है। इन सड़कों की कमी से किसी किसी गांव में तो रिश्ते ही नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे गांव में आने जाने का रास्ता नहीं है और हमारे लड़के लड़की बड़ी मुश्किल से आ जा सकेंगे इसलिए वे रिश्ता नामन्जूर कर देते हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां पर रेत ही रेत हैं और वहां सड़क का नाम भी नहीं सुना गया है, तो कम से कम जब नई सड़कों का निर्माण किया जाय तो ऐसे इलाकों को विचारार्थ ध्यान में रखा जाय और उन्हें प्राथमिकता दी जाय। जहां पर न बैलगाड़ी जा सकती है, न पैदल ही चला जा सकता है, बिजली का वहां नामोनिशां नहीं और तालाब या बान्ध

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

वहां नहीं बन सकते ऐसे इलाकों में सड़कें बनाई जायं ताकि उनको यह न महसूस तो हो कि आजादी के इतने साल बाद कुछ तो हुआ है। किसानों का नाज बिकने के लिए मंडियों तक नहीं जा सकता है तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद का और अफसोस का विषय है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 5 के बारे में निवेदन कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस इलाके की बात आपके सामने रख रहा हूं जहां आज से 60 वर्ष पूर्व आजादी का बिगुल बजा था, जहां पर उस आजादी के बिगुल को माननीय पथिकजी और माणिक्य-लाल जी वर्मा ने उस बुरड़ के क्षेत्र में बजाया था जिसको कि आज आजादी के 25 वर्ष बाद भी हमारी सरकार ने बिल्कुल अछूता रख रखा है। उस क्षेत्र के अन्दर आज आप देखते हैं कि मनुष्य एक जानवर की जिन्दगी व्यतीत कर रहा है। वहां पर जो आदिवासी लोग रहते हैं, जो भील लोग वहां पर रहते हैं उनकी, कुटिया के स्तर को मैंने देखा है, वहां के रहने वालों के वस्त्रों को मैंने देखा है दौरों पर रहने के मौके पर। किस प्रकार की उनकी जिन्दगी है जिसको जानवर से बेहतर नहीं कह सकते हैं। मैं दावे के साथ यह कहता हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसका जीवन किस पर निर्वाह करता था यह मैं आपको वहां की हिस्ट्री बताना चाहता हूं। यह पूले जो घास के पूले होते हैं, उन दो पूलों को देकर वह एक हाण्डी में छाछ ले जाता था। उस छाछ से भी रोटी थोड़ी बहुत मकई जो वहां पर छोटे मोटे बान्ध बना कर रखे थे उनसे पैदा करके वह उस मकई का दलिया बनाकर या रोटी बनाकर उससे खा लेते थे, किन्तु आज यह हालत है वह घास भी वहां पर गायब हो गया है। आज पुरड़ के इलाके में घास भी नजर नहीं आता है। आज उस भील की जिन्दगी बहुत दर्दनाक है।

दूसरी कौम जो वहां पर रहती है वह गूजर कौम है। गूजर कौम ज्यादातर पशु-पालन का काम करती है। आप देखिये कि सारे बुरड़ के इलाके में पशु-पालन का काम होता है। सब माननीय सदस्य इस बात पर आश्चर्य करते होंगे कि मांग पी. डबल्यू. डी. की है और बोल रहा हूं रोड पर हैं तो मैं उसी विषय पर आ रहा हूं कि इन सब के लिए यह बहुत जरूरी है कि उस इन्सान की तरक्की के लिए यह जरूरी है कि वहां पर सड़क दी जानी चाहिए। उस इन्सान के लिए उसकी तरक्की के लिए जरूरी है कि बिजली दी जानी चाहिए। वह मेरी विधान सभा क्षेत्र का आधा इलाका ऐसा है कि जो बुरड़ का इलाका है वहां नानकजी भाई, जो देशी रियासतों के समय वहां पर शहीद हुए हैं, उनका 13 जून को जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं, इस इलाके को बिल्कुल अछूता छोड़ा गया है सरकार का उस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं गया है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उस इलाके के अन्दर से आज 50 लाख सालाना की

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

आमदनी उसके पत्थर से हो रही है। वहां की पट्टियों का पत्थर है ? बस का पत्थर हरियाणा और गुजरात तक जाता है और वह इलाका इससे 50 लाख की रायल्टी बराबर देता आ रहा है, लेकिन इस बारे में सरकार की आंखें बन्द हैं कि वह सड़क तो बराबर उनको मुहैया करे।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा से बिजोलिया की रोड जो डोरा होकर जाती है, उस रोड की क्या हालत है ? मुझे कान्स्टीएटूम्सी की दौरों के नाते वहां जाना पड़ता है तो जो जीप जाती है, वह जगह जगह वहां पर अड़ जाती है। बस चलती है लेकिन बस के पहिये दो ढाई फीट ऊंचे रहते हैं गड्ढे उसमें मौजूद हैं। जो 5 लाख की सड़क प्लान में मौजूद है उस पर 5 हजार रुपये दिये गये हैं। हम वायदों के ऊपर वायदे करते आये हैं और इस प्रकार से जनता को हम क्या दे पायेंगे मुझे इस बात का कभी कभी ख्याल होता है। माननीय उपाध्यक्ष, आप से निवेदन करूंगा कि सड़क का इसलिए भी प्रश्न है कि वह एक पशु-पालन का इलाका है और वहां पर डेरी फार्मिंग हो सकता है। पशु-पालन का धन्धा वहां पर अच्छी तरह से पनप सकता है और वहां से दूध यदि सड़क हो तो बाहर भी भेजा जा सकता है। वहां से दूध बून्दी पहुंच सकता है, कोटा पहुंच सकता है, लेकिन सड़क के अभाव में आज वह ऐसा करने में मजबूर हैं। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि ऐसे इलाके की तरक्की के लिए सड़क ही एक ऐसी चीज है जो उनको तसल्ली जरूर दे सकती है। वे लोग गत 35 वर्षों से टिमटिमाती हुई आंखों से हमारी ओर देख रहे हैं कि सड़क तो हमें कम से मुहैया कर सकें जिससे कि उनके जीवनोपार्जन के साधन मुहैया हो सकें और वहां पर डेरी फार्मिंग हो जाय तो इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट का कुछ आभास हो सके। वे यह जान सकें कि आज देश ने क्या तरक्की की है।

(2.47 म प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बुधपुरा की लाखों रुपये और करोड़ों रुपयों का पत्थर आज बाजार में बिकता है। जो पत्थर वहां से निकलता है वह बाहर जा रहा है, लेकिन उन लोगों के चरागाहों पर मलवा ठेकेदरों की ओर से डाला हुआ है। मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि अगर उस मलवे को इस सड़क पर डलवाकर सड़क बनाई जा सकती है क्योंकि पत्थर मौजूद है और जो पत्थर टूट रहा है वह मौजूद हैं बहुत आसानी से सड़क को बनाया जा सकता है। उससे डबल नुकसान हो रहा है जो मलवा डाला गया है उससे चारागाह दबा दिये गये हैं, और पशुपालन जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं वहां के इलाके का मुख्य धन्धा है तो उनके चरागाह पत्थर के मलवे के नीचे दबा दिये गये हैं तो दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बहुत जरूरी है कि जो इलाका 50 लाख रुपया सालाना देता है उसमें सड़क बनवा दी जाय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बर का बावड़ी, डोरा और लक्ष्मीपुरा की यह रोड है।

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया)

दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि क्रैश प्रोग्राम से सरकार का किस तरह से भला हो रहा है। क्रैश प्रोग्राम के अन्दर प्लान बनाते हैं, स्कीम बनाते हैं और एस्टीमेट्स बनाते हैं यह पी० डब्ल्यू० डी० का टेक्निकल सेक्शन करता है और पेमेन्ट देता है आपकी पंचायत समिति तो यह विभाग इस चीज को बरदाश्त नहीं करता है और ज्यादातर यह कोशिश करता है कि वहां के सरपंच से लिखवा देता है कि लेबर एवेलेबल नहीं है, क्योंकि यह सीधा रास्ता है। हमारे जिले के क्रैश प्रोग्राम की मीटिंग में बखूबी देखा है, लेकिन जब सरपंच से मिला, उनसे तहकीक की तो इस बात में घोटाला पाया गया। इन्जीनियर्स को इस बात को कहा। स्थिति यहां तक है कि पी. डब्ल्यू. डी. इन्जीनियर ने क्रैश प्रोग्राम के बारह लाख के बजट के पैसे को ज्यों का त्यों लैप्स कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्रैश प्रोग्राम खास तौर पर अलग तरीके का प्रोग्राम है जिसको लोगों को एम्प्लायमेंट के लिए चलाते हैं, इसलिए इसका खास महत्व है। मैं पी. डब्ल्यू. डी. मन्त्री से निवेदन करूंगा कि विभाग के इन्जीनियर्स को आदेश दे कि क्रैश प्रोग्राम के पैसे को वह लैप्स न होने दें जब कि लिंक रोड, छोटी छोटी रोड्स का अभाव है, लोगों के अभाव-अभियोग हैं और लोग परेशान हैं तो फिर रोड्स क्यों नहीं बनाते हैं। मैं निवेदन करूं, बून्दी जिले में, बून्दी-डबलाना रानीपुरा होकर एक रोड है जिसका महत्व है। रानीपुरा नैनवा का दूसरा डिवीजन है, वह महत्वपूर्ण सड़क है, इसकी दस साल से मांग की जा रही है लेकिन हमारी सरकार की उस ओर निगाह नहीं गई। मैं निवेदन करूं, और तो और, यह जो

(समय समाप्ति-सूचक घन्टी)

कोटा बून्दी और जयपुर की रोड आती है, उसकी चौड़ाई दस बारह फीट है, आये दिन घातक एक्सीडेंट होते हैं। ट्रक्स साइड नहीं देते हैं और गाड़ियों को दिन रात खतरा बना रहता है। अभी जब केन्द्रीय सरकार के यातायात मन्त्री श्री राजबहादुर साहब आये थे, उनसे इस बात की मांग की कि इसको हाई वे डिक्लेअर किया जाय, यह ऐसी रोड है जो बम्बई तक जाती है, इसलिए इसको सरकार हाई वे का रूप दे, तो मैं समझता हूं कि लोगों को बहुत कुछ तकलीफ दूर हो सकती है। मैं निवेदन करूं कि सड़कों के लिहाज से बून्दी की जितनी भी रोड्स हैं, नये पच्चीस वर्ष से, जो पहले सड़क थी, वह फिल्म के सम्मान धूंधली होकर गायब होती जा रही हैं। एक भी रोड के लिए पी डब्ल्यू, डी. यह नहीं कह सकती कि यह रोड है जो सही हालत में है। मै निवेदन करूं, जिन सड़कों पर जाते हैं तो देखते हैं, गिट्टियां पड़ी हुई है। सब काम तैयार है, मामूली पैसे से कई हजार और लाख रुपये बचाये जा सकते हैं। लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई धनी धोरी नहीं है, राष्ट्र के पैसे का। कोई देखने वाला नहीं है। वह गिट्टियां बैलों के पांवों में लगती है। वह परेशान होते हैं। तो जो काम करा जाता है उससे बैलों के साथ में इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग न भी रहे तो उसके बजाय भी काम चल सकता है जिम्मेदारी के साथ। अगर पच्चीस लाख की सड़क के लिए पांच लाख दिये जाय। तो किस प्रकार से जिम्मेदारी निभायेंगे, जनता से क्या कह पायेंगे, क्या काम कर पायेंगे। इस प्रकार मैं निवेदन करूं, उमर गांव है,

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया)

जहां पर सैनिक लोग रहते हैं जो जान देते हैं, सीमा की रक्षा के लिए उनकी स्त्रियां अपना सिन्दूर मिटाती हैं, उस गांव की ओर दस साल से यह सरकार देखने को तैयार नहीं है। वहां पर नदी पर पुलिया है जिस पर रोड है, वह पुलिया की जगह पहले दस फीट थी, फिर बीस फीट हो गई और पच्चास फीट है आज। अगर बरसात के पहले बना दिया तो पन्द्रह-बीस हजार में काम चल जायगा नहीं तो एक लाख रुपया लगाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं. यह चीज ऐसी है, जहां मारबल की तरह इतना कीमती पत्थर निकलता है ऐसी ऐसी जगह को दर गुजर करते है। मैं आपसे विवेदन करूंगा, यह बहुत जरूरी है, आप बूंदी से चितौड़गढ़ रोड़ को देख लीजिये। इस गई बरसात में मैं खुद बिजोलिया में पड़ा रहा हूं, पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर को भी बिजोलिया में पड़ा, शिवचरण माथुर को। सब से महत्व की बात यह है इस विभाग के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सड़क एक साल में बनती है और छः महीने के बाद उसमें खड्डे पड़ जाते हैं लेकिन उसको देखने वाला नहीं है। ठेकेदार से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछते हैं। जब कि लाखों करोड़ों रुपये का धन इन्जीनियर्स पर बहाया जाता है तो फिर उनके अलावा इसके लिए कौन जिम्मेवार है। इसके लिए मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा मसला है, देश के निर्माण के लिए बहुत बड़ा मसला है जिस पर ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं आपसे निवेदन करूं ....

श्री अध्यक्ष : समय आपका हो गया है। समय के हिसाब से कह दीजिये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : मैं निवेदन करूं, इस प्रकार से लिंक रोड, छोटी छोटी रोड हैं, जिन रोड को पूरा नहीं कर पाये तो मुश्किल की बात हो जायेगी और हम इस प्रकार से जन जीवन को चला पायेंगे। कई भाइयों ने कहा कि बीमार आदमी वहां तक नहीं आ सकते, चार चार महीने तक वह कट ऑफ हो जाते है। जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान किया, हजारों आदमियों ने जान दी है, उनको यह पुरुस्कार दिया है कि चार महीने के लिए वह कट ऑफ हो जाय, जन जीवन से अलग हो जाय मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, से निवेदन करूंगा कि इन हालत को देखते हुए पी. डब्ल्यू.डी. के अन्दर खास तौर से पैसा दिया और उसके द्वारा इन सड़कों की हालत को ठीक किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा-जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उसकी सड़कों के बारे में नीति है वह दोषपूर्ण हैं। इसका नतीजा यह होगा कि हमारी अर्थ व्यवस्था को पक्षाघात हो जायगा और आत्म हत्या की स्थिति में चली जायगी।

राजस्थान की जन संख्या देश की जन संख्या का पांच प्रतिशत है, राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 10.5 प्रतिशत है। लेकिन जब सड़कों का काम लिये जाने के लिए जो प्रावधान किया गया है प्लान में उसको देखते है तो बहुत निराशा होती हैं।

(श्री अमृतलाल गहलोत)

देश की चौथी पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक क्षेत्र में 16000 करोड़ रुपयों की हैं, उसमें स्टेट सेक्टर में 6600 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। सड़कों का सेन्ट्रल सेक्टर में 418 करोड़ का और स्टेट सेक्टर में 458 करोड़ रुपये का प्रावधान हैं। यह दुर्भाग्य कीबात हैं। पांच साल में नेशनल हाई वे की लम्बाई केवल 1256 किलो मीटर हैं, राजस्थान की आबादी देश की आबादी का पांच प्रतिशत है और राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का साढ़े दस पर्सेन्ट हैं, इस अनुपात से यदि पचास प्रतिशत वेटेज जन संख्या को दिया जाय और 50% वेटेज क्षेत्रफल को तो भी राजस्थान को सेन्ट्रल सेक्टर से 33 करोड़ मिलने चाहिये। लेकिन इसके बावजूद नेशनल हाई वे के लिए अधिक राशि क्यों नहीं मिली? इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में ट्रांसपोर्ट और काम्युनिकेशन पर अनुपात में बहुत कम खर्च किया गया हैं। 1969-70 में 1.23 करोड़ रुपया खर्च किया, 1970-71 के अन्दर 1.73 रुपया खर्च किया। पिछले वर्ष अनुमानतः 2.58 करोड़ रुपया खर्च कर पाये। इस वर्ष केवल 1.21 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान है। इस प्रकार चौथी पंच वर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में कुल 6.75 करोड़ रुपया खर्च करा जायगा। इसमें ट्रांसपोर्ट और सड़क का अलग है, कम्युनिकेशन का अलग है, इस प्रकार इन चार वर्ष में चौथी पंचवर्षीय योजना में 6.75 करोड़ खर्च पायेंगे। इसके अनुपात को देखा जाय तो 458 करोड़ में से जन संख्या के अनुसार दिया जाय तो 23 करोड़ होना चाहिए। यह 23 करोड़ खर्च होना चाहिए जब कि राजस्थान में इस समय एक लाख मोटर गाड़िया हैं जिनमें से 32000 बसें व ट्रकें हैं, 25 हजार कारें व जीपें हैं, 25000 मोटर साईकल व स्कूटर हैं, 17000 हजार ट्रैक्टर्स है और 3 हजार अन्य तरह की गाड़िया है। इन एक लाख मोटर गाड़ियों से केन्द्रीय व राज्य सरकार प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कुल लगभग 30 करोड़ रुपया वार्षिक कर लेती है। आप ताज्जुब करेंगे, पेट्रोल पर कितना भारी इस समय टैक्स है, जयपुर पेट्रोल 1 रुपया 54 पैसे प्रति लिटर बिकता है, इसमें केन्द्रीय सरकार की एक्साइज ड्यूटी 1 रुपया 12 पैसे है, कम्पनी का मूल्य केवल 16 पैसे है, पम्प वाले का, डीलर कमीशन 4 पैसे है, 1 रुपया 12 पैसे सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी है, राजस्थान सरकार सेल्स टैक्स 15 प्रतिशत है जो 20 पैसे प्रति लिटर होता है और 2 पैसे आक्ट्राट है। इस प्रकार से सब मिला कर 1 रुपया 54 पैसे हो जाता है। यह बहुत बड़ा कर भार है। केन्द्रीय सरकार एक्साइज ड्यूटी के रूप में जो लेती है, वह मोटर साइकल व स्कूटर पर 10 से 12.5 प्रतिशत है, मोटर कार व ट्रक पर 15 प्रतिशत है, मोटर पार्ट्स पर 10 प्रतिशत, पेट्रोल पर 1 रु० 12 पैसे प्रति लिटर, डीजल पर 64 पैसे प्रति लिटर, टायर्स पर 50 प्रतिशत और लुब्रीकेटिंग पर 13 प्रतिशत। केन्द्रीय सरकार को एक्साइज ड्यूटी से साल भर में 19 करोड़ रुपया मिलता हैं, राजस्थान सरकार प्रत्यक्ष रूप में 4 करोड़ टैक्स लेती है और सेल्स टैक्स के लेती है तो 30 करोड़ जिस सेक्टर से लेते हैं उसके लिए हम केवल एक दो करोड़ खर्च करें यह कितना घोर अन्याय है।

(श्री अमृतलाल गहलोत)

जो सड़कें हमने बनाई हैं यदि उनकी मरम्मत नहीं की गई तो कई गुना ज्यादा पैसा उससे चाहिए।

आपके जरिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कान्ट्रोवर्शल है। आपने कुछ दिन पहले फरमाया था कि एक करोड़ रुपए सड़कों के लिए हैं। मैंने वित्त मन्त्री से बात की, वह कहते हैं २ करोड़ प्लान में रखे हैं। ३ करोड़ और कुछ नान प्लान सेक्टर में रखते हैं। कुल ५।। करोड़ रखे हैं। पता नहीं ५।। करोड़ कैसे है, आप दोनों आपस में ठीक करें।

अब मैं अपने नगर की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। हमारे यहां पत्थर का उद्योग है, 25 हजार मजदूर हैं। जोधपुर नगर में ३।। लाख की संख्या है और राज्य का दूसरे दर्जे का शहर है। मैंने मांग की कि सड़कें इतनी टूट चुकी है कि केवल माइनिंग एरिया से 10 लाख रुपए रायल्टी के रूप में, 10 लाख सैल्स टैक्स और 2 करोड़ किराए के रूप में राज्य सरकार वसूल करती है। पिछले 5 साल में एक करोड़ वसूल किया है और सड़कों पर खर्च नहीं किया है। मैंने कहा 5 लाख मरम्मत के लिए तो 11 लाख का एस्टीमेट आया। इस ओर ध्यान दें नहीं तो भगवान ही मालिक है या मन्त्री महोदय मालिक है।

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल भार्गव। (अनुपस्थित)

श्री सुरेशचन्द्र।

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपुतली) : अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों के सम्बन्ध में वादविवाद चल रहा है। मैं समझता हूं, सड़कों के बारे में इतना कहा जा चुका है कि हर माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र की सड़कों की समस्या की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है और इसलिए शायद सड़कों के नाम सुनते सुनते मन्त्री महोदय ऊब गए होंगे और माननीय सदस्यों की बात पर गौर करना सम्भव नहीं रहा होगा।

सबसे पहले मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सड़कों की हालत सुधारना शायद आपके लिए सम्भव नहीं होगा। इसलिए सा० नि० विभाग का नाम आप बदलने की कृपा करें और उसका नाम रखें "स्वयं निर्माण विभाग" क्योंकि इसमें केवल उस विभाग के अधिकारियों का ही निर्माण होता है, बाकी जनता का निर्माण नहीं होता है। पहले तो योजना नहीं बनेगी, योजना बनेगी तो पैसा नहीं, पैसा एलाट होगा तो उपयोग नहीं और वह लैप्स हो जाता है। सड़कों की हालत ऐसी है कि उनके लिए मैं चाहता हूं कि एक लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए, पूरे राज्य के लिए और योजना इस तरह बनानी चाहिए कि हम निश्चित तौर से कह सकें कि हम राजस्थान के प्रत्येक गांव में सड़क बना सकेंगे।

हरियाणा का उदाहरण लीजिए। मैं वहां की बात इसलिए करता हूं कि वह मेरे इलाके के पास से लगता हुआ क्षेत्र है। जब हम उस इलाके में जाते हैं तो मतदाता कहते हैं कि उस तरफ देखें और फिर हमारी तरफ देखते हैं। हम जवाब नहीं दे

(श्री सुरेश चन्द्र)

पाते लेकिन मन्त्री महोदय हमें जवाब नहीं दे सकेंगे, केवल एक जवाब दिया जाता है। जब हम कहते हैं कि हरियाणा के हर गांव में बिजली है हर गांव में सड़क है तो जवाब मिलता है कि वह छोटी जगह है। राजस्थान छोटी जगह नहीं है। मेरा निवेदन है कि वहां की करों की आमदनी कितनी है, बजट कितना है, फण्ड्स कितने हैं, वह भी तो छोटे है। पिछले दिनों एक बात चली थी कि राजस्थान को दो हिस्सों में बांटा जाए। कहा जाता है कि हरियाणा छोटा है इसलिए उसने तरक्की की है। यदि राज्य का बड़ा होना अभिशाप है तो उसकी तरक्की के लिए छोटा करना ही ठीक है। इस बात की योजना बननी चाहिए, लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। मैंने एक सवाल पूछा था कि कोटपुतली से डावला की सड़क के बारे में। मेरे बचपन से मांग होती आई है, मैं मतदान करने योग्य हुआ, इस सदन में आने योग्य हुआ और कुछ दिखावटी सफेद बाल भी आने लगे, लेकिन अभी तक सड़क पूरी नहीं हुई। मन्त्री महोदय से पूछा गया तो चतुराई से बताया कि एकुइजीशन की कार्यवाही चल रही है। मेरा निवेदन है कि केवल दो बीघा जमीन का एकुइजीशन होगा, लेकिन यह कहकर टाल दिया। वास्तविकता क्या है? विभाग में घुसकर असलियत पर नजर डाली। पता लगा पैसा मंजूर होता है लगाया जाता है कहीं और। सुनकर हैरानी होती है। अनेक बार आश्वासन सुने, अनेक बार शीघ्र शब्द सुना। तो ठिकाने के समय से बनी हुई सड़क आज तक 25 साल आजादी के बाद भी उस ओर विचार नहीं।

मैं हालांकि टेक्नीकल एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन मैंने हरियाणा में देखा है। जब सड़क बनाई जाती है तो उस बारे में मालूम हुआ कि तीन बातें होती हैं: कच्ची सड़क डामर व पुल। हमारे यहां स्थिति दूसरी है। पहले कच्ची सड़क की मांग करेंगे, कई सालों तक आश्वासन मिलेंगे, फिर फन्ड्स एलाट होंगे। उसके बाद डामर करवानी है तो प्रयास करेंगे 5-10 साल, उसके बाद पुल बनवानी होती है। तब जाकर सड़क पूरी होती है। मत्री महोदय इस बारे में इन्जीनीयर्स से जांच करायें कि कारण क्या है। तरीका यह होना चाहिए कि पहले कच्ची सड़क, उसके बाद डामर उसके तुरंत बाद पुल। सब एक साथ। आप कोई भी एरिया ले लें तो कम से कम पूरी तो हो जाए। जितने सदस्य हैं सब कहते हैं कि सड़क नहीं, मंत्री महोदय सुनते सुनते थक जाते हैं या तो बंटवारा कर दें पंचायत समितिवार या जिलेवार कि इस जिले को पूरा करना है स्कीम बनाकर। सड़क ऐसी चीज है कि बिना इसके सारा विकास रुका है। चाहे कृषि की बात हो चाहे शिक्षा हो। मेरे इलाके में कुल 4 सड़कें हैं जिनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। कोटपुतली से डाबला। बताया गया था कि एक लाख स्वीकृत हुआ है लेकिन काम रुका हुआ है। मंत्री महोदय चतुर हैं। कहेंगे केश में रख दिया है, इसको प्लान में रख दिया है, पाइलट प्रोजेक्ट में रखा है लेकिन उसके बावजूद सड़क कब तक पूरी होगी, मालूम नहीं। मैं मानता हूं कि सदस्यों ने एक तरीका निकाल दिया है। मंत्रीजी को निमन्त्रण दिया, फिर अपनी मांग रख देंगे। मैं भी चाहूंगा कि निमंत्रण दूं लेकिन मेरा निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे

(श्री सुरेशचन्द्र)

क्योंकि सड़क भी खराब है पहुंचना मुश्किल होगा। मैं नहीं चाहता कि मंत्रीजी को तकलीफ हो। उसके बाद दूसरी मुख्य सड़क है उसको आपने ले लिया लेकिन तीन किलो मीटर को लिया। मिट्टी गिर गई। अब कहते हैं कि आर्डर होने वाला है कि काम बन्द कर दिया जाय, वर्कआर्डर दे दिया। बावेठी से सड़क है 5 किलो मीटर उसमें से 2 किलो मीटर मंजूर हुई। उसमें मिट्टी गिरी हुई है। अकाल में काम शुरू हुआ था लेकिन रोलर नहीं है। इसलिए सड़क नहीं बन पा रही है। इसी प्रकार गोवर्धनपुरा से सड़क जाती है उस पर दस हजार रुपया खर्च किया गया। मिट्टी ही बह गई होगी। फिर दस हजार लगेंगे तब जाकर मिट्टी बिछेगी। जनता के दस हजार रुपए बेकार गए। ये जो छोटे छोटे टुकड़े है 5-10 किलोमिटर के इनको यदि स्वीकृति देते हैं वह कम से कम पूरी हो जाए और विभागीय अड़चन आती है। पहले फंड्स एलाट हुए, फिर मंजूरी फिर टेन्डर्स। फिर डामर नहीं मिले, पत्थर नहीं मिले सारा समय फारमेल्टीज में जाता है और फड्स लेप्स हो जाते हैं या दबाव के कारण फंड्स को ट्रांसफर किया जाता है। मुझे बताया गया कि मेरे क्षेत्र को इस वार पैसा नहीं दिया गया क्योंकि दूसरी जगह चुनावों के समय खर्च किया तो उसको एडजस्ट किया जाएगा। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि जहां जहां सरकार ने मंजूरी दी है उसको पूरा करवाया जाए फिर वित्तीय स्थिति के अनुसार चलें ताकि लोगों से हम कहें कि कुछ हो रहा है, काम बंद होने से जनता निराश होती है।

दूसरी बात यह है कि मैं विरोधी पक्ष का सदस्य हूं इसलिये मेरे क्षेत्र में काम नहीं होगा ऐसी मैं उम्मीद करके नहीं चलता हूं। क्यूंकि राज्य सरकार को तो जनता के हित के लिये काम करना है, इसलिये राज्य सरकार मेरे क्षेत्र में भी जो कि पिछड़ा हुआ है, उसमें जरूर काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को चाहिये कि वह एक निश्चित कार्यक्रम से काम करे और उसी कार्यक्रम के अनुसार सड़कों का विकास किया जाना चाहिये। आज मेरे क्षेत्र में सड़कों का अभाव है, जनता को आने जाने में परेशानी होती है, इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वह पुरानी सड़कों की मरम्मत कराये और नई सड़कें जनता की सुविधा के लिये बनाये। धन्यवाद मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मेरे जिले में जो स्थिति है, उसके बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। आज अध्यक्ष महोदय, चूरू जिले में सड़कों की बड़ी ही दयनीय स्थिति है, वहां पर जनता को सड़कों के अभाव में बड़ा ही कष्ट होता है। पिछले तीन चार सालों से वहां पर भयंकर अकाल पड़ा है और अकाल के समय पानी जनता को पहुंचाने के लिये सड़कों के अभाव में बड़ी ही तकलीफ हुई। हालांकि अकाल के समय कुछ अकाल राहत कार्य जरूर खोले गये, पर उन कार्यों से जो भी कार्य हुआ वह बेकार हुआ है। पहले

(श्री लूणाराम)

तो सड़कें बनायी गयी है वह पूरी तरह से निर्माण भी नहीं हुई कि अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये गये। इसलिये कई जगह सड़कें अधूरी पड़ी हैं। और जो अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण हुआ, उसमें करोड़ों रुपये का घोटाला हो गया है। और जितना काम हुआ है उससे कई गुना ज्यादा राज्य सरकार के धन का दुरुपयोग हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण चूरू जिले का दूं। एक सड़क जो कि आडसर से पूनरासर 43 किलो मीटर बननी थी वह सिर्फ 30 किलो मीटर ही बनी पर उसका पेमेंट 43 किलो मीटर सड़क का ठेकेदारों को किया गया है। और अध्यक्ष महोदय, जिन मजदूरों ने इस सड़क पर काम किया था, उस पर कोई पेमेन्ट मजदूरों को नहीं किया गया है। आज तीन तीन साल हो गये हैं पर मजदूरों को मजदूरी ठेकेदार द्वारा नहीं दी गयी है। स्थिति यह है कि ठेकेदार ने पेमेन्ट उठा लिया है। इस सड़क के अन्दर लाखों रुपये का घोटाला किया गया, उसकी शिकायतें राज्य सरकार को की गयी, पर कार्यवाही नहीं की गयी। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा निवेदन है कि ठेकेदारों के खिलाफ भी शिकायतें आये उसकी जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से नहीं करवा कर कलेक्टर या एस० पी० या दूसरे एस० डी० ओ० वगैरह से करानी चाहिये। इससे तो कार्यवाही हो सकेगी अन्यथा ठेकेदार लोग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मिले हुए होते हैं और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी उन्हें हमेशा बचाते रहते हैं। आज अध्यक्ष महोदय, जो चूरू जिले में अकाल राहत कार्य हुआ था, उसमें लाखों रुपये का ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। इसके लिए मैं आपके मारफत राज्य सरकार से चाहूंगा कि वह दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करें। इसी प्रकार जो सड़कें बनानी थीं जैसे लिखमीसर से कातर तक उसमें भी लाखों रुपये का पेमेन्ट हो गया है पर असलियत में उसमें लाखों रुपये का पेमेन्ट तो हो गया पर सड़क नहीं बनी। मिट्टी तक भी नहीं डाली गयी और सड़क का निर्माण का पैसा उठा लिया गया। और इन सभी बातों के लिए जिम्मेदार है उस वक्त एक सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर बीकानेर जिनके खिलाफ कार्यवाही तो नहीं हुई बल्कि राज्य सरकार ने उन्हें प्रमोशन दे दिया। इस प्रकार आज दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और राज्य के धन का दुरुपयोग ठेकेदारों और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इससे ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर आप उसके लिए शिकायतें करते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी अपने पुराने घोटालों को छिपाने में लगे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि सड़कों का निर्माण नहीं हो सका। जनता को परेशानी होती है पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, चूरू जिला धोरा धरती है और इस क्षेत्र में आने के साधन नहीं है, इसलिए सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, डूंगरगढ़ से बीदासर सड़क का ठेका दिये हुए डेढ़ पौने दो साल हो गए हैं पर वह काम भी पूरा नहीं हो सका। जो काम एक साल में पूरा होना चाहिए था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि इस काम के लिए दो ठेकेदारों को ठेका

(श्री लूणाराम)

दिया गया, एक ने तो कार्य करना शुरू कर दिया पर दूसरे ने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि काम ठेकेदारों द्वारा न कराया जाकर राज्य सरकार को चाहिए कि खुद ही विभाग द्वारा करायें। अध्यक्ष महोदय, ये ठेकेदार लोग बहुत ही गुरु होते हैं अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अफसर उन्हें कुछ कहते हैं तो वो ठेकेदार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को डांट कर कहते हैं कि अगर आपने कुछ किया तो हम आपके पुराने कामों का भण्डाफोड़ कर देंगे। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि काम ठेकेदारों से नहीं कराया जाये और जो कार्य ठेकेदारों द्वारा कराये जा रहे हैं उन्हें तुरन्त बन्द करवा कर राज्य सरकार विभाग द्वारा ही कराये जाने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, इस जिले की सड़कों का विकास किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है और इसके लिए पुरानी सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए वे नयी सड़कें बनाई जानी चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सवाई से लूणकरणसर की सड़क पर जो डामर होनी चाहिये वह पूरी कराई जानी चाहिए। आज उस सड़क की ऐसी स्थिति है कि ज्यों ज्यों आगे सड़क बनती गयी त्यों त्यों पीछे पीछे डामर हटता ही गया इस प्रकार का काम हो रहा है यह तो कार्य उस प्रकार से हो रहा है जिस तरह कि हम प्याज के छिलके को उतारते रहते हैं और उसके नीचे पत्ता निकलता रहता है और उसका अन्त भी नहीं होता है। यही हाल इनका है आज स्थिति ऐसी है कि अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत की जाती है तो विभागीय अधिकारियों द्वारा ही उन्हें बचाने का प्रयास किया जाता है और इस प्रकार मामले को दबा दिया जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो भी जांच करायी जाये वह सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं करायी जाकर दूसरे कलेक्टर्स, एस. डी. ओज. वगैरह से करायी जानी चाहिये। दूसरे सड़कों के लिये जो पेमेन्ट ठेकेदार को किया जाता है उसके लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि ठेकेदार को पहले कलेक्टर्स और ट्रान्सपोर्ट अधिकारियों से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और जब वे सर्टिफिकेट दे दे कि हां रोड़ बनी है और ठीक है तो ही पेमेन्ट किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे इलाके में सड़कें नहीं हैं और जनता काश्तकारों को अपना माल लाने लेजाने में बड़ी असुविधा होती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि नयी सड़कें बनायी जायं ताकि जनता को राहत पहुंचे। एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा वह है डूंगरगढ़ से कातर वाया बाना जो बन रही है यह सड़क बननी जरूरी है। उस सड़क के बनने से न ही उस तहसील को ही फायदा होगा पर उसका फायदा पूरे जिले की जनता को मिलेगा। इस प्रकार पड़िहारा से भीमसर तक की सड़क भी बननी चाहिये। आज जोधपुर से मकान बनाने के पत्थर की पट्टियें आती हैं और आगे तक जाती है लेकिन सड़कों के अभाव में जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बा समय नहीं लूंगा और थोड़े में ही निवेदन कर दूंगा। तो यह निवेदन कर रहा था कि अगर यह

(श्री लूणाराम)

सड़कें बन जायं तो जोधपुर से जो पत्थर आता है उसको लाने लेजाने में काफी सुविधा रहेगी। इसी प्रकार डूंगरगढ़ से लूणकरणसर सड़क वाया कालू को बनाना बहुत ही आवश्यक है। वैसे लूणकरणसर से कालू तक सड़क तो है पर वह अगर श्री डूंगरगढ़ तक चली जाये तो काफी जनता को राहत पहुंचेगी। अध्यक्ष महोदय, एक 3 किलो मीटर का टुकड़ा है रेलवे स्टेशन बिग्गा से नैशनल हाइवे नं 11 उसका बनाना अत्यन्त ही आवश्यक है। पहले इसका ठेका दिया गया था पर बाद में यह ठेका कैन्सल कर दिया था कि यह कार्य नैशनल हाइवे नम्बर 11 के तहत में दिया था जो उसके एरिया में आता है इसलिये राज्य सरकार इस कार्य को अपने बजट से हाथ में ले सकती क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इस बारे में ऐतराज करता है।

इसके साथ बीकानेर के सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर ने जवाब दिया था इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा इस छोटे से टुकड़े को शामिल किया जाय तो गांव के बीच में जाने में और स्टेशन पर जाने में सहूलियत हो सकती है। सरदारशहर से नोहर की सड़क बनाने की आवश्यकता है और सारे फैमिन का जो काम पत्थर का हुआ वह बेकार पड़ा है। इस काम को हाथ में नहीं लिया गया तो सारा काम चौपट हो जायगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा, मूमासर से पड़िहारा वाया लाडूसर जो काम हुआ है—इस काम को प्लान में लेकर शुरू करवाया जाय तो एक तहसील से दूसरी तहसील और एक गांव से दूसरे गांव को मिलाने का अच्छा तरीका हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार आज हमारी पंचायत समितियों के अन्दर जो निर्माण काम हुआ है इस विभाग द्वारा अगर सहयोग होता उनकी भी मदद होती तो काम अच्छा होता। मैं निवेदन करूंगा पंचायत समितियों के जितने निर्माण कार्य हैं वे इस विभाग के असहयोग के कारण ठप्प पड़े हैं। आज कोई भी पंचायत समिति निर्माण काम कराना चाहे तो उसे इस विभाग के प्लान की, इस विभाग के एस्टीमेट की आवश्यकता पड़ती है। आज तो केवल सरकार ने जिला परिषदों को ही ओवरसियर दे रखा है पर जिला परिषदों में होते हुए भी सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि मैं निवेदन करूं चूरू जिले में सिंचाई का कोई कार्य नहीं है पर जो ओवरसीयर पधारे हैं सारा काम उनके थ्रू होता है जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग में होता था। मैं निवेदन करूंगा ए. इ. एन. का जो काम है वह एक्स.इ.एन. के मार्फत होना चाहिये-ओवरसीयर का कोई उपयोग नहीं है। ओवरसीयर, ए. इ. एन, एक्स. इ. एन. ये सारी पोस्टें विभाग को खत्म कर देनी चाहिये। इसी प्रकार हमारे डूंगरगढ़ में सड़कों का काम बहुत है। पर सारा काम होते हुए ए. इ. एन. सरदारशहर को हैडक्वार्टर है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा ए. इ. एन. की पोस्ट डूंगरगढ़ में स्थापित की जाय। भादरा-सादुलपुर की सड़क का आवश्यक कार्य है पर वह भी बीच में ठप्प पड़ा हुआ है। आज उस सड़क पर कुछ काम नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा वह शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाया जाना चाहिये। इसी प्रकार दूसरी बात जो सड़कों के नाप तौल के बारे में कही जाती है वह मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं।

(श्री लूणाराम)

अब मैं आपसे यह निवेदन करूंगा इसी प्रकार बीकानेर से आगरा सड़क है वाया रतनगढ़ उस सड़क पर ट्रैफिक बहुत बढ़ चुका है और आदमियों का उस सड़क पर से निकलना मुश्किल है और वह सड़क प्लान के मुताबिक जितनी चौड़ी बननी चाहिये थी वह बीकानेर से गुसाईंसर तक नहीं बनी इसलिए जितना क्षेत्र गुसाईंसर से रतनगढ़ तक पड़ता है उसे प्लान के मुताबिक बनाया जाय ताकि उस बढ़ते हुए ट्रैफिक से लोगों को परेशानी न हो। इसी प्रकार मैं निवेदन करूंगा कि किसान की जमीन सड़कों के बीच में आ जाती है उसका मुआवजा नहीं दिया जाता है और उन पर सड़कें बना ली जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा जो जमीनें सड़कों के बीच में आती है चाहे वह किसी भी रूप में आये और किसी भी विभाग के अधीन आये—किसान की जमीन सदैव सदैव के लिये खतम हो जाती है इसलिये ऐसी जमीनों का मुआवजा दिया जाना चाहिये। इसके साथ साथ निर्माण विभाग का काम यह भी था कि 20 साल के अन्दर एक गांव को दूसरे गांव से और एक तहसील को दूसरी तहसील से जोड़े बिना सड़कों से ही छोड़ेंगे पर आज उसकी रूपरेखा क्या है—इसका भी जिक्र स्पष्ट नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा यह 20 साला प्रोग्राम आपका कब लागू होगा और 20 साला प्रोग्राम के बारे में जिला परिषद् और पंचायत समितियों में प्रतियां रख कर स्पष्ट करें। जहां पर कम से कम एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने की बात हो उसे अवश्य जोड़ना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री लूणाराम : अब मैं इतना कह कर ही समाप्त करूंगा स्टेशनरी व प्रेस विभाग की जो मांग प्रस्तुत है आज पंचायत समितियों या अन्य संस्थाओं में सरकारी फार्म वितरित किये जाते हैं उसमें एकरूपता होनी चाहिये। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर सब में एक समान उपलब्ध होने चाहियें सारी जगह सरकारी प्रेसें हैं लेकिन वहां उन फार्मों के मिलने की असुविधा रहती है। सब जगह एक से फार्म उपलब्ध होने चाहिए। उन क्षेत्रों में फार्म न मिलने से अधिकारियों को भेज कर मंगाने पड़ते हैं उससे अनावश्यक खर्च बढ़ता है और अनावश्यक समय बेकार जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सब जगह फार्म उपलब्ध होने चाहियें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री गौरीशंकर।

श्री गौरीशंकर मुनीम (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 28 के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। निर्माण विभाग के विषय में सदन के सब माननीय सदस्य काफी प्रकाश डाल चुके हैं और मुझे पीछे वाली बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं है। मैं केवल खास मुद्दों की बात पर ही माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। मैं झालावाड़ क्षेत्र के खानपुर क्षेत्र से चुनाव लड़कर आया हूं। यह क्षेत्र ऐसा है कि जो 15 साल तक विरोधी पक्ष के हाथ में रहा है। माननीय मन्त्री महोदय सोचें मैं किस मुसीबत से वहां से जीत कर आया हूं। मैं खासतौर से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो

(श्री गौरीशंकर मुनीम)

सड़कों का हाल हो रहा है और वहां की जनता ने किस शर्त पर वोट दिया है उसके विषय में मैं माननीय मन्त्री महोदय को आगाह करना चाहता हूं सड़कें बहुत खराब हो रही हैं और अभी 3·4 रोज पहले मन्त्री महोदय ने फरमाया था कि आपके खानपुर की सड़कों के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। मुझे विश्वास है जरूर माननीय मन्त्री महोदय विचार करेंगे। परन्तु मैं इस विषय में 2-4 बातें फिर माननीय मन्त्री महोदय के सम्मुख रखना चाहता हूं वह यह है कि मोई से अरनिया तक जो जो सड़क जाती हैं वह इतनी खराब हो रही हैं जिसकी कोई हद नहीं। इस बरसात में रास्ते बन्द हो जायेंगे। बारां से झालावाड़ सड़क जो मोई से आती है वह इस बरसात में खानपुर से सारे रास्ते बन्द हो जायेंगे। खानपुर से साडोका का गांव बीच में पड़ता है। वहां पर तीन-चार हजार की आबादी है। अब अगर वहां पर सड़क खराब हो जाने से कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो वे बेचारे बड़ी मुसीबत में पड़ जायेंगे। मैं समझता हूं मन्त्री महोदय ने जरूर फरमा दिया है परन्तु इतनी लम्बी चौड़ी सड़क कैसे ठीक हो जायगी, यह मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं निवेदन करूं यह सड़क ऐसी बननी चाहिये जो कम से कम पांच साल तो चले। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार बजट में पैसा पूरा रखती है सड़कों के बारे में फिर भी सड़कें एक साल भी नहीं चल सकतीं, इसका क्या कारण है? इस कारण के ऊपर कोई पहुंचा नहीं है। मैं खासतौर से निवेदन करूंगा कि सड़कें जो बनाई जाती है, उनके ऊपर पूरा पैसा नहीं लगता। गिट्टी जबकि 9 इन्च की रखी हुई है तो फिर गिट्टी 6 इन्च भी नहीं डलती है और तीन-चार इन्च गिट्टी बच जाती हैं, इसलिए वे सड़कें एक साल से ज्यादा नहीं चलती हैं। अगर पूरा मेटेरियल डल जाये तो फिर इन्जीनियर्स को खाने के लिए पैसा कहां से मिले। बस यही एक रास्ता है कि माल पूरा नहीं डालते और हिस्सा पूरा कर लेते हैं। माननीय मन्त्री महोदय यह नहीं समझें कि मैं कोई शिकायत कर रहा हूं। मुझे आप में पूरा विश्वास है और विश्वास के साथ कहूंगा कि जो कुछ हम कहेंगे उसका निराकरण करेंगे। इन इन्जीनियर्स का क्या भरोसा रखें। बस इनके खाने का एक ही जरिया है कि पूरा माल नहीं डलाते हैं और सड़क साल भर भी नहीं चलती है जब कि वे कम से कम पांच साल चलनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि आप यह समझें कि कोई शिकायत आये तो इन्जीनियर्स का तबादला कर दें इससे कुछ नहीं होने वाला है। इनका क्या होगा कि यहां से जायेंगे तो दूसरी जगह खा जायेंगे और वहां दूसरी जगह वाला आयेगा तो यहां भी खायेगा। इसलिए इसको मिटाना बड़ा मुश्किल नजर आता है। इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन सड़कों पर काफी ट्रक्स चलते हैं और उनसे लाखों रुपया हमको टैक्स के बतौर मिलता है लेकिन समझ में नहीं आता कि वह पैसा सड़कों के ऊपर क्यों नहीं लगता है क्योंकि वह पैसा सड़कों के नाम से आता है क्योंकि उनसे टैक्स लिया जाता है अगर पैसा लगता है तो मैंने दशा बता दी कि सड़कों की यह दशा होती है। इसलिए मुझे निवेदन करना है कि मुझे

(श्री गौरीशंकर मुनीम)

लम्बा चौड़ा भाषण नहीं देना है सिर्फ यही कहना है कि न तो मैं आपसे कभी किसी इन्जीनियर के तबादले के लिए कहने आया और न कभी किसी ओवरसियर के तबादले के बारे में आया क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी का भी तबादला करायेंगे तो फिर वैसा ही आजायेगा, क्योंकि इनकी तो आदत पड़ गई है तो मेरा निवेदन यह है कि माफ करना मैं देशी आदमी हूं क्योंकि मैं काबिल तो हूं नहीं, स्पीकर हूं नहीं, वकील हूं नहीं–इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि हाउस मेरी बात पर ख्याल न करे मेरा निवेदन यह है कि मैंने बताया कि सड़कों का यह हाल है मैं समझता हूं कि पुलियायें तो रेल्वे की बनती हैं और वह ऐसी बनती हैं कि वर्षों तक चलती है और अपनी पुलियाओं के बनाने के लिए उतना ही पैसा दिया जाता है फिर भी साल भर में ही खतम हो जाती हैं और उनकी पुलियाओं का कुछ नहीं बिगड़ता। आप सोचें कि ऐसा क्यों होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज ही बोलने का मौका दिया है इसलिए थोड़ा और बोलने दिया जाये। मैं सुझाव रख रहा हूं कि मंत्री महोदय और सारा हाउस मान लेगा कि वह ऐसी चीज है कि जो हमारे देश के लिए फायदेमन्द है······

श्री अध्यक्ष : देश के फायदे की बात आप जरूर कहें।

श्री गौरी शंकर : तो मेरा निवेदन यह है कि कम से कम एक बात कहूंगा और फिर समाप्त करूंगा। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप यदि चैंकिग कराने के लिए किसीं को भेजेंगे तो उन्हीं को भेजेंगे जो कि एस्टीमेट बनाते हैं– इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये इन्जीनियर्स और ओवरसीयर्स सब मिले हुए हैं। अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस चैंकिग का तरीका यह है सड़कें अगर पांच साल नहीं चलें तो मेरे कान पकड़ लेना क्योंकि अभी तो पांच साल मैं यहीं पर हूं। सड़कों पर पूरा मेटेरियल डले और सड़क पर मान लीजिए जब 20 मील का टुकड़ा बन जाता है तो उसको उखाड़कर देखें किसी भी जगह से कि गिट्टी पूरी है या नहीं, मैटल पूरा है या नहीं और यह नहीं कि पहले से ही इन्जीनियर कह दें कि फलां जगह जाऊंगा, मर्जी आये जहां चैकिंग कर लो चैंकिग इस तरह करें कि जो सड़क बनकर कम्पलीट हो गई हो उसमें किसी जगह से 20 बाइ 20 फुट को खुदाकर देखें कि एस्टीमेट के मुताबिक मैटिरियल डला है या नहीं। अगर पूरा मैटीरियल नहीं डला हो तो ओवरसियर व इंजीनियर को सस्पेंड कर उनसे जवाब तलब किया जाय और फिर देखें कि पांच साल तक सड़कें चलती हैं या नहीं। तो मेरा निवेदन यही है कि जब सड़क बन जाये तो पेमेन्ट तब दें जब कि आप चैक कर लें। यह तो है नहीं कि आपको रोज ही जाकर चैक करना पड़े, जब काम पूरा हो जाय तो आप चैक करो किसी भी रोज। इससे लोगों को भी डर होगा, इन्जीनियर्स को भी डर होगा, ओवरसीयर्स को भी डर होगा। बस मेरा यही निवेदन है। फिर कभी मौका आयेगा तो बोलूंगा।

जयहिन्द!

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रकुमार !

श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे जिला डूंगरपुर की रोड्स के बारे में कटौती के प्रस्ताव हैं। जिला डूंगरपुर राजस्थान के अन्य जिलों से पिछड़ा हुआ जिला है और इस जिले में 80 प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं। पिछले तीन चार वर्षों में जो अकाल पड़ा उस अकाल में डूंगरपुर जिले में रिलीफ के द्वारा कई सड़कें बनी हैं, कई सड़कों पर आज बसें भी चल रही हैं लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं कि जिनको मेटल रोड़ बनाना बहुत जरूरी है। ये रोड्स गुजरात के बोर्डर से लगी हुई हैं और इधर मध्यप्रदेश को जाने वाले रास्ते हैं वह मिलते हैं, इस तरह से कुछ दूसरी रोड्स हैं वह उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों को मिलाती हैं। तो अध्यक्ष महोदय; मेरा आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि डूंगरपुर जिले में जितनी भी रोड्स हैं उनको पक्का बनाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि आज हम समाजवाद का नारा लगाते हैं। समाजवाद तब आयेगा जब पिछड़े इलाकों में जो सड़कें हैं उनके द्वारा एक गांव से दूसरे गांव को मिला दिया जायेगा। इससे किसानों को लाभ होगा तभी समाजवाद आ सकता है। डूंगरपुर जिले में कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनको पक्की बनाना बहुत ही आवश्यक है। डूंगरपुर से थाना और थाना से मेवाड़ रोड जो कि गुजरात से मिलाती है इसको पक्की बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि गुजरात से भी बसें आती हैं और डूंगरपुर की बसें गुजरात को जाती हैं। इसलिए इस रोड़ को पक्की बनाना बहुत जरूरी है। इसी तरह से सागवाड़ा से प्रतापगढ़ वाया सरोदा, साबला होकर रोड़ जाती है, बरसात में गाड़ियां रुक जाती है और बीच में दो बड़ी नदियां माही और सोम पड़ती हैं और इन नदियों पर लाखों रुपया खर्च करके पुल बने हैं लेकिन इसके अलावा छोटा पुल बनाना चाहिए और अगर नहीं बना तो सागवाड़ा से साबला और प्रतापगढ़ रोड जाती है उसके ऊपर चार बसें चलती हैं और बरसात में तीन-चार महीने वह बसें बन्द रहती हैं और नदियों पर पुल होते हुए भी जनता को इसका लाभ नहीं मिलता है, इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि सागवाड़ा से प्रतापगढ़ वाया सरोदा, साबला रोड जाती है उसको पक्की बनाई जाये। और

(3 38 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके पुल को बनाया जाये। इसी तरह से मांडव माइन्स, पाडवा, करियाना, बड़ी पादिड़ी यह रोड 20 मील पक्की बन गयी है और माइन क्लोराइड की खान भी बीच में पड़ती है और वहां पर मजदूर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। उस रोड पर 6 पुलिया की जरूरत है और वह बन जायेगी तो उस रोड पर बसें चलेंगी। इस रोड के चारों तरफ बड़े बड़े गांव हैं और उन गांवों में बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं लेकिन बरसात के दिनों में उनको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को अभी थोड़ा सा ही टाइम मिला है, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, आप मुझे माफ करेंगे।

तो उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर से मांडवा माइन्स सड़क पर छः पुलिया बना

(श्री महेन्द्र कुमार)

दी जावें तो इससे बसें चलेंगी और मांडवा माइन्स पर जितने भी मजदूर जाने वाले हैं वे मजदूर बस में बैठकर जायेंगे और आयेंगे। इसके साथ साथ अन्य गांव हैं, मांडवा, भासोवा, कोटापुरा आदि इन गांवों के लोगों को भी डूंगरपुर आने जाने की सुविधा मिल जाएगी। बरसात में तीन चार महीने तक इन गांवों के लोगों को दस दस माइल तक पैदल चल कर जाना पड़ता है। पहले रिलीफ में काम हुआ था और काफी पुलियां बनी थी और अर्थ वर्क भी शुरू हो गया था। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि मांडवा माइन्स तक मैटल रोड बनायी जाय, क्योंकि यहां पर रिलीफ का भी काफी मैटिरियल पड़ा हुआ है और हजारों लाखों रुपये का मैटिरियल इकट्ठा किया हुआ है, उस मैटिरियल को आज गांवों के लोग अपने मकान बनाने के लिए या अन्य कामों के लिए बैलगाड़ियों द्वारा उठा कर ले जाते हैं और मैटिरियल को खराब कर रहे हैं। तो यहां मेरा निवेदन है कि इस रोड को मैटल रोड बनाया जाय।

इसके साथ साथ बाबू खानपुरा रोड है यह बीस, पच्चीस मील की सड़क है जिस पर बसें चल रही हैं, इस पर रिलीफ में कुछ पुलियां बनी थीं वे टूट फूट गई हैं। इन पुलियों की रिपेयरिंग हो जावे तो रूट चल सकेगा और लोगों को उससे लाभ मिलेगा। क्योंकि डूंगरपुर जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है। इस जिले के अन्दर आदिवासी बसते हैं लेकिन फिर भी उनके गांवों में जाने आने की रोड्स पर कम ध्यान दिया जाता है क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला राष्ट्रपति के द्वारा ट्राइबल एरिया घोषित किया गया है तो सरकार को भी इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि गरीब लोगों की तकलीफें दूर हो सकें। डूंगरपुर जिले में पैदावार भी अच्छी होती है। यहां पर फ्लोराइट की भी खानें है, सोप स्टोन की भी कई खाने हैं, यहां पर गांवों से आकर लोग अपना धन्धा करते हैं

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

और ट्रकों द्वारा माल रेलों तक पहुंचाते हैं। वहां पर रेल मार्ग भी है। इस तरह से डूंगरपुर जिला सड़कों के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि राजस्थान में कुल 31,527 किलोमीटर रोड बनी उसमें से डूंगरपुर में केवल 707 किलोमीटर रोड है और दूसरे टोंक और झुंझनूं के मुकाबले में बहुत ही कम रोड बनी हैं। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर जो गरीब एरिया है, गरीब एरिया में जितनी भी रोड्स हैं उन रोडों को अच्छा बनाया जाय।

इसके साथ साथ पीड़ से पुनावाडा तक जो गुजरात का मार्ग बनाया गया है उस रोड़ पर पिछले जून महीने में भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी वहां पधारे थे और उन्होंने घोषणा की थी कि यहां पर एक पुल बनाना जरूरी है और वह पुल बनाया जाएगा। तो मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि इस पुलिया को बनाने के लिए सरकार ध्यान दे। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

(श्री महेन्द्र कुमार)

अब इसके साथ साथ दूसरी कुछ और रोड्स हैं जिन पर बसें चलती हैं उन रोड़ों को भी सुधारने के लिए सरकार को ध्यान रखना चाहिए। जहां बसें चलती हैं वहां कम से कम कोई पुलिया खराब हो जाय या अर्थ वर्क थोड़ा सा करना पड़े तो उस काम को (अनवरत-समय समाप्ति सूचक घण्टी) पी. डब्लू. डी. के द्वारा जल्दी से जल्दी कराना चाहिए ताकि वहां जितनी भी बसें उन रोड़ों पर चलती हैं वह बराबर चलती रहेंगी और लोगों को लाभ होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, इस साल जब पाकिस्तान के खिलाफ हम अपनी डिफेंसिव लड़ाई लड़ रहे थे तो मिलिट्री का आपरेशन और मूवमेंट राजस्थान में काफी हुआ। पंजाब में भी मिलिट्री का मूवमेंट और आपरेशन हुआ इस लड़ाई के दौरान। यह ठीक है, मान्यवर, कि इस डिफेंसिव लड़ाई को हमने जीता। उस वक्त जो ब्रिजेज हमको बनाने पड़े और मिलिट्री को जिन सड़कों के मोडिफिकेशन और आल्ट्रेशन की जरूरत थी उनको पी. डब्ल्यू. डी. के आफिसर्स और कर्मचारियों ने बड़ी ईमानदारी से और एफिशियेंटली किया। मगर इतने रिपेयर्स और उसके मेंटीनेंस में जो खर्चा आएगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में है। पंजाब ने अपने एस्टीमेट पेश कर दिए हैं और हमारी सरकार अभी तक कर सकी है या नहीं, यह मैं जानकारी सरकार से चाहता हूं क्योंकि एक डेढ़ माह तक मिलिट्री का मूवमेंट चलता रहा। आप ताज्जुब करेंगे कि हमारे झुंझुनूं के इलाके की सड़कों की हालत ही बदल गई है। नए ब्रिजेज थे उनमें आल्ट्रेशन करना पड़ा, उन पर टैंक्स चलते थे और बड़ी हैवी वेहिकल्स चलती थी, उनके कारण सारी की सारी सड़कों की शक्ल ही बदल दी गई। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार इसके लिए एस्टीमेट सबमिट करेगी और सेंट्रल की जिम्मेदारी है कि इनके रिपेयर्स पर और मेंटीनेंस पर जो हमने खर्चा किया है, वह सेंटर हमें पूरा पैसा दे।

दूसरा, मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि जो सेंट्रल असिस्टेंस का पैटर्न है वह बदलना चाहिए। अब फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के सामने हमारे पी. डब्लू. डी मिनिस्टर साहब अपना केस किस प्रकार पेश करते हैं यह भी जानकारी वे दें।

मान्यवर, इस हाउस में कई बार जो बोर्डर रोड्स हैं, उनके सम्बन्ध में, उनके अन्दर के स्कैंडल्स के बारे में चर्चा हुई थी। इसमें 24·25 करोड़ रुपया खर्च हुआ और उसके बारे में हमें बताया गया था कि सेंट्रल के जो चीफ इंजीनियर पी. डब्ल्यू. डी हैं वे इस मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने अब तक क्या ट्रेस किया, किनकी गलतियां थीं, कितना खर्चा हुआ और कितना स्कैंडल हुआ, कौन आफिसर दोषी है, ये सारे फैक्ट्स हमारे सामने आने चाहिएं। इसके साथ ही, मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे बोर्डर रोड्स पर खर्च का प्रश्न हो, इसमें 56 करोड़ रुपया खर्च हुआ, फैमिन के वक्त पर भी बोर्डर रोड्स पर 24 करोड़ रुपया खर्च हुआ, चाहे और रोड्स के स्कैंडल का सवाल हो, मेटिरियल परचेज के बारे में स्कैंडल का सवाल हो, चाहे आपके डिपार्टमेंट के बारे में कोई

(श्री केदार नाथ)

सवाल हो, उसके लिए आप कोई मशीनरी इवोल्व करें जो आपके डिपार्टमेंट से ऊपर हो। जैसे सेंटर में चीफ टेक्निकल एग्जामिनिर रखा हुआ है ऐसी ही कोई मशीनरी आप यहां पर भी इवोल्व करें जो इस प्रकार के स्कैंडल्स की जांच कर के ट्रेस आउट करें, और फैक्ट्स सामने रखें। उससे आपको भी फायदा मिलेगा। आप इन्क्वायरी करें, चाहे विजिलेंस कमीशन से इन्क्वायरी करावें, चाहे टेक्निकल एग्जामिनर के मार्फत इन्क्वायरी करायें चाहे और किसी मशीनरी को इवोल्वड करें ताकि डेफिनेट जांच हो सके और स्केंडल्स इसके पीछे क्या हैं, यह सामने आ सके।

मान्यवर, इसके साथ ही फर्स्ट फाईव ईयर प्लान से फोर्थ फाईव ईयर प्लान में आउटले कम होता गया है। सैकिंड प्लान में टेन परसेंट आउटले था, थर्ड प्लान में फोर परसेंट हो गया और फोर्थ प्लान में दो परसेंट हो गया। इस तरह से हर प्लान में आउटले का हमारा परसेंटेज कम होता गया और इसलिए हमारा डिस्ट्रिक्टवाइज अन-ईवन डवेलपमेंट हुआ। क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट में नए आए हैं इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप इस ओर ध्यान देंगे। आप इसकी स्ट्रीमलाइन कीजिए। यह डिपार्टमेंट वैसे भी बदनाम है, इसके बारे में चर्चाएं होती रहती हैं, इसलिए इस पर कन्ट्रोल करने की जरूरत है, एक्सपेंडीचर को डिसीप्लीन करने की कोशिश करें, खर्चा कम करें और इसके लिए आप डिपार्टमेंट को टोन-अप कीजिए और जो आपका टोप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके लिए भी आप कोई न कोई फार्मूला इवोल्व करें, एक्सपेंडीचर को डिसिप्लीन करें। आखिर यह इतना बड़ा डिपार्टमेंट किस बात के लिए है।

दूसरी बात, मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि सेंटर ने जब यह बिल पास कर दिया कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाय। आप जानते हैं कि 15 से 25 परसेंट तक ठेकेदार कमाते हैं इस काम में। आखिर वह दिन कब आने वाला है जब यह ठेकेदारी प्रथा समाप्त होगी और जो पैसा लगता है वह हमारे अपने रेवेन्यू को आगमेंट करने में लगेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना काम शुरू कीजिए ताकि लेबर को पार्टीसिपेशन मिले, एडमिनिस्ट्रेशन टोनअप हो और जो पब्लिक का पैसा है वह अपने काम में आवे। आखिर यह कब होगा। आज लेबर के झगड़े हैं। मैं पब्लिक सेक्टर के सम्बन्ध में निवेदन करता हूं कि आप तो कम से कम लेबर का पार्टीसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में दें, किसी लेवल पर तो दें ताकि उनके ग्रिवेंसेज दूर हो सकें और वे यह समझ सकें कि वे अपना काम कर रहे हैं। एक टेबल पर आकर बैठें, उनके ग्रिवेंसेज दूर हों, उनकी डिमाण्ड्स के बारे में चर्चा हो, उनका अपना पार्टीसिपेशन हो। तो यह सब आप अपने पब्लिक सेक्टर में तो कीजिए। ये मैंने कुछ मुद्दे जनरल पीलिसीज के बारे में आपके सामने रखें हैं, जिन पर आप विचार करें और इनके बारे में अपनी बात रखें।

अब मैं हमारे झुंझनू जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर। हमारे ज़िले के दो माननीय सदस्यों ने चर्चा की है वहां की सड़कों के बारे में। अभी यहां पर एजेन्डे के पार्ट-ए में सड़कों के बारे में चर्चा

(श्री केदारनाथ)

हुई थी और जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया और सड़कों के ठेके देने के सम्बन्ध में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट और हनुमानगढ़ में जीरो से थर्टीन किलोमीटर तक की सड़क बनाने में जो गड़बड़ी हुई उसके बारे में यहां एलीगेशन्स लगाए गए। मैं यह मानता हूं कि अगर कोई एलीगेशन्स लगाए जाते हैं तो उसका कुछ आधार होना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि ट्रांसफर्स होवर हैड हुए उसमें कई व्यक्तियों के ट्रांसफर हुए, एस. ई. का ट्रांसफर भी हुआ, एक्स.ई.एन. और ए. ई. एन्स. के ट्रांसफर भी हुए लेकिन उससे टैटर तो क्रियेट होता है। एक व्यक्ति जयपुर आये और ट्रांसफर करवा कर ले जाए। चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्ति हो क्या उसका स्थान है उसकी पार्टी में, मंत्री से उसका कितना एशोसियेशन है, यह नहीं देखना चाहिये। मैं समझता हूं कि डिपार्टमेंट अपने आप इस चीज को सोचेगा। कई सड़कों के नाम लिये गये हैं, इन केसेज की जांच आप अपने चीफ सेक्रेटरी से, विजिलेन्स कमिश्नर से करवा दीजिये ताकि ये सारी चीजें साफ हों मैंने यहां पर यह बात रखी है कि पी.डब्ल्यू. डी. के बारे में चर्चाएं होती हैं, वे बुरी चर्चाएं हैं। इसकी ओर देखना चाहिये। एक टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, इसमें जितना खर्चा हो रहा है उसके बारे में आप एक कमेटी बनावें। बोर्डर रोड्स के बारे में जांच हो रही है, इसका कोई जिक्र नहीं आया है अब तक कि कौन व्यक्ति इसके लिए दोषी था और उसने कितना रुपया वेस्ट किया। इसकी जांच होकर इसका सारा पिक्चर हमारे सामने आना चाहिये। यह परफारमेन्स बजट आपने दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप नये मंत्री आये हो, एक क्रिटीकल व्यू पेश किया जाना चाहिये हमारे सामने कि अब तक इतना पैसा खर्च हुआ बोर्डर रोड्स पर, अन्य रोड्स पर, फेमिन रोड्स पर, उसमें इतने इतने स्केन्डल हुए, डिस्ट्रिक्टवाइज इतना इतना अलाटमेंट किया गया। ये सारी चीजें हमारे सामने आनी चाहिये ताकि राजस्थान में पी. डब्ल्यू. डी. विभाग का यह कार्य हुआ है। ऐसी क्रिटीकल प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें मिले, ताकि हमारी आलोचना करने का स्टेन्डर्ड भी सुधरे। हमें भी यह मालूम होगा कि राजस्थान में कितना खर्चा हुआ है, उसका एक क्रिटीकल व्यू हमारे सामने होगा। तो ऐसी रिपोर्ट हमारे सामने आनी चाहिये।

इसके अलावा एक बात और है। फोर्थ प्लान में रोड्स के बारे में चेप्टर है। यह कहते हैं कि स्टेट्स टाइम के अन्दर एस्टीमेट्स पेश नहीं करते हैं और इस कारण उनको सेंक्शन करने में डिले होती है और इसीलिये आपको भी प्रोग्रेस में डिले होती है। 2–3 महीनों में एस्टीमेट्स पेश करते हैं और पैसा मिल जाता है और फिर तीन महीने रह जाते हैं और उसमें ही यह खर्च करना जरूरी होता है। तब हेपहैजर्ड वे, अनियमित रूप से वह पैसा खर्च किया जाता है। उसको खर्च करने के लिये कोई एप्रोच नहीं होती है। इसका एक इन्टीग्रेटेड एप्रोच होना चाहिये। इसलिये आपको टाइमली एस्टीमेट्स सबमिट करना चाहिये ताकि आपको भी टाइमली पैसा मिल सके और काम हो तो वह भी ठीक हो। गंगानगर जिले में 15 जनवरी से 30 मार्च तक 15/20 लाख का पेमेंट किया गया। वहां पर इतना लेबर नहीं मिल सकता, इतना माल नहीं मिल सकता, इतने ट्रक नहीं मिल सकते यह एक क्लीअर केस है, इसमें स्केन्डल है।

(श्री केदारनाथ)

मुझे यह मालूम पड़ा कि किसी एक व्यक्ति ने वहां के आफिसर को ट्रंक किया पेमेंट करने के लिये। जयपुर में यह व्यक्ति कौन है जो ट्रंक पर यह आदेश देता है कि फलां फलां व्यक्ति को पेमेंट कर दो। ये सारे केस प्राइमा फेसी मालूम पड़ते हैं। अगर इनकी जांच नहीं की गई तो लोग यह कहेंगे कि आज एक आदमी का राज्य है। मैंने यह निवेदन किया है और मुझे यह विश्वास है मैंने यह नहीं कहा है किसने तो चंदा लिया है और और किसने चन्दा दिया है, परन्तु मैं यह मानकर चलता हूं कि मेरे इस निवेदन पर आप लाजमी तौर पर गौर करेंगे।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुद्रणालय के बारे में कहना चाहूंगा। दो मिनिट में समाप्त करता हूं। तीन तरह के सर्विस रूल्स यहां पर लागू हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि 1-11-57 के पहले काम करने वालों पर राजस्थान सर्विस रूल्स लागू है और 1-11-67 के बाद जो काम करते हैं उनको टैक्निकल, मैकनीकल और दूसरे नियम लागू होते हैं और उसके बाद वालों पर फैक्टरी लॉ लागू होते हैं। आप इन इम्पलाइज पर एक ही प्रकार के रूल लगाइये। इनको एक ही प्रकार के रूल्स से गवर्न करिये। उनकी यह मांग है और मुख्य मन्त्री ने यह कहा था कि आप इनमें से किसी एक को आप्ट कर लीजिये। उन्होंने इसको आप्ट कर लिया है। उनके लिये राजस्थान सर्विस रूल्स बेनीफिसियल है। इसी तरह से रिक्रूटमेंट का सवाल है। आप ताज्जुब करेंगे कि जिस तरह का पेटर्न बनाया गया है, डी.पी.सी. 65 से पहले बैठी थी और उसके बाद आज तक नहीं हुई है। एक ही बार बैठी फिर किस तरह से प्रमोशन कर दिये गये हैं। इसी तरह से मशीनरी का सवाल है। मैटेरियल का सवाल है। हमारे यहां हाउस में, हम देखते हैं कि जो रिपोर्टिङ्ग होती है उसका जो कागज है, वह अच्छी क्वालिटी का नहीं है। उस पेपर पर चार कापियां ही निकल पाती है। मैटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं है। जो सेम्पल परचेज कमेटी तय करती है, उसके अनुसार सामान नहीं आता है। इस प्रकार इसमें स्कैन्डल है। इसको भी देखना चाहिये जो वहा के कर्मचारियों की मांग है कि उन पर राजस्थान सर्विस लागू किये जाये, सारे राजस्थान के इम्प्लाइज को एक ही कैडर में रखा जाये। उन इम्पलाईज को प्रमोशन मिलना चाहिये। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बनाई जानी चाहिये और 50 परसेंट प्रमोशन और 50 डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट इनके लिये रखना चाहिये, मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में घोषणा आज ही मंत्री महोदय कर देंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल जयपुर): माननीय उपाध्यक्षजी, आज सार्वजनिक निर्माण के बारे में बहस हो रही है। इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार जयपुर शहर से मनोरंजन कर के रूप में 30 लाख 67 हजार रुपया प्रति वर्ष लेती है। और दस रुपया प्रति शो, तीन होते हैं, जयपुर में सात सिनेमा हैं। यह नगरपरिषद की आय होनी चाहिये परन्तु नगरपरिषद् को डेढ़ लाख रुपया दिया जाता है। यह कहा जाता है कि राज्य सरकार जयपुर के सड़कों की मरम्मत करती है। यह 183 सदस्यों से सम्बन्धित प्रश्न है। विधान सभा के माननीय

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

सदस्यों को भी इससे असुविधा होती है। इस असुविधा के निवारण के नाते में आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को सुन कर मन्त्री महोदय इसका उत्तर देने की कृपा करेंगे।

आज जयपुर शहर के जौहरी बाजार में, चांदपोल बाजार में, त्रिपोलिया बाजार में, किशनपोल बाजार में, किसी भी मार्ग में सड़क ठीक नहीं है और बाहर के एरियाज में संसार चन्द्र रोड पर जायेंगे तो वहां की हालत भी सोचनीय है। मेरी प्रार्थना है कि जयपुर शहर की मनोरंजन कर की आय आप वसूल करते हैं और आपके विभाग द्वारा इस पर खर्च किया जाता है, और एक बार जयपुर शहर का विकास करने की बात आप कह चुके हैं और यह बात इस सदन के अन्दर भी कही गई है तो इन 15 दिनों के अन्दर जयपुर शहर की सड़कों की मरम्मत कराने का अभियान आप प्रारम्भ करा दीजिये। आमेर के रास्ते के दोनों तरफ नाले हैं और इसकी मरम्मत कराने की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। जो माधोविलास अस्पताल है वहां की हालत खराब है। वहां पर बरसात के दिनों में नहीं जा सकते और कोई न कोई वहां दुर्घटना वहां पर होती रहती है। गणगौरी बाजार वाली सड़क, माधोविलास के पीछे तक की सड़क, सिरेड्योढ़ी बाजार की सड़क जहां पर कि विधायक गण आते रहते हैं। इससे आगे बरसात के दिनों में राम प्रकाश सिनेमा के पास आप देखें आप वहां पर नाव चला सकते हैं, इतना पानी वहां पर भर जाता है। अगर आप वहां जायेंगे तो गाड़ी नहीं चला सकते। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि बड़ी चौपड़ से आमेर के रास्ते तक, चार दरवाजा, मोती कटला तक सड़क पर गड्ढे पड़े हुए हैं। विधान सभा को देखने के लिये बहुत से लोग आते हैं और इसी रोड से आमेर जाते हैं। वे क्या धारणा लेकर जाते होंगे। इस लिये निवेदन है कि इस सड़क को तो आप ठीक करावें। इसके बाद में अनियमितताएं कर रहे हैं वह यह है कि आमेर की सड़क को ऊंचा बना दिया गया है तो उससे जयपुर के लोगों का ऊंचा स्तर तो नहीं हुआ, लेकिन सड़क को ऊंचा तो बना दिया। आपने कहा था कि जयपुर शहर के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करना चाहता हूं, तो जीवन स्तर तो ऊंचा नहीं करेंगे लेकिन आमेर की सड़क को ऊंचा करेंगे। इससे दोनों चौकड़ियों में वर्षाकाल में पानी भर जाता है। सड़क की सतह को ऊंचा करने के लिए गटर लाइन के मेन होल में पानी भरने का ध्यान नहीं करते हुए मेनहोलों को डामर से ढक दिया गया है। इस सारे काम को आप देख लें। घोड़ा निकास रोड का इसी तरह का हाल है। यह गलता रोड का हाल है जो कि एक पर्यटक सड़क है और सार्वजनिक निर्माण विभाग की एक प्रमुख सड़क है। जयपुर शहर में जो भी व्यक्ति आता है वह गलता स्नान करने जरूर जाता है, जिसकी सड़क बिल्कुल खराब है।

दूसरी बात शायद आपको याद होगा कि जयपुर नगर के अन्दर शहर की चौकड़ियों के भीतर की सड़कों की मरम्मत कराने का काम भी लगभग 6 साल पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा था। इस प्रकार की पत्रावली नगरपालिका के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पास में भी है और आपके आफिस में भी होगी इसलिये आप उनको देख लें। जयपुर नगर पालिका की आर्थिक दशा कभी अच्छी नहीं रही और न है कि वह गलियों की सड़कों की मरम्मत करा सके। उनकी हालत यह है कि कोई भला आदमी उन सड़कों पर नहीं चल सकता। सैंकड़ों गड्ढे होते है। गलियों में आपके रिश्तेवार भी रहते होंगे और आप उनसे मिलने के लिए गये होंगे। शहर के परकोटे के भीतर की गलियां जो कि आप को ट्रान्सफर हो चुकी हैं मरम्मत कराने के लिए उनकी मरम्मत करायेंगे, क्योंकि 8 साल हो गये हैं।

इसके बाद में नजूल सम्पति के बारे में भी बराबर जिक्र किया गया है कि वे म्युनिसिपैलिटीज में लगाई जायं। जयपुर, बीकानेर और जोधपुर इन तीनों नगरों में जो नजूल की सम्पति है जो अभी पी० डब्ल्यू० डी० की दुकाने हैं या जो भवन हैं जिनमें रामप्रकाश सिनेमा भी है जो कि पी. डब्ल्यु. डी. की सम्पत्ति हैं जो आपके कृपापात्र श्री हसन चांद को लीज पर दी हुई हैं और ऐसा लगता है कि श्री हसन चांद भी असलमें उनका मालिक हो। नजूल सम्पत्ति जैसा कि कई राज्यों में नगरपालिका को दे दी गई हैं उसी प्रकार से जो नजूल सम्पति, पी. डबल्यु. डो. की दुकानें और भवन हैं वे नगरपालिका को स्थानान्तरित करनी चाहिए जिससे कि उनकी आय का स्रोत बन सके। न तो वे हाउस टेक्स देते हैं और न सरकार को बराबर किराया देते हैं। लाखों रुपयों का पेमेंट सिनेमाओं द्वारा किया जा रहा है, और रामप्रकाश से भी काफी आय आपको होती होगी लेकिन नगरपालिका को एक कौडी आय नहीं होती है। इसलिए आप नजूल सम्पति को नगरपालिका को ट्रान्सफर करेंगे। यह मेरी आप से मांग है।

इसी प्रकार से नाहरगढ़ के किले में एक टांका बना हुआ है। इसके टूट जाने के कारण बाढ़ आई थी और नाहरी के नाके की बस्ती के मकानों में गलियों में मिट्टी भर गई थी और पुरानी बस्ती की भी यही हालत हो गई थी और गलता रोड़ पर यही हालत टांका टूटने से हुई थी। वहां पर टांके बने हुए हैं और गलता रोड़ पर पानी के स्रोतों को रोका गया हैं उनको ठीक करायेंगे, क्योंकि जो कि नाहरगढ़ पर रहने वाले व्यक्ति है, मीणा जाति के लोग हैं उनको लाभ होगा और जो पानी उनको उपलब्ध नहीं होता है वह उनको नहीं मिल सकेगा।

जयपुर शहर के अन्दर कुछ विशेष खण्डहर पड़े वह हैं और उनके मालिक नहीं है। उनके मालिक अब आप हैं तो उन खण्डहरों की मरम्मत कराई जाय और उनमें कोई चित्रकला करानी हो या और किसी प्रकार से उनका उपयोग करना हो, उस तरह से उनका उपयोग करें, क्योंकि जयपुर शहर में जो भी आदमी या पर्यटक आता है वह इस प्रकार के खण्डहरों को देखता हैं तो अच्छा नहीं लगता है।

हम जिस विधान सभा भवन में बैठे हैं उसकी छत पर अभी 10 लाख रुपया खर्च हुआ है और इतना रुपया खर्च हो जाने के बाद भी मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप ऊपर जाकर छत को देखेंगे तो चारों ओर एक लकीर खींची हुई आपको दिखाई देगी और ऐसा लगता है कि

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

वह छत टूट चुकी है और बिल्कुल अलग है। इस प्रकार से 10 लाख की लागत की छत इस विधान सभा भवन की बनी थी उसमें बहुत बड़ी दरार आ चुकी है इसके बारे में आप जांच करेंगे।

एक बार यहां सदन में बातचीत हुई थी, जयपुर शहर की सफाई के बारे में और आप उस समय शायद नहीं थे सेक्रेटेरियेट लेवल पर बात हुई थी उसमें नाहरगढ़ को जो रास्ता जाता है और खजाने वालों का रास्ता है जो कि मूर्तिकला के केन्द्र हैं और मूर्तियां खरीदने के लिए पर्यटक लोग आया करते हैं, उनको ठीक कराने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके पास फण्ड्स आ गये होंगे और आपने इन दो रास्तों की मरम्मत कराने का काम शीघ्र करा देंगे। यह तो जयपुर शहर की समस्या के बारे में हुआ।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं सीमावर्ती सड़कों के बारे में जिनके लिए सन् 1965 से आज तक कई बार जिक्र हुआ इस सदन में। सारी बातें अनियमितताओं की कही गयी थी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गए थे बार बार उनके बारे में। आप अपने भाषण में जो उत्तर आप देंगे कुछ जिकरा उनका करेंगे। जो आरोप विरोधी दल के लोगों ने लगाये थे, सीमावर्ती इलाकों में सड़के बनाई गयी थी उनके बारे में जो आरोप लगाये थे उनके बारे में बाद में क्या हुआ उसकी जनकारी आप दें।

श्री जगनसिंह भूतपूर्व एम. एल. ए. ने एक सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर मि. टी. एस. मेहता के बारे में काफी बातें कहीं थी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है और चीफ मिनिस्टर को भी लिखा है और मेहता साहब के बारे में फाइल भी बनी हुई है। उन्होंने शायद भूख हड़ताल भी की, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई। उनके बारे में क्या कार्यवाही हुई इससे सदन को अवगत करायेंगे। जो 10-15 चार्जेज उन पर लगाये थे, मैं समझता हूं कि अगर उनको पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जायगा, उनके घोटाले तो बहुत हैं लेकिन कोई आयरन की खरीद का मामला है तो कौन से फन्ड से खरीदा गया है उसकी जानकारी दे दी जाय। कई बार उनका जिक्र इस सदन में आ चुका है।

इसी प्रकार से अकाल में भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के मार्फत जितना रुपया खर्च हुआ है और उस रुपये का दुरुपयोग हुआ है इसके बारे में कई बार इस सदन में आपका ध्यान आकर्षित किया गया है। उस संबंध में क्या जांच की गई है वह बताएं। अकाल राहत के कार्य अलवर और बाढ़ राहत के कार्य अलवर में हुए हैं और इसी प्रकार से भीलवाड़े में अकाल राहत के कार्य के पैसों से डाक बगले अलवर में भी और भीलवाड़े में भी बनवाये गये हैं। उस समय रामप्रसादजी लड्ढा इरिगेशन मिनिस्टर थे। उनके क्षेत्र में अकाल सहायता के पैसों से डाक बंगले बनाये गये हैं। इनके बारे में आप सदन को जानकारी देंगे, क्योंकि मुझे जानकारी है कि भारत सरकार से आपको अकाल राहत के कार्य के लिए पैसा मिलता है उसमें से 36 लाख रुपया भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया था वह आपने मन्जूर कर दिया और आपने अकाल राहत कार्यों पर भी उसको खर्च नहीं किया और उस

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

पैसे को डाक बङ्गले बनाने में खर्च किया है। इसके बारे में जानकारी देंगे।

सार्वजनिक विभाग में उद्यान भी आते हैं। जयपुर में एक राम निवास बाग है। आज जयपुर की जन संख्या 5 लाख से ऊपर हो गई है तो उससे काम नहीं चल सकता है इसलिए और भी उद्यान आप बनायेंगे और राम निवास बाग को ठीक प्रकार से बनायेंगे इस प्रकार से यह मेरा निवेदन है।

अब रहा सवाल यह कि जो ठेकेदारी की प्रथा है तो मेरी ऐसी मान्यता है कि इस ठेकेदारी प्रथा को आप समाप्त करेंगे। आप राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। बसों का आप राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं, नाज के व्यापार के राष्ट्रीयकरण की आप बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि ठेकेदारी की प्रथा में जो घोटाले होते हैं कि कितना सीमेंट लगना चाहिए था और कितना लगा और कुछ ही दिनों में सड़कें टूट जाती हैं और यह बात सही है कि कुछ समय बाद तो सड़कों का पता ही नहीं चलता है। दिल्ली में सड़कें बनी उनमें किस प्रकार का मेटेरियल उपयोग में लाया गया है— मैं समझता हूं कि किस दल के द्वारा बनाई गई है, उस सारे दलदल में मैं नहीं फंस कर यही कहना चाहता हूं कि यदि उन्होंने अच्छा काम किया है तो उसका उदाहरण भी ले लें और उस प्रकार से बनवायें। दिल्ली में जिस आधार पर सड़कें बनाई गई हैं वह हम यहां भी कर लें। तो ठेकेदारी प्रथा समाप्त करना चाहिए और इस ठेकेदारी प्रथा का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। क्यों न डिपार्टमेंटली काम कराया जाय। आप रोडवेज को अपने हाथ में ले लें, नाज के व्यापार को अपने हाथ में लेने की बात करते हैं, और कई आप अपने हाथ में लेने की बातें करते हैं जिनका दुरुपयोग होता है जैसा कि हाण्डा साहब ने आरोप लगाया है और बहुत सारी मोटी फाइल मेरे पास में भी हैं। ठेकेदारी प्रथा का राष्ट्रीयकरण करके डिपार्टमेंटली काम करायें तो राजस्थान सरकार इस सारे पैसे का दुरुपयोग कर सकेगी।

इसी प्रकार से भारत सरकार में एक विजिलेन्स सेल बना हुआ है। उस विजिलेन्स सेल में यह होता है कि किसी ने भी शिकायत की कि ठेकेदार मिट्टी मिला रहा है या ठेकेदार गड़बड़ कर रहा है तो वह विजिलेन्स सेल में जाकर दरख्वास्त दे देगा, लेकिन राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यहां पर दो-दो, तीन-तीन बार दरख्वास्त देने पर भी उनको दबा दिया जाता है चाहे ठेकेदार मिट्टी मिला रहा हो, डामर पोत रहा हो या काला पोता ही फेर रहा हो।

इसलिए राजस्थान में भी भारत सरकार के समान ही विजिलेंस सेल बनाने की कृपा करें जिससे किसी को शिकायत हो, कोई सड़क खराब हो, मैटिरियल ठीक नहीं लगाया हो तो वह दरख्वास्त दे सके।

फिर जो पक्षपात हुआ है। एक इंजीनियर को निलम्बित किया गया, और भी कितने ही ऐसे मामले हैं। एक जयपुर में एडीशनल चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग एस. के. कल्ला, उनको निलम्बित कर दिया। उस कल्ला को जोधपुर में नियुक्त करते हैं। कल्ला द्वारा भूमि आवंटन में पद

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

का दुरुपयोग, यह अखबार में 1 अगस्त 71 को छपा है। इसके सम्बन्ध में इस विधान सभा में कई प्रश्न पूछे हैं। यह हो जाने के बाद जो गड़बड़ी हुई, उसके बारे में फोटो-स्टेट डाकूमेंट पेश किये गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एडिशनल चीफ इंजी-नियर अप्पा साहब हैं, वह ईमानदार व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं उनको तो माइनिंग डवलपमेंट में लगा दिया गया, लेकिन जिस आदमी के संबंध में विधान सभा में शिका-यत हुई, जिसके बारे में कई बातें कही गई, उस कल्ला साहब को एडीशनल चीफ इंजी-नियर प्रोजेक्ट बना रखा है। अप्पा साहब का तीन बार ट्रान्सफर हो गया क्योंकि यह देखा गया, कल्ला साहब की जगह आ जाय तो कल्ला को रिवर्ट होना पड़ेगा, इसलिए वह नहीं आ सकते। तो वह रिवर्ट हो नहीं जिसके लिए अखबारों में समाचार प्रकाशित हों, विधान सभा में चर्चा हो, और इसके विपरीत जिनकी ईमानदारी में जनता का विश्वास हो, विधान सभा के सभी सदस्यों का विश्वास हो, जो बड़ा ईमानदार हो उसको यह पद नहीं मिलेगा, बल्कि बेईमान को मिलेगा। जो काम ईमानदारी से करता है, भली प्रकार से काम करता है ऐसे आदमी को आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। और जो आदमी बेईमान है, जिसके बारे में आम चर्चा है, जिसकी आपने जांच करा ली है और मंत्री महोदय, आप मंत्री अभी ही नहीं बने हैं, पुराने मंत्री हैं, इस सदन के अन्दर चीफ मिनिस्टर के बाद में आप ही बड़े जिम्मेदार है, आप उनकी ओर से उत्तर देते हैं, आपको इस संबंध में विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं हमारा फर्ज है कि सरकार के सामने सारी बातें लानी चाहिए, वह ला दी है। मैं समझता हूं कि जब आपका भाषण होगा उत्तर देने के नाते उसमें आप जयपुर शहर के बारे में, सड़कों की मरम्मत आप कब तक करा देंगे, उसकी क्या व्यवस्था करना चाहते हैं, आप सीमा की सड़कों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जगतसिंहजी ने जो कहा, उसके बारे में क्या किया और इसके अलावा अकाल के समय सड़क निर्माण कार्य के बारे में, और भारत सरकार के समान विजिलेंस सेल बनाने की बात कही उसके बारे में और ठेकेदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिए उसके लिए आप कहिए कि क्या करना चाहते हैं। आज लोग समझते है कि इस वर्ष नया मन्त्रिमण्डल बना है, इसलिए अच्छा काम होगा क्योंकि विरोधी पक्ष का डर नहीं हैं, जो आप करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, गरीबी मिटायें या नहीं, समाजवाद लायें या नहीं, यह आप पर है। हम तो केवल जनता के कष्ट, जनता जो महसूस करती हैं, वह सदन में रख देते हैं। मैं समझता हूं कि सूर्य भगवान की दिशा भी आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, आप कह दें कि सूर्य भगवान पश्चिम में उगते हैं तो लड़के को इम्त-हान पास करना होगा तो वह लिखेगा, बहु-मत राजस्थान सरकार, सूर्य पश्चिम में उगता है। पश्चिम में सूर्य उगता है, यह लिखेगा तो पूरे नम्बर मिलेंगे, पूर्व में लिखेगा तो जीरो मिलेगा। ऐसा बहुमत आपको मिला हैं, जी भर भर कर वोट मिले हैं। फिर भी आपको सजग करना विरोधी का कर्तव्य हैं और उस नाते मैंने कहा है। आशा है, अपने भाषण में इन सारी बातों को आप इण्डीकेट करेंगे। सिर्फ यह कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह राठौर।
(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव रखे हैं और उस सम्बन्ध में सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि पिछले दस साल में मेरे चुनाव क्षेत्र में पी. डब्ल्यू. डी. की ओर से कोई काम नया नहीं हुआ। यह बात तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा तो सड़क थी, वह टूट फूट गई हैं, 1962-72 तक का इस विभाग के कार्य का यह इतिहास है, 1962 तक तो मैं गवर्नमेंट में था। उसके बाद मैं इस सदन में नहीं था, उस कारण जो सड़कें मन्जूर हुईं वह खत्म हो गई और जो बनी उन सड़कों की उचित मरम्मत नहीं हुई। पिछले पांच साल से इस जिले के मन्त्री चले आ रहे थे, वह पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर थे, अलवर जिले के थे और तिजारा के रहने वाले थे तो अलवर जिले की दस तहसीलों में से एक उनकी थी, बाकी नौ जो हैं उनकी यह शिकायत थी कि पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर की कान्स्टीट्यूएन्सी में काम हुआ है, और में नहीं हुआ।....

श्री उपाध्यक्ष : उनके साथ शिकायत चली गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां शिकायत चली गई।

एक माननीय सदस्य : सरकार में लेने की सिफारिश कीजिये इनकी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मुख्य मन्त्री को अलवर जिले से ले आये हैं, क्या बात है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हम यह सोचते थे कि इस विभाग के द्वारा अलवर जिले में इम्बेलेन्स क्रियेट हुआ है, एक चुनाव क्षेत्र में काम हुआ और बाकी नौ में नहीं हुआ। मेरे चुनाव क्षेत्र में नौ साल में एक भी सड़क नहीं बनी, एक सड़क, 1967 में जब चुनाव हुआ था, तब मन्जूर हुई थी, उसमें चौदह हजार का काम था, वह काम पूरा नहीं हुआ है। बाकी कोई नई सड़क बनाने का सवाल नहीं है। मैंने जो कट मोशन पेश किया है, वह इसलिए किया है कि अभी जो इम्बैलेन्स कायम है, वह आयन्दा नहीं रहे...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुख्य मंत्री भी अब तो आपके क्षेत्र के हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुख्य मंत्री सारे क्षेत्र के हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तिजारा के।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं पी. डब्ल्यू. डी. की डिमाण्ड पर अर्ज करदूं कि मेरे यहां सड़क बनी हुई है उनकी हालत खराब है, उन पर मोटर चल नहीं सकती। मैंने पांच साल तक शिकायत नहीं की, आज भी मेरा इरादा नहीं था, मेरा नाम भी नहीं दिया गया, वैसे मुझे कहा था, तुम्हारा नाम भेजा है। अब आपने मेरा नाम पुकार लिया, तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके चुनाव क्षेत्र के लिए भी कह दूं। उपाध्यक्ष महोदय, सब चुनाव क्षेत्रों की यह शिकायत है, केवल एक चुनाव क्षेत्र के अन्दर काम हुआ है, पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर को कहा, कुछ काम कर रहे हैं, पुरानी सड़कों की मरम्मत को लिया है। अगर उनकी मरम्मत कर दें तो कोई शिकायत न रहे। मैंने इसलिए इस पर कट मोशन रखा है कि आप इस पर गौर करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जान मोहम्मद।

श्री जानमोहम्मद (पिड़ावा) : सदरे मोहतरीम, हुजरात सदरे मोहतरीम कहते हैं क्योंकि नये सदन के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष को सदर कहते हैं, इसलिए सदरे मोहतरीम कहा....

श्री उपाध्यक्ष : नायब सदर कह सकते हैं।

श्री जान मोहम्मद : सदरे मोहतरीम कहा जाता है। मैंने आज तक यही सुना है। अभी मैं दिल्ली गया था। सड़कों पर चर्चा चल रही थी। सड़कों के लिए बराबर हरियाणा की मिसाल देने की बात कही जाती है। जो अब्दुल जो हिन्दुस्तान के आला लीडर हैं। उनसे पूछा, क्या वजूहात है कि हरियाणा की तारीफ की जाती है। आप लोग क्या करते हैं, जगह जगह सड़क बनाली। मैं पिछले दिनों उनके पास था, वह मेरे चचा लगते हैं। उन्होंने फर्माया हम सख्त से काम करते हैं और रिश्वत के खिलाफ कोशिश करते हैं। जितने इंजीनियर हैं उनको अहतियात बरतने के लिए कहते हैं, जितना पैसा दिया है वह टाइम पर खर्च नहीं किया तो सस्पेन्ड कर दिये जायेंगे। यह कारण बताया जिससे बराबर हरियाणा की बात करते हैं कि उसने तरक्की की। वहां लोग ईमानदारी से काम करते हैं। यह सब जानते हैं, इसलिए हमारा पड़ोसी है वह आगे हुआ है और हम पड़ोसी से पिछड़े हुए हैं। टोंक का इलाका है वह पिछड़ी हुई रियासत मानी जाती थी, पिड़ावा के लिए मैं अर्ज करूं कि बरसात में पानी का जखीरा बन जाता है। वहां की हालत खराब है। भवानी मण्डी के काश्तकार हैं, वह बरसात में चार महीने तक परेशान रहते हैं। सुनेल तक झालावाड़ से सड़क है वह बना दी, उसके बाद उसकी मरम्मत का टाइम नहीं आया। दस बारह पुलिया पिछली साल बनाई गई थीं, वह बदकिस्मती से टूट गई। क्यों टूट गई, मैं समझता हूं, यह इंजीनियर्स की टेक्निकल गलती है, उनकी जिम्मेदारी है। इस प्रकार पुलिया टूट जाती है उससे सरकार का लाखों रुपया खराब होता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि उनका कुछ बिगड़ता नहीं है, जनता का बिगड़ता है, जनता को परेशानी होती है। जनता हमसे पूछती है, सड़कों की मंजूरी लाए या नहीं। हम कहते हैं, मंजूरी हमारे पास नहीं है। तो वह कहते हैं कि क्यों गये थे। इस किस्म की बात पूछते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कई सड़कों के काम ठेकेदार को दिये गये, ठेकेदार भाग गये तो बाकी की पुलिया भी टूट गई। वह इसलिए हुआ है कि इसमें मनमानी हुई है, पैसा खा गये हैं। मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज करता हूं कि वह इन्क्वायरी करायें और जो गुनहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। फौरन इन्क्वायरी होनी चाहिए। जिन लोगों ने गलतियां कीं, राज्य का लाखों रुपया जाया किया है, साबित हो तो उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो यहां तक अर्ज करना चाहता हूं कि अगर उनका कसूर हो और जो पैसा राज्य का गया है वह उनसे वसूल करना चाहिए। इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि बारिस में कम से कम पिड़ावा एक टापू बन जाता है, उसके दो रास्ते हैं। एक सुनेल से पिड़ावा जो सड़क बनी है, 10-12 छोटी पुलियां हैं आप चाहें तो बनवा सकते हैं।

दूसरा रास्ता है पिड़ावा से मध्य प्रदेश वहां कुछ डामर की सड़कें बनाई जाती हैं। यह कुदरतन पहाड़ है। मैं अर्ज कर रहा हूं

(जान मोहम्मद)

कि ज्यादातर मोटरें झालावाड़ को इसी रास्ते से जाती हैं और तमाम काश्तकार, हमारे इलाके के मुकदमे वाले या दूसरे झालावाड़ इसी रास्ते से जाते हैं। पिड़ावा से पीलाकाल 6 फर्लांग पर है। 4.5 हजार रुपया का खर्चा होगा, पुलियें बन सकती हैं। इससे जनता को फायदा होगा। जब बारिस के अन्दर मोटरें बन्द हो जाती हैं तो जंगलों में रात को लोग पड़े रहते हैं भूखे प्यासे। अगर पुलियायें बन जाती है तो थोड़ा सा पैसा खर्च होगा। यह छोटासा काम है, बड़ा काम नहीं है। कम से कम एक रास्ता खुल जाय हमारे लिए, जनता परेशान है। लोग मुझसे कहते हैं कि ऑर्डर लाओ जैसे कि कोई ऑर्डर मेरी जेब में पड़ा है। इसलिए अर्ज है कि जनता ने हमको इसलिए भेजा है कि हम निहायत ईमानदारी के साथ अपनी बात रखें, उसमें राजनीति न हो। पिड़ावा रियासत का इलाका रहा है। महाराजा झालावाड़ के दिनों में कुछ काम हुआ था उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हमारी बदकिस्मती है कि एक डिप्टी मिनिस्टर कन्हैयालाल पटेल था, इतना पैसा दिया गया उसको अपने इलाके में और $1\frac{1}{2}$ लाख की जमीन है काश्तकारी की उसकी, उस अकेले व्यक्ति ने अपने को फायदा पहुंचाया। इसकी जांच कराई जाए, अगर गलत हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। इसके अलावा और भी फायदा अपने को पहुंचाया। जहां पर उसकी जमीन है वहां पर बिजली लगवा दी। राज्य का पैसा खर्च हुआ। जहां घाटे का बजट है वहां देखिये नाजायज खर्च कैसे होता है। मैं यहां तक अर्ज करता हूं कि जिन अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी हैं सरकार को, उनको मुअत्तिल किया जाय और पटेल साहब से रकम वसूल की जाए जिसने फायदा उठाया है। पिड़ावा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, मिनिस्टर साहब से अर्ज है कि इसको देखें। हमने वायदा तो नहीं किया न जनता के साथ कसमें खाई हैं, लेकिन उनको विश्वास दिलाया है कि आप हमको भेज रहे हैं, हम आपकी मांगों को जरूर विधान सभा में रखेंगे। मैं निहायत ईमानदारी से अर्ज करूंगा मिनिस्टर साहब से कि आप कम से कम एक रास्ता खुलवा दें या भवानी मन्डी का या मध्य प्रदेश का।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है सार्वजनिक निर्माण विभाग पर। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान परबतसर की ओर दिलाना चाहता हूं। नागौर जिले में परबतसर ही एक ऐसा स्थान है, जहां हमारा भारत का सबसे बड़ा और मशहूर मेला होता है और उसमें हमारे भारतवर्ष के तमाम व्यापारी अपनी अच्छी नसल के पशु खरीदने के लिए आते हैं और हमारे व जोधपुर जिले के लोग यहां अपने पशु क्रय-विक्रय के लिए ले आते हैं। लेकिन परबतसर जो शहर है उसके पास दो सड़कें बनी हैं एक परबतसर से हरसोर और दूसरी परबतसर से पुष्कर। ये सड़कें आज से 25 साल पहले की बनी हुई हैं जिन पर खाली रोड़ी डालकर सड़कें बनाई गई थीं उस पर काफी बसें चलती हैं। हरसोर से परबतसर सड़क पर रोडवेज की बसें चालू हो गई हैं लेकिन उसके बीच में एक गांव आता है रोहनी उस गांव के पास में एक पहाड़ है और जो घाटी है जिस पर सड़क गुजरती है, वह इतनी ऊंची है जो पहले सरकार ने कटवाई थी और पत्थर भी इकट्ठे किए थे लेकिन पत्थर तो लोग वहां से ले गए और वहां

Page No 132

(श्री जेठमल बरबड़)

खाली जो घाटी है उसके कंकर ही रह गए हैं और बसों का आना मुश्किल हो गया है। कई बार बसें ऊपर चढ़कर वापस नीचे आ जाती हैं। उस सड़क से कोई भी गाड़ी-कार तो ले नहीं जा सकते, जीप से जाते हैं तो भी परेशानी होती है। यह 25 साल पहले की बनी हुई सड़क है जिसमें बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। रपटों की वजह से दीवारें खींची गई हैं। दीवारों के पास में प्रोटेक्शन के लिए फेंसिंग वगैरह नहीं है। दोनों तरफ से खड्डे पड़े हुए हैं। जो बसें वहां चलती हैं, थोड़ा चलने के बाद खड्डे में गिर जाती हैं। यह इतना बड़ा पवित्र स्थान है जहां लाखों रुपये की सरकार को आमदनी होती है। मेले के अन्दर सेल्स टैक्स और पशुओं पर टैक्स उसके बावजूद परबतसर इलाके की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैसा मैंने बताया पुष्कर जो सड़क जाती है वहां धार्मिक स्थान है, पुष्कर में पशु मेला लगता है उस मेले में हमारे इलाके के लोग जाते हैं तीर्थ स्थान की दृष्टि से और पशु खरीदने के लिए और बेचने के लिए भी लेकिन उस सड़क की हालत बहुत खराब हो गई है। जो सड़क बनाई है वह खतम हो गई और उसकी जगह एक नाला बनाया गया और उसके बीच होकर हमें जाना पड़ता है। सरकार की निश्चित नीति होनी चाहिए कि जो सड़क आज से 20 साल पहले बनी है उसको पहले लेंगे। कई जगह सड़कें हाल ही में बनाई गई, वह खराब हुई फिर दुबारा बनी। लेकिन हमारे इलाके की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आज हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो इस बात की तरफ जनता हमारा ध्यान खींचती है क्योंकि आज किसान की हालत सुधरी है, वह अपने खेत में मकान बनाना चाहता है। वह पत्थर लाता है तो उसमें दिक्कत होती है। जोधपुर से जब पट्टियां आती हैं तो जोधपुर से परबतसर को जाने वाले माल पर इतना खर्चा नहीं आता जितना वहां से गांव को ले जाने में होता है। नागौर जिले में सड़कों की हालत बहुत खराब है। एक सब-डिवीजन से दूसरी सब-डिवीजन जाने के लिए डामर की सड़क नहीं है। इसलिए हमारे जिले में सड़कों का सुधार करना चाहिए।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज मकराने के पत्थर की खानों से जब राज्य सरकार को हर साल लाखों रुपये की रायल्टी मिलती है, तो वहां पर सड़कों का अभाव क्यों है? जब राज्य सरकार को रायल्टी से पैसा मिलता है और उन खानों का पत्थर बाहर तक जाता है, तो राज्य सरकार को चाहिये कि वहां के लोगों को जो असुविधा आपने माल को बाहर लेजाने में हो उसे दूर करें। आज जब वहां से ट्रकों द्वारा माल बाहर जाता है सड़कों के अभाव में व्यापारियों को तो दूसरी जनता के साथ साथ असुविधा होती है पर ट्रकें भी खराब हो जाती हैं। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम इस बारे में सार्वजनिक विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि वहां पर सड़के माईनिंग डिपार्टमेन्ट वाले बनायेंगे और माईनिंग डिपार्टमेन्ट वाले कहते हैं कि यह हमारा काम नहीं है तो यह सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम है। बड़ी विषम स्थिति है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे मकराना क्षेत्र में जल्दी से जल्दी सड़कें बनाने की व्यवस्था करावें। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन

(श्री जेठमल बरबड़)

करना चाहूंगा वह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के काम करने की ऐसी प्रक्रिया है कि वहां साल भर 11 महीनों तक तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और जब एक महीना घटता है तो निर्माण कार्य हाथ में लेते हैं ताकि जो धनराशि उन्हें एलोट होती है वह 31 मार्च तक उपयोग करली जावे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस प्रक्रिया को दूर करावें। और जो मकराना क्षेत्र में सड़कों का अभाव है, उसे तुरन्त मिटाने की व्यवस्था करावे। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में नागौर जिला वैसे ही बहुत ही पिछड़ा हुआ है पर आज मकराने के क्षेत्र में बावजूद इसके कि वहां पत्थर का भारी उद्योग हैं, फिर भी सड़कों का बहुत ही अभाव है। नयी सड़कें बनी नहीं हैं जो पुरानी सड़कें हैं वह टूट फूट गयी है इसका नतीजा यह हुआ है कि रास्ते में जगह जगह गड्ढे पड़ गये हैं जिससे ट्रकें वगैरह जो जाती है उन्हें बहुत ही असुविधा रहती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जनता को असुविधा से बचाने के लिये मकराना को दूसरे क्षेत्रों से सड़कों द्वारा मिला दिया जाय तो जनता को बहुत ही सुविधा होगी । बस यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरूंलाल

श्री भैरूंलाल (अकलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में झालावाड़ एक ऐसा जिला है जो कि सबसे पिछड़ा हुआ है । इस क्षेत्र में आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिला एक आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद दूसरी जगह चाहे काम हुआ होगा पर इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। वहां पर सड़कों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। पक्की सड़कों का अभाव है और जो पुरानी सड़कें थीं वह कच्ची हैं इसलिये बहुत ही खराब स्थिति में हैं। इसलिये आज उन्हें पक्की कराने की आवश्यकता है ताकि जनता को राहत पहुंचे । उपाध्यक्ष महोदय, पहले एक सड़क हरनावदा से 16 मील लम्बी कच्ची बननी थी उसका 3–4 साल पहले ही काम शुरू होने को था पर वह भी नहीं बन सकी । इसी प्रकार से इकलेरा से हरनावदा तक सड़क बनना बहुत ही जरूरी है । इकलेरा क्षेत्र में एक बड़ा गांव है जहां पर उस क्षेत्र की 25 हजार की आबादी है वहां पर सड़क का अभाव होने से जनता को बहुत ही परेशानी होती है । पुराने स्टेटों के जमाने में जो सड़कें बनी थीं वही आज तक चली आ रही हैं और जब हम आज के सड़कों की हालत को देखते हैं तो समझते हैं कि पहले हालत स्टेटों के जमाने में बहुत ही अच्छी थी । इसके अलावा जो मैं और निवेदन करना चाहूंगा वह है मनोहरथाना से लेकर हरनावदा तक सड़क बनाने के बारे में यह सड़क बाया जावर जायें तो राज्य सरकार के इस कार्य से जनता को ज्यादा सुविधा होगी । मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि जो कार्य पंचायत समितियों को सड़क निर्माण कार्य के लिये दे दिये गये हैं या सड़कों की मरम्मत के लिये इस क्षेत्र में दे दिये गये हैं वह कार्य राज्य सरकार को अपने हाथ में लेने चाहिये । आज राज्य सरकार एक सड़क की मरम्मत के लिये पंचायत समिति को 300 रुपये की राशि स्वीकृत करती है तो

(श्री भैरूंलाल)

क्या 300 रुपये में सड़क की मरम्मत हो सकती है। यह राशि तो नहीं के बराबर है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मारफत मन्त्री महोदय से निवेदन है कि जो 25 हजार की आबादी वाला क्षेत्र है उसको ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण जल्दी से जल्दी करया जाना चाहिये। इसी प्रकार इकलेरा से भालता सड़क का कार्य पूरा कराया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है। आज वहां पर 25 हजार के क्षेत्र में बस्ती है आपको मजदूर भी मिल सकते हैं और चूंकि वह इलाका पहाड़ी है इसलिये सड़क निर्माण करने के लिये पत्थर भी आपको मिल जायेगा और इस प्रकार सरकार का खर्चा भी कम होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज उस क्षेत्र का इलाका मध्यप्रदेश की सीमा से लगा हुआ है वहां की सड़कों की हालत को देखते हुए यहां की सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। अगर एक आदमी वहां से मध्यप्रदेश में जाता है तो ज्योंही मध्यप्रदेश का सरहद से आगे गुजरते हैं मोटर से तो आपको तुरन्त ही पता पड़ जायेगा कि हम मध्यप्रदेश में आगये हैं और उधर से आते वक्त भी यात्री मोटर में पता लग जायेगा कि हम राजस्थान की सीमा में आ गये हैं। अतः आज वहां सड़कों की मरम्मत कराना जरूरी है। और मेरा तो यह सुझाव है, वहां पर नयी सड़कें बनाई जानी चाहिए। इसी प्रकार जो काली खाड़ी नदी पर जो पुलिया बनाने की योजना मन्जूर है उसको बहुत ही शीघ्र बनाया जाना है, उसका भी शीघ्र काम शुरू कराना जरूरी है। इसके अलावा आज, उपाध्यक्ष महोदय, अकलेरा से आसलपुर ग्राम तक व बेरागढ़ ग्राम तक सड़क निर्माण करके उन्हें मिला दिया जाये तो जनता को काफी राहत पहुंचेगी। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत यह भी मन्त्री महोदय, से निवेदन करना चाहूंगा कि मनोहर थाना से राजगढ़ की सड़क को भी जल्दी से ठीक कराई जावे ताकि जनता को सुविधा हो। बस मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपको सार्वजनिक निर्माण विभाग पर जो मांग हैं उसके लिये निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जालोर और बाड़मेर राजस्थान के ऐसे जिले हैं जहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कभी काम नहीं हुआ। आज राजस्थान बने हुए इतने साल हुए और दूसरे जिलों में सड़कें बनीं पर इस क्षेत्र में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। दूसरे जिलों को देखते हुए आज जालोर जिले में, बाड़मेर जिले में जो कि राजस्थान के पश्चिम हिस्से में है और इन दोनों जिलों की सीमा इधर तो गुजरात में पाकिस्तान से लगती हैं उधर बाड़मेर के आगे पाकिस्तान की सीमा आ गयी है। पर बावजूद इसके कि यह एक सीमान्त जिला है फिर भी सड़कों के विकास की दृष्टि से इसकी हमेशा से उपेक्षा की गयी है। आज अगर बाड़मेर और जालोर जिले की आबादी को देखते हुए या क्षेत्रफल की दृष्टि से या प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही कम किलोमीटर सड़क आयेगी। पिछले सालों में जरूर थोड़ा बहुत कार्य हुआ क्योंकि भारत पाक संघर्ष हुआ था तब पर इन जिलों की महत्वपूर्णता को देखते हुए कुछ भी काम यहां पर सड़कों के विकास के नाम

(श्री मंगराज चौधरी)

पर नहीं हुआ। वैसे भी राजस्थान बनने के बाद जितना दूसरे डिवीजनों में विकास कार्य हुआ है उसमें जोधपुर डिविजन हमेशा से पिछड़ा ही रहा है। आज जब भौगोलिक दृष्टि से इसकी इम्पोरटेन्स है तो उसके मुताबिक काम होना चाहिये। पर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान बनने के 15 साल तक इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ। राज्य सरकार को इस बारे में कई बार निवेदन किया गया, पर कोई सुनवायी नहीं हुई। यह तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा तब जाकर कुछ काम किया गया। पर इस अकाल राहत कार्य के अन्दर जो सड़कें बनी हैं वह तो ग्रेवल रोड्स की ही बनी हैं या कच्ची सड़कें बनी हैं वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ। रूरल रोडिफिकेशन के नाम पर बहुत ही कम काम हुआ है। आज जो ग्रेवल रोड्स हैं, उनकी हालत खराब है जगह जगह से उनकी मरम्मत की आवश्यकता है। राज्य सरकार को चाहिये कि वहां पर मेटल्ड रोड बनाई जाये, जिससे जनता को राहत पहुंचे। बाड़मेर में तो ज्यादा वर्षा नहीं होती, पर हमारे जालोर में वर्षा होती है और वर्षा के दिनों में इन सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे इन सड़कों की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, इसलिये इन रोड्स को मेटल्ड रोड्स बनाना बहुत ही आवश्यक है। आज वहां की सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। वह पिछड़ा हुआ इलाका है और अगर दूसरे इलाकों को देखें तो हमें मालूम होगा कि वहां पर उस जगह पर कोई डामर की सड़क बनी हुई नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत राज्य के मन्त्री महोदय, से यह निवेदन करूंगा कि जो उस इलाके में कच्ची सड़कें हैं उन्हें पक्की बनायी जायें और नयी सड़कें भी जालोर जिले में बनायी जायें। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि जालोर जिले के क्षेत्र में सात पंचायत समितियां हैं उनमें से दो तीन पंचायत समितियां तो ऐसी हैं जिनका की मुख्यालय सड़क से काफी दूर है जैसे जसवन्तपुरा पंचायत समिति वह जसवन्तपुरा ग्राम में है। मैं चाहूंगा रोड्स का जो अलोकेशन है, इस इम्बेलेन्स को दूर किया जाय और जयपुर की पापूलेशन और साइज को देखते हुये, सड़क का काम यहां ज्यादा किया जाय और इस बात के लिये मैं और भी निवेदन करूंगा यह निवेदन मंत्री महोदय से नहीं केबिनेट से निवेदन करूंगा। रोड्स को जो प्रायरिटी दिया है, मैं उसको बहुत ही मानता हूं क्योंकि जैसा आप चाहते हैं इकोनोमिक डवलपमेंट देश का हो, प्रान्त का हो तो उसमें बिजली पानी के साथ साथ सड़क भी एक इम्पार्टेन्ट फैक्टर है। इनफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं— Road is one of the most important factors in infrastructure. आज रोड्स बनाने से सिर्फ जो कम्यूनिकेशन बढ़ता है यह बात सही है किन्तु ऐग्रीकल्चरिस्ट को भी उसका फायदा मिलता है। उसका जो प्रोड्यूस है वह मार्केट में इजीली आ सकती है, उसको ट्रान्सपोर्टेशन सस्ता उपलब्ध हो सकता है। आज उसको ट्रान्सपोर्ट कम पड़ता है और खर्चीला भी अधिक पड़ता है उससे ऐग्रीकल्चरिस्ट के घर में ज्यादा पैसा आता है। आज तक राजस्थान में रोड्स को जितना हमको इम्पॉरटेन्स देना चाहिये, जितना महत्व

Page No 136

(श्री भगराज चौधरी)

रोड्स को देना चाहिये वह नहीं दिया है। राजस्थान की स्थिति को देखते हुये, इतने सारे प्लान ले लिये हैं जो प्रायरिटि दिया है उससे कम से कम डबल प्रायरिटि रोड्स को मिलना चाहिये। इस बात को ध्यान में रखते हुये चाहे आपको एन्युअल प्लान का रि-अलोकेशन करना पड़े लेकिन रोड्स का जो रखा है यह बहुत ही अनुचित है। इसको रि-एडजस्टमेंट करना चाहिये। इस साल तो केवल मेन्टीनेन्स के लिये है। आज एक नई सड़क नहीं ली है। सारा प्लान मेंटीनेन्स का है। एक टुकड़ा आपने लिया नहीं है और पिछले बजट में लिया था—जहां पहले कच्ची मिट्टी भी डाल दी है उनको भी नहीं लिया है। इस साल उसको नहीं रखने से उसका भी वेस्ट जाता है। इसलिये मैं मंत्री मण्डल से निवेदन करूंगा प्लान को रि-एडजस्ट करके रोड्स को कुछ पैसे देने चाहिये और जयपुर डिस्ट्रिक्ट की सड़कों के मामले में बेकवर्डनैस है उसमें ज्यादा पैसा रोड्स का मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल भदादा।

(अनुपस्थित)

श्री नन्दलाल।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे 5-7 कट मोशन्स हैं-मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी के लिये। उसमें सिर्फ दो सड़कों की तरफ जिनका काम अधूरा पड़ा है जो फुलेरा में तोब से खन्डेला है उसको पिछले साल में रखा था—इस साल में उसको नहीं रखा है। मेरा सुझाव है माननीय मंत्री महोदय से, अकाल का खाता मैंने देखा है दो करोड़ 43 लाख रुपया अकाल में सड़क बनाने के लिये है। मैं सुझाव देना चाहता हूं जो एक करोड़ सड़क खाते रखा है, उसमें जो रुपया है वह इसमें लगायें। मैं एक बात और कहना चाहूंगा पिछले साल दूदू, फागी, फुलेरा तहसील में सड़कों का काफी नुकसान हुआ था। जो पी. डबल्यू. डी. मिनिस्टर थे 6 जनवरी को मुआयना किया था और जो बरसात से डेमेज हुआ है उसका नुकसान पूरा होने को कहा था। उसके लिये टेन्डर निकाले गये और काम कराया गया और उसमें 13 लाख रुपया खर्च हो गया और साढ़े चार लाख रुपया मेरे जिले में खर्च होना बता दिया गया। अभी उस बारे में इंजीनियर और ए. इ. एन. भी सस्पेन्डेड हैं। मेरा निवेदन है जो 13 लाख रुपया दिया था वह रुपया हमको नहीं मिला। मैं चाहता हूं वह 13 लाख जिसका टेन्डर निकाला गया और सड़क का निर्माण बता दिया गया वह एम्ब-जलमेंट हो गया। वह 13 लाख रुपया हम को दे दिया जाय।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा जयपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जैसा माननीय भगराज जी ने कहा पापूलेशन के आधार पर कुछ पैसा दिया जाय मैं, इस बात से सहमत हूं और मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज तक फेयर वेदर रोड्स और सरफेस रोड्स के नाम पर कुल मिलाकर जो सड़कें हैं वह हैं अजमेर में 1600 कि. मी., अलवर में 1348 कि.मी. भरतपुर में 1428

(श्री पी० के० चौधरी)

किलोमीटर, बाड़मेर में 1343 और जयपुर में 1410 किलोमीटर है। गंगानगर में 1451, कोटा में, नागौर में 1735 उदयपुर में 3262। मेरा कहने का मतलब यह है कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वह एक पूरा डिविजन है जो बूंदी झालावाड़ डिविजन के बराबर है जिसमें 3400 किलोमीटर सड़कें हैं। उदयपुर अकेले में 3260 किलोमीटर हैं जबकि जयपुर जिले में 1410 किलोमीटर हैं यानि सड़कों की दृष्टि से जयपुर का इम्बेलेंस है राजावाड़ समिति है लेकिन सम्बलगढ़ मुख्यावास नहीं हो पाया है। एस०डी०ओ० का हैड क्वार्टर जरूर है। हमारी सरकार की काफी दिनों से योजना चल रही है। पंचायत समिति का मुख्यावास नहीं रहने देंगे। जिले का मुख्यालय न हो परन्तु, उपाध्यक्ष जी, आज तीन पंचवर्षीय योजनायें खतम हो चुकी हैं और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से हम गुजर रहे हैं चौथी योजना में अगर जिले का हेडक्वार्टर नहीं हो पायेगा तो हम क्या आशा करें कि यह सरकार कुछ कर सकेगी। पंचायत समिति का मुख्यालय है वहां हायर सेकेन्डरी स्कूल है, पुलिस स्टेशन भी है और और दूसरी विकास की योजनायें भी हैं। काफी बड़ा कस्बा है इतना होते भी यदि मुख्यालय नहीं हो पाया तो यह हमारे लिये बड़ी दयनीय स्थिति है। क्या कारण है राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं उनके साथ उपेक्षा का व्यवहार किया जा रहा है और अन्य जिलों में सड़कें बराबर बनती जायगी? माननीय मन्त्री महोदय स्वयं विचार करें आखिर उनके पास जवाब क्या है इसका। क्या वहां की जनता और नागरिक सरकार को पैसा नहीं देते हैं? जो भी आपकी योजनायें है, उनमें बराबर का हिस्सा देती है। सेल्स टैक्स की वसूली आप करते हैं, भू-राजस्व भी वहां के नागरिक आपको देते हैं और भी आपके टैक्सेज हैं उनको भी सरकार के खजाने में जमा करवाते हैं, वह भी देते है जो भी आय के साधन हैं नान रेवेन्यू टैक्सेज भी सरकार के खजाने में जमा करवाते हैं तो फिर क्यों उन जिलों की उपेक्षा की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय इस सदन में मुझे दूसरा मौका मिला है-पहले भी मैं रह चुका हूं। पहले भी मैंने कोशिश की थी जो भी पिछड़े जिले हैं बराबर पिछड़ते ही जा रहे हैं मेरा निवेदन है उनकी तरफ भी आप ध्यान दें। अगर पिछड़े इलाकों को आप बड़े बड़े कस्बों और बड़े बड़े गांवों से नहीं जोड़ेंगे तब तक पिछड़े गांव वालों के लिये आने जाने के साधन, आवागमन के साधन, ट्रान्सपोर्ट के साधन से नहीं जोड़ेंगे तो वे और भी पिछड़े रह जायेंगे। उनकी वेश-भूषा, उनके खानपान का तरीका, उनकी संस्कृति का आदान-प्रदान यातायात के साधन नहीं होने से ठीक नहीं बैठता है और वे अन्य समाज के बराबर नहीं हो पायेंगे। जब तक सड़कों की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पायेगा तब तक किसी प्रकार का विकास सम्भव नहीं होगा। मैं कोई प्रिफरेन्सियल ट्रीटमेंट की भी मांग नहीं करता हूं...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

जो आबादी की कुल संख्या है उस बात को ध्यान में रखते हुये सड़कों के विकास में जो पैसा लगना चाहिये वह नहीं लगा है। बस मैं इतना कह कर ही अपना भाषण समाप्त करता हूं।

"एक बात मैं परफार्मेन्स बजट के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। परफार्मेन्स बजट पी. डबल्यू. डी. का आपने दिया है और दूसरे

(श्री पी० के० चौधरी)

विभाग का भी दिया है लेकिन इस परफार्मेन्स बजट को देने की मन्शा हमारी यह है कि जो मेम्बर्स हैं या दूसरे लोग हैं उनको साफ साफ जानकारी मिल जाये। हम कोई एक्सपर्ट्स या कोई टेक्नीशियन्स तो हैं नहीं लेकिन इसका मतलब यह था कि हमको कम से कम यह मालुम हो जाये कि पी. डब्लू. डी. का काम कैसा चल रहा है, फिजिकल टारगेट्स का एचीवमेन्ट कैसे चल रहा है। इससे हमको खासतौर से मालुम होता है कि इस साल का बजट का प्रावीजन था और उसके अगेन्स्ट में इतना एचीवमेंट हुआ है। इससे हम को यह भी मालूम हो जाता है कि परफार्मेन्स बजट से कि हमारा टारगेट इतना था कि इतने मील हम इस साल में करना चाहते थे उससे इतना खर्चा हुआ और इतने मील का फिजिकल एचीवमेंट हुआ। इस तरह की जानकारी देते तब तो हम अन्दाजा लगा सकते थे...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अन्दाज तो इसी से लग गया कि पी. डब्लू. डी. की रिपोर्ट तक नहीं दी इन कटमोशन्स के पहले उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन डिपार्टमेंट डिसकस हो उसके दो रोज पहले ही हमें डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मिल जाये। आज पांच-छः डिमाण्ड्स चल रही हैं और इसमें 80 पर्सेन्ट डिमाण्ड्स की रिपोर्ट ही नहीं है।

श्री पी. के चौधरी : इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि परफार्मेन्स बजट देते हुए इस प्रकार का इन्डीकेशन आना चाहिये कि इस साल के बजट में इतना रुपया रखा और उसमें इतने मील तो सरफेस रोड़ का प्रावीजन था और इतने मील अनसरफेस रोड़ का प्रावीजन था और जब साल पूरा हुआ तो इतने मील सरफेस रोड़ तैयार हुई और इतने मील अनसरफेस रोड़ तैयार हुई तब जाकर मालुम पड़ता कि क्या काम हुआ है।

फिर एक बात मैं मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि जो परफार्मेन्स बजट आपने दिया उससे हम यह पाते हैं कि फर्स्ट प्लान में जो सड़क हुई सरफेस रोड़ वह 787 कि. मी. थी और थर्ड प्लान में ऐलोकेशन था टोटल 5 साल का 10 करोड़ 60 लाख रुपया। इस रुपये से सरफेस रोड़ 8700 कि. मी. से बढ़कर 13154 कि. मी. हुई। इसका मतलब यह हुआ कि 4367 कि. मी. हमने सरफेस रोड़ तैयार किया। इसका दूसरा मतलब यह हुआ कि 1 करोड़ रु. में 436 कि.मी. रोड़ सरफेस हुई। अब हम नैक्स्ट प्लान में पाते हैं थर्ड प्लान में 9 करोड़ 62 लाख रुपये में 4142 कि. मी. सरफेस रोड़ तैयार हुई। इसका भी वही प्रपोर्शन आ जाता है। अब उसके बाद आता है, उपाध्यक्ष महोदय आपका एनुअल प्लान। 1966-67 में 1 करोड़ 90 लाख रुपये का खर्चा किया और इस रुपये को खर्च करके हमारी 435 कि. मी. सरफेस रोड़ तैयार हुई जब कि सेकिण्ड और थर्ड प्लान में परफार्मेन्स देखें तो उसमें 1 करोड़ रुपये में 435 कि. मी. का आंकड़ा आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एनुअल प्लान में याने 1967-68 में 1 करोड़ 5 लाख रुपया खर्च किया और उसमें सरफेस रोड़ तैयार हुई 375 कि. मी.। नेक्स्ट हमने खर्च किया 1 करोड़ 12 लाख और उसमें सरफेस रोड़ तैयार हुई 375 कि. मी.। नेक्स्ट हमने खर्च किया 1 करोड़ 12 लाख और उसमें सरफेस रोड़ तैयार हुई 266 कि. मी.। फिर हमने खर्चा किया 1 करोड़ 46

(श्री पी० के० चौधरी)

लाख रुपया 1969-70 में और इस रुपये में 270 कि. मी. सरफेस रोड़ तैयार हुई और फिर 1971-72 में 2 करोड़ 30 लाख का खर्चा किया और इसमें 330 किलो मीटर सरफेस रोड़ तैयार हुई। यह जो परफार्मेन्स बजट से इन्डीकेशन मिला है उसमें हमको मालुम पड़े कि फर्स्ट प्लान में वह 423 किलो मीटर सरफेस रोड़ हुई 1 करोड़ रुपये में, सेकिण्ड प्लान में 414 किलो मीटर हुई, फिर थर्ड प्लान में 435 किलो मीटर हुई और फिर नैक्स्ट प्लान में 216 किलो मीटर ही हुई। तो यह हमारी फिगर कम होती गई।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

तो आप बतायेंगे कि परफार्मेन्स बजट का जो इण्डीकेशन है वह सही है या गलत है? सही है तो उसके रीजन्स क्या है? क्यों हमारा परफार्मेन्स नीचे गया? जब परफार्मेन्स बजट है वह ऐसा होना चाहिये जिससे कि हमारी समझ में आये कि जो फिजिकल टारगेट है वह एचीव हुआ। सही हुआ या गलत हुआ वह समझ में आ सकता है। इस प्रकार का परफार्मेन्स बजट होना चाहिए। यही कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार की तरफ से उत्तर होगा।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय समाप्त होने वाला है इसलिए जब तक मांगें पारित हों तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि जब तक मांगें पारित न हों तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मन्त्री महोदय।

श्री नारायणसिंह (मन्त्री, मुद्रण एवं लेखन) : उपाध्यक्ष महोदय, लेखन सामग्री और मुद्रण के विषय में हाऊस में कुछ मेम्बर्स ने ध्यान आकर्षित किया मैं उसके लिए तो बहुत आभारी हूं कि जो चीजें बताई गयीं उन पर गौर किया जा सकता है। मैं शुरू में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि पुरानी स्टेट्स से हमको मशीनरी मिली और वह मशीनरी भी करीब 50-60 साल पुरानी है। भवन की आवश्यकता भी है, भवन भी छोटा है और बदकिस्मती की बात यह है कि नान-प्लान बजट के अन्दर इसको सारा पैसा रखा जाता है और प्लान के अन्दर कोई चीज नहीं आती हैं। इसलिए मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए और दूसरे काम करने के लिए बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। उनको रेशनेलाइज की जायें और दूसरे लेबर की समस्या है। इसलिए मशीनरी पुरानी है यह मैं स्वीकार करूंगा। इस प्रकार से फिर भी मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि हमने प्रेस सुपरिन्टेन्डेन्ट को लन्दन भेजा है टेक्नोलाजी की ट्रेनिंग के लिए और एक असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट को सितम्बर के अन्दर जर्मनी भेजा जायेगा....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पुरानी मशीनों को नई करेगा लन्दन में?

श्री नारायणसिंह : नई तो नहीं करेगा लेकिन ट्रेनिंग लेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तो नया हो जायेगा लेकिन मशीनें वही रहेंगी।

श्री नारायणसिंह : इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रिन्टिंग के काम का फीगर बढ़ा है और और हर जगह बढ़ा है। तो प्रेस के पास में काम बढ़ा ही है।

जहां तक परचेजेज का सवाल है स्टेशनरी परचेज करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनी हुई है और वह कमेटी टेन्डर मंगाती है और वही तय करती है। इस कमेटी में होम कमिश्नर चेयरमैन हैं, डाइरेक्टर प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेन्स है और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर पी. डब्लू. डी. हैं। टेन्डर्स जो आते हैं वे आल इण्डिया बेसिस पर लिये जाते हैं। और उसमें 15 परसेन्ट की रियायत प्राइज प्रिफरेन्स स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को दिया जाता है......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक दो मेम्बर्स इस हाउस के भी डाल दो इस हाई पावर कमेटी में ?

श्री रोशनलाल : इससे यह कमेटी और भी हाई पावर हो जायेगी।

श्री नारायणसिंह : प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी में रहेंगे तो उनकी हैसियत के माफिक यह नहीं होगा। कुछ इसमें यह भी सवाल आया कि कागज इन्फीरियर क्वालिटी का है और कागज ठीक तरह का नहीं मिलता। मैं निवेदन करता हूं कि डायरेक्टर जनरल आफ सप्लाईज एण्ड डिस्पोजल की मार्फत ही गवर्नमेंट आफ इण्डिया की रेट पर कागज खरीदा जाता है और काफी अच्छा कागज खरीदा जाता है। कहीं किफायत भी की जाती है और इस तरह से किफायती कागज भी काम में आता है लेकिन जहां तक छपाई का और दूसरे प्रश्न हैं वह कई किताबें भी निकलती हैं, कई रिपोर्ट्स भी निकलती हैं, दूसरी चीजें भी निकलती हैं, उनको देखने से लगता है कि काफी अच्छी तरह से छपाई होती है।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोफेसर केदार जी ने रखा है। वह आज हमारे सामने भी है और एक दिक्कत पैदा करता है। शुरू शुरू में जब यह प्रेस शुरू हुआ था तो सारे गवर्नमेंट एम्पलाईज माने गए थे और आर. एस. आर. के मुताबिक गवर्न होते थे और उनको सी. एल. 15 और पी. एल. 33 एक साल में मिलती थी। 1-11-57 के बाद फैक्ट्रीज एक्ट लागू हुआ और इससे फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक जो जो उनको सहूलियतें इसके बाद में हो सकती थीं, उनको मिलीं। बाद वालों को। 1-11-57 से 31-7-66 तक जो भी आए, उनको राजस्थान इलेक्ट्रिकल एण्ड वाटर वर्क्स रूल्स के तहत सुविधाएं दी गई और इसके बाद 31-7-66 के बाद वालों को फैक्ट्री एक्ट के रूल्स 79 से 85 तक के अनुसार रखा गया। इसमें सी. एल. का कोई प्रावधान ही नहीं है। 18 दिन की अर्न्ड लीव मिलने का प्रोवीजन इसमें है। फिर भी गवर्नमेंट ने इस बात पर गौर किया। अभी उनका जो रिप्रजण्टेशन हुआ, उस पर और गवर्नमेंट ने इस बात को मान लिया कि सी. एल. और दे दी जायगी। यह मैं मानता हूं कि यह एक प्रकार का फैक्ट्रीज एक्ट से बड़ी दुविधा का मामला है कि तीन तीन तरह से वहां के एम्पलाईज को अलग अलग रूल्स के तहत कवर किया जाय, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट में भी प्रिफरेंशल ट्रीटमेंट का क्लोज है और उसमें इन सारी चीजों को रखा गया

(श्री नारायण सिंह).

है। कांस्टीट्यूशन में भी डिस्क्रीमिनेटरी ट्रीटमेंट का प्रोवीजन है और कांस्टीट्यूशन के अनुसार ही रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इस तरह से जो पुराने लोग लगे हुए हैं वे पुराने रूल्स से गवर्न हो रहे हैं, उसके बाद वाले दूसरे रूल्स से गवर्न हो रहे हैं और जब से फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ है वह फैक्ट्री एक्ट मातहत चल रहे हैं। आज समानीकरण की बात ··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो वही बात हुई कि ऊपर वाले बम्बई जा रहे हैं और नीचे वाले कलकत्ता जा रहे हैं, गाड़ी एक ही है। कोई यूनिफिकेशन तो हो।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यूनिफिकेशन की मुझे खुद चिन्ता है। फैक्ट्री एक्ट सब पर लागू हो और जो प्रिविलेजेज दूसरे गवर्नमेंट एम्पलायीज को मिले हुए हैं वे खत्म होने चाहिए। इस बात की चिन्ता मुझे रहती है और फैक्ट्री से बाहर निकालना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इसको स्टेट एण्टरप्राईज के रूप में लिया गया है। मेरी इस दिक्कत को देखते हुए भी इस पर जरूर ध्यान दे रहे हैं कि सरकार द्वारा इस एनोमोली को किस प्रकार ठीक किया जाय।

माननीय सदस्यों ने और जितनी बातें इन मांग पर कही हैं, मैं समझता हूं कि मैं उनके विषय में निवेदन कर चुका हूं और अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस मांग को पारित करने का कष्ट करें।

श्री केदारनाथ : लॉ सेक्रेट्री ने जो रिपोर्ट दी है वही मान लीजिए।

श्री नारायण सिंह मसूदा : उसकी भी जांच करेंगे, देखेंगे और हम आलरेडी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से करें।

श्री उपाध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी।

श्री हरिदेव जोशी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने कई सुझाव निर्माण विभाग के सम्बन्ध में दिए। जो चर्चा यहां पर हुई उसे मैं तीन हिस्सों में बांटता हूं। एक तो निर्माण विभाग के काम के सम्बन्ध में असंतोष। दूसरा अपने क्षेत्र में अथवा अपने जिले के लिए मांग और तीसरा उसके इम्प्रूवमेंट के सम्बन्ध में सुझाव।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं कि जो बजट एलोकेशन किए गए हैं, वह दरअसल नाकाफी हैं और किसी भी रूप में माननीय सदस्यों की मांग अथवा आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते। बल्कि जैसा कि अभी कहा गया है, एक समय ऐसा था जब लगभग दो करोड़ रुपया प्लान में प्रोविजन था थर्ड फाइव ईयर प्लान के पीरियड के अन्दर और आज जब इस बजट के ऊपर चर्चा हो रही है, केवल एक करोड़ रुपया रोड्स के लिए प्रोवाईडेड है। लगभग जनवरी में प्लान एलोकेशन्स में जब इण्डीकेशन दिया गया उस समय 1 करोड़ 71 लाख का इण्डीकेशन दिया गया था और जब बजट माननीय सदस्यों के समक्ष रखने का समय आया, उस समय इसे काट कर एक करोड़ रुपया कर दिया गया। माननीय सदस्यों की

(श्री हरिदेव जोशी)

आकांक्षाएं यह हैं, वे यह समझते हैं कि वे अपने क्षेत्र से इन चुनावों में ताजा ताजा चुन कर आए हैं, लोगों को आश्वासन देकर आए हैं, कई लोग तो नए नए हैं, वे यह समझते हैं कि हम लोगों को कह कर आए हैं वह बात अगर पूरी नहीं होगी, तो हमारी मानसिक स्थिति क्या रहेगी, लोगों के सामने हमारी हालत क्या रहेगी। और डिपार्टमेंट की हालत यह है कि जो इण्डीकेशन एक करोड़ 71 लाख का दिया गया था, उसके हिसाब से प्लान बना लिया और प्रोग्राम बना कर डिस्ट्रिक्ट लेवल आफिसर्स को इण्डीकेट कर दिया। अब इसको रिड्यूज करके एक करोड़ में कैसे समेटा जाय। इसलिए कई माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि बजट के किताबों में कई रोड्स के बारे में पांच हजार का प्रोविजन है, इसका मतलब यह है कि यह टोकन प्रोविजन है जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जब कि हालत यह है कि राजस्थान के अन्दर आज भी दो सब डिविजन हैडक्वार्टर ऐसे हैं जो जिले से जुड़े हुए नहीं है। चित्तौड़गढ जिले का प्रतापगढ और भरतपुर जिले का धौलपुर सब डिविजन ऐसे हैं जो जिले से जुड़े हुए नहीं है सड़कों के मामले में। इसी तरह से उदयपुर जिले की तीन तहसीलें आज भी राजस्थान में जिले से जुड़ी हुई नहीं है। इसी प्रकार और भी कई ऐसे स्थान हो सकते हैं। लिंक रोड को छोड़ दीजिए, रिंग रोड्स को भी छोड़ दीजिए और दूसरी रोड्स को भी छोड़ दीजिए, मगर आज तहसीलें डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से जुड़ी हुई नहीं है। यह हमारी स्थिति है। इसमें माननीय सदस्य देखेंगे कि फर्स्ट प्लान में टोटल प्लान एलोकेशन पी. डब्ल्यू. डी. का 10.2 परसेंट था, सेकिंड प्लान 9.9 परसेंट था, थर्ड प्लान में 4.6 परसेंट था और थर्ड प्लान एलोकेशन में 3.02 परसेंट था और अब फोर्थ प्लान के अन्दर 2.47 परसेंट बजट एलोकेशन है। तो अमाउण्ट इस प्रकार से रिड्यूज होता चला गया है, यह हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। इसके कारणों की विगत में आने की आवश्यकता नहीं है। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के अन्दर उन सारी स्थितियों का उल्लेख किया है। किस प्रकार से हमारे ऊपर ओवर ड्राफ्ट बढ़ा, फैमिन रिलीफ के कारण और दूसरी स्थितियों के कारण जिनसे एक प्रकार से हमारा प्लान और बजट सिक होता चला गया और आज जो आपने मांगे रखी हैं उनके लिए सिवाय मेरे पास में सुनने और सहानुभूति प्रगट करने के दूसरा कोई जरिया नहीं रह जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर भी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो एलोकेशन्स हुए हैं उनमें अगर वेरियस एडजस्टमेंट्स के लिए वे सलाह देंगे तो उसके अनुसार किया जाएगा। ऐसी चीजें जिसे वे प्रायरिटि देते हैं जिले में, बैठ कर, मिलकर विचार करें और बतावें तो उनके ऊपर हमें आज फिर से पुनर्विचार करने में कोई एतराज नहीं है। और आज मैं तो निश्चित रूप से इस मत का हूं कि दस सड़कें पांच, पांच हजार की लागत से बनायी जायें अथवा एक सड़क 50 हजार की बनाई जाये इसको माननीय सदस्यों को सोचना होगा। आज हालत यह है कि 11 करोड़, 12 करोड़ के रोड़ वर्क्स हाथ में है और बजट एलोकेशन है केवल एक करोड़ रुपये का। एक भी नई सड़क को हाथ में नहीं लिया

(श्री हरिदेव जोशी)

गया है और बजट एलोकेशन इस तरह का है किस तरह से हम इस काम को पूरा कर पायेंगे। यह आपको कन्डीशन्स हैं और इस हार्ड फेक्टस को सदन को समझना है और मैं सदन के सामने इसीलिए रखना चाहता हूं। ठीक यही स्थिति मेन्टीनेन्स की है। गवर्नमेंट आफ इन्डिया के लोनस् को अगर हम स्टेन्डर्ड लोन माने, आज को हमारी रोडस् हैं, उनकी मेन्टेनेन्स के लिए लगभग साढ़े चार करोड़ रुपया हमको चाहिए। आज जो परमानेन्ट गैंग्स हैं, उनकी सेलेरी अमेनीटिज और मेन्टीनेन्स के ऊपर लगभग पौने दो करोड़ रुपये और 3 करोड़ के करीब मेन्टीनेन्स का खर्च बजट प्रोविजन में मिला है। यह सही है कि जो स्टेन्डर्ड मेन्टीनेन्स होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। हम इस कशमकश में हैं कि एसपीरेशन लोगों की बढ़ी हुई है और हमारे पास में फण्डस् कम हैं। माननीय सदस्यों ने यहां पर जो अपने भाषण में कहा है, मेरा उनसे कोई डिफरेन्स ऑफ ओपीनियन नहीं हैं। इलेक्शन के दरमियान में मैंने कई डिस्ट्रिक्ट का इन्टेन्सिव दूर किया है और मुझे स्वयं यह महसूस होता था कि हमारे रोड्स की हालत खराब है। कोटा डिविजन की बात कहिए, चाहे सवाई माधोपुर की बात कहिए, चाहे नागौर और उस इलाके की बात कहिए, कई माननीय सदस्यों ने अपने इलाकों की बातें इम्फेटिकली कही है और यह बतलाने की कोशिश की है कि उसमें तत्काल कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं यह प्रयत्न करूंगा कि जो बिगड़ी हुई रोड्स हैं वे और ज्यादा न बिगड़े। इसके लिए सफीसियेंट अमाउन्ट इस वर्ष रिपेयर्स का प्रोवाइड किया है, चाहे उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करना पड़े। इस प्रकार से नये काम को आगे ले जाने के बदले जो बिगड़े हुए काम है या जो बिगड़ रहे हैं, उनको हम पहले रिपेअर्स कर सकें, इस प्रकार की कोशिश इस वर्ष के अन्दर की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने गंगानगर जिले में जो कुछ काम हुआ है पिछले समय में उनके बारे में शिकायत पेश की। उन्होंने अथवा दूसरे किसी ने कुछ साइक्लोस्टाइल मेटेरियल भी मुझे सप्लाय किया। मैं उनका आभारी होता अगर वे विश्वास करके और 15 दिन पहले यह लिखकर दे देते तो मैं आज किसी नतीजे पर पहुंच सकता और बतला सकता कि कोई न कोई गलतियां हुई हैं और विभाग में उनके ऊपर क्या कदम उठाये गए हैं। किन्तु जैसे कि गंगानगर से आने वाले चारों माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं उनकी बात पर विश्वास करके नहीं चलता हूं। मैं जो केसेज उन्होंने साइट किये हैं उनको हाइएस्ट लेविल पर इन्क्वायरी करवाऊंगा और यह कोशिश करूंगा कि जो लोग दोषी हैं उनको सजा दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मि० मेहता के बारे में, सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर के बारे में कहा गया। उनके खिलाफ एलीगेशन है उसको विजिलेन्स कमिश्नर के पास भेज दिया गया है और उन्होंने इनक्वायरी करके अपाइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट को अपनी रिपोर्ट भेज दी है, ऐसी सूचना मुझे दी गई है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विजिलेन्स कमिश्नर की जो फाइन्डिंग्स होंगी, गवर्नमेन्ट उससे सहमत होगी और उसी प्रकार से उस पर कार्यवाही करेगी।

(श्री हरिदेव जोशी)

इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ के पिड़ावा एरिया में डेमेजेज हुए हैं–उनके बारे में यहां पर कहा गया है कि इन्जीनियर्स की नेगलीजेन्स के कारण ये हुए है। इनकी भी मैं जांच करवाऊंगा और अगर कोई नेगलीजेन्ट पाया गया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, एस. ई. एन. तिवारी के खिलाफ कुछ एलीगेशन थे, उनके बारे में भी चर्चा आई। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, दोषी प्राइमा फेसी के अन्दर मि० तिवारी को पाया गया और उन्हें सस्पेन्ड कर दिया गया है और दूसरे जो लोग हैं उनको भी सस्पेन्ड कर दिया गया है और डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी चल रही है। मैं सदन को यह विश्वास दिला सकता हूं कि जो जानकार उन्होंने दी है अथवा दूसरे जरिये से विभाग के पास अथवा मेरे पास आयेगी, उसमें किसी को बचाने की कार्यवाही नहीं की जायेगी, चाहे वह कितना ही उच्च अधिकारी ही क्यों न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने उस क्षेत्र के अन्दर कम पैसा खर्च हुआ, इस क्षेत्र के अन्दर कम पैसा खर्च हुआ, इस प्रकार की बातें कही है। अपनी बात को कहते हुए गंगानगर जिले से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा है कि गंगानगर की सड़कों की हालत खराब है। मैंने इस सारी लिस्ट को उठाकर देखा है और राजस्थान में सबसे ज्यादा खर्च सड़कों पर कहीं हुआ है तो वह गंगानगर जिले में हुआ है। कई गरीब बेचारे जिले तो ऐसे हैं कि उनको गंगानगर के बराबर हुए खर्चे के लगभग एक चौथाई भी नहीं मिला है उसके बराबर भी नहीं पहुंच पाते हैं। गंगानगर जिले के ऊपर अब तक कुल खर्चा 584 लाख हुआ है और जबकि उदयपुर जिले के ऊपर जो कि उसका डेढ़ गुना है ढाई लाख का खर्चा हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : आप इसमें राजस्थान कैनाल को भी जोड़ रहे है?

श्री हरिदेव जोशी : क्या इसमें राजस्थान की जनता का पैसा नहीं है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह डेवलपमेन्ट स्कीम है।

श्री हरिदेव जोशी : किसी भी स्कीम के तहत हो, राजस्थान की जनता उस पर टैक्स देती है जो डेवलपमेन्ट गंगानगर के अन्दर हो रहा है, मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य जो राजस्थान कैनाल की रोड्स हैं, वह मानेंगे कि उस पर जीपें चलती है, ट्राफिक होता है। चाहे वह प्लान रोड्स हों उन पर गाड़ियां तो चलेंगी ही।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : कहने का अर्थ यह है–

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी प्रार्थना करने का अर्थ यह है

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें आर. सी. पी की रोड्स है वे तो केवल कागजों पर हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसको जांच करवा लूंगा।

(श्री हरिदेव जोशी)

परन्तु लायन शेयर गंगानगर जिले को मिला है । इसकी शिकायत उनको नहीं होनी चाहिये । इर्रीगेशन में हो, चाहे डवलपमेन्ट में हो, वह गंगानगर में ज्यादा हुआ है । रोड्स के डवलपमेन्ट को अगर लिया जाये तो उसमें भी गंगानगर आगे है । कोलोनाइजेशन के डवलपमेन्ट को अगर लिया जाये तो उसमें भी गंगानगर आगे है । शिकायत तो उन लोगों की होनी चाहिये जहां कि आज तहसील हैडक्वार्टर जिले से जुड़े हुए नहीं हैं । सब डिविजनल हैड क्वार्टरस् जिले से जुड़े हुए नहीं हैं । मैं माननीय सदस्यों से यह भी प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी ग्रिवेन्सेज को रखते हुए रेशनल होने की कोशिश करें । अपनी ग्रिवेन्सेज को रखते हुए थोड़ा संतुलित होने की कोशिश करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी कान्स्टीट्युन्सीज की बातें को कहा है । मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं किन्तु फिर भी उनमें से प्रत्येक को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है वह मैंने लिख लिया है......

श्री सांवरमल मोर : और जिनको बोलने का मौका नहीं मिला है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रोसीजर के विपरीत है ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं कोशिश करूंगा कि उनकी ग्रिवेन्सेज को भी किसी हद तक मीट कर सकता हूं तो करूंगा । इसमें कहीं पोलिटिक्स नहीं आती । यह प्रश्न नहीं है कि माननीय सदस्य किस पार्टी के हैं और किस पार्टी के नहीं हैं । मेरा यह प्रयत्न होगा कि जितना भी ज्यादा जुडिशियसली इसमें एलोकेशन्स कर सकें उतना करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन डिटेल्स को अपने पास में रख लेता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहा गया कि बोर्डर रोड्स के बारे में कुछ शिकायतें थीं, उनकी कोई एन्क्वायरी हुई ? ये शिकायतें आई थीं । गवर्नमेंट आफ इंडिया की ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री उसकी एन्क्वायरी कर रही है । इसलिए जब गवर्नमेंट आफ इंडिया इस मेटर से सीज्ड है, और वह गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास में है तो मैं पिक्चर में नहीं आता ।

उपाध्यक्ष महोदय, फ्लड्स की रिपेयर्स के बारे में डिफेन्स रोड्स के बारे में कहा गया तो हमने अपने एस्टीमेट्स भेज दिये हैं । उन्होंने कहा कि एस्टीमेट्स भेज दो तो हमने उसी समय अपने एस्टीमेट्स भेज दिये हैं । गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास में विचाराधीन हैं ।

तो उसी तरह से फ्लड डेमेजेज के बारे में गवर्नमेंट आफ इंडिया की यह ताकीद थी कि 1971–72 की जनवरी तक ही इन सभी की रिपोर्ट्स आ जाना चाहिए और वह काम हो जाना चाहिए । इसलिए जितने रिपेयर्स हो सकते थे उनको करवाकर उनकी रिपोर्ट भेज दी गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर नजूल प्रापर्टी के बारे में और ई. एस. आई. की डिस्पेन्सरी के बारे में बात कही गई । माननीय सदस्यों ने कहा कि छतें चू रही हैं और ई. एस. आई. की डिस्पेन्सरी की

Page No 146

(श्री हरिदेव जोशी)

दीवार के अन्दर क्रैक आ गई है और डिपार्टमेंट ने मुझ से यह कहा है कि यह चीज सही नहीं है। मैं जब तक माननीय सदस्य इसको फिर से वह नहीं करते मैं डिपार्टमेंट की बात को इसलिए सही मानकर चलता हूं कि अभी तक उसके ऊपर एक साल ही गुजरा नहीं है इसलिए छत के चूने का सवाल ही पैदा नहीं होता है....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप खुद जाकर देख लें।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे क्षमा करेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अजमेर रोड पर है।

श्री उपाध्यक्ष : आप उत्तर को शान्तिपूर्वक सुनें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह अजमेर रोड पर है आप खुद मुलाहिजा फर्मा लें कि छत पर डामर डली हुई है। मेरे पास उसके फोटोग्राफ्स थे आज इत्तिफाक से भूल आया हूं। क्रैक्स को मैं देखकर आया हूं और फोटोग्राफ्स लेकर आया हूं।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जब सीमेंट की छतें डाली जाती हैं तब कई मर्तबा क्रैक आते हैं तो डामर से उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। प्राइवेट मकानों में भी यह करना पड़ता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप 18 हजार रुपये महीने के क्यों दे रहे हैं? क्या इसकी आपको सूचना नहीं है? न तो वहां पर वाटर है न लाइट है और आप स्टॉफ को एन्गेज करके 18000 रुपया महीना क्यों दे रहे हैं?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे जो सूचना दी गई है वह यह है कि टेम्पोरेरी कनेक्शन दे दिया गया है और परमानेन्ट कनेक्शन के लिए....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय मैं चैलेन्ज करता हूं अगर वहां पर बिजली पहुंच गई हो तो मन्त्री महोदय मेरे साथ शर्त लगायें। या तो वे इस्तीफा दे दें या मैं इस्तीफा दे दूं....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जब स्टॉफ नियुक्त कर दिया है और मरीज आये नहीं तो....

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपको पता नहीं है कि यह खबर ब्लिट्ज में छपी है और यह सारी इन्फर्मेशन ब्लिट्ज की है।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय की ऐसी सूचना है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : विभाग ने आपको गलत सूचना दी है और मन्त्री महोदय जो उत्तर दे रहे हैं वह गलत दे रहे हैं। जहां पर पैसा खर्च किया जाय .

श्री हरिदेव जोशी : मेहरबानी करके जब आप सारा उत्तर सुनेंगे तब आपको मालूम होगा। अगर आप सुनेंगे नहीं और

(श्री हरिदेव जोशी)

अपनी ठेस में बोलते जायेंगे तो आपने अपनी बात कह दी लेकिन मैं अपनी बात कैसे कहूंगा ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ठेस में बोलने का प्रश्न नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य शान्तिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन जो कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, वह यह है कि मुझे यह इत्तिला दी गई है कि टेम्पोरेरी कनेक्शन दे दिये गये हैं और दूसरी ओर परमानेन्ट कनेक्शन के लिए 10664 रुपये डिपाजिट करवा दिये गये हैं। दूसरी चीज यह है कि पानी का कनेक्शन हो गया है। फिर भी जो माननीय सदस्यों ने कहा है उसकी लाइट में मैं देखूंगा कि कनेक्शन नहीं होने की वजह से हास्पिटल फन्क्शन कर रहा है या नहीं मैं उसको देखने की कोशिश करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जो पेमेन्ट हो गया है करीब 80 हजार डाक्टर्स और नर्सेज पर उनका क्या होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : आई विल लुक इन्टू दी डिटेल्स।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कार्पोरेशन उसको स्टेण्ड करेगी या गवर्नमेंट स्टेण्ड करेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं इमीजियेटली तो इस बारे में नहीं कह सकता हूं कि कौन स्टेण्ड करेगा या क्या करेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जिन अधिकारियों ने गलत खबर दी है उनके अगेन्स्ट में आप एक्शन लेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : अगर गलत साबित होगी तो जरूर लिया जायेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : थैंक यू।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अगर आप जांच करेंगे तो जो सूचना अधिकारी ने दी है उसको आप निश्चित रूप से गलत पायेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जांच तो आप जल्दी कर लेंगे ? ऐसा न हो कि 5 वर्ष निकल जायं जांच करने में।

श्री रोशनलाल शर्मा : आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इसके सिवाय अपने अपने क्षेत्रों की जो बातें कही है उनको मैं निवेदन कर चुका हूं और जिन माननीय सदस्यों ने कट मोशन्स तो दिये हैं किन्तु जिनको बोलने का मौका नहीं मिला है उनके लिए भी मैं यह देखुंगा कि उनकी अगर कोई ग्रीवान्स ऐसी है जिनको मीट किया जा सकता है तो यह कोई जरूरी नहीं कि वह यहां पर बोले हैं जो उनकी तो बातें करली जाय और जो नहीं बोले हैं उनकी बातों को नहीं किया जायेगा। तो मैं यह प्रयत्न करूंगा कि डिपार्टमेन्ट की ओर से उनको जवाब भेज दिया जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ जो मांग पेश की गई है उसको पारित करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री मीठालाल : लालसोट के पास में जो 10-15 साल से पुल बन रहा है उस पर केवल छत डालना बाकी है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं किसी एक पर्टिक्यूलर केस के बारे में विभाग की ओर से कोई आश्वासन देकर ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहता हूं। मैं देखूंगा कि यदि इसको पैसा दिया जा सकता है और काम कराया जा सकता है सो करा दूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर शहर की सड़कों के बारे में निवेदन किया था और नजूल सम्पति के बारे में कहा था उनका उत्तर आपने नहीं दिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको उत्तर देना चाहिए था लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया···

श्री हरिदेव जोशी : मैंने जनरली एक एक रोड की बात नहीं कही है! ···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज तक परिपाटी यह रही है कि कटौती प्रस्ताव पर जो बोलते हैं तो उनको या तो डिबेट में उत्तर मिल जाता है या उनको उनके घर पर उत्तर मिल जाता है। अब यह कहा जा रहा है कि कटौती प्रस्तावों के उत्तर नहीं भिजवायेंगे और यहां पर बोले हैं तो उत्तर नहीं दिया जायेगा। यह बिल्कुल नई परिपाटी है ··

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य को मालूम नहीं है क्योंकि वे नये आने वाले सदस्य हैं। उनको यह पता नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि हर चीज को यहां पर रिपीट किया जाय। अगर 200 चीजें कहीं गई हैं तो 200 चीजों को मैं यहां पर रिपीट करूंगा तो मुझे 6 घण्टे लग जायेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा यह कहना है कि हमारी बातों का उत्तर दिया जाय। जयपुर शहर के हमने जितने प्राब्लम रखे हैं उनमें एक भी बात का···

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कल से एक नई परम्परा आप इस सदन में डाल रहे हैं। बजट के भाषण के जवाब में हर मुख्य मन्त्री बोलते हैं। केन्द्र में भी बजट के बारे में प्रधानमन्त्री बोली थीं। बजट के भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पार्टिसिपेशन नहीं किया है।

श्री केदारनाथ : जो पाकिस्तान एग्रेशन के वक्त में मिलिट्री का मूवमेंट हुआ उसमें जो नुकसान हुआ था उसके बारे में पंजाब में तो पैसा मिल गया है तो हमें क्यों नहीं मिला ?

श्री हरिदेव जोशी : पंजाब को कैसे मिल गया और हमें कैसे नहीं मिला, यह तो मुझे मालूम नहीं है। हमने अपने ऐस्टीमेट्स गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को भेज दिये हैं। इसके बारे में गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखूंगा कि पंजाब के साथ में और हमारे साथ में अलग अलग बर्ताव नहीं किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सरकारी उत्तर के पश्चात् मतदान होता है और कोई प्रक्रिया नहीं है।

श्री रोशनलाल शर्मा : हमेशा से यह परम्परा रही है कि वाद-विवाद के बाद में प्रश्न किये जाते हैं ।

Page No 149

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे चुके हैं मंत्री महोदय, आपने प्रश्न किये हैं उनका जवाब आ चुका है।

श्री रोशनलाल शर्मा : नहीं आया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है कि जवाब खत्म होवे के बाद में प्रश्न रख सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : विधान सभा की छत में क्रैक्स आगये हैं। इसकी जांच के बारे में कुछ कहना चाहिए। जिस छत के नीचे आप बैठे हैं उस पर 10 लाख खर्च हुए हैं। उसके बारे में तो कम से कम आप जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इस संबंध में जवाब दिया जा चुका है।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : मेरा एक प्रश्न यह है कि हमारा बजट का एलोकेशन तो कम होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, अधिक होता जा रहा है जबकि सर्विसेज जो उनमें लगी हुई हैं एक्स. ई. एन., ओवरसियर्स आदि उनकी संख्या, उनकी स्ट्रेन्थ वही की वही हैं और बल्कि बढ़ रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जिसे हिसाब से यह बजट अधिक हो रहा है उसी हिसाब से सर्विसेज को अधिक किया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कमी करें ताकि ये बुड्ढे बाघ जो बैठे हैं जो कि सारे राजस्थान का पैसा खा गये हैं उनसे निजात मिले। उनको घर बैठाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर मतदान! माननीय सदस्य!

श्री रोशन लाल शर्मा : जवाब तो आने दीजिये। मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब दिलाना नहीं चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आ चुका है। माननीय सदस्य, तशरीफ रखिये, काफी समय हो चुका है।

श्री रोशन लाल शर्मा : वह दे रहे हैं, स्टाफ का महत्वपूर्ण सवाल है। सड़कें कम हैं और स्टॉफ बढ़ता जा रहा है जवाब आने दीजिये।

श्री पी. के. चौधरी : मंत्री महोदय यह बतायें, सेन्ट्रल सेक्टर में नेशनल हाई वे के लिए 1971-72 के लिए एलोकेशन था उसमें हेवी शार्ट फाल कैसे हुआ?

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा है, एलोकेशन वर्ष के आखिर के अन्दर रिवाइज नहीं किया गया जो यूटिलाइज नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर मतदान!

प्रश्न यह है, मांग संख्या 28, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य, 50-सार्वजनिक और निर्माण कार्य भवन सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा ओजार और स्थिर संयंत्र पर व्यय, 52-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13, 16, 56, 000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

Page No 150

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : नो नो नहीं, इनको (श्री गिरधारी लाल भार्गव) कहिये, हां कहें।

श्री पी. के. चौधरी : मांग पारित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : मांग पारित की गई।

प्रश्न यह है, मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–109–अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

आर्डर प्लीज !

श्री रोशन लाल शर्मा : एक ही ना की आवाज आई।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : एक ही बहुत है

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक-68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,15,53,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांगें स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 5.32 बजे मंगलवार दिनांक 9-5-72 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

परिशिष्ट 1 (क)

(तारांकित प्रश्न संख्या 351 की सूची)

सूची उन निरीक्षकों की जिनका फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ है

क्रम संख्या	नाम निरीक्षक
1	2
1.	श्री योगानन्द गुप्ता
2.	श्री श्रीराम वर्मा
3.	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव
4.	श्री रामगोपाल पुरोहित
5.	श्री प्रेम प्रकाश तनेजा
6.	श्री विरेन्द्र कुमार गुप्ता
7.	श्री रोशनलाल गुप्ता
8.	श्री ललितचन्द्र बंसल
9.	श्री पुरुषोतमलाल मेहता
10.	श्री गोपाल लाल मित्तल
11.	श्री वानसदास त्रिपाठी
12.	श्री राम स्वरूप
13.	श्री राम किशोर
14.	श्री गोपाल दास यादव
15.	श्री परमहंस
16.	श्री रघुवीर शरद्द गोयल
17.	श्री सुरेन्द्रकुमार त्रिवेदी
18.	श्री अशोक कुमार व्यास
19.	श्री पारसचन्द बसाली
20.	श्री यशवन्तराज जोशी
21.	श्री राधाकिशन पुरोहित
22.	श्री बद्री प्रसाद व्यास
23.	श्री बनवारीलाल गोडवाल
24.	श्री प्रतापसिंह मान
25.	श्री असरफी लाल वर्मा
26.	श्री हरीप्रसाद भटनागर
27.	श्री पी. वी. वाडवानी
28.	श्री रमेश कुमार शुक्ला

Page No 152

1	2
29.	श्री रामजीलाल भार्गव
30.	श्री दौलतसिंह सोलंकी
31.	श्री शोभाराम पंवार
32.	श्री बजरंगराज लोढा
33.	श्री शफी मोहम्मद शेख
34.	श्री कैलाश चन्द्र बोडिया
35.	श्री पूनमचन्द गर्ग
36.	श्री बुधराज भण्डारी
37.	श्री मनोहरलाल सोमानी
38.	श्री गणेशनारायण माथुर
39.	श्री शिवसिंह चौधरी
40.	श्री अकबर खां
41.	श्री जमनालाल पारख
42.	श्री ब्रिजकिशोर श्रीवास्तव
43.	श्री रामेश्वर दत्त आसोपा
44.	श्री हरगोविन्द तिवाडी
45.	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता
46.	श्री हनुमान सहाय पारीक
47.	श्री प्रकाश चन्द्र जैन
48.	श्री रामेश्वर प्रसाद पुष्करना
49.	श्री पदमचन्द जैन
50.	श्री लक्ष्मीनारायण वर्मा
51.	श्री प्रेमनारायण माथुर
52.	श्री केदारनाथ शर्मा
53.	श्री रोशनलाल गुप्ता
54.	श्री भंवरलाल महेश्वरी
55.	श्री छोटेलाल गुप्ता
56.	श्री शान्तिलाल चौबीसा
57.	श्री मगनबिहारी सक्सेना
58.	श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा

परिशिष्ट (ख)

सूची उन निरीक्षकों की जिनके नाम वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किये गये हैं

क. सं.	नाम निरीक्षक	विभाग जिससे आये थे
1	2	3
1.	श्री लक्ष्मण दास	पंचायत विभाग
2.	श्री शिवसिंह	,,
3.	श्री बद्री प्रसाद	,,
4.	श्री हाकिम सिंह	,,
5.	श्री रघुवीर शरण	,,
6.	श्री बलवन्तसिंह	,,
7.	श्री बी. डी. भार्गव	,,
8.	श्री चैनसिंह	,,
9.	श्री रामगोपाल	,,
10.	श्री विरेन्द्रसिंह	,,
11.	श्री जगन्नाथ प्रसाद	,,
12.	श्री नटवरलाल	,,
13.	श्री गजराज सिंह	,,
14.	श्री ललुनारायण	,,
15.	श्री प्रतापसिंह मान	,,
16.	श्री जमनालाल	,,
17.	श्री भंवरलाल रामदिसानी	,,
18.	श्री धन्नीराम	,,
19.	श्री राजेन्द्रसिंह	,,
20.	श्री एस. एन. सचदेव	,,
21.	श्री छोटेलाल	,,
22.	श्री जी. के. दीवन्डो	भू प्रबन्ध विभाग
23.	श्री जसवन्तराज जोशी	,,
24.	श्री दानाराम	,,
25.	श्री हुक्मसिंह	,,
26.	श्री मुकुट बिहारी	,,
27.	श्री मनोहरलाल	,,
28.	श्री लाडलीप्रसाद	,,

1	2	3
29.	श्री मांगीलाल	भू-प्रबन्ध विभाग
30.	श्री दौलतसिंह	,,
31.	श्री गोपालदास	,,
32.	श्री अर्जुनलाल धुपाल	राष्ट्रीय बचत योजना
33.	श्री सुरेशनारायण माथुर	,,
34.	श्री ललीतचन्द्र बंसल	,,
35.	श्री नन्दलाल गुप्ता	,,
36.	श्री मुन्नालाल अग्रवाल	,,
37.	श्री श्यामसुन्दर शर्मा	,,
38.	श्री सान्तीलाल चौबीसा	,,
39.	श्री प्रेमनारायण माथुर	,,
40.	श्री सूर्यनारायण जोशी	,,
41.	श्री पी. एन. श्रीवास्तव	,,
42.	श्री देवीसिंह चौहान	,,
43.	श्री हनुमानसहाय पारीक	,,
44.	श्री जयसिंह राठौड़	,,
45.	श्री वैद्यनाथ पंवार	,,
46.	श्री एल. एम. शर्मा	पुनर्वास विभाग
47.	श्री रतनलाल मलहोत्रा	,,
48.	श्री ए. एस. माथुर	,,
49.	श्री एम. आर. जोटवानी	,,
50.	श्री के. एन. माथुर	,,
51.	श्री एस. ए. बुलन्द	,,
52.	श्री द्वारका प्रसाद	,,
53.	श्री पी. बी. बाडवानी	,,
54.	श्री प्रेमलाल	,,
55.	श्री गणेशनारायण माथुर	खाद्य विभाग
56.	श्री मगनबिहारी सक्सेना	खाद्य विभाग
57.	श्री रामकिशोर	उद्योग विभाग
58.	श्री अकबर हुसेन	,,
59.	श्री मोहनप्रसाद शर्मा	,,
60.	श्री एच. के. टण्डन	सिंचाई विभाग
61.	श्री पी. सी. गर्ग	,,

Page No 155

1	2	3
62.	श्री जी. आर भण्डारी	सिंचाई विभाग
63.	श्री कैलाशचन्द्र बोडिया	,,
64.	श्री एस. पी. मुखपाल	,,
65.	श्री एस. जेड. मोहम्मद	,,
66.	श्री पी. एन. माथुर	,,
67.	श्री एल. पी. जोशी	,,
68.	श्री डी. आर. मनोत	,,
69.	श्री एस. एम. शेख	,,
70.	श्री कैलाशचन्द्र गुप्ता	उद्योग विभाग
71.	श्री फरीदुदीन खान	,,
72.	श्री प्रेमप्रकाश तनेजा	,,
73.	श्री जगदीश प्रसाद	,,
74.	श्री विजय प्रकाश गर्ग	,,
75.	श्री चान्दमल राठी	,,
76.	श्री मगनसिंह चौधरी	,,
77.	श्री नरेन्द्र प्रसाद माथुर	,,
78.	श्री बृजमोहन जैन	,,
79.	श्री ओम प्रकाश गर्ग	,,
80.	श्री श्यामलाल जैन	,,
81.	श्री इन्द्रमोहन मल्होत्रा	,,
82.	श्री बांके बिहारी लाल गुप्ता	,,
83.	श्री रोशनलाल गुप्ता	,,
84.	श्री भंवर लाल महेश्वरी	,,
85.	श्री रमेशचन्द्र गुप्ता	,,
86.	श्री योगानन्द गुप्ता	,,
87.	श्री ओमप्रकाश मंगल	,,
88.	श्री रामगोपाल पुरोहित	,,
89.	श्री अब्दुल गफार	,,
90.	श्री मीठनलाल भाबा	,,
91.	श्री बनवारीलाल वर्मा	,,
92.	श्री पदमचन्द जैन	,,
93.	श्री आर. के. पालीवाल	,,
94.	श्री प्रेम बहादुर श्रीवास्तव	,,

1	2	3
95.	श्री ओमप्रकश शर्मा	उद्योग विभाग
96.	श्री ए० पी. रामदेव	,,
97.	श्री इकरामुद्दीन कुरेशी	,,
98.	श्री हरीशचन्द्र गोधा	,,
99.	श्री जे० डी० उपरोली	,,
100.	श्री मूलचन्द्र शुक्ला	,,
101.	श्री एस ०पी० कौशिक	,,
102.	श्री गुमानसिंह	,,
103.	श्री शोभाराम झंवर	,,
104.	श्री एम. एल. गुप्ता	,,
105.	श्री भगवान सहाय शर्मा	,,
106.	श्री हरीप्रसाद भटनागर	,,
107.	श्री मोहनलाल भण्डारी	,,
108.	श्री अशोक कुमार व्यास	,,
109.	श्री विरेन्द्र कुमार गुप्ता	,,
110.	श्री रोशनलाल गुप्ता	,,
111.	श्री वेदप्रकाश अग्रवाल	,,
112.	श्री पारसचन्द बंसाली	,,
113.	श्री बनवारीलाल यादव	सोल्ट इन्सपैक्टर
114.	श्री गणेशदत्त शर्मा	,,
115.	श्री टी० एन० मल्होत्रा	,,
116.	श्री जे० एन० कोल	उद्योग विभाग

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 352 में उल्लिखित नियम)

Government of Rajasthan

Town Planning Department

NOTIFICATION

Jaipur the 2-9-1965

No. F.4/32/LSG/59 :-In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government hereby makes be following amendment to the Rajasthan Improvement Trust (Co-ordination between the Municipalities and the Improvements Trusts with regard to construction of Buildings) Rules, 1964, namely.

Amendment

In the said rules,

1. in rule 2;

(i) for sub-rule (1) the following shall be substituted namely :-

(I) In the area within the jurisdiction of the Trust whenever a Building is proposed to be erected re-errected, or altered or added, a plan shall be furnished to the Improvement Trust concerned and a copy thereof to the Municipality concerned duly prepared in accordance with the bye-laws framed under section 170 of Rajasthan Municipalities Act, 1959."

(II) In sub-rule (2) the expression 'fifteen days occurring after the expression' within a period of (shall be substituted by the expression 'thirty days'.

By Order of the Governor.
Sd/- SHER SINGH,
Secretary to the Government.

NOTIFICATION

Jaipur the 22nd May, 1964

No. F. 4/32/LSG/59 :- In exercise of the powers conferred by clause 74, sub-clause 1 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959) the State Government hereby makes the following rules namely :-

Page No 158

1. Short title and commencement.

1. These rules may be called the Rajasthan Improvement Trust (Co-ordination between the Municipalities and the Imrovement Trusts with regard to construction of Buildings) Rules, 1864.

2. The rules shall come into force upon their publication in the Official Gazette.

2. Co-ordination between Municipal Board Council and the Trust in matters of construction of Buildings.

1. In area in respect of which the Improvement Trust having jurisdiction has framed a scheme and the same has been notified under sub-section 1 of section 32 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 and the said notification is in force, whenever, a building is proposed to be erected, re-erected, altered or added a plan shall be furnished to the Improvement Trust concerned and a copy there of to the Municipality concerned duly prepared in accordance with the by-laws framed under section 170 of the Rajasthan Municipalities Act, 1959.

2. The Improvement Trust shall scrutinise the plans so received and ensure that the plan is conformity with the Scheme in force in the arae or does not run counter to any master plan under preparation for recommendations to the Municipality within a period of fifteen days from the date of receipt of such plan.

3. If the Improvement Trust has approved of the plans the Municipal Board/Council shall sanction the same. If however, the Trust has suggested modifications the plans shall be returned to the applicant for carrying out the modifications in the light of the recommendations of the Trust, and for presentation thereafter, directly to the Municipal Board/Council for sanction.

3. The presentation fee etc. will be charged by the Municipal Board/Council.

By Order of the Governor.
Sd/- P. N. SETH,
Dy. Secretary to the Govt.

Page No 159

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. संख्या 356 की सूची)

संस्था का कार्य संचालन एक बोर्ड करता है जिसके निम्न पदाधिकारी एवं सदस्य हैं—

1. प्रेसीडेन्ट — श्री राम कुमार लाल श्री वास्तव, एडवोकेट।
2. सेक्रेटरी — श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह, एडवोकेट।
3. ट्रेजरार — सरदार सेवा सिंह
4. सदस्य — श्री लक्ष्मीनारायण शुक्ला, एडवोकेट।
   — श्री बी. एच. धावन, एडवोकेट।
   — श्री धीनाथ सिंह, एडवोकेट।
   — डॉ. एस. मलिक।
   — श्री मोहम्मद अमीन।
   — सरदार हरभजन सिंह।
   — हाजी टी. उल्ला।
   — श्री शोभा नाथ मिश्रा।
   — श्री शारदा सिंह।
   — श्री जयनारायण वर्मा।
   — श्री रुद्र प्रताप सिंह।
   — श्री पुरदिलराम।
   — श्री हरगोविन्द।
   — श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह, एडवोकेट।
   — श्री केदारनाथ सिंह।

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 359 की सूची)

नाम नगरपालिका	स्वीकृत राशि निर्माण कार्य हेतु वर्ष 1971-72	विशेष विवरण
बून्दी	51,778/-	राशि इस वर्ष में व्यय की जायेगी।
लाखेरी	13,725/-	,,
केशोरायपाटन	12,171/-	,,
नैनवा	वर्ष 1971-72 में कोई अनुदान निर्माण कार्यों के लिए नहीं दिया गया है।	

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 360 की सूची)

1. दमोई खुर्द	2. दमोई कलां	3. भीयां खुर्द
4. भीयाँ कलां	5. डोबरी कलां	6. डोबरी चावलदास
7. डोबरी मन्द	8. डोबरी खुर्द	9. सरनावडा
10. शिवराशी	11. जसवन्तपुरा	12. मुनवडा
13. खरडिया	14. धापरा	15. मुण्डा खेड़ी
16. रामलिया	17. मनानी	18. मनाना
19. डुबिया	20. मोडी चारण	21. मोडी भीखा
22. गेडा कलां	23. डावरिया	24. गेडा खुर्द
25. जखमालिया	26. रानी गांव	27. उचेरिया
28. कुडी	29. सिरिणयां	30. बलाधना
31. बिन्जारी	32. कल्याणपुरा	33. गोठडी
34. भवाद	35. मण्डुपुरा	36. इण्डोका
37. लखालिया	38. नवाद	39. जिवाबिया
40. धाधन्वा	41. रातलिया	42. भासरखा
43. मंगलाव	44. गच्छीपुरा	45. पावा
46. कुचेटिया	47. धोरज	48. अमरसर
49. धीरजपुरा	50. मोखमपुरा	51. वेसरोली

परिशिष्ट 6

(ता. प्र. सं. 349 की सूची)

पाली जिला:—

1. लालकी	2. बाकरीवाला	3. बाटिया
4. मुकनपुरा	5. नीमलीउरा	6. बेगरिया
7. सांवलता खुर्द	8. सांवलता कलां	9. घोगाना
10. भाटन	11. बाडाई	12. चोटिला
13. बीटु	14. मोरिया	15. भुरयानी
16. कलाल	17. रामपुरा टिगरा	18. नीमली मारामीनों का
19. दुदिया	20. निमली पाठेलों का	21. डाबर कलां
22. मांडली घर जिम्रा	23. मोडिया	24. गरदावरी के दर्रे
25. रुपावास	26. मूलियावास	27. मुकारली
28. जैतपुर	29. गुरवालिया	30. बिन्जा
31. सार की घानी	32. चंडा	33. खुप्लानी
34. मीडावास	35. पचपदरिया	36. गुडिया
37. दयालपुरा	38. लापोद	39. विघुड़ा
40. बचुंडा	41. चानोद	42. मावनगर
43. सुन्डेलाम्रो	44. सकादड़ा	45. पेनवा
46. भाटलो की घानी	47. बलदेवों की ढाणी	48. केरला
49. किरवां	50. गुडा एन्डला	51. भरवाड़ा
52. साली	53. बालराई	54. हटलाई
55. सवाईपुर	56. टोन्गावास	57. कनाम्दरा गांव
58. ढोला	59. रामलिया	60. हेमावास
61. गुडा सोलिगड़ा	62. कानेलामो	63. बाला
64. डेन्डा	65. कुरिया	66. पादरला
67. दिगाई	68. बेतपुरा	

जोधपुर जिला :— लूनी पंचायत समिति

1. गुडा विश्नोई का	2. खोजरली कलां	3. खोजरली खुर्द
4. मोगर कलां व खुर्द	5. खारावेरा	6. निम्बला
7. धानड़िया	8. खारावेरा पुराहितों	

परिशिष्ट

(अ. ता. प्र. सं. 116 की सूची)

प्रशिक्षित एस. टी. सी. बेरोजगार अध्यापक

जिला 1	बेरोजगार अध्यापक 2
1. भीलवाड़ा	381
2. नागौर	217
3. जोधपुर	123
4. चित्तौड़गढ़	94
5. बाड़मेर	17
6. श्री गंगानगर	481
7. अजमेर	1366
8. चूरू	21
9. जयपुर	859
10. बांसवाड़ा	77
11. सिरोही	87
12. सीकर	272
13. भरतपुर	698
14. बूंदी	147
15. पाली	176
16. अलवर	439
17. उदयपुर	453
18. झालावाड़	247
19. झुंझुनू	241
20. डूंगरपुर	152
21. टोंक	75
22. जैसलमेर	3
23. बीकानेर	158
24. कोटा	380
25. जालौर	37
26. सवाई माधोपुर	406
कुल प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक	7,510

परिशिष्ट 8

(स्थगित प्रश्न संख्या 16 की सूची)

सूची परिशिष्ट (क)

वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं की सूची:—

1. दिनांक 15-10-71 को बिना राजकीय आदेशों के तत्कालीन अधिकारी श्री डी.पी. माथुर को कार्यमुक्त कर देना और श्री प्राणचन्द्र चौधरी को अधिशासी अधिकारी का का ' भार सम्भलवाना।

2. बैंक के वर्तमान व्यवस्थापक, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा बैंक की सोचनीय आर्थिक स्थिति को अनदेखा करके कश्मीर काफ्रेन्स भाग लेना ।

3. बैंक में बिना आवश्यकता के दो सुपरवाईजर की नियुक्ति अनियमानुसार बिना स्क्रीन्य के की गई।

4. बैंक की जीप गत 6 माह से बे मरम्मत पड़ी है और उसकी मरम्मत नहीं करवा कर गाड़ी किराये पर ली जाती है जिसमें भारी धन का व्यय हुआ है।

शुद्धि-पत्र

सोमवार, दिनांक 8 मई, 1972

स्तम्भ सं०	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
2	ऊपर से	3	रजस्थान	राजस्थान
3	अन्तिम से	13	प्रद्यम्नसिंह	प्रद्युम्न सिंह
8	ऊपर से	1	फुड	फूड
27	,,	5	लगी	लगा
	अन्तिम से	5	हुम्रा	हुआ
73	ऊपर से	6	क	—
	,,	12	श्री हरसहायक	श्री हरसहाय
	,,	12	हल्या	हल्का
	,,	14	हल्या	हल्का
	...		में	को
	अन्तिम से	12	हिादुस्तान	हिन्दुस्तान
82	,,	16	है	था
	,,	18	कराई	पराई
86	,,	18	विभत्स	वीभत्स
97-98	शीर्ष		र	पर
107	ऊपर से	7	श्री चिमन सिंह	श्री चिम्मन सिंह
113	,,	1	नीम का थाना	—
116	अन्तिम से	14	मगराज	भगराज
145-300	शीर्ष		अनुदानों की मांगों	अनुदानों की मांग सं० 28, 33 व 43
147-	,,	9	दुल्हान	दुल्हन
150	,,	7	फासन्झिने कयेट	फाइनेन्स क्रियेट

1	2	3	4
156	अन्तिम से	17 अल्दी	जल्दी
	,,	4 को	की
158	ऊपर से	7 के किसी	के वाद किसी
247	,,	13 सोचनीय	शोचनीय
248	से	13 धोड़ा	घोड़ा
261	ऊपर से	1 जान मोहम्मद	श्री जान मोहम्मद
264	,,	8 हम.ारे	हमारे
267	,,	8 करया	कराया
269	,,	16 की	—
	,,	6 मिलना	मिलनी
273	अन्तिम से	1 योजनायें	योजनायें
274	ऊपर से	7 जिॉल	जिलों
	,,	15 तब	जब
	अन्तिम से	12 पायेगा	पायेंगे
275	ऊपर से	8-11 मालुम	मालूम
	अन्तिम से	8 डिण्माड्स	डिमाण्ड्स
276	ऊपर से	4 मालुम	मालूम
277	,,	19 जब	जो
285	ऊपर से	8 लोनस	लोन्स
286	ऊपर से	17 जानकार	जानकारी
289	,,	13 क्वार्टरस	क्वार्टर्स
	,,	20 बातें	बातों
290	,,	16 फ्लड्स की रिपेयर्स के बारे में डिफेन्स रोड्स के बारे में	फ्लडस से टूटी डिफेन्स रोड्स की रिपेयर्स के बारे में
290	अन्तिम से	9 जाना	जानी
291	ऊपर से	4 मैं	—
294	ऊपर से	1 श्री योगेन्द्रनाथ	श्री योगेन्द्रनाथ

1	2	3	4
297	अन्तिम से	9 श्रिक	स्रिक
	,,	8 श्रिक	स्रिक
298	,,	11 सार्वजनिक और निर्माण कार्य भवन सड़के	सार्वजनिक निर्माण कार्य भवन और सड़कें
301	,,	13 शरह	शरण
	,,	10 बसाली	भंसाली
302	ऊपर से	5 शकी	शफी
303	अन्तिम से	15 श्री ललुनारायण	श्री लल्लूनारायण
304	ऊपर से	6 श्री ललीत चन्द्र	श्री ललित चंद्र
	,,	10 श्री सान्तीलाल	श्री शान्तिलाल
307	,,	11 Improvments	Improvement
	,,	19 re-errected	re-erected
308	,,	5 1864	1964
		6 The	These
		19 by-laws	byelaws
		23 arar	area
309	ऊपर से	8 श्री धीनाथ	श्री श्रीनाथ
	ऊपर से	7 का	कार्य
313	,,	8 वक	बैंक
	,,	8 सोचनीय	शोचनीय
	,,	9 काफ्रेन्स भाग	कांफ्रेन्स में भाग
	,,	11 स्ट्रेंथ	सैंक्शन